

शिक्षा में नए आग्राम एवं नवाचार

श्रीमती सरला चड्ढा,
एड. एड.

विशाल प्रकाशन
45, माला बुन्दाराद, इलाहाबाद-201002

प्रकाशक

विशाल प्रकाशन

45, सराय खुन्दाबाद

इलाहाबाद-211001

•

लेखक

•

मूल्य 40 रुपये

प्रथम संस्करण 1982

•

पचमीय मुद्रणालय

१८, राय रामचरण दास रोड

इलाहाबाद-211002

अपनी बात

मध्य प्रदेश अनेक विविधताओं एवं विरोधाभासों का राज्य है। शिक्षा में यहाँ अनेक प्रयोग, नवाचार होते रहते हैं तथा नए आयाम खुलते रहते हैं। औपचारिकतर शिक्षा के मध्य प्रदेश मॉडल की रूपाति इतनी फैली कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने इसे देश के सम्पूर्ण राज्यों के लिए अनुशसित किया है। "होशंगाबाद विमान" का अभिनव प्रयाग जा यहाँ चल रहा है देश में अद्वितीय है। 'पढ़ा और कमाओ' योजना मूर्त रूप में देखी जा सकती है। हम लगता है कि हम कुछ ऐसे अंधरे में हैं कि हमें अपना हाथ ही नहीं सूझता है। हमारे आसपास, देश व प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है इसकी अद्यतन जानकारी इस पुस्तक में मिल सकेगी। वर्ष 80-81 से प्रदेश के बी० एड०, एम० एड० पाठ्यक्रम में नवाचारा, नए आयामों को समाविष्ट किया गया है। इन सभी की एक साथ जानकारी यहाँ उपलब्ध हो सकेगी। श्री सुरेश चन्द्र जी द्विवेदी, एम० ए०, एम० एड०, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष लोक शिक्षण सचालनालय म० प्र० तथा अन्य विद्वत्तजनों के हम आभारी हैं जिनकी प्रेरणा और मार्ग दर्शन से यह पुस्तक लिखी जा सकी है।

हम लोग विद्वान तो नहीं हैं लेकिन 'व्याहें न बारात गए' की श्रेणी के भी नहीं हैं। जा कुछ देश व प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, होन के लिए विचार मथन चल रहा है उसे लिख दिया। "निज वचित केहि लाग न नीका" के अनुसार हम लोग क्या कह, बी० एड०, एम० एड० के छात्र गण, विद्वान शिक्षक प्रशिक्षक तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले, शिक्षा में शाश्वत बनाने वाले विद्वत्तज ही इसका निणय कर सकेंगे कि इसमें 'नाना पुराण निगमागम सम्मतम् यद' के अलावा "वचित अयतोपि" है।

यदि शिक्षा में रुचि रखने वाला, छात्रा, एवं शोधार्थियों को इससे कुछ लाभ हुआ तो हम लोग अपनी मेहनत सफल समझेंगे।

बन्त पचमो

1982

उमा शर्कर चतुर्वेदी

तथा

धोमती सरला चतुर्वेदी

पूज्य पिता जी (दादा जी)

को

सादर
समर्पित



अनुक्रमणिका

1	औपचारिकतर शिक्षा	1
2	जनसख्या शिक्षा	18
3	बालिका शिक्षा	33
4	आदिवासियों की शिक्षा	46
5	हरिजनो की शिक्षा	58
6	प्रौढ शिक्षा	65
7	पर्यावरणीय शिक्षा	75
8	दूरदर्शन द्वारा शिक्षा	84
9	पढो और कमाओ योजना	90
10	शांता संगम योजना	103
11	हाशगबाद विज्ञान योजना	111
12	शालेय शिक्षा से सम्बन्धित यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं	121
	(i) प्रायोजना क्र०—1 प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण योजना ।	
	(ii) प्रायो० क्र०—2 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण ।	
	(iii) प्रायो० क्र०—3 सामुदायिक शिक्षा एवं सहयोग की विकासात्मक गतिविधियां ।	
	(iv) प्रायो० क्र०—4 पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं परिवेश की स्वच्छता ।	
	(v) प्रायो० क्र०—5 प्राथमिक शिक्षा का व्यापक उपागम ।	
13	भारत में पञ्चवर्षीय योजनाएँ तथा शैक्षिक आयोजन	141
14	इकाई शिक्षण एवं सतत् मूल्यांकन योजना	160
15	प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापकरण	165
16	छात्रवृत्तियाँ एवं प्रतिभा की खोज	17

17	सूक्ष्म शिक्षण विधि	187
18	अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण	193
19	म० प्र० मे अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	200
20	शिक्षा के राज्य स्तरीय संस्थान	206
21	शैक्षिक सप्ताहकार, परामर्शदात्री एवं अन्य परिषदें/ समितियाँ	214
22	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान एवं वाणिज्य शिक्षा निधि समिति	227
23	पाठ्यपुस्तकें एवं पाठ्यक्रम का नवीनीकरण	232
24	शैक्षिक सांख्यिकी	243

औपचारिकेतर शिक्षा^१

(Non-Formal Education)

शिक्षा पद्धति में हम हमेशा सखीर के फकीर रहे हैं । अग्रेजी से प्राप्त शिक्षा पद्धति का हम ढोल पीटत आए हैं । हम किसी भी पद्धति में डरत-डरते बसाव करते हैं । शिक्षा का सही दिशा में मोड़ने के लिए अनेक बार चिंता हुई, प्रयास हुए लेकिन यथा स्थिति ही बनी रही । हमन उन माता पिता या सरक्षक का कुछ ध्यान नहीं रखा जो खेती-किसानी या अथवा धंधा में लगे हैं, गरीब हैं और अपने बालकों को शाला नहीं भेज पाते हैं । हमारा देश 80 प्रतिशत गावों में बनता है । किसानों के विचार आज भी शिक्षा के विषय में हैं कि "अधिक पढ़े ता घर से गए, छोटे पढ़े तो हल में गए", अर्थात् अधिक पढ़े जाने पर बालक घर से दूर चला जाता है और कम पढ़ने पर हल चलाने से दूर भागता है । जब हमारे कृषि प्रधान देश के किसान अपने बच्चा की शिक्षा के प्रति ये विचार रखते हैं तो यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों, देश के कणधारों के लिए गंभीर चुनौती है ।

हमारे देश की औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था में कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं है । हमारी शिक्षा-व्यवस्था औपचारिकताओं की भूल-भुलैया में खो सी गई है । शाला-भवन, शिक्षक, आवासगृह, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शाला-समय, उपकरण आदि अनेक बातों में कहीं कहीं तो कहीं विसंगतियाँ हैं तो कहीं अटपटापन है । इन्हीं बातों से हम काफी प्रयास करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं । हमने अपने ढंग से शालाओं के समय निर्धारित किए हैं, अपने ढंग का पाठ्यक्रम बनाया है, बिना यह सोचे समझे कि शाला-समय या पाठ्यक्रम उनके अनुकूल है या नहीं जिनके बालक-बालिकाओं का हम शिक्षा दे रहे हैं । हमने यह भी नहीं सोचा कि पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल है या नहीं । जब खेती-किसानी का काम प्रारम्भ होता है तभी स्कूल खुल जाते हैं । जब अनाज की बोनी और कटनी का समय होता है तब शालाओं में अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित होती हैं । इस प्रकार कृषि परक परिस्थितियों के विपरीत हमने शाला के कार्य-दिवस रखे हैं ।

वही हास शासना समय का है। दिन में जब किसानों को घंटों में काम रहना है, अर्थात् काम करते हैं तभी उनके बच्चों को स्कूल जाना होता है अर्थात् खेती किसानों तथा अन्य धंधों का जो समय होता है वही शासना समय का समय होता है, परिणाम यह होता है कि या तो बालक-बालिकाएँ अपने माँ बाप को सहयोग दें या शासना पढ़ने जायें। इस विरोधाभास की स्थिति में वही हाता है जो होता चला आ रहा है। बालक शासनाओं में नहीं जाते हैं या जा जाते हैं वे भाग आते हैं। कुछ बालक कुछ दिन बाद शासना त्याग कर देते हैं। हमने यह भी नियम बना रखा है कि बालक एवं ही कक्षा एक वय में उसी श्रेणी में रह सकता है। इन सब बातों का ऐसा अटकटा परिणाम निकला कि अभी भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन दशक बाद भी हम प्रारम्भिक शिक्षा के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। दश में 611 आयु वर्ग के 84 प्रतिशत तथा 11-14 आयु वर्ग के 39 प्रतिशत बालक शासनाओं में आ सकें। दर्ज सख्या की दृष्टि से आज भी आठ प्रान्त काफी पिछड़े हुए हैं। ये प्रांत हैं—आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

देश में क्षति एवं अवरोध की समस्या भी प्रारम्भिक स्तर पर काफी चिन्तनीय है। मोटे तौर पर देश में 70 प्रतिशत बालक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने के पूर्व शासना त्याग देते हैं। मध्य प्रदेश में तो और भी स्थिति खराब है। यहाँ प्रारम्भिक स्तर पर यह स्थिति 76 प्रतिशत है। शासना परित्याग के कुछ कारण इस प्रकार हैं—

- (1) परिवार की गरीबी
- (2) सामाजिक परिस्थितियाँ
- (3) अनाकंपक प्रारम्भिक शिक्षा
- (4) बालक एवं समाज की आवश्यकताओं से शिक्षा का असंगत।

हमारे सामने बालक की शासनाओं में लाने के साथ साथ शासनाओं में उन्हें बनाए रखने (रिटेंशन) की भी समस्या है। स्थानाभाव, उपकरणों की कमी परीक्षाओं का बोझ, शासनाओं का अनाकंपक वातावरण, सभी तो उन्हें शासनाओं से दूर भगाते हैं। आज हमारे सामने स्थिति यह है कि जो बालक शासनाओं में आ रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यक यूनितम आवश्यकताएँ भी नहीं जुटा पा रहे हैं, यदि हमने शतप्रतिशत बालकों को शासनाओं में लाने का लक्ष्य रखा है तो हम अपने सारे खर्चे बढ़ कर शिक्षा पर ही व्यय करना होगा।

किन्तु यह शायद समझ भी न होमा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था औपचारिकता से परे नहीं कर सकते हैं ? हमें लोक से परे हटना ही हागा। लोक से हटकर ही क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं।

औपचारिकेतर शिक्षा क्या है ? अस्तु औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था से तो हमारा अभीष्ट पूरा होन से रहा। इस व्यवस्था ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। हमें अपन भविष्य के नागरिकों को शिक्षित करना ही है अत विवक्ष्य यही है कि औपचारिकता से हटकर ऐसी शिक्षा-व्यवस्था हम अपनाएँ जिसमें ये सब तामझाम, औपचारिकताएँ न हों जो शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हैं। समस्या के निराकरण के लिए औपचारिक शालेय शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा बालकों का शिक्षा दी जाय। इस औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्था में न समय का बर्धन है, न पाठ्यक्रम को कठोरता, न भवन उपकरणों की चिन्ता। यह व्यवस्था सभी बच्चों से मुक्त है और इसीलिए भारतीय गरीब जनता के लिए जो गरवा में बसती है, उसके लिए ग्राह्य होगी। इस व्यवस्था द्वारा पढ़ सकने वाले वे बालक जो आर्थिक, सामाजिक, तथा धातावरणीय असुविधाओं के कारण नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें प्रजातन्त्र के लिए उपयोगी, मुपठित, साक्षर और समझदार नागरिक बनाया जा सकता है।

औपचारिक ढाँचे में अक्सर स्कूल की दुनिया और बाहर की कामकाजी दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। औपचारिकेतर शिक्षा इन दोनों के बीच एक सार्थक सम्बन्ध खोजती है और बढ़ाती है। काम छोड़कर पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्कि काम के बाद पढ़ा जा सकता है। औपचारिक परम्परा में बच्चे को सिखाया जाता है जबकि इस व्यवस्था में बच्चे स्वयं सीखते हैं और इसमें उनकी सहायता भर की जाती है। उम्मीद यही है कि बच्चे इस तरह से पढ़ने के बाद या तो आगे जाकर औपचारिक व्यवस्था में वापस आ पायेंगे या व इतना ज्ञान पा लेंगे कि उनकी सामाजिक उपयोगिता और निजी क्षमता एक पुष्ट आधार पा जायगी।

औपचारिकेतर शिक्षा को सुविधाएँ—निम्नांकित सुविधाएँ हैं—

1. समय की सुविधा—इसमें सबसे बड़ी सुविधा शाला-समय तथा शाला के अवकाश की है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण का समय, शिक्षण की अवधि तथा छुट्टियाँ को निश्चित किया जा सकता है।

2. भवन सम्बन्धी सुविधा—इन औपचारिकेतर केन्द्रों के लिए अलग से शाला-भवन की आवश्यकता नहीं होती। सावजनिक स्थानों, शाला

मंदिरों, उत्साही नागरिकों द्वारा दिए गए स्थानों पर मुबह, शाम या वर्षा भी भालाएँ मगाई जा सकती हैं।

3 शालिक सामग्रियों की सुविधा—औपचारिकीकेतर केन्द्रों के लिए स्थानीय शाला तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का सहायक सामग्रियों के उपयोग की सुविधाएँ प्राप्त हैं।

4 अध्यापकों की सुविधा—प्रास्ताह्यन राशि के कारण अध्यापक पाठन कार्य के लिए सुगमता से मिस जान हैं। शासन का पूर्णकालिक शिक्षक का नेतृत्व भी बचता है, अध्यापकों की भी आपिश साम होता है।

5 बहु बिन्दु प्रवेश—प्राथमिक पाठ्यक्रम को १८ इकाइयों में बाँटा गया है। आवश्यक नहीं है कि बालक पहली इकाई में ही भरती हा, उस जिस स्तर का ज्ञान है उसी इकाई में भरती किया जा सकता है।

6 समय की बचत—प्राथमिक पाठ्यक्रम जो औपचारिक स्कूलों में 5 वर्ष में पूरा होता है बालक इस व्यवस्था में 2 साल में ही पूरा कर सकता है।

7 प्रशासनिक सुविधा—इस विधि में प्रवेश तथा उपस्थिति के नियमों का बर्धन औपचारिक शालाओं की तरह नहीं है।

8 शालिक सुविधा—(अ) अध्यापक को यह सुविधा है कि वह बालकों की प्रगति के अनुसार अपने शिक्षण क्रम तथा विधि को बदल सकता है।

(ब) छात्र को पाठ्यक्रम पूरा करने में समय का बर्धन नहीं है यह अपनी सुविधानुसार इकाइयाँ पूरी करता है। छात्र अपने पारिवारिक और व्यावसायिक कामों के साथ-साथ शिक्षा को जारी रख सकता है।

औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकीकेतर शिक्षा

1 औपचारिक, शिक्षा (फार्मल एज्युकेशन)—औपचारिक शिक्षा एक निश्चित ढाँचे में बाँधा हुई शिक्षा है। इसमें शाला का समय, सत्र, प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम तथा कक्षाप्रति आदि सबके निश्चित नियम होते हैं। इसमें व्यक्तिगत बालक की सुविधाओं का ध्यान में रखना समभव नहीं है। शिक्षक को नियमों में परिवर्तन करने की छूट नहीं है। इस पद्धति में छात्र सक्षमा अधिक हाने से सामूहिक-शिक्षण समान रूप से सबको दिया जाता है। इस पद्धति में नियम, व्यवस्था, श्रेणी-बद्धता की बाध्यता इनकी होती है कि यह निधन लागू को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है।

2 अनौपचारिक शिक्षा (इन फार्मल) या सहज शिक्षा—यह मनुष्य जीवन के प्रारम्भ से अतः तब तक चलन वाली शिक्षा है। इसमें अतः गत प्रगति

ओपचारिकेतर शिक्षा

अपन दैनिक अनुभवों के माध्यम से परिवार व समाज में प्रचलित कार्य-कलापों से ज्ञान प्राप्त करता है। आकस्मिक और संयोगवश शिक्षा ही अनौपचारिक शिक्षा है। व्यक्ति जितना ही वित्तवश को बार सजग होगा उतना ही अधिक सीखता है।

3 औपचारिकेतर शिक्षा (नॉन-फारमल एज्युकेशन)—औपचारिकेतर शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की जटिलता, औपचारिकता तथा रुढ़िवादिता नहीं रहती है। इसमें औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, तथा मूल्यांकन तो है परन्तु समय, स्थान, तथा प्रवेश नियम आदि बहुत सरल तथा सजीले होते हैं। यह शिक्षा छात्रों की सुविधा अनुसार दी जाती है। बालक अपने घर गृहस्थी तथा रोजी-राटी का काम करते हुए भी पढ़ सकता है। वास्तव में जो बालक अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किसी भी शाला में प्रवेश नहीं ले सके अथवा मध्य में ही शाला छोड़ चुके हैं उनके लिए यह व्यवस्था बरदान है।

औपचारिकेतर शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुशसार्णें

1 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिबदन "होने की सीख" (लर्निंग टु बी) (Learning to be) में सभी पहलुओं से विचार कर शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुशसार्णें की हैं। इन अनुशसार्णों के आधार पर कई देशों में बड़े व्यापक रूप से औपचारिकेतर शिक्षा का कार्य प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

2 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' ने औपचारिकेतर शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी अनेक बैठकों में अनुशसार्णें की हैं। इनमें से विशेष उल्लेखनीय 1947 एवं 1976 की अनुशसार्णें हैं।

(अ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने 9-14 आयु वर्ग के बालकों के लिए औपचारिकेतर शिक्षा से सम्बन्धित प्रस्ताव निम्नानुसार हैं।

"केवल औपचारिकेतर शिक्षा विधि पर मात्र दिए गए महत्व को छोड़ना होगा और शिक्षा-प्रणाली में औपचारिकेतर शिक्षा को भी जोड़ना होगा। बहु-विध प्रवेश एवं अलग-अलग शिक्षा के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करना होगा।"

'मण्डल का यह विश्वास है कि सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य केवल औपचारिक विधि को आधार मानकर तथा एक विधु प्रवेश, द्रमिक स्वरूप, पूर्णकालिक शालेय शिक्षण एवं पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा प्राप्त

नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के पुनर्गठन हेतु समस्त राज्यों का कार्यक्रम बनाकर प्रारम्भ कर देना चाहिए। इन परिस्थितियों के पक्ष में जनमत को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय शासन राज्य के शिक्षा सस्थान, राज्य शिक्षा विभाग, निरीक्षणालय एवं शिक्षण समुदायों द्वारा विशाल कार्यक्रम बनाना चाहिए। राज्यों के शिक्षा विभागों को नवीन चुनौतियों को ग्रहण करने के लिए शिक्षकों के सम्मुखीकरण के विशेष प्रयास करने चाहिए। राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा सद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, आवश्यक पाठन सामग्री, तथा तकनीकों को तुरंत तैयार करना चाहिए।

(ब) औपचारिकतर शिक्षा तीन श्रेणियों के बालकों के लिए अनुशंसित है—

(1) वे बालक जिनका कक्षा १ में प्रवेश नहीं हुआ किन्तु 2-5 वर्ष में शामिल होने के इच्छुक हैं, 6 या इसके समतुल्य आयु के वे बालक जो कक्षा 1 में प्रविष्ट हुए हैं परन्तु कुछ माह पश्चात् शाला छोड़ गए, जिन बालकों ने पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना किसी भी स्तर पर शाला छोड़ दी, इन सब बालकों को अशकालीन-औपचारिकतर शिक्षा देना होगा जिससे वे 11+ की आयु में छटी कक्षा में प्रवेश लेने हेतु योग्य बन सकें।

(11) वे बालक जिन्होंने पाँच वर्ष की विद्यालयीन शिक्षा पूर्ण कर छटी कक्षा में 11+ या उसके समतुल्य आयु में प्रवेश लिया था, किन्तु कुछ महिनों के पश्चात् ही किसी बिन्दु पर तीन वर्षीय माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पहले ही शाला त्याग दी, अथवा अशकालीन शिक्षा द्वारा इन बालकों को इस योग्य बनाना होगा, कि वे 14+ आयु में 11 वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें।

(111) पाँचवी कक्षा पास के बालक जो शाला छोड़ चुके हैं, किन्तु अब जाने पढ़ना चाहते हैं, इन बच्चों को अशकालीन शिक्षा द्वारा 8वीं में प्रवेश लेने हेतु योग्य बनाना होगा।

(स) सन् 1976 की बैठक की अनुशंसाएँ—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने अपन वष 1976 की बैठक में निम्नानुसार अनुशंसा की है —

(1) “पाँचवी याजमा में औपचारिकतर शिक्षा के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के उपरांत समिति को सन्तोष है कि औपचारिकतर शिक्षा की विचार-धारा, जिसका इस देश में एक सम्बन्धी परम्परा रही है, फिर से मूल रूप में लौट रही है। यह भी सत्य की बात है कि धीरे-धीरे हमारी शिक्षा-प्रणाली के एक अनिवार्य अंग के रूप में हमारे समाज के सीखने की आरंभ बढ़ते हुए महत्वपूर्ण चरण के रूप में और राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता प्राप्त करती जा रही है। इसके माध्यम से समस्त नागरिक अपने

व्यक्तियों, अधिकारों, और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनेंगे और एक अभि-
नव, जनतात्मिक, धर्म निरपेक्ष और समाजवादी समाज की रचना में अविरल
भागीदारी के लिए तैयार होंगे। इस कार्यक्रम को हमें इस प्रकार आगे बढ़ाना
चाहिए कि हमें बड़े पैमाने पर आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाय, स्रोत व्यक्ति
प्रशिक्षित हो जाय, आवश्यक शिक्षा सामग्री तैयार हो जाय, राष्ट्र, राज्य
और जिला स्तरों पर आवश्यक संगठनों का निर्माण हो जाय और इस
कार्यक्रम के पक्ष में प्रबल जनमत तैयार हो जाय। उससे हम छटी योजना में
इस कार्यक्रम को सारे राष्ट्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकसित कर सकेंगे।
समिति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि औपचारिकेतर शिक्षा सभी
वर्गों के युवा और प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए जो उपयोगी कौशल और ज्ञान
प्राप्त करना चाहते हैं, सीखने की एक प्रभावी विधि है।

(11) प्राथमिकताएँ—औपचारिकेतर शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय
महत्व के हैं अतः उन्हें सारे देश में प्राथमिकता मिलनी चाहिए —

(1) वे कार्यक्रम जो आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए
वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इन वर्गों में भी उनकी जो बीस
सूचीय कार्यक्रम से सीधे सम्बन्धित हैं, अथवा उससे साधन उठा रहे हैं।

(2) वे कार्यक्रम जो परिवार-कल्याण के प्रयासों को शैक्षिक समर्थन
दत्त हैं।

(3) वे कार्यक्रम जो बच्चा, युवक और महिलाओं की न्यूनतम शैक्षिक
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, युवकों के लिए वे कार्यक्रम जिनमें उन्हें रोज-
गार के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(4) हृषिको एवं औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम जिससे देश की आर्थिक
प्रगति तत्ती से हो।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विचार

“औपचारिकेतर शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो अब शैक्षिक भाषा का एक
अंग बन गया है, यद्यपि यह शैक्षिक कार्यक्रम का एक सन्धा और पूरा भाग
नहीं हो पाया है। औपचारिकेतर शिक्षा की समग्र दृष्टि को प्रतिबिम्बित करनी
है और उसे स्कूलों और कालेजों तक अर्थात् सस्थागत शिक्षा एवं निर्देशन की
सक्रिय धारणा से मुक्त करती है, क्योंकि यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि
सीखना मनुष्य माल का एक अनिवार्य लक्षण है जो पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व
एवं विकास के लिए आवश्यक है। जीवन की सब परिस्थितियों में मनुष्य सीखना
है। ज्ञानार्जन एवं ज्ञान के अनुप्रयोग विशिष्ट अथ में सीखने की प्रक्रिया के अन्त

स्कूल में ही नहीं। तभी वरन् घर में और कम के परिवेश में भी सीप में बर्न एवं जीवन की अग्रिमोक्ष परिस्थानयो में चसनी रहती हैं। इसी परिद्रेश्य में औपचारिकतर शिक्षा का अपना पूण ओर विशिष्ट अय प्राप्त होता है।'

(घ) यूनेस्को का दृष्टिकान

स्पष्ट हा निरक्षरता यदि विकास का दृष्टि से पिछटपन का एक पहलू है तो साक्षरता प्रसार किसी एम विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए जो मनुष्य को अपन स्वयं का स्वाभा बन और अपन विकास के लिए जानबूझ कर प्रयास करने में सहायक हो। उपयुक्त निष्कर्ष ही उन क्षेत्रों में शैक्षणिक, सामाजिक, और आर्थिक कार्यक्रमों के रूप में सश्रिय साक्षरता के मिश्रात का जनक है जो क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए प्रथमिक आधार पर धुन गए हैं और जहाँ निरक्षरता एक बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित है।

नसार के लोगो को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इस प्रयास का प्रभाव दूरगामी और दर अन्तत इस जारी रहना चाहिए, फिर भी वर्तमान पीढ़ी का इन परिस्थिति का दुप्रभाव से बचाने के लिए निम्नलिखित अनेक हलो को सावधानी से अनुसरण करना समब हो सकता है।

“पूणवर्त्मिक पूरी प्राथमिक शिक्षा, अक्षरतात्मिक पूरी प्राथमिक शिक्षा, समुचित अंतर से आवृत्ति के रूप में प्राथमिक शिक्षा, बालका तथा प्रौढा के लिए अपूण प्रारम्भिक शिक्षा और 12 से 16 वर्ष की आयु के युवका के लिए और विशेषकर उनके लिए जो कभी स्कूल नहीं गए हैं।

औपचारिक एवं औपचारिकतर शिक्षा—सुतनात्मक विवेचन

दोनो शिक्षा पद्धतिया में निम्नानुसार अंतर स्पष्ट किया जा सकता है।

औपचारिक शिक्षा

औपचारिकतर शिक्षा

(अ) उद्देश्य

- (1) दीर्घकालीन और सामा य
- (2) प्रमाणपत्र आधारित शिक्षा

- (1) अल्पकालीन एवं विशिष्ट
- (2) प्रमाण पत्रों की मा यता विहीन शिक्षा प्रणाली

(ब) समय

- (1) दीर्घ चक्राय
- (2) नियोजनात्मक।
- (3) पूर समय की शिक्षा

- (1) लघु चक्राय
- (2) तात्कालिक।
- (3) अक्षरतात्मिक शिक्षा

(स) विषय वस्तु

- | | |
|--|--|
| (1) पुस्तकीय तथा मानवीकृत । | (1) उत्पादन के द्रव तथा वैयक्तिक । |
| (2) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम । | (2) प्रयोगिक पाठ्यक्रम । |
| (3) प्रवेश के नियमों से प्रवेशार्थी का निश्चित किया जाना । | (3) प्रवेशार्थी की सुविधानुसार प्रवेश नियमों का बनाया जाना । |

(द) सामाज्य प्रणाली

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| (1) सत्या आधारित | (1) पर्यावरण आधारित |
| (2) प्रयत्नकृत | (2) समुदाय सम्प्राप्त |
| (3) सुनिश्चित सरचना | (3) परिवर्तनशील सचीली सरचना । |
| (4) शिक्षण केन्द्रित | (4) शिक्षार्थी केन्द्रित |
| (5) खर्चीली शिक्षा | (5) कम खर्चीली शिक्षा |

(ध) शासन एवं प्रबंध

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) वास्तव व्यवस्था | (1) आत्म व्यवस्था |
| (2) पारस्परिक अनुशासन | (2) जनतन्त्रात्मक अनुशासन |

(र) आय

- | | |
|---|--|
| (1) एक विन्दु प्रवेश | (1) बहु विन्दु प्रवेश |
| (2) सभी बालकों की शिक्षा | (2) 9-14 वय का आयु के शाला अप्रवेशी तथा शाला त्यागी बालकों के लिए शिक्षा |
| (3) प्राथमिक शिक्षा 4 वय में पूरी की जा सकती है | (3) प्राथमिक शिक्षा 2 वय में पूरी की जा सकती है । |
| (4) घरेलू कार्यों के साथ शिक्षा सम्भव नहीं है | (4) घरेलू कार्यों के साथ शिक्षा सम्भव है । |
| (5) कक्षा पद्धति | (5) कक्षा पद्धति नहीं है । |

मध्य प्रदेश में औपचारिकतर शिक्षा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इतने विशाल अंतराल तथा पांच पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी करने के बाद भी हम प्रारम्भिक शिक्षा के शतप्रतिशत लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके हैं । इतने वर्षों में हमने जो प्रगति की है वह ज्यादा प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती है । पाँचवी योजना के अंत तक म० प्र० में 6-11 आयु वय के 63% तथा 11-14 आयु वय के 28% बालक-बालिकाओं को हम

शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार

शाळाओं में सा सत्र हैं। यदि 6-14 आयु वर्ग के सत्रों में लगभग 51% बालक/बालिकाएँ शाळाओं में आए हैं अर्थात् शाळा जान योग्य बालक-बालिकाओं के आधे बाहर भूम रहे हैं। जो भर्ती हैं उनमें से भी बितने स्कुल छात्र जिनमें यह भी निश्चित नहीं है।

हमारे सामने, हमारे प्रश्न के सामने कुछ समस्याएँ भी हैं जिसमें हम प्रगति नहीं कर सके। ये प्रमुख समस्याएँ हैं —

- 1 अनुसूचित जाति और जन जाति की विनाश जनसंख्या
- 2 प्रश्न का विस्तृत पैसाव
- 3 बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन
- 4 भौगोलिक असंतुलन परिस्थितियाँ
- 5 बालकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति
- 6 प्रारम्भिक स्तर पर दाति एवं अवरोध

प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति से जब हम राष्ट्रीय स्तर की तुलना करते हैं तो हम बहुत पिछड़े हुए लगते हैं।

बालक बालिकाओं की दृष्टि संख्या (साथों में)

भारत

(1978-79 की स्थिति)

सं० प्र०

आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	433	280	713	29 88	13 98	43 86
प्रतिशत	101 0	68 2	84 9	83 00	41 11	62 66
11-14	125	60	185	7 79	2 66	10 45
प्रतिशत	51 4	26 5	39 8	41 00	15 65	28 24
6-14	558	350	898	37 67	16 64	54 31
प्रतिशत	82 8	53 5	68 6	68 51	31 98	50 75

शालिका से स्पष्ट है कि अभी वर्तमान स्थिति की ही जैसी तो संविधान की धारा 45 की मशा पूरी करने के लिए शाळा जान योग्य कुछ बालक बालिकाओं की बाधी संख्या अर्थात् लगभग 54 लाख बालक/बालिकाओं की शाळाओं में लाना होगा। छटी योजना के अन्त तक और वृद्धि होगी यह अलग बात है। इतने बालकों को सामान्य शिक्षा दाँव से शिक्षित करना संभव ही नहीं असंभव है। वित्तीय साधनों का दबाव है न तो शालाएँ ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं,

न शिक्षक और न सासाभवन, उपकरण। एक ही विकल्प हमारे सामने बचा या और आज भी है और वह है औपचारिकेतर शिक्षा-व्यवस्था द्वारा शिक्षा।

हमारा प्रयोग—औपचारिकेतर शिक्षा के विस्तृत आयाम हैं। यह औपचारिक शिक्षा के साथ चलने वाली है तथा इसकी समाप्ति के बाद भी चलने वाली है। इसके विविध आयामों से परिचित होते हुए म० प्र० शिक्षा विभाग ने औपचारिकेतर शिक्षा के सचीलेपन का तत्त्व एक सीमिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनाया है। यह लक्ष्य है शिक्षा की सुविधाओं से वंचित 9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक-बालिका जो शाला में प्रवेश न हुए हों या शासनात्यागी हों, जो शिक्षा के ऐसे अवसर देना जो समय, स्थान, अवधि, आदि की दृष्टि से उनके अनुकूल हों। औपचारिकेतर शिक्षा का दृष्टिपथ आगे जाकर बहुत विस्तृत हो जाता है परंतु फिलहाल म० प्र० में यह लक्ष्य सामने है कि शिक्षा-वंचित बालक-बालिकाएँ अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और व चाह तो फिर शिक्षा की मुख्य धारा में आ जावें। वास्तव में हमारी औपचारिकेतर शिक्षा लक्ष्य है विद्यालयीकरण एवं पुनर्विद्यालयीकरण (स्कूलिंग एंड रिसूल्डिंग)।

उद्देश्य—प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में औपचारिकेतर शिक्षा एक प्रभावशाली पूरक प्रयास है इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं—

- 1 9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाएँ जो शाला अग्रवेशी या शासनात्यागी हों उन्हें प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सुलभ कराना।
- 2 प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।
- 3 2 वर्ष की अवधि में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कराना।
- 4 उसी प्रकार 2 वर्ष की ही अवधि में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कराना।
- 5 शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करना जिससे छात्रों को आजीविका तथा पारिवारिक कार्यों में बाधा न हो।

प्रयोग की शुरुआत और प्रगति

1 फरवरी 1957 से म० प्र० में योजना का प्रथम चरण प्रारम्भ हुआ और 10 जिलों में 5-5 केन्द्र के हिसाब से 50 औपचारिकेतर शिक्षा-केन्द्र खोले गए। प्रयोग के तौर पर केन्द्र के लिए वे ग्राम चुने गए जहाँ ग्राम में प्रवेश कम तथा शैक्षिक क्षति अधिक थी। य बालिका शिक्षा-निधि से खोले गए।

2 द्वितीय चरण जुलाई 1957 से प्रारम्भ हुआ। राज्य की ग्रन्थालय बुना-पाटी संस्थाओं के माग-दर्शन में एक-एक केन्द्र खोला गया। इस प्रकार कुल 45 केन्द्र खोले गए। ये केन्द्र भी बालिका शिक्षा निधि से खोले गए।

3 मई, जुलाई और अगस्त 1977 में 51 क्षेत्र पुनः बालिका शिक्षा निधि से प्रारम्भ किए।

4 मार्च 1978 में 250 क्षेत्र शासन द्वारा उपयोगिता क्षेत्र में घोषित तथा 1 क्षेत्र बालिका शिक्षा-निधि द्वारा चलाया गया।

5 फरवरी 1978 में 200 क्षेत्र शासन द्वारा घोषित गए।

6 वर्ष 79-80 में 2000 औपचारिकतर शिक्षा क्षेत्र शासन द्वारा चलाए गए। पूरे में बस रहे 117 क्षेत्र जो बालिका शिक्षा निधि से चले गए हैं। शासन के क्षेत्रों में समाहित कर लिया गया और 79-80 में सभी औपचारिक क्षेत्र शिक्षा शासकीय निधि से चल रहे हैं और इतर संख्या 2450 है।

इन क्षेत्रों पर 4000 से ऊपर छात्र शिक्षा पा रहे हैं। ये बच्चों को काम भी करते हैं और सुविधानुसार शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जिन छात्रों ने प्राथमिक परीक्षा दी है उनके परिणाम भी 50 प्रतिशत से ऊपर रहे हैं।

नई व्यवस्था के आरम्भ

इस व्यवस्था में कुछ ऐसे आरक्षण हैं जो अपने आप बालक-बालिकाओं को आवंटित करते हैं।

1 सीमित साधना द्वारा जान की उपलब्धि।

2 9-14 वर्ष के शासनात्मकी और अप्रवर्ती सुविधा संबंधित बालकों की शिक्षा।

3 घरसे कार्य के साथ शिक्षा की प्राप्ति।

4 स्थान, समय और भवन का बंधन नहीं।

5 बहु विधु प्रवेश।

6 पाँच वर्ष की शिक्षा 2 वर्ष में।

7 कक्षा का पद्धति नहीं। 5 वर्ष का पाठ्यक्रम 2 वर्ष में पूरा होता है।

8 बालक और बालिका की सुविधा से शिक्षा-क्षेत्र का समय।

9 सरल और सस्ती व्यवस्था। औपचारिक व्यवस्था में जहाँ कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर एक बालक पर 550 रु० व्यय आता है वहीं इस व्यवस्था पर लगभग 90 रु० व्यय आता है।

10 शासकीय/अशासकीय/स्वच्छिक संस्थाओं द्वारा क्षेत्र चालन।

11 शिक्षा की प्रति छात्र 50 रु० प्रोत्साहन राशि।

12 पाठ्यपुस्तकों का बिना मूल्य छात्रों को प्रदाय।

13 गरीब बालका को मुलम शिक्षा ।

14 बासको को शिक्षा की मुख्य धारा में पुन लाना ।

वित्तीय व्यवस्था

1 यह योजना अशासकीय निधि में प्र० बालिका/शिक्षा-निधि से प्रारम्भ की गई ।

2 बाद में सभी केन्द्र अब शासकीय निधि से चल रहे हैं । बालिका शिक्षा निधि वाले केन्द्र भी शामिलीय में समाविष्ट कर दिए गए ।

3 प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष 100 रु० आकस्मिक व्यय के लिए दिए जाते हैं ।

4 छात्रा को पुस्तकें और कपिया मुफ्त प्रदान की जाती हैं ।

5 शिक्षको को 50 रु० प्रति छात्र के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

6 भवन व्यवस्था पर कोई व्यय नहीं किया जाता है ।

7 २० छात्र वाले केन्द्र पर प्रतिवर्ष लगभग 1100, रु० का व्यय आता है ।

प्रशासनिक व्यवस्था

(1) म० प्र० में औपचारिकेतर शिक्षा योजना का निर्देशन, पर्यवेक्षण साक शिक्षण संचालनालय द्वारा होता है ।

(2) प्रशिक्षण, सदरशन एवं निरीक्षण का कार्य राज्य शिक्षा सस्यान करता है ।

(3) केन्द्रों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा-सस्यान तथा समागीक शिक्षा अधीनस्थ कार्यालयों में औपचारिकेतर शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं ।

(4) चुने हुए जिला में स्थापित केन्द्रों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं ।

(5) बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं से सलग्न केन्द्रों का निरीक्षण बुनि० प्रशि० संस्थाओं के प्राचार्य करते हैं ।

(6) शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित केन्द्रों का पर्यवेक्षण शिक्षा महाविद्यालय करने हैं ।

शक्षिक व्यवस्था

(1) जिला के केन्द्रों पर कम से कम २० तथा बुनि० प्रशिक्षण संस्थाओं के केन्द्रों पर न्यूनतम ३० छात्रों की संख्या निर्धारित है ।

(2) जिला के केन्द्रों पर एक अध्यापन काय करता है और इसका निर उसे अपनी नियमित नौकरी के अतिरिक्त प्रति छात्र 50 रु० प्रासादित राशि प्रदान करते हैं।

(3) बी० टी० आई० के केन्द्रों पर प्रशिक्षणाधियों द्वारा अध्यापन कार्य होता है क्योंकि उसे अध्यापन का एक अंग माना जाता है।

(4) प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का शिक्षण अपेक्षित है।

(5) स्थानीय परिस्थितिया के अनुसार केन्द्र द्वारा अपना अद्वय निधारित किया जाता है।

(6) शाला का समय छात्रों की सुविधा व अनुसार निश्चित किया जाता है।

(7) शिक्षण विधियों में स्वाध्याय तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर धन दिया जाता है।

(8) लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र को फिर उपस्थित होने पर उसका शिक्षण वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ उसने छोड़ा था।

(9) नए प्रवेशार्थी की उचित जाँच पड़ताल कर उपयुक्त इकाई में प्रवेश दिया जाता है।

(10) प्रत्येक छात्र की उपस्थिति और प्रगति का विधिवत अभिलेख रखा जाता है।

औपचारिकतर शिक्षा पर रखे जाने वाले अभिलेख

केन्द्र की समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि केन्द्र के काय और सामग्री का लेखा जोखा रखा जाय। ये अभिलेख केन्द्र प्रभारी को बाँधने के लिए नहीं बल्कि उसके काय को सुगम और सरस बनाने के लिए हैं। ये अभिलेख निम्नानुसार हैं—

- | | |
|--------------------|--|
| 1—सर्वेक्षण अभिलेख | बालक, बालिकाओं का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण अभिलेख। |
| 2—सम्पक पंजी | केन्द्र प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से समाज में किए गए सम्पक का विवरण। |
| 3—प्रवेश पंजी | छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी विवरण होना। |
| 4—उपस्थिति पंजी | छात्रों की उपस्थिति का समुचित रिकार्ड रखा जाता है। |
| 5—कैश बुक | निधारित प्रारूप में। |

- 6—स्टाक रजिस्टर निर्धारित प्राप्ति में।
- 7—पत्र आवक/जावक इसमें डाक के आने-जाने तथा पत्रों का विवरण पत्रिका होगा।
- 8—शिक्षक डायरी इसमें शिक्षक अपने शिक्षण तथा कार्य का विवरण रखेगा।
- 9—वार्षिक यात्रा प्रत्येक केंद्र अपनी वार्षिक योजना बनाकर रखेगा।
- 10—मूल्यांकन प्रपत्र इसमें छात्रों की प्रगति एवं केंद्र का मूल्यांकन रखा जायगा।

पाठ्यक्रम निर्माण

पाठ्यक्रम के तीन मुख्य पक्ष होते हैं व्यक्ति, समाज और अध्ययन विषय। जिस पाठ्यक्रम में ये तीनों का अच्छा सामंजस्य होगा वह पाठ्यक्रम उपयोगी होगा।

पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नावृत्ति निर्देशक बिन्दु ध्यान में रखे जाने चाहिए—

- 1—पाठ्यक्रम का आधार शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को बनाना चाहिए।
- 2—पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसमें पाठ्य-विषयों को सरलता से जोड़ा जा सके ताकि औपचारिक शिक्षा की धारा में जा मिलने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों को सुविधा रहे।
- 3—विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का साम उठाते हुए शिक्षार्थी का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर उन्हें वांछित विषय-वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।
- 4—प्रत्येक शिक्षार्थी को एक इकाई समझ कर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करना चाहिए।
- 5—पाठ्यवस्तु का माध्यम स्थानीय भाषा ही हो ताकि शिक्षार्थियों को विषय-वस्तु ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो।
- 6—विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश एवं आवश्यकताओं से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भी सक्षम बनाना चाहिए।

इस योजना के लिए पाठ्यक्रम उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर राज्य शिक्षा-संस्थान में किया गया है।

- 1—प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों स्तर का पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है।
- 2—प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम 18 इकाइयाँ में विभक्त है।
- 3—पाठ्यक्रम बसावार नहीं है।
- 4—दो वर्ष में पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार पूर्व माध्यमिक स्तर का भी।
- 5—पाठ्यक्रम पुनर्गठन में सारसम्यता नहीं टूटी है।

शैक्षिक सामग्री का निर्माण

- 1— प्रत्येक इकाई की विस्तृत योजना तैयार की गई है।
- 2—इकाइयों के आधार पर अध्यापकों द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है।
- 3—कुछ सहायक सामग्री संस्थाओं एवं स्थानीय स्त्रियों से उपलब्ध की जा रही है।
- 4—अपनी शाला की समस्त सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक औपचारिकतर के द्र पर करता है।

राज्य शिक्षा संस्थान की भूमिका

राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० की इस याजना के त्रिया बयन का दायित्व सौंपा गया है। इस हेतु रा० शि० संस्थान में “औपचारिकतर शिक्षा प्रकाष्ठ” की स्थापना की गई है। काय संचालन विधि इस प्रकार है—

- 1—औपचारिकतर शिक्षा के द्र प्रारम्भ करने हेतु क्षेत्र का चुनाव सर्वेक्षण।
- 2—क्षेत्र छालने हेतु अनुमति प्रदान करना।
- 3—शिक्षकों को त पुरुषा का उमुखीकरण।
- 4—सम्बन्धित साहित्य का निर्माण व के द्र पर वितरण।
- 5—प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक पाठ्यक्रम का सक्षिप्तीकरण।
- 6—त्रिया बयन की काय योजना तैयार करना।
- 7—प्रशासन और पयवर्णन।
- 8—शिक्षना की प्रोत्साहन राशि का वितरण।
- 9—प्रगति का मूल्यांकन करना।
- 10—क्षेत्रा की मागदर्शन एवं उनका कठिनाइयों का निराकरण।
- 11—क्षेत्रा की प्रगति व बारे में लोक शिक्षण संचालक व शासन का अलग करना।

12—भावी याजना का निर्माण ।

औपचारिकतर केन्द्रों को प्रभावशाली कैसे बनायें ?

औपचारिकतर शिक्षा-केन्द्रों का प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं—

- 1—केन्द्रों का पर्यवेक्षण निता न आवश्यक है ।
- 2—जिस गाँव में केन्द्र संचालित हो रहा है उस गाँव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक का निवृत्त किया जाय कि वह भी माह में केन्द्र का एक बार आकस्मिक निरीक्षण करे ।
- 3—सहायक पिला शाखा निरीक्षक प्रतिमाह केन्द्र का निरीक्षण करे ।
- 4—शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन केन्द्रों में संचालन में सट्याग दन एवं इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन में इन काय का स्थान मिलना चाहिए ।
- 5—केन्द्रों का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन होना चाहिए । प्रत्येक जिले के उत्तम केन्द्रों का प्रशंसा पत्र दिया जाना चाहिए ।

औपचारिकतर शिक्षा योजना की व्याप्ति

मध्य प्रदेश में प्रारम्भ की गई औपचारिकतर शिक्षा योजना की व्याप्ति सार्वजनिक मंडलों की नीति के अनेक शिक्षा शास्त्रीय विशेषण इसे निकट से देखने का माह उपकरण नहीं कर सके । 1977 में योजना आयोग भारत सरकार का एक दल म० प्र० में आया और इस दल ने सागर सभाग के कुछ केन्द्रों का निरीक्षण कर भूरि-भूरि प्रशंसा की । 1978 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के एक दल ने केन्द्रों का निरीक्षण और प्रगति पर हार्दिक सन्तोष व्यक्त किया ।

म० प्र० में इस योजना का सफल प्रिया वयन देखकर केन्द्र सरकार ने अन्य सभी प्रांतीय सरकारों का निर्देश दिया कि औपचारिकतर शिक्षा के म० प्र० मण्डलों की आश मानकर कार्य किया जाय । इस पुनीत काय में सलग्न प्रदेश के अधिकाधिका, शिक्षका, छात्रा के लिए इससे बढ़कर और अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है । केन्द्र शासन इस व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराता है जो केन्द्र और राज्य के बीच 6 और 5 के अनुपात में होती है ।

सुबह का भूला शाम को घर आ जाय ता भूला हुआ नहीं कहलाता है । यदि इस योजना द्वारा हम प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण कर सकें ता अभी भी कोई देर नहीं हुई है और हम भट्टे हुए नहीं कहलायेंगे ।

जनसंख्या शिक्षा

(Population Education)

भूमिका—हमने दत्तचित होकर जितना समय और शक्ति देश की जनसंख्या वृद्धि करने में खर्च की है उसना शक्ति और दूसरे निर्माण और विकास के कार्यों में लगाते तो हमारा देश स्वर्ण धन गया होता। एक बार हम देश को समृद्ध बनाने के प्रयास में लगे हैं किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सारे प्रयासों को विफल कर रही है, विकास की गति धीमी पड़ रही है। परिणाम यह है कि न केवल हमारा देश बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्र अभी भी निधनता, बेकारी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं। जिस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उस पर यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी सारी योजनाओं पर पानी फिर जायगा। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या 371 करोड़ थी। विश्व के समस्त विकसित और विकासशील राष्ट्र इस समस्या पर चिंतित हैं। १६ अगस्त 1974 से 30 अगस्त 74 तक बुखारेस्ट में जनसंख्या की समस्या पर काबू पाने के लिए विश्व के 135 राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और भविष्य की व्यूह रचना में कई समुक्त-राष्ट्रों ने भी वर्ष 1974 का "जनसंख्या शिक्षा" वर्ष घोषित किया और समस्त राष्ट्रों को इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए आह्वान किया।

आज हमारे देश की अनेक समस्याओं का मूल कारण अनपेक्षित जनसंख्या ही है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष १ करोड़ 13 लाख के लगभग नए बच्चे जुड़ जाते हैं। यदि इस वृद्धि पर काबू नहीं पाया गया तो जो भारत की आबादी सन् 1971 में 54.7 करोड़ थी, सन् 20०0 तक 1 अरब हो जाने की संभावना है। इस प्रकार की अप्रत्याशित जनसंख्या-वृद्धि हमारे लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। हमारे उत्पादन, हमारे विकास की गति, जनसंख्या-वृद्धि की गति के सामने बमजोर पड़ रही है। हमारे सामने एक बड़ा भारी प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। अभी तक देश का जनसंख्या वृद्धि की गति आगे की तालिका से जाँची जा सकती है—

जन गणना वर्ष	जनसंख्या (10 लाख में)	प्रति दशक वृद्धि की प्रतिशत दर
1901	238 4	—
1911	252 2	5 75
1921	251 3	0 32
1931	279 0	11 01
1941	316 7	14 02
1951	361 1	13 91
1961	439 2	21 50
1971	547 0	25 0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या आजादी के बाद बड़ी द्रुतगति से बढ़ी है।

जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण

- 1—परिवार को सीमित और नियंत्रित करने में सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध।
- 2—भावनात्मक कारण यथा बच्चा को ईश्वरीय कृपा समझना और परिवार को सीमित रखने के प्रयासों में असहयोग।
- 3—बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के प्रति मोह।
- 4—गम जलवायु और बालिकाओं का शीघ्र युवा होना।
- 5—कम उम्र में सड़कियाँ का विवाह।
- 6—शिक्षा का अभाव।
- 7—विवाह की मनोरंजन का साधन समझना।
- 8—विक्षिप्त आयुर्विज्ञान, जन-स्वास्थ्य सुविधाओं से शिशुओं की मृत्यु दर में कमी।
- 9—विज्ञान और आराम्य सुविधाओं की वजह से औसत आयु में वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट।
- 10—विभिन्न कारणा से भारत में ऊँची जन्म दर।

- 2—बयस्का, बालका की समझाना कि मानव जीवन की क्रियाएँ किस तरह जनसंख्या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं, उदाहरणार्थ विवाह की उम्र, परिवार की सीमा, आवास का चुनाव, शिक्षा या व्यवसाय आदि निर्णयों का कितना सम्बन्ध सुखी जीवन एवं जनसंख्या परिवर्तन से है।
- 3—जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार उससे तथा समाज के जीवन को प्रभावित करते हैं।
- 4—जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि परिवार का आकार सीमित किया जा सकता है तथा सीमित जनसंख्या राष्ट्र के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हो सकती है। सीमित परिवार जीवन की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने में सहायक होता है।
- 5—शिक्षार छात्रों को यह भी ज्ञान दिया जाय कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, कल्याण, आर्थिक उन्नति तथा सुखी भविष्य के लिए सीमित परिवार का होना लाभकारी है।
- 6—जनसंख्या के पर्याप्त ज्ञान की समझाना और उसके शैक्षिक महत्व की प्रस्थापना कर शालाया में उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।
- 7—एक विकासशील देश में अत्यधिक जनसंख्या राष्ट्र के विकास के लिए कितनी बाधक है, इसका ज्ञान कराकर राष्ट्रीय विकास में सहायता देना।
- 8—इससे सम्बन्धित योग्यता का निर्माण करना और स्रोत सामग्री यथा मकसे, चाटू स, रेखाचित्र आदि बनाना और उसकी व्याख्या करना।
- 9—छात्रों को कुछ क्षेत्रीय अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना, जैसे स्थानीय समुदाय की जनगणना, सर्वेक्षण, नागरिकों की प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का अध्ययन।
- 10—जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामों के प्रति चेतना विकसित करना, जैसे—(i) अपत्याप्त बाह्य, (ii) प्रति व्यक्ति आय, (iii) जीवन स्तर में गिरावट, (iv) बेरोजगारी, (v) शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था, (vi) आवास की कमी, (vii) बस्तों की कमी।
- 11—शिक्षकों को प्रेरित करना कि जहाँ सम्भव हो अपने शिक्षण के पाठ्य-विषय में इस समस्या की जानकारी दें और उसका प्रतिपादन प्रभावशील ढंग से करें।

in the year 555/1982

- 12—उस दशा का वास्तविक ज्ञान कराना जहाँ तक मनुष्य और विभिन्न समाज एक दूसरे पर अत्यधिक आधारित होते जा रहे हैं जिससे उनकी भलाई एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित है।
- 13—दुनिया के स दर्भ में भारत की जनसंख्या की गतिशीलता, जनसंख्या वृद्धि की दर और जनसंख्या की संरचना के बारे में आधारभूत समय देना करना।
- 14—जनसंख्या सम्बन्धी आधारभूत धारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ का विकास करना।
- 15—मनुष्य जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जनसंख्या के सुझाव के प्रभाव को जानने हेतु समझ का विकास करना।
- 16—इस विचार का समझने के लिए प्रोत्साहित करना कि अलग-अलग परिवारों के लाभ के लिए परिवार का आकार नियोजित किया जा सकता है।
- 17—छोटे परिवार को एक व्यवस्था के रूप में लेने की समझ पैदा करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का उच्चस्तर पाने की अधिक संभावनाएँ हैं।
- 18—दश की जनसंख्या सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में चेतना का विकास करना।

जनसंख्या शिक्षा का महत्व—वर्ष 1974 में बुखारेष्ट में हुए विश्व जनसंख्या सम्मेलन में जनसंख्या शिक्षा का महत्व इस प्रकार स्वीकार

किया गया—

- 1—उन्नति की प्रेरणा प्रदान करने में शिक्षा का सर्वोपरि स्थान है तथा उसके द्वारा युवक-युवतियाँ अपनी उन्नति के लिए सक्षम होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
- 2—जिन्हा का चरम उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उन्नति के लिए भावों नागरिका के ज्ञान, कौशल, योग्यताओं एवं अभिवृत्तियों का उत्थान कर सम्पूर्ण मानवी साधना का विकास करना है।
- 3—प्रत्येक राष्ट्र की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए आहार, आवास स्वास्थ्य, राजगार, शिक्षा प्राप्ति के अवसर, उच्च जीवन स्तर एवं मुखी पारिवारिक जीवन की समस्याओं के हल प्राप्ति से सम्बन्धी होने के

कारण जनसंख्या शिक्षा से जुड़ा शिक्षा-व्यवस्था का वास्तविक एवं सार्थक बनाती है।

1—जनसंख्या शिक्षा का अर्थ न विगुह्य शैक्षिक आधार है। प्रत्येक राष्ट्र की जनसंख्या का विशिष्टताएँ तथा उसमें हो रहे परिवर्तन का सीमा सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के सम्पूर्ण जीवन से है चाहे राष्ट्र की आबादी घनी हो या विरल अथवा राष्ट्र विकसित या विकासामुखी हो।

जनसंख्या शिक्षा के अवयव—जनसंख्या शिक्षा के निम्नांकित अवयव हो सकते हैं—

1 जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक—इसमें छात्रों को यह बताया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक या कारण कौन-कौन से हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण हैं—छोटी उम्र में विवाह, गरीबी, निरक्षरता, अल्प विधवा आदि।

2 उमाश्राफी—इसके अंतर्गत छात्रों को भूतकाल एवं वर्तमान काल में जनगणना प्रणाली का तुलना करके जनसंख्या परिस्थितियों का समझाया जा सकता है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की परिवर्तन करने का क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ मृत्यु तथा जनसंख्या दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि में होने वाले प्रभावों का समझाया जा सकता है।

3 जनसंख्या वृद्धि के परिणाम—इसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा स्वास्थ्य, आवास रोजगार तथा उच्च जीवन स्तर पर पड़ने वाले गलत प्रभावों का और अच्छा का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

4 मानव पुनरुत्पादन प्रक्रिया की आधारभूत जानकारी—इस प्रकार की जानकारी विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को देनी चाहिए। विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार की जानकारी के लिए उपयुक्त है। कई शालाओं में छात्रों के आयुस्तर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा एवं गृहविज्ञान की कक्षाओं में इस विषय का समावेश भी उपयुक्त ही है। वास्तव-जालिकाओं का इस विषय से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन इस तरह कराया जाय कि उन्हें वैज्ञानिक पाठ्यक्रम में स्वाभाविक क्रम में आवे।

5 शिशु जन से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी—माता के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला जो बात है तथा जिनकी छात्र अवस्था एवं

अनुभव के आधार पर की जा चुकी है उन्हें इसके अन्तर्गत बताया जा सकता है।

(क) अल्प वय माता तथा प्रौढ़ माता के गम धारण।

(ख) विभिन्न गर्भों के बीच न्यूनतम अन्तर।

(ग) उच्च समनुन्यता न्यूनतम अन्तर।

यह भी विचार किया जा सकता है कि उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में उत्पन्न बच्चा की स्वास्थ्य समस्याएँ क्या हैं। इस तरह बताया जा सकता है कि परिपक्व आयु में विवाह हान से माता और उनकी सन्तानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। य विधायक छोटी कक्षाओं की स्वास्थ्य शिक्षा में प्रारम्भ हो सकते हैं और उच्च कक्षाओं में स्वास्थ्य शिक्षा और विज्ञान की कक्षाओं में इनका विस्तृत विवरण दिया जा सकता है।

6 परिवार के आकार पर सुखी जीवन निर्धार—अच्छे नागरिकों के दायित्व निर्माण के लिए प्रत्येक छात्र को यह स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि जनसंख्या नीतियाँ एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का सीधा सम्बन्ध है। प्रारम्भ में सामान्य जानकारी देकर उच्च कक्षाओं में जनसंख्या नीतियाँ एवं सुखी परिवार के साधनों का विस्तृत ज्ञान दिया जा सकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन के साथ इसको पढ़ाया जा सकता है। माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा भूगोल की कक्षाओं में यह विषय पढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान कक्षाओं में स्वाभाविक रूप से इसका बताया जा सकता है।

जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र

जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष या औपचारिक शिक्षा और दूसरी अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक एवं सामुदायिक शिक्षा। बालक, युवा, तथा विश्व विद्यालयीन छात्र अनेक संगठनों से परिचित एवं संगठित रहते हैं तथा धार्मिक तथा विभिन्न कार्यकर्ता समुदायिक संगठनों यथा कल्याण केंद्र, महिला-मण्डल, युवा समूह, सहकारी संगठन तथा वृषि समितियाँ आदि से सम्बन्ध होने के कारण इनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं।

(1) औपचारिक शिक्षा (Formal Education)—युवकों में नवाचार के माध्यम से पाठ्यक्रम की सीमा एवं परिधि के बाहर इस प्रकार की जागरूकता उत्पन्न की जाय जिससे उनमें परिस्थितियों को समझने एवं उन्हें सुगमता से समझने एवं हल करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षक

प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रश्न और दीक्षित प्रशासन को अधिक मुखरित किया जाना आवश्यक है।

शिक्षण में निम्नांकित विचार बिंदु ध्यान में रखने होंगे। स्थानीय परिस्थितियाँ विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तथा बौद्धिक प्रतिवेश तथा परिपक्ष को दृष्टिगत रखना होगा। प्रकरणों का निर्धारण इन बिंदुओं पर भी किया जा सकता है।

- (क) डेमोग्राफिक झुकाव उनके निर्धारक एवं परिणाम।
- (ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास उद्देश्य विधियाँ एवं आवेद।
- (ग) मानवीय समस्याएँ एवं जनसंख्या वृद्धि।
- (घ) समाज समुदाय एवं परिवार का संगठन।
- (ङ) अतिसंख्या के परिप्रेक्ष्य में परिवारिक जीवन।
- (च) जनसंख्या जगत, पशु जगत और मानव जगत में प्रजनन।
- (छ) परिवार का आकार इसके मानदण्ड।
- (ज) मानवीय विकास के प्रारम्भिक मूल्य एवं गुण।

इन सबके लिए भूगोल, सामाजिक अध्ययन, जीवन विज्ञान, गृह विज्ञान आदि को जीवन्त बनाना होगा। जनसंख्या-शिक्षा में शिक्षक और छात्र के मध्य ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें कि इस शिक्षा को जीवन की शिक्षा बनाया जा सके।

(11) अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education)—एक ओर औपचारिक शिक्षा जनसंख्या का कतिपय विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन मात्र प्रशस्त करती है तो दूसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा जीवन को चुनौतियाँ स्वीकार कर सकती है। विकासशील देशों में भी अशिक्षितों की संख्या काफी बढ़ रही है। जब तक ग्रामीण और अशिक्षित जनता का जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में सामिल नहीं किया जायगा तब तक सरलता नहीं मिल सकती है। अनौपचारिक शिक्षा में चुनौतियाँ भी काफी हैं।

जनसंख्या शिक्षा का आरम्भ किन स्तर से हो ?

बहुत से विरोधों की यह राय है कि शालीन जनसंख्या शिक्षा का आरम्भ प्राथमिक स्तर से होना चाहिए। विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के मूल्यों एवं आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक मात्र माध्यम प्राथमिक शिक्षा ही है। जो छात्र माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं उनके सोटन की

समाधान कम रहती है। आवादी के परिवर्तनों से पीड़ित ग्रामवासियों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगे। दूसरा तब यह है कि परिवार की सीमा सम्बन्धी धारणाएँ जीवन के आरम्भिक समय में ही निर्मित होती हैं इसलिए जनसंख्या शिक्षा का समावेश एवं प्रारम्भ प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए।

कुछ विद्वानों का मत है कि विकासशील देशों में जनसंख्या शिक्षा के लिए सीमित बजट और सीमित कार्यकर्ता उपलब्ध होने से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर से ही जनसंख्या शिक्षा प्रारम्भ की जाय।

अच्छा तो यह होगा कि जनसंख्या शिक्षा की प्रारम्भिक अवधारणाएँ प्रारम्भिक ज्ञान प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाय और विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में क्रमशः समाविष्ट की जाय। जनसंख्या शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम में अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का योगदान होगा। प्राथमिक शालाएँ, माध्यमिक शालाएँ, उच्चतर माध्यमिक शालाएँ, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ एवं विश्वविद्यालय सभी इसमें सहयोगी भूमिका निभाएँगे। विकसित एवं विकासशील देशों में विस्तार सेवा-कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

जनसंख्या शिक्षा की चुनौतियाँ

1—जनसंख्या शिक्षा के प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों का विश्वास उत्पन्न करना।

2—जनसंख्या शिक्षा की योजनाओं को तैयार करना तथा उनमें समन्वय बनाए रखना।

3—प्रचलित पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा का समावेश करना।

4—जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्येतर कार्य कक्षाएँ विकसित करना—

जैसे—अध्यापक प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं औपचारिकेतर शिक्षा।

5—विद्यार्थियों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में जनसंख्या शिक्षा के कार्य बंटवारा एवं नियंत्रण के लिए नवीन बृहत् रचना के अनुसार मानवीय साधन, सामग्री एवं समय तथा आवश्यक कार्य स्थल प्राप्त करना।

6—प्रगति का सुसंगठित मूल्यांकन करना। योजनाओं से सम्बन्धित संस्थाओं एवं अध्यापकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सतत सुधार की व्यवस्था करना।

7—आवश्यकतानुसार त्रियात्मक अनुसन्धान (एक्सन रिसच) प्रोत्साहित करना ।

अध्यापक संगठनों क दायित्व—जनसख्या शिक्षा के परिप्रश्य में अध्यापक संगठनों के निम्नानुसार दायित्व होना चाहिए—

1—जनसख्या शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण क सभी स्तरा के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाना—पृथक् पाठ्यक्रम क रूप में अथवा वतमान पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर ।

2—अध्यापकों, प्रशिक्षण विशेषणा एवं छात्राध्यापकों क लिए जनसख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्य गोष्ठिया, परिचर्चाएँ एवं व्याख्यान का आयोजन करना ।

3—अध्ययन एवं अध्यापन सामग्री विकसित करने क लिए कार्य गोष्ठियों का आयोजन करना ताकि पाठ्यक्रम निर्देशिकाएँ एवं नवीन सामग्री प्राप्त हो सके ।

4—जनसख्या शिक्षा के लिए सवारन प्रशिक्षण का आयोजन करना तथा याजनाभा के लिए मुसगठन प्रयास करना ।

5—सरकारा एवं अन्य संस्थाओं का प्रोत्साहित करना कि व अध्यापकों के लिए विभिन्न स्तरा पर अध्ययन शिष्य वृत्तियाँ उपलब्ध कराएँ, ओर जनसख्या शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सक्षम विशेषज्ञ तैयार करन में सहायक हों ।

6—अध्यापकों के व्यावसायिक संगठनों से आग्रह करना कि व जनसख्या शिक्षा के मूलभूत ज्ञान के विकास में सहायता करे ।

7—जनसख्या शिक्षा के अभिलेखा एवं सामग्री का सन्तुलन तथा प्रकाशन कर उसका प्रसारण संगठन क सदस्या में करना ।

8—आवश्यकतानुसार सहायकार सचाएँ, शिष्य वृत्तियाँ, आंतराष्ट्रीय, स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों का आगान प्रगान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना ।

9—जनसख्या शिक्षा क लिए कार्य समूहा का प्रोत्साहित करना ।

10—राष्ट्रीय अध्यापक संगठना को अपन दक्ष के जनसख्या शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठना का विषय व विभिन्न क्षेत्रों में उसी प्रकार की समीक्षा करना चाहिए ताकि दोनों स्तरा पर समन्वय स्थापित हो सके ।

परिवर्तन हेतु अभियान

समार में वही भी जनसंख्या शिक्षा के आदर्श नमूने नहीं हैं जिन्हें शिक्षक अपना नक्का या अपना आधार बना सकें। इस सम्बन्ध में शैक्षिक सामग्री के चयन की सुविधाएँ भी सीमित हैं। जनसंख्या शिक्षा का पूरा वर्णित धारणाओं और शिक्षा प्रणाली की विविधताओं के आधार पर कुछ मुद्दाय इस प्रकार हो सकते हैं।

1—शिक्षा एवं परिवार-वर्धन सस्याजों के मध्य तालमेल

जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी अधिराश योजना निर्माण और प्रियावर्धन का बाय शिक्षा के नियन्त्रण में होना चाहिए। यह समय जेना आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षा, परिवार-वर्धन कार्यक्रमों से पृथक् है। अतः परिवार-वर्धन विशेषता की शिक्षका पर अपने मन का आरोपण नहीं करना चाहिए। दोनों में तालमेल अवश्य रहे लेकिन कार्यक्रम भिन्न होंगे पर्याप्त शास्त्राओं की विषय सामग्री अनेक विद्वानों पर वयस्था के कार्यक्रम से भिन्न होगी।

2—शिक्षक प्रशिक्षण की उच्च प्राथमिकता

शिक्षक प्रशिक्षण उन बानी सस्याजों की ओर सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक प्रशिक्षण सस्याजों में परिवर्तन सरल बात है। शिक्षक का इस दिशा में रुचि बढ़ाने के अनेक आधाम हैं। जनसंख्या शिक्षा की शिक्षका की सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। कुछ स्रोत पुरख तैयार करन हागे और शैक्षिक विधिया में भी परिवर्तन करना होगा।

3—ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का अध्ययन

वे० ए० पी० (Knowledge, Attitude and Personality) के अन्वेषणात्मक अध्ययन वयस्था के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उ हैं शाला के बालका की अभिरुचि के लिए भी अपनाया जा सकता है। परिवार-वर्धन के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के निष्कर्षों से शिक्षका को यह ज्ञान हागा कि जनसंख्या कार्यक्रमों की शैक्षिक आवश्यकताओं का किस प्रकार पूरा किया जाय।

4—बुनियादी संदेशों का प्रकाशन

जनसंख्या शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री का निर्माण विशेष महत्व रखता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सामग्री में संशोधन करना हागा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई जनसंख्या शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक का निर्माण विशेष सावधानी से करना हागा।

इस प्रकार की पुस्तक देश-विदेश की जानकारी का समावेश होगा और यह पुस्तक सभी के लिए सार्वजनिक ग्रन्थ का काम देगी।

5—प्रचलित पाठ्यक्रम के संशोधन की क्रिया का जनसंख्या शिक्षा से मेल

शासनाग्रा के प्रचलित पाठ्यक्रम की संशोधन कर स्वाभाविक रूप में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का समावेश करना।

6—जनसंख्या विशेषज्ञों का प्रशिक्षण

कुछ ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने होंगे जो इस कार्यक्रम में सहायता कर सकें। जनसंख्या शिक्षा में आने वाली कठिनाइयाँ का निवारण कर सकें और लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकें। विशेषज्ञों का प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

भारत में जनसंख्या शिक्षा के कार्य का इतिहास

एशिया के देशों में छठवें दशक में “जनसंख्या शिक्षा” की खोज अचानक हो गई।

भारत के परिवार-कल्याण संघ ने इस दिशा में सर्व प्रथम कदम उठाया। उसने महाराष्ट्र सरकार को एक आपन प्रस्तुत किया जिसमें शालेय पाठ्यक्रमों में संशोधन कर जनसंख्या शिक्षा को सम्मिलित करने का आग्रह किया। इस संगठन ने जन मानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए सगोष्ठियाँ, शिक्षक पुनः अध्ययन आदि आयोजित किए।

इस बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 21 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से जनसंख्या शिक्षा के प्रचार के लिए आग्रह किया गया।

हरियाणा और म० प्र० सरकारों ने जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रम में सामिल कर लिया है। अब इस समय लगभग सभी सरकारों ने इसे अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित या तो कर लिया है या करने की तैयारी कर ली है।

जनसंख्या शिक्षा की औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों के अंतर्गत पाठ योजनाएँ, धार्ताएँ, वाद-विवाद आदि तरीकें उपयोग में लाए जा रहे हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है। चूँकि भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अवस्था में निवास करती है अतएव शिक्षा का सबल आधार ग्रामीण मुखी शिक्षा होना चाहिए।

जनसख्या शिक्षा

मध्य प्रदेश में जनसख्या शिक्षा की प्रगति

प्रदेश में जनसख्या शिक्षा के कार्य की गति प्रदान करने में मार्ग-दर्शन देने तथा कृत कार्य की समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा सहायता में प्र० में जनसख्या शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ की स्थापना निम्नांकित उद्देश्यों से की गई है।

उद्देश्य

- 1—जनसख्या वृद्धि एक संकट है अतः इसका प्रचार प्राथमिक शिक्षा से करना।
- 2—सुलभित जीवन यापन की सुविधा एवं प्रेरणा देना।
- 3—जनसख्या वृद्धि करने वाली सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना।
- 4—परिवार-कल्याण तथा नियोजन की विचारधारा का पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
- 5—शालीय शिक्षा के विषयों के अनुरूप पाठ तैयार कर पाठ्यपुस्तका में जोड़ना।

कार्य—जनसख्या प्रकोष्ठ निम्नानुसार कार्य सम्पन्न कर रहा है :—

- 1—साहित्य सृजन—प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान विषयों के लिए जनसख्या शिक्षा पर आधारित पाठों का निर्माण, क्षेत्र परीक्षण, संशोधन व पुनरावलोकन।
- 2—शिक्षण सामग्री का निर्माण—स्लाइड व फिल्मों, जनसख्या के रिटो, चार्टों का निर्माण करना।
- 3—जनसख्या शिक्षा की संकल्पना का प्रचार व प्रसार—जनसख्या शिक्षा पर आधारित स्लाइड व फिल्मों द्वारा प्रचार व प्रसार करना।
- 4—सेवा कानून प्रशिक्षण—इस प्रयोजना के अन्तर्गत समस्त शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचार्य व व्याख्याता, शिक्षक, सहायक जिला शाला निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शाला के लिए उ-मुखोत्तरण संगोष्ठियाँ आयोजित करना।

कृत कार्य—अभी तक इस प्रकार कार्य किया जा चुका है :—

1—वर्षा 3 से 11 वर्ष के लिए सामाजिक अध्ययन एवं भाषा के पाठों का निर्माण कराया गया।

2—शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री निर्मित की गई।

3—शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों का उन्मुखीकरण किया गया जिसमें जनसंख्या शिक्षा के भावी कार्यक्रमों की स्वरूपा तैयार की गई।

4—प्रदेश के सभी विद्यालयों में इन पाठों का क्षेत्र परीक्षण कार्य कराया जा रहा है।

5—क्षेत्र परीक्षाधीन 100 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया।



बालिका शिक्षा

(Girls Education)

पृष्ठ भूमि—भारतीय नारी का चित्रण करते हुए महाकवि तुलसी ने लिखा है कि “मुन्दरता कहैं सुन्दर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई” किंतु हम भारतीय नारियाँ को अघकार में रखने आए हैं। “यत्न नायस्तु पूज्यत रम ने तत्र दवता” के आदेश वाले देश में बालिकाओं की अशिक्षा एक चिंता की विषय है। भारतीय नारी “वज्रान्पि बटोरानि, मृदनि कुमुदापि” एवं “अचल म मूष जोर आँखा में पानी” जैसे विरोधाभासीगुणों से मण्डित है। एक ओर हमने उसे अवला कहा है तो दूसरी जगह “का न करै अवला प्रबल” भी कहा है। जहाँ एक ओर अपनी हरन, हसन, और लीखी चितवन से घायल करती है तो दूसरी ओर लक्ष्मीबाई जैसी रणचण्डो का नेप धारण कर लाखों को रण में भी घायल करती हैं, अर्थात् भारतीय नारी किसी बात में कम नहीं है केवल वितात्री शिक्षा हम उसे नहीं दे पाए है। हमारी अवोध बालिकाएँ आज भी अपने माँ बाप या पालकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण शिक्षा से वंचित हैं। अधिकांश पालकगण आज भी बालिकाओं की शिक्षा पर किए गए व्यय को व्यर्थ मानकर तथा उन्हें पराया धन मानकर उनके हाथ पीले कर देने में अपना कर्तव्य मानते हैं।

वस्तुन देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का भविष्य अच्छी शिक्षा युक्त बालकों पर निर्भर करता है और बालकों को मस्कार युक्त बनाने तथा उन्हें शिक्षित करने का काफी उत्तरदायित्व माँ पर ही है। माँ का शिक्षित और मस्कार युक्त होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। नारी शिक्षा ही राष्ट्रनिर्माण की कुंजी है। डा. राधाकृष्णन जी के शब्दों में “एक व्यक्ति को शिक्षा देने का मतलब एक व्यक्ति को ही शिक्षित करना है तथा एक महिला को शिक्षा देना समस्त परिवार को सुशिक्षित करना है।” देश, समाज, परिवार का सर्वांगीण उत्थान महिला शिक्षा पर ही निर्भर करती है। नारी शिक्षा ही वह धुरी है जिस पर राष्ट्र की कार्य कुशलता निर्भर करती है। बालिका, माहिला शिक्षा की प्रगति के बिना हमारे सभी सपने अधूरे रहेंगे।

स्वतंत्रतापूर्व बालिका/महिला शिक्षा—विश्व में महिला शिक्षा की प्रगति व अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। त्रिम युग में हमने उसे धार्मिक और सम्मान की दृष्टि से देखा उसके लिए प्रगति का द्वार खुल रहा जब उसे सम्मान नहीं दिया तो उनका लिए शिक्षा अनावश्यक महसूस की गई। वैदिक काल में हमारे यहाँ महिलाओं को समाहित करने का आग्रह रहा है और तभी से यह युग हम जागरण एवं प्रगति की प्रेरणा देता आ रहा है। उस युग में नारी को सम्मान देने के साथ-साथ पुरुषों से बराबर का स्थान दिया गया। सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक श्रेणियों में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। माता-पिता अपने बालक-बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। इस सामाजिक व्यवस्था में वैदिक युग में अनेक विद्वानों महिलाएँ पैदा हुई जिन्होंने देश की श्रद्धाओं का प्रणयन किया। नारी शिक्षा की व्यवस्था विश्व इतिहास में वैदिक काल की बहुत बड़ी विशेषता थी। मानववैद्य ऋषि व साथ शास्त्रार्थ करने वाली विद्वानों महिला मार्गों तथा जगद्गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाली मदन मिश्र की पत्नी भारती को बौद्ध नहीं जानता। इनके अलावा विश्वतारा, अपाना मैत्रेयी, लोपमुद्रा आदि अनेक महिलाएँ तथा मुस्लिम युग की जेनुप्रिया, रजिया, गुलबदन एवं ग़ुरजहाँ आदि नारियाँ के नाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में नारी शिक्षा का पर्याप्त महत्त्व दिया जाता था। इन महिलाओं ने सिद्ध कर दिया कि महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर योग्यताएँ और क्षमताएँ रखती हैं बशर्ते उन्हें अवसर और सुविधाएँ तथा माता-पिता की प्रेरणा मिल सके।

इसके बाद कुछ बीच में ऐसा समय आया जब इस स्वर्णिम व्यवस्था का लोप हो गया। बालिकाओं, महिलाओं की शिक्षा-व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया और हमने उस मकान चहारदीवारी में ही रह लिया। अठारहवीं शताब्दी तक महिला शिक्षा के लिए कोई संस्थानीय कार्य व प्रयास नहीं हुए। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ तक भी कुछ वैदिक प्रगति नहीं हुई और औपचारिक शिक्षा के लिए काफी कम व्यवस्था थी। सन् 1901 में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 0.8 था। स्कूलों में दस 100 लड़कों के मुकाबले में बालिकाओं की संख्या प्राथमिक स्तर पर 12 और माध्यमिक स्तर पर 4 थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन 264 था। बीसवीं सदी से कुछ बालिका शिक्षा के विषय में ज्यादा जागरूकता आई। स्वामी विवेकानन्द ने नारी शिक्षा की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि—“हम चाहते हैं कि भारत की नारियों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे निभय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भलाभाँति निभा सकें और सब भिला, लीला, अद्वितीयादी,

तथा मोराबाई आदि भारत की महान् नारियाँ द्वारा चलाई गई परम्परा को भागे बढ़ा सकें तथा वीर प्रसू बन सकें। सवप्रथम नारी जाति को सुशिक्षित बनाओ फिर वे स्वयं कहेंगी कि उन्हें किन मुघारों की आवश्यकता है।" इस प्रकार नारी की गिरी हुई अवस्था, उनमें व्याप्त अशिक्षा, रुढ़िवादिता और घमण्डिता को दूर करने के सुनियोजित प्रयत्न प्रारम्भ हुए। किन्तु अनेक प्रयासों के बावजूद भी महिला शिक्षा की प्रगति धीमी रही जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	प्राथमिक शास्त्रांश में प्रति 100 छात्रा पर छात्रावा की संख्या	मिडिल स्कूला में प्रति 100 छात्रा पर छात्रावा की संख्या
1901-02	12	4
1911-12	18	5
1921-22	23	6
1931-32	36	8
1941-42	37	12
1946-47	39	21

यद्यपि बालिका शिक्षा में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास हुआ है किन्तु वास्तविकी तुलना में यह प्रगति काफी कम है। सामान्य साक्षरता के मामले में भी यही स्थिति है जो नीचे की तालिका में देखा जा सकता है।

(साक्षरता प्रतिशत में)

	1951		1961		1971	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
भारत	27 14	8 86	40 40	15 33	39 45	18 70
म० प्र०	18 01	3 58	32 19	8 09	32 70	10 92

तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि सामान्य साक्षरता और स्त्री साक्षरता में क्रमशः वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु अभी भी स्थिति अत्यन्त सोचनीय है।

आज भी देश में लगभग 81 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं तथा म० प्र० में लगभग 89 प्रतिशत। अतः इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करना होगा।

स्वतन्त्र भारत में बालिका/महिला शिक्षा की प्रगति व अवरोधक कारण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान में स्त्री और पुरुषों में समानता तथा समाज के अनेक क्षेत्रों में उनकी महत्ता प्रतिपादित की गई। संविधान की यह भाषा हमारी सभी पञ्चवर्षीय योजनाओं में परिलक्षित हुई है। सभी योजनाओं में बालिका शिक्षा की प्रगति के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं। संसार के सभी राष्ट्र महिला शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार कर चुके हैं। 1952 में यूनेस्को द्वारा सभी राष्ट्रों को प्रस्तावित भेजी गई थी जिसके निष्पक्ष रूप में यह सामने आया कि विश्व के सभी राष्ट्र महिला शिक्षा को अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

हमारी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें बालिका/महिला शिक्षा के प्रति चिन्तित हैं तथा तदनुसार प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय संविधान के 6 ब्रह्मों अध्याय की प्रथम धारा में स्त्री और पुरुषों की शिक्षा प्राप्ति का समान अधिकार है। भारत सरकार ने बालिका/महिला शिक्षा को ध्यापक बनाने व उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार कर सुझाव देने के लिये समय-समय पर अनेक समितियों का निर्माण किया है जो इस प्रकार हैं —

- 1—माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जिसने सभी के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किये।
- 2—भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय के प्रस्ताव क्र०/एफ/34-12/57 बी-5 दिनांक 18 मई 1958 के द्वारा “दि नेशनल कमेटी ऑन वीमन एजुकेशन” का गठन किया। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित सभी समस्याओं का अध्ययन किया और महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये।
- 3—श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में बालक/बालिकाओं की पाठ्य चर्चाओं में विशेषीकरण के लिये नियुक्त समिति।
- 4—श्री एम० भक्त वत्सल्य की अध्यक्षता में नियुक्त समिति, जिसने कम विकसित लड़कियों की शिक्षा वाले छह राज्यों में समस्या का अध्ययन किया।
- 5—शिक्षा आयोग 1964-66, जिसने बालिका शिक्षा पर भी विस्तृत विचार प्रकट किये।

6—'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के लिए गठित संसद सदस्यों की कमेटी 1967।

7—राज्या में राज्य स्त्री शिक्षा परिषदों का गठन।

8—प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के सम्बन्ध में गठित कार्यवाही दल 1978।

भारत शासन तथा प्रान्तीय सरकारों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी बालिका शिक्षा की प्रगति काफी कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक की स्थिति इस प्रकार है —

भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक/बालिकाओं की दर्ज संख्या-प्रतिशत

1950-51 55-56 60-61 65-66 68-69 73-74 78-79

प्राथमिक स्तर

बालक	59.8	70.3	81.4	93.0	93.4	100	100.2
बालिका	24.6	32.4	41.9	54.6	57.0	65.0	67.8
योग	42.6	55.9	62.3	75.1	76.0	84.0	84.5

पूर्व माध्यमिक स्तर

बालक	20.7	25.5	35.9	43.8	45.0	47.0	49.2
बालिका	40.0	6.9	12.1	16.7	18.0	21.0	26.0
योग	12.7	16.5	24.3	34.6	32.0	35.0	38.1

उ० मा० स्तर

बालक	8.7	12.8	18.5	24.2	27.0	28.0	25.6
बालिका	1.8	2.6	4.4	7.8	10.0	11.0	11.5
योग	5.3	7.8	11.7	16.1	18.0	20.0	18.8

विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, शिक्षिकाओं की अधिकाधिक नियुक्तियों तथा उन्हें अनक प्रदत्त सुविधाओं, बालिका शिक्षा के लिये गठित समितियों की सिफारिशों व उनके क्रिया कर्मों के बावजूद भी बालिकाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। दश में वर्ष 78-79 की स्थिति में 6-11 आयु वर्ग की 72 प्रतिशत बालिकाएँ तथा 11-14 आयु वर्ग की केवल

20.6 प्रतिशत बालिकाएँ एवं 14-17 वर्ष की 11.5% ही शास्त्राभा में जा रही हैं। इसी स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। मार दम में बालिका शिक्षा की सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं उनके निराकरण के उपायों में साथ ही दोस्त विशेष की विविष्ट समस्याओं का समुचित निराकरण अत्यन्त आवश्यक है। अभी दो बातें सामने हैं —

- (1) पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा में जो विचार चाहिए हैं उस उतनी जरूरी नहीं पाटा जा रहा है जितना आवश्यक है।
- (2) देश के कम विकसित क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति में सिय कुछ करने का बाकी है।

किये गये प्रयास—बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जनक प्रयास किये तथा —

- (i) छात्राभा के लिये छात्र युक्तियाँ।
- (ii) स्कूल मदम की नियुक्तियाँ।
- (iii) बालिका शास्त्राई खोलना।
- (iv) महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति।
- (v) महिला शिक्षिकाओं का आवास गृह।
- (vi) शिक्षण प्रशिक्षण में महिला शिक्षकों को स्टाफपद का प्रदाय।

इन प्रयासों के बावजूद लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच जो काफ़ी बड़ी खाई थी वह धीरे धीरे घटती जा रही है फिर भी अभी बालिकाओं की शिक्षा बालकों के स्तर तक लाने में काफी प्रयास अपेक्षित हैं। संसद सदस्यों की शिक्षा पर रिपोर्ट (1967) जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तन्त्र में गी गई थी, के अनुसार “स्वात सत्तर साल में बालिकाओं की दज सक्या तथा शिक्षिकाओं की सक्या में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काफी वृद्धि हुई है किन्तु बहुत कुछ किये जाने के बावजूद भी बालक और बालिकाओं की दर्ज सक्या में शिक्षा के हर स्तर पर काफी अंतर है। इसलिये बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष धन दिया जाना चाहिये तथा बालिका शिक्षा का प्रगति के लिये प्रमुख प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित कर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। शीघ्र क्रियाचयन के लिये तेज प्रयास किये जाये। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखत हूँ।”

प्रारम्भिक शिक्षा व साक्षरतापीकरण हेतु गठित कार्यकारी दल (1977-78) ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि देश में जो शांता न आन वाला की सख्या है उसमें दा निहाई बालिकाएँ हैं। 6-11 आयुग में 133 लाख और 11-14 आयुग में 183 लाख बालिकाएँ शांताओं से बाहर हैं। इसलिये इनको शांताओं में लान हेतु निम्नानुसार प्रयास करने होंगे।

(1) अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु प्रचार प्रसार।

(2) महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति।

(3) दससख्या बढ़ाने के लिय प्रोत्साहन।

(4) शांता मातृ (स्कूल मदम) की नियुक्ति।

(5) पूर्व प्राथमिक शांताओं, नमरी शांताओं की स्थापना।

बालक/महिला शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण

बालिकाओं की शिक्षा के पिछड़ेपन के दश व प्रदेश में अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं—

1—पालकों की निग्रहता।

2—परम्परागत रुढ़िया व अंध विश्वास।

3—बालिका शिक्षा के प्रति पालकों की उदासीनता।

4—महिला शिक्षिका की कमी।

5—ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों का न रहना।

6—घर से विद्यालय की दूरी।

7—महिला शिक्षकों के लिये आवास व्यवस्था की कमी।

8—पूना समय उपयुक्त न जाना।

9—शांताओं का दीक्षावकाश कृपि परक परिस्थितियों तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल न जाना।

10—बालिकाओं के निम्न उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें न जाना।

11—अपना शांताओं की कमी।

12—सह शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की आपत्ति।

13—बालिकाओं का बाल विवाह न पदा प्रथा।

14—बालिकाओं की पराया धन मानन की प्रवृत्ति।

15—बालिकाओं से गृह राय लिया जाना।

मध्य प्रदेश में बालिका/महिला शिक्षा

1 नवम्बर 1956 का मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। नया म० प्र०, विध्य प्रदेश, महाबोशल, मध्य भारत, रोवा और भोपाल रियासत का मिलाकर बनाया गया। इन क्षेत्रों में महिला शिक्षा का स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की थी। दश का जनसंख्या का दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल में पहला राज्य है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 10.92 है जब कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 18.70 है। म० प्र० विविधभाषा और विरोधाभाषा संयुक्त राज्य है। यहाँ भौगोलिक विषमता है। ग्रन्थ का आबादी में लगभग एक तिहाई आदिवासियों और हरिजनों की जनसंख्या है जो गरीबी में जीवन बिताते हुए काफी पिछड़े हुए हैं।

प्रदेश निर्माण से लेकर अभी तक यद्यपि शासकों का लक्ष्य, शिक्षक संख्या तथा व्यय में कई गुनी वृद्धि हुई है तथापि उस अनुपात में बालिकाओं की साक्षरता या दजसंख्या प्रतिशत में अनुकूल वृद्धि नहीं हुई। क्रमिक विवास अवश्य हुआ है लेकिन मजिस्त काफी दूर है। 79-80 की स्थिति 6-11 आयुवर्ग में बालिकाओं का दज प्रतिशत 41.0, 11-14 आयुवर्ग में 18.0 तथा 14-17 आयुवर्ग में दजसंख्या प्रतिशत 6.26 है। राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं का दज प्रतिशत 6-11 आयुवर्ग में 72.0, 11-14 आयुवर्ग में 28.6 तथा 14-17 आयुवर्ग में 11.5 है। स्पष्ट है कि हम राष्ट्रीय स्तर में काफी पीछे हैं।

म० प्र० में बालिका शिक्षा हेतु किए गए प्रयास—म० प्र० में बालिका शिक्षा की प्रगति एवं प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) राज्य स्त्री शिक्षा परिषद् की स्थापना—वर्ष 1960 में राज्य स्त्री शिक्षा परिषद् की स्थापना म० प्र० शासन द्वारा की गई। इस परिषद् का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं का शिक्षित करना तथा उनके स्तर का उन्नयन करना है। पिछड़े वर्ग और दह्रात की महिलाओं और बालिकाओं का आग वढ़ाना इसका विशेष प्रयास रहेगा। इस परिषद् का जिला स्तरीय समितियाँ भी हैं। परिषद् के निम्नांकित उद्देश्य हैं—

(अ) बालिकाओं, महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए शासन की प्रस्ताव देना।

(ब) बालिका शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में कठिनाइयाँ और समस्याओं का निदान एवं उपचार।

(स) बालिका शिक्षा विकास के कार्यक्रम और योजनाओं के लिए बैठक एवं सम्मेलन करना ।

(द) बालिका एवं महिला शिक्षा के लिए आशासकीय समस्याओं का सहयोग प्राप्त करना ।

(य) महिला शिक्षा की बार शासन और जनता का ध्यान आरपित करना ।

(2) बालिका शिक्षा-निधि की स्थापना—13 दिसम्बर 1972 से बालिका शिक्षा निधि की स्थापना म० प्र० में की गई है । पाँच कराह रुपये का लक्ष्य निर्धारित कर इसकी स्थापना की गई है । काफी बड़ा राशि अनुदान एवं दान द्वारा इकट्ठी हो गई है । यह धन-राशि बालिकाओं का मध्याह्न भोजन, गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, शिक्षिका आवासगृह तथा औपचारिकतर शिक्षा केंद्र आदिक द्वारा शैक्षिक प्रेरणा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है ।

(3) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं का निशुल्क शिक्षा व्यवस्था ।

(4) छात्र वृद्धि हेतु विशेष अभियान चलाया गया ।

(5) महिला वर्ष 1975 के दौरान प्रशिक्षित महिलाओं को बिना चयन परीक्षा के नियुक्ति तथा आयु में 35 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई ।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में आवासगृहों का निर्माण ।

(7) कन्या शालाओं की स्थापना तथा उनमें मूलालया का निर्माण ।

(8) गरीब एवं भेद्योनी छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ, शिष्यवृत्तियाँ ।

(9) हरिजन आदिवासी छात्राओं का ग्यारहवीं वर्षा तक मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रदाय ।

(10) पिछड़ एवं गरीब वर्ग की छात्राओं को मुफ्त गणवेश ।

(11) शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी ॥ महिलाओं के लिए आरक्षण ।

(12) महिला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पण्डा का स्थापना ।

(13) महिलाओं के लिए उपयोगी विभिन्न पाठ्यक्रमों से परिपूर्ण विविध शिल्प कला मंदिर भाषाओं का स्थापना ।

(14) प्रदेश में चल रहे उपशालाओं में स्थानांतरित महिलाओं को प्राथमिकता ।

(15) नसरत शालाओं में शिक्षक की पत्नी का नियुक्ति ।

मध्य प्रदेश में बालिका/महिला शिक्षा

1 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तथा म० प्र० विध्य प्रदेश, महाबोशल, मध्य भारत, रोवा और भापान रियासत को मिलाकर बनाया गया। इन क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की थी। देश का जनसंख्या का दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल में पहला राज्य है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 10.92 है जब कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 18.70 है। म० प्र० विविधताओं और विरासतों का समुच्चय राज्य है। यहाँ भौगोलिक विपन्नता है। प्रदेश की आबादी में लगभग एक तिहाई आदिवासियों और हरिजनों की जनसंख्या है जो तराई में जाकर जीवन बिताते हुए काफी पिछड़े हुए हैं।

प्रदेश निर्माण से लेकर अभी तक यद्यपि बालिका का संघर्ष, शिक्षक संख्या तथा व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है तथापि उस अनुपात में बालिकाओं का साक्षरता या दर्जसंख्या प्रतिशत में अनुकूल वृद्धि नहीं हो सकी। ग्रामिक विद्यालयों का अभाव है लेकिन मजिल काफी दूर है। 19-80 की स्थिति 6-आयुवर्ग में बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 41.0, 11-14 आयुवर्ग में 16.0 14-17 आयुवर्ग में 7.26 प्रतिशत 6.26 है। राष्ट्रीय स्तर पर बालिका का दर्ज प्रतिशत 6-11 आयुवर्ग में 72.0, 11-14 आयुवर्ग में 21.14-17 आयुवर्ग में 11.5 है। स्पष्ट है कि हम राष्ट्रीय स्तर पाछे हैं।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निर्माण से अभी तक 25 वर्षों में ८० लाख शालाबा और पूर्व माध्यमिक शालाबा की संख्या में लगभग 6 गुनी और प्राथमिक शालाबा में तीन गुनी तथा पूर्व प्राथमिक शालाओं की संख्या में लगभग बारह गुनी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार छात्राओं की दज संख्या और शिक्षिकाओं की संख्या में भी कई गुना वृद्धि हुई है। किन्तु अभी भी एक काफी बड़ी संख्या बालिकाओं की शालाबा के बाहर है। नीचे की तालिका से यह देखा जा सकता है—

बालिकाओं की संख्या जो शालाओं में नहीं हैं (Non Enroled Girls) 1978

संख्या लाखों में	6-11 आयु वर्ग	11-14	14-17
भारत	132 00	177 00	189 40
म० प्र०	20 ०6	15 35	17 3

इस प्रकार मध्य प्रदेश और पूरे देश में हमें गहन प्रयास करने होंगे जिससे बालिकाओं की एक विशाल संख्या जो शालाओं में दज नहीं है उसे शिक्षा दिलाई जा सके।

छटी योजना में रणनीति हेतु सुझाव—छटी योजना (1980-85) के अंत तक यदि हमें बालिकाओं की दज संख्या के लक्ष्य 6-11 आयु वर्ग में 90 प्रतिशत तथा 11-14 में 45 प्रतिशत, प्राप्त करने हैं तो हमें युद्ध स्तर के प्रयास करना होंगे अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यद्यपि हमारे साधन सीमित हैं ता भी सीमित साधनों में भी हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रयास निम्नानुसार हैं।

1—विस्तृत सर्वेक्षण से पता लगाया जाय कि जिन स्थानों पर बालिकाओं की दज संख्या कम है उनके कारण क्या हैं और उन्हें दूर किया जाय।

2—दज संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षिका, शिक्षिकाओं का नियमित रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाय।

3—गरीब अभिभावकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाय।

4—बालिका शालाओं की संख्या में वृद्धि।

5—बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं की नियुक्ति।

6—शिक्षिकाओं की भर्तों में विशेष सुलियतें उपलब्ध कराई जाय।

7—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय जिससे वे दूरस्थ स्थानों में आवास की दिक्कत महसूस न करें।

(16) औपचारिकतर शिक्षा के क्षेत्र में 9-14 आयुवर्ग की शालात्म्यागी एवं अप्रवशा छात्रावा की शिक्षा-व्यवस्था ।

(17) प्राइम शिक्षा कार्यक्रम में 15-30 आयुवर्ग की महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था ।

(18) यूनीसेफ सहायता प्राप्त एक अत्यन्त ब्राह्मिकारी योजना द्वारा 0-20 आयुवर्ग की महिलाओं का क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था ।

(19) बालिकाओं के लिए उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का निमाण किया गया है तथा प्रामोण व पहरी परिवर्ष के अनुसार पाठ्यपुस्तकें उनके लिए तैयार की की गई हैं यथा बालिका भारती, माँ भारती, आदि आदि ।

(20) जा पदना नहीं चाहती हैं उन्हें प्ररित कर पदपट योजना के माध्यम में शिक्षित किया जा रहा है ।

बालिका शिक्षा की अभी तक की प्रगति—प्रदेश निमाण से लेकर अभी तक उपयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप जा प्रगति हुई है यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है ।

शालाओं का प्रकार	बालिका शालाओं की संख्या 1956—1979-80	
उच्चतर माध्यमिक	65	367
पूव माध्यमिक	154	1040
प्राथमिक	1388	3660
उपशालाएँ	—	2
पूव प्राथमिक शालाएँ	24	302

बालिका रज सभा एवं शिक्षिकाएँ

शाला का प्रकार	शिक्षिकाओं की संख्या		शिक्षिकाएँ	
	1956—1979-80	1956	1979-80	
उच्चतर माध्यमिक	28749	211606	1539	7034
पूव माध्यमिक	45854	3,15,58	1656	11356
प्राथमिक	203158	13,89,034	3935	19857
उपशाला	—	1631	—	139
पूव प्राथमिक	1561	15707	213	993

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निमाण से अभी तक 25 वर्षों में ८० मा० शालाआ और पूर्व माध्यमिक शालाआ की सख्या में लगभग 6 गुनी और प्राथमिक शालाआ में तीन गुनी तथा पूर्व प्राथमिक शालाआ की सख्या में लगभग बारह गुनी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार छात्राओं की दज सख्या और शिक्षिकाओं की सख्या में भी कई गुनी वृद्धि हुई है। किन्तु अभी भी एक पाफो बनी सख्या बालिकाओं की शालाओं के बाहर है। नीचे की तालिका से यह देखा जा सकता है—

बालिकाओं की सख्या जो शालाओं में नहीं हैं (Non Enroled Girls) 1978

सख्या लाखों में	6-11 आयु वर्ग	11-14	14-17
भारत	132 00	177 00	189 40
म० प्र०	20 56	15 35	17 3

इस प्रकार मध्य प्रदेश और पूरे देश में हमें गहन प्रयास करने होंगे जिससे बालिकाओं की एक विशाल सख्या जो शालाओं में दज नहीं है उसे शिक्षा दिलाई जा सके।

छटी योजना में रणनीति हेतु सुझाव—छटी योजना (1980-85) के अंत तक यदि हम बालिकाओं की दज सख्या के लक्ष्य 6-11 आयु वर्ग में 90 प्रतिशत तथा 11-14 में 45 प्रतिशत, प्राप्त करने हैं तो हम युद्ध स्तर के प्रयास करना होंगे अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यद्यपि हमारे साधन सीमित हैं तो भी सीमित साधन में भी हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रयास निम्नानुसार हैं।

1—विस्तृत सर्वेक्षण से पता लगाया जाय कि जिन स्थानों पर बालिकाओं की दज सख्या कम है उनके कारण क्या हैं और उन्हें दूर किया जाय।

2—दज सख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों, शिक्षिकाओं का नियमित रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाय।

3—गरीब अभिभावकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाय।

4—बालिका शालाओं की सख्या में वृद्धि।

5—बड़ी सख्या में शिक्षिकाओं की नियुक्ति।

6—शिक्षिकाओं की भर्ती में विशेष सट्टलियते उपलब्ध कराई जाय।

7—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं के निवास आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय जिससे वे दूरस्थ स्थानों में आवास की दिक्कत महसूस न करें।

8—जहाँ बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत कम है वहाँ प्राथमिक कक्षा के पूर्व बालकों की आयु समूह के लिए नर्सरी शाखाओं की स्थापना तथा “पति पत्नी दोनों शिक्षक” को नियुक्ति। शिक्षक के साथ उसकी पत्नी को भी प्रतिमाह कुछ निश्चित राशि प्रदान कर प्राथमिक शाखा से सम्बन्धित नर्सरी स्कूल का संचालन कराया जाय। इस प्रकार पति-पत्नी एक साथ जहाँ एक ओर बालिकाओं की शिक्षा में सापेक्षता करेंगे वहीं उनका आर्थिक और पारिवारिक स्तर भी सुधरेगा। म० प्र० में यद्यपि यह योजना 80-81 में लागू हो गई है किन्तु इसके विस्तार की आवश्यकता है।

9—ग्रैंड महिलाओं की तरह बालिकाओं के लिए भी क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था हो।

10—पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के साथ प्रत्येक वर्ग की गरीब बच्चियाँ को प्रोत्साहन स्वरूप मुफ्त गणवेश, मध्याह्न-भाजन, पुस्तकें, कागज क्लम आदि उपलब्ध कराई जाय।

11—प्रचार-प्रसार माध्यमों द्वारा अभिभावकों में बालिका शिक्षा की प्रति रुचि जागृत की जाय।

12—बालिकाओं के लिए उनके अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था की जाय। यद्यपि म० प्र० में यह कार्य प्रारम्भ हुआ है किन्तु इसे और भी प्रगति की ओर ले जाना होगा।

13—आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षिकाओं को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण विद्यापीठ की स्थापना आवश्यक है।

14—शाखाओं का दीर्घविकाश स्थानीय परिस्थितियों तथा कृषि परक परिस्थितियों के अनुरूप रखा जाय।

15—शाखा समय में परिवर्तन आवश्यकतानुसार किए जाने की छूट स्थानाध्यक्ष को हो।

16—बालिकाओं के लिए अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिपाएँ प्रदान की जाय तथा वे प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें शिथिल की जाय।

17—आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में शिक्षण की व्यवस्था।

18—बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक समता, जन सेवा संस्थाएँ, व्यक्तियों का आना आना चाहिए सभी बालिका शिक्षा की यह विशाल समस्या पर ध्यान दिया जा सकता है।

19—औपचारिकतर शिक्षा-व्यवस्था में अधिकाधिक विस्तार किया जाय । जिससे शाला न आने वाली या बोच में छोड गई बालिकाएँ सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

20—शालाओं विशेषकर माध्यमिक शालाओं के साथ छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे दूर की बच्चिया भी छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा ज्यादा आवश्यक है । बालिकाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है । वे देश की भावी नागरिक तो बनेगी ही सुगृहणिया और माताएँ बनकर घर भी सभालेगी । अतः बालिकाएँ शैक्षिक प्रगति में पीछे न रह सकें इसके लिए हमें कोई कसर नहीं उठा रखना चाहिए । एक बालिका शिक्षित होने का मतलब है पूरा घर शिक्षित होना । इसलिए हम अपने प्रयास बढ़ाने चले ता अभी भी देर नहीं हुई है ।



आदिवासियों की शिक्षा

(Tribal Education)

हम सब पढ़-लिखा न सम्यता के, शिक्षा के, रहन सहन के असंग अलग मापदण्ड बना लिए हैं। जा बिजली को रोशनी में रहना है, सम्य है, जो लालटेन या दिए के प्रकाश में रहता है, वह पिछड़ा है और जो लकड़ियाँ, कड़े जलाकर उसी की रोशनी में रोटी बनाकर खाकर सो जाना है वह तो गया-बोता है। फरटि स जो अंग्रेजी बोल सता है वह शिक्षित है, आक्सफोर्ड की अंग्रेजी बोलता है तो और भी अधिक शिक्षित है। केवल हिंदी ही जानना है तो कम शिक्षित है और अपनी घरेलू या आचलिक बाली ही बोलता है तो निरा गँवार ही है। पश्चिमी वेशभूषा साहिबी का प्रतीक है। साधारण वेशभूषा गँवारपन का और लँगोटी तो पिछड़ेपन का प्रतीक ही मान लिया गया है। हम अपनी भाषा बोलत हैं तो गँवार हैं, लिखत हैं तो साहित्यिक जन उसमें ग्राम्यत्व दोष निकामते हैं। तो ऐसी ही हमने सम्यता-संस्कृति, शिक्षा आदि की विभिन्न परिभाषाएँ बना रखी हैं। हमें लगता है हमारा चस्मा खराब है या कि दृष्टि दोष है।

हमने आदिवासियों को पिछड़ा मान रखा है। उनके बच्चे हमारी पाठ्य-पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। इस कारण हम उन्हें परीक्षा में फेल कर देते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि उनकी भाषा में यदि हमें पढ़ाया-लिखाया जाय तो हमारी क्या स्थिति होगी। हमने यह कभी नहीं सोचा कि आखिर वे किस बात में कम हैं? उनमें शारीरिक शक्ति भरपूर है, सर्दी, गर्मी, बरसात में रहने और सहने की सहनशीलता भी है। संसार के शोर-सरावे से दूर, न भाघी का देना, न ऊषा का देना। तुलसीदास जी के अनुसार "नाथ हमारा यही सेवकाई सेहि न वासन बसन चुराई" के सिद्धांत का पालन करते हुए सुख से रह रहे हैं। जीवन का असली आनंद आदिवासियों ही सठाते हैं। उन जैसे भेले और मिसन हम लोगों में कहाँ होते हैं? "घोटुल" की कल्पना से ही किसके मन में मिसरी नहीं घुसने लगती? उनके "घाटुल" संसार के उत्कृष्ट प्रणय केन्द्र हैं। क्या हम सम्य कहलाने वाला का कोई घोटुल हैं। हम सब तो ऊपरी दिखावे छत्तावे में ही प्रमित हैं। व अच्छा प्यार

और स्नेह जानन हैं। सभी एक साथ अपने परिवार में हितमिल कर रहते हैं। खाते हैं, पीते हैं नाचते हैं, राग-रग में मस्ती करते हैं। जब व (घोड़ा) पर मधुरस पान कर समूहों में नृत्य गान करते हैं तो उनकी महफिलों में रत जगें का आलम हो कुछ और होता है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर देश की अमूल्य निधि है।

ससार का सुख और सतोष तो आदिवासी अच्छा में बिखरा मानूम पड़ता है। मैं एक बूढ़ा खाकर भी सतोष कर लेता हूँ और हम नौ सौ बूढ़े खाकर भी हज करने की सोचते हैं। नृत्य ऐसा बढ़िया करने हैं कि उनकी हम भी नकल करते हैं, बिरतू महाराज भी चकराते हैं। ईमानदारी में उनकी बराबरी नहीं। सतोष धन होने से उन्हें सार धन धूल के समान है। आदिवासी बालाओं का स्वाभाविक रूप सौन्दर्य, अगा का उठान, सुघडता, कोमलता और पठोरता, लुनाई और लावण्यता, चपलता और चातुर्य और चंचलता देखते ही बनती है। वहाँ की बालाओं की प्रवृत्तिदत्त लुनाई कुछ और ही है। प्रवृत्ति उसे और भी तरासती रहती है। उस लावण्यता को "ज्या-ज्या निहारिए नेरे हूँ नेनन, त्यो त्यो खरी निकरे सु लुनाई" वाली पंक्ति अक्षरसः सत्य प्रतीत होती है। उनके जीवन साथी चुनने के तरीके इतने विकसित, फावड हैं कि उनके सामने हम सब पिछड़े लगते हैं। उनमें कोई विकार नहीं, मलिनता नहीं जबकि हम सब के रोमांस में विकार दिखाई देता है। उन्हें देखकर मन सहज हो उठता है जबकि भौतिकवाद में वैसी सहजता नहीं है।

जब उन्हें जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा हमसे अच्छी प्राप्त है तो भी हमने उन्हें पिछड़ा मान लिया है और वह भी महज इसलिए कि उन्हें किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन्होंने स्कूला, कालेजा का मुह नहीं देखा। उनके पिछड़ेपन के लिए हम सभी तो जिम्मेदार हैं। यदि उन्हें किताबी ज्ञान भी देना पड़े तो हम उन्हें क्यों नहीं प्रेरित कर सकें कि वे स्कूल जावें और शिक्षा प्राप्त करें। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम साधनों की कमी से उनकी तरफ आवश्यक ध्यान नहीं दे सके। जो जितना चित्लाया उसे उतने अधिक साधन सुलभ हुए। बेचारे आदिवासी अपनी मस्ती में रहे इसलिए उनकी तरफ ध्यान भी आनुपातिक रूप से कम दिया जा सका। लेकिन हमें फिर आभास हुआ कि प्रदेश की कुल आबादी में 20 प्रतिशत जो आदिवासीगण तथा 13 प्रतिशत हरिजन हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमने महसूस किया कि उनके लिए किताब, पाठ्यक्रम, उनके हितों का चिन्तन राजधानी की अट्टालिकाओं में न होकर उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के अवलोकन में हो सकता है।

हम सभी और हमारी सोच बन्धनकारी गंवार आन्विमिया का शिगा, दीगा उनके स्तर उचयन के लिए काफी कुछ रचित है और काफी चिन्तन काफी प्रयास इस शिक्षा में किए जा रहे हैं। हम देखें कि आन्विमिया, दीगिर दोह में कहाँ है? सामान्य स्थिति तथा अर्थों के माय सान में क्या कुछ करना होगा इसी समाप्ता भी करें।

हरिजन एवं आदिवासियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति—प्रदेश में आन्विमिया की सगभग। करोड़ एवं अनुसूचित जाति की 58 लाख जनसंख्या है। दोनों मिलाकर कुल आबादी के एक तिहाई से अधिक हैं। इनका सागरता की स्थिति इस प्रकार है—

(1) साक्षरता का प्रतिशत (1971)

सम्पूर्ण प्रदेश	साक्षरता प्रतिशत (सभी वर्ग)	अनुसूचित जनजाति	अनु० जाति
योग	22 12	योग 7 62	12 33
पुरुष	32 76	पुरुष 13 04	22 15
महिला	10 84	महिला 2 18	3 88

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आन्विमियासंग साक्षरता में काफी पिछड़े हैं। उनकी साक्षरता का प्रतिशत, सम्पूर्ण से सगभग एक तिहाई है। प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 10 84 है जबकि आन्विमिया महिलाओं का यह प्रतिशत 2 18 है जो कि काफी कम है और चिंता का विषय है।

(2) दजसंख्या और उसका प्रतिशत (1978-79)

अनुसूचित जनजाति	बालक	बालिका	योग
(अ) वय 1 से 5 तक की दजसंख्या (साक्षा में)	5 03	1 71	6 75
(ब) 6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या सेदज संख्या का प्रतिशत	70 00	25 10	48 20
(स) वय 6 से 8 तक की दज संख्या (साक्षा में)	0 64	0 13	0 77

(द) 11-14 आयु वर्ग की कुल सख्या से दर्ज सख्या का प्रतिशत	16 90	3 60	10 40
(र) कक्षा 9 से 11 तक की दज सख्या	0 24	0 04	0 28
(य) 14-17 आयु वर्ग की कुल सख्या से दज सख्या का प्रतिशत	6 25	1 10	3 68

अनुसूचित जाति

(अ) कक्षा 1 से 5 में दज सख्या	3 98	1 30	5 28
(ब) 6-11 आयु वर्ग में दज सख्या का प्रतिशत	82 00	29 40	58 00
(स) कक्षा 6 से 9 तक की दज सख्या	0 85	0 16	1 01
(द) 11-14 आयु वर्ग की कुल सख्या से दर्ज सख्या का प्रतिशत	34 40	7 00	21 20
(य) 14-17 आयु वर्ग में दज सख्या	0 36	0 05	0 41
(र) दज सख्या प्रतिशत	13 88	2 15	8 20

इस प्रकार हरिजन और आदिवासी छात्र छात्रावा की शैक्षिक स्थिति-काकी पिछड़ी हुई है। यद्यपि प्राथमिक स्तर पर स्थिति सामान्य के आसपास है किन्तु पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्थिति काकी चिन्तनीय है। अखिल भारतीय स्तर पर इन वर्गों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

भारत में अनुजाति और जनजाति की दज सख्या प्रतिशत (वर्ष 1978-79)

आयु वर्ग	अनु० जाति		अनु० जन जाति			
	प्राथमिक	वालि०	याग	वालि०	याग	
6-11	102 9	55 9	79 9	89 3	43 4	66 4
11-14	37 7	14 5	26 5	25 6	10 0	17 9

राष्ट्रीय स्तर पर भी हरिजन और आदिवासी वर्गों के वासका का शिक्षा काफी पीछे है। यदि प्रदेश की तुलना राष्ट्रीयस्तर से करें तो हम अनुपाति और जनजाति की शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं। -

म० प्र० में हरिजन आदिवासियों की शैक्षिक व्यवस्था

आदिवासी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने अनुजाति एवं जनजाति की शिक्षा का भार हरिजन एवं आदिम कल्याण विभाग को 1964-65 में सौंपा। हरिजन एवं आदिवासी प्रधान 27 जिलों का उपयोजना क्षेत्र का नाम दिया गया। इन क्षेत्रों में शालाएँ/छोटी-छोटी जिल्मे दारी आदिम जाति कल्याण विभाग की है, किन्तु योजना निर्माण शिक्षा विभाग करता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय आवश्यकता एवं अनुपातिक रूप में शिक्षा विभाग के बजट से तथा शेष के द्वाय अलावा राशियाँ से हाता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग अपने बजट से आदिवासी छात्रावास, आश्रम शालाएँ तथा अन्य शालाएँ भी खोलता है तथा बहुत से प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाता है।

इस समय म० प्र० के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 465 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ 2603 मिडिल स्कूल, 16982 प्राथमिक शालाएँ, 388 उप शालाएँ तथा 145 पूर्व प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में शालाएँ	(1979-80 की स्थिति)		
	वासक	वासिका	योग
उ० मा० शालाएँ	399	66	465
पूर्व मा० शालाएँ	2322	281	2603
प्राथमिक शालाएँ	16082	900	16982
उप शालाएँ	388		388
पूर्व प्राथमिक शालाएँ	68	77	145
योग	19259	1324	20583

इन शालाओं में अलावा आदिवासी क्षेत्रों में 151 आश्रम शालाएँ, 1350 छात्रावास संचालित हैं। आश्रम शालाएँ और छात्रावास आदिम कल्याण विभाग के अन्तर्गत हैं।

हरिजन आदिवासियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण

1—हरिजन एवं आदिवासी बालक शासनाये जाने हैं मगर बहुत कम। उनको समझ में नहीं आता कि स्कूल क्या जाना चाहिए।

2—अभिभावकों की गरीबी शैक्षिक प्रगति में प्रमुख कारण है।

3—जो बालक स्कूल जाते हैं वे भी बहुत से बीच में ही शाला छोड़ देते हैं। अथवा बालकों में भी यह प्रवृत्ति है किन्तु इन वर्गों के बालकों में अधिक है। तीन चौथाई बालक पाँचवी तक आते-आते शाला छोड़ देते हैं।

4—इन वर्गों के बालक अनुपस्थित रहते हैं। कई कारणों से शाला नहीं आते हैं यथा शाला का अनाकंपक होना। खेती-किसानी का काम, त्योहारों पर मौज-मस्ती मारना आदि।

5—हम आदिवासी बच्चा को उनकी भाषा में न पढ़ाकर सबकी भाषा में पढ़ाते हैं। हमारी भाषा उनकी समझ में नहीं आती है, इसी वजह से भाषा में हिजरे की गलतियाँ भी बहुत होती हैं।

6—विज्ञान और गणित में भाषा के शब्द ही समझना उन्हें कठिन है फिर विज्ञान के मूल तत्व या समझना और भी कठिन है।

7—हम उन्हें भूगोल का ज्ञान देते हैं। जो बालक घर से बाहर ही नहीं गया उस ता दूरी का ध्यान ही नहीं आता है। इतिहास विषय का भी यही हाल है।

8—टाइम टेबुल उन्हें अनुकूल नहीं है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक सभी को टाइम टेबुल बाध रहता है। जो बालक उम्रकत रहता हो वह टाइम टेबुल में कैसे बँधकर पढ़ सकता है।

9—परीक्षा सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। आदिवासी बालक नाचता है, गाता है, काम खूब करता है, शिकार खेलता है, किन्तु हम केवल किताबी ज्ञान की परीक्षा लेकर उसे फैन कर देते हैं।

10—परीक्षा में हम जो पूछना चाहते हैं उसे वह जानता ही नहीं है तो उत्तर कैसे देगा।

11—पोस्ट मेट्रिक बर्जीफा प्राप्त बालकों के सर्वेक्षण से पता चलता कि उन्हें उनके गुणों और रुचियों का परीक्षण कर सही दिशा नहीं दिखाई गई।

12—समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, रुढ़िवादिता, अंधविश्वास भी शैक्षिक प्रगति में बाधक है ध्यातव्य है कि इन वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा में।

13—पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें उनके अनुकूल नहीं हैं, उनकी रुचि और आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं।

14—शालाओं का समय भी उनके अनुकूल नहीं है।

15—शिक्षा के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार और जागृति की गयी।

उपर्युक्त कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने सन्ने अन्तराल के बाद भी इन वर्गों के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई है।

हरिजन, आदिवासियों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

इन वर्गों की शिक्षा प्रगति के लिए निम्नानुसार प्रयास किए गए हैं —

1—शालाओं की स्थापना—मध्य प्रदेश के उपजाऊना क्षेत्र में शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा खोली गई वष 79-80 की स्थिति 465 उ० मा० शालाएँ, 2603 पूर्व प्राथमिक 116982 प्राथमिक, 388 उपशालाएँ तथा 145 पूर्व प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं। वर्ष 80-81 में म० प्र० मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार सभी ऐसे ग्राम जिनकी जाबागी 300 या अधिक है सभी में प्राथमिक शालाएँ खोली गई हैं। किसी भी इंचे का 1 किलोमीटर से अधिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं चलना पड़ेगा।

2—आश्रम शालाएँ—आदिवासी क्षेत्रों में जो काफी विरल हैं और जन संख्या फेरी है उन क्षेत्रों की प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए आश्रम शालाओं की स्थापना की गई है। ये शालाएँ सनिवास शालाएँ हैं। इनकी संख्या वर्ष 78-79 की स्थिति में 151 है।

3—पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाएँ—जिन आदिवासी या हरिजन वन्त क्षेत्रों में साक्षरता कम है वहाँ प्राथमिक शालाओं में खदान नवरी गानाएँ खाली गई हैं। गाँव में प्राथमिक शाला के शिक्षक की पत्नी को नर्सरी शाला चलाने का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक की पत्नी को प्रतिमाह निश्चित मान दय प्राप्त होगा। वष 80-81 में इन क्षेत्रों के लिए 2130 पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाएँ स्वीकृत हुई हैं।

4—सघु शालाएँ—जहाँ की आबादी 300 से कम है एवं जहाँ 15-20 बालक उपसंघ हो सकते हैं ऐसी जगह स्थानीय शिक्षित व्यक्ति को 150 रु० प्रतिमाह मानदेय दकर ये शालाएँ संचालित की गई हैं। इनमें बच्चा 1 से 3 तक बच्चाएँ रहती हैं।

5—छात्रावास—बालक, बालिकाएँ गरीबी की वजह से दूर जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः उनकी शिक्षा-व्यवस्था हेतु हरिजन, आदिवासियों के

लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है जिनमें रहकर वे शालाओं में पढ़ सकें। इनका व्यवसाय शासन बहन करता है।

6—भवन निर्माण—उपयोजना क्षेत्र में कुछ तो राज्य शासन की निधि से और कुछ केन्द्र के छात्रावास राशियों से शालाभवनों का निर्माण कराया गया है जिससे बालकों को शालाओं में अच्छा परिवेश मिल सके।

7—प्रोत्साहन कार्यक्रम—हरिजन आदिवासियों के बालक/बालिकाओं को शिक्षा में रुचि जागृत कर अध्ययन जारी रखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम चालू किए गये हैं जो इस प्रकार हैं।

(i) बुक बैंक योजना—प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई 1975 से मध्य प्रदेश की शालाओं में बुक बैंकों की स्थापना की गई है। इन बुक बैंकों के माध्यम से कक्षा 3 से 11 तक शालाओं में अध्ययन रत सभी हरिजन और आदिवासी बच्चा को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

(ii) बालिकाओं को गणवेश—गरीब बच्चियों को शालाओं में आने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निशुल्क गणवेश दिया जाता है।

(iii) मध्याह्न आहार कार्यक्रम—उपयोजना क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है। इसमें से कार्यक्रम हैं 6-14 आयुवर्ग के लिए मध्याह्न आहार कार्यक्रम तथा दूसरा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं व गर्भवती माताओं के लिए है। वर्तमान में लगभग 14 लाख बच्चा, माताओं को निशुल्क पोषिक आहार प्राप्त हो रहा है।

(iv) अभिभावकों और शिक्षकों को आर्थिक प्रोत्साहन—गरीब पालक अपने बच्चा को शाला भेजें और उसमें पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करें, इसके लिए पालका हेतु आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। उसी प्रकार दल संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

(v) छात्र वृत्तियाँ—हरिजन और आदिवासी छात्र छात्रावासों को कक्षा 3 से 11 तक राज्य छात्र वृत्तियाँ तथा उससे आगे मेट्रोकोतर छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जाती हैं। इन्हें समय पर वितरण करने के लिए कारगर व्यवस्था की गई है।

8—औपचारिकतर शिक्षा-केंद्रों की स्थापना—आयुवर्ग 9 से 14 के शालात्यागी एवं शाला अप्रवेशी छात्र छात्रावासों के लिए औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर बच्चा की समय सुविधा अनुसार

पढाई होती है। उपयोगिता क्षेत्र में संगम 1000 औपचारिकतर शिक्षा सिद्धा में नए आदाम एव नवाचार के द हैं।

9--विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार—आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान में शिक्षा का प्रचार-प्रसार 79 एव विज्ञान म्युजियम की स्थापना की गई है। वर्ष 80-81 से एस्ट्रोनामी के माध्यम से शिक्षा का विज्ञान प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(10) मिलन दिवसों का आयोजन—औपचारिक उपयोग का अपने में कोई महत्व नहीं है यदि उसमें भावात्मक मूल्यता न हो। सभी सस्थाएँ एक परिवार हैं और समस्त हावर समान उद्देश्य के लिए क्रियाशील हों। इस औपचारिक शिक्षा के लिए 5 दिन रचे जा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन शान्तावृत्तों के सभी शिक्षक और छात्र एकत्र होकर समान कार्यक्रम में भाग लें हैं इन्हें मिलन-दिवस कहा जाता है। यह दिवस सम्पूर्ण शिक्षावृत्त की सम्पूर्ण शिक्षा का नामि-बिन्दु है। यह दिवस विभिन्न ग्रामों में बारी बारी से आयोजित होता है। इस दिन के मुख्य कार्यक्रम होते हैं खेलकूद और परिसंवाद। प्रतिस्पर्धा के लिए सप्ताह भर प्रयास होता है। मिलन-दिवस स्थानीय प्रतिभा के प्रस्तुतन और विकास के लिए संवर्धन स्थल की भूमिका बढ़ा करेगा जहाँ पर उच्च अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता, अवसर और मार्ग-दर्शन मिलेगा। वर्ष 79-80 से इस प्रकार के दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। 79-80 में प्रथम बार शासन ने सात लाख का प्रावधान इस कार्य हेतु रखा था।

(11) प्राथमिक शिक्षा वृत्त—बौद्धिक आयोग ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा परिसरों की कल्पना की थी किन्तु आदिवासी क्षेत्रों में तो प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षा की समस्या है। जहाँ पाँच सात पारा या ग्रामों में एव उनकी शाखाओं को मिलाकर एक शिक्षा वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त में शिक्षा की सम्पूर्ण आवश्यकता की जिम्मेदारी उस वृत्त में कार्यरत स्कुल की होगी। प्राथमिक शाखा या उपशाखा में एव-एक शिक्षक वहीं कार्यरत होगा। यह सम्पूरा वृत्त ही एक वैयक्तिक परिसर होगा। इसमें अवस्थित सस्थाओं में से एक के द्वीय विद्यालय होगा और उस के द्वीय विद्यालय का प्रधान सम्पूर्ण गुरुकुल का प्रधान होगा। इस प्रकार शिक्षा वृत्त प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत इकाई होगा।

(12) मिलन मंडई का आयोजन—“मिलन मंडई” का तात्पर्य है प्रदेश के कोन कोन से आये आदिवासी/हरिजन छात्र छात्राओं का विचार-आत्मक,

भाषात्मक आनन्द, उत्साह एवं रचनात्मक अनुभूति से भरा मिलन महोत्सव। इसका मुख्य उद्देश्य है "विकास में युवाशक्ति का योगदान।" सर्वप्रथम म० प्र० म यह आयोजन 21 से 27 जनवरी 1979 में आयोजित किया गया जिसमें वयस 8 से 11 म पढ़ने वाले 14 से 18 आयु वर्ग के 3000 हरिजन/आदिवासी छात्र छात्राओं का भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक प्रतिभा का परिचय दिया। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ हुईं, मनोरंजन हुआ।

इस आयोजन के प्रत्येक दिन छोटे-छोटे समूहों ने विषय की दिशा में मुख्य विषयों पर चर्चाएँ भी कीं। मुख्य दिशाएँ ये हैं—

- (क) जिम्मा का संघात्मक और गुणात्मक विकास।
- (ख) नागरिक जिम्मा।
- (ग) सम्भागिता।
- (द) सहनिर्माण।
- (य) वन एवं वृक्षारोपण।

इस प्रकार मिलन महर्षि कार्यक्रम अपने आप में एक अतृप्त रचनात्मक शैक्षणिक आयोजन है। इसके बाद हर 6 माह बाद जिला स्तर पर छोटे-छोटे आयोजन होते हैं।

(13) खेलकूद परिसरों का विकास—हमारे आदिवासी भी खेलकूद में अग्रणी हो सकते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक माध्यमिक शाला को विशेष रूप से सुसज्जित किया जा रहा है। खेलकूद के अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

(14) स्वाच्छर एवं गाइडर का प्रशिक्षण—आदिवासी बच्चों को स्कार्टिंग एवं गाइडिंग की अच्छी शिक्षा देकर उन्हें देश के अच्छे नागरिक बनाया जा रहा है।

(15) शिक्षिका आवास गृहों का निर्माण—महिला शिक्षक आवास की दिव्यता के कारण गाँवों में नहीं जाती हैं अतः ग्रामीण बालिका की शिक्षा पर काफी विपरीत असर पड़ता है। अब आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षक आवास गृह बनाए जा रहे हैं।

(16) पुस्तकालयों और वाचनालयों का विकास—आदिवासी हरिजन बच्चों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिये विद्यालयों में वाचनालयों का विकास किया गया है। जिससे पुस्तकालय भी स्थापित किये गये हैं।

शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार

(17) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार—पिछले और आदिवासी बच्चा व लिये वर्तमान पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अनुकूल नहीं पा। अतः उनकी आवश्यकताओं और समाज की इच्छाओं के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया गया है। ग्राम भारता, बासिका भारती, आदिवासियों के लिये वन भारती पुस्तकें बनाई गई हैं।

(18) शालाओं में फर्नीचर टाटपट्टी का प्रभाव—आदिवासी क्षेत्रों में सभी स्तर की शालाओं में फर्नीचर और टाट-पट्टी प्रदान कर उनकी भौतिक सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है जिससे छात्रों की अनुविद्या न हो।

(19) विज्ञान उपकरणों का प्रभाव—उ० मा० विद्यालयों एवं प्रारम्भिक शालाओं में क्रमशः विज्ञान के उपकरण एवं विज्ञान किट्स प्रदान किए गये हैं जिससे विज्ञान की शिक्षा समुन्नत हो सके।

(20) बालक, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण—अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से नियमित किया गया है कि बालक बालिकाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय। अतः बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और बच्चा का स्वस्थ रहने की सलाह दी जाती है।

राज्य की छठवीं आयोजना (1980-85) में आदिवासी एवं हरिजनों के शैक्षिक विकास के लिये निम्नानुसार प्रस्तावित किए गए हैं—

- 1—शालाओं की संख्या में वृद्धि।
- 2—शालाओं में शिक्षकों की कमी को पूरा करना।
- 3—भौतिक सुविधाओं का विकास।
- 4—गुणात्मकता के प्रयास।
- 5—स्थानीय भाषा में शिक्षण।
- 6—विज्ञान शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
- 7—हरिजन बहुते क्षेत्रों में शालाएँ खोला जाना।
- 8—प्रोत्साहनों में वृद्धि एवं विकास।
- 9—प्रशासन में सुधार।
- 10—आदिवासी हरिजनों की शिक्षा विकास के लिये अलग से शिक्षा संचालनालय का निर्माण।
- 11—औपचारिक और शिक्षा के क्षेत्रों का विस्तार।

12—पढ़ो कमाओ योजना का विस्तार ।

आदिवासी/हरिजनो की शिक्षा के लिए क्या करें ?

आदिवासी/हरिजना को हम शिक्षित कर सामान्य स्तर तक लाना है । प्रयास ऐसे होने चाहिये जो कारगर हो । मोटे रूप में इनकी शिक्षा के लिये प्रयत्न इस प्रकार होना चाहिये—

- (1) इन क्षेत्रों की शालाएँ आकर्षक हो । उ मुक्त वातावरण हो । या कहा जाय कि स्कूल ही न हो अर्थात् स्कूल ऐसा हो कि उसे स्कूल न कहा जाय ।
- (2) पाठ्यक्रम स्वतन्त्र हो, कोई लकीर के फकीर पर चलने वाली क्रमबद्धता न हो, जितना चाहो पढाओ जितना न चाहो न पढाओ ।
- (3) सब चीजे पाठ्यक्रम में आना चाहिये, वह भी पढे उसका गुरु जो भी पढे ।
- (4) पाठ्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में बैठकर बनाया जाय ।
- (5) पाठ्यक्रम खुले छोर वाला हो अर्थात् उसमें सब तरफ से परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन की गुंजाइश रहे । पाठ्यक्रम सतत चलने वाला हो ।
- (6) प्रारम्भिक स्तर पर बालक की भाषा में ही शिक्षा दी जाय ।
- (7) पिछड़े क्षेत्रों में जीवन यापन की समस्या है अतः पाठ्यक्रम खाने का बनाया जाय ।
- (8) आकर्षण के लिये शैक्षिक सुविधाएँ दी जाय ।
- (9) किसी वयन में बालक को बाधा न जाय ।
- (10) विज्ञान, गणित के कठिन भाव सरल भाषा में सिखाय जाय और उसके अनुरूप शिक्षकों का प्रशिक्षण भी हो ।

हम आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों को खानना है, इन बालकों को पान देना है तभी वह धौडगा, खाय करेगा । यह देखा गया है कि जो बालक स्कूल जाता है वह नाचता नहीं है, गाता नहीं है, काम भी करना बंद कर देता है, माँ बाप का भी नहीं मानता है । हम उसे ऐसी शिक्षा दे कि वह मेहनतकश भी रहे, नाचे-गाय और माँ, बाप तथा अपने गुरुजना के प्रति आज्ञाकारी हो ।

किताबी शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी उसे मिले ।

हरिजनो की शिक्षा

(Education of Scheduled Caste)

अनुसूचित जातियों

गांधी जी को हरिजन अत्यन्त प्रिय थे। उनके उद्धान, सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक के लिये गांधी जी ने अग्रिम प्रयास किया। जातिगत के अन्तर्गत वर्गवाद भी इनका जिन्ना-दोष्ठा सामान्य स्तर तक नहीं आ सता है। जातिगत स्तर भी अन्तर्गत वर्गवाद है सामाजिक स्तर के लिये सामान्य स्तर की भावना पैदा हो रही है। जातिगत, जो वर्ग इतने वर्गों में पिछड़ा हुआ रहा है उसे सामान्य स्तर तक आन में निश्चय ही समझ लाया, लेकिन यदि समझ बढ़ प्रयास न किया जाय तो पूर्व के लिये वर्ग प्रयास भी बेकार चले जान हैं। स्पष्ट है कि हम इनके लिये विशेष प्रयास करने होंगे। अनुसूचित जाति के विकास के लिये निम्नलिखित कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन में विशेष बाधकों को निर्धारित करने तथा श्रियान्वयन के लिए अनुसंधानों की हैं।

देश में हरिजनों की जनसंख्या कुल आबादी का 15 प्रतिशत है, म० प्र० में इस वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की आबादी का 13.3 प्रतिशत है। पूरे देश की हरिजन जनसंख्या का 5 प्रतिशत म० प्र० में निवास करता है जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है। हरिजन बहुसंख्यक प्रदेशों में मध्य प्रदेश का स्थान उठता है। हरिजन बाहुल्य आबादी के क्रम में प्रदेश इस प्रकार हैं—उत्तर प्रदेश (हरिजन आबादी 185 लाख), पश्चिमी बंगाल (88 लाख) बिहार (79.50 लाख), तमिलनाडु (73.15 लाख), आंध्र प्रदेश (57.14 लाख) तथा म० प्र० (57.52 लाख)। देश एवं प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या को नजर अंश कर हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के 6-11 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का दर्ज संख्या प्रतिशत 79.9 है और 11-14 आयु वर्ग में यह प्रतिशत 26.5 है। 14-17 आयु वर्ग में तो लगभग 15 है। म० प्र० में अनुसूचित जाति के 6-11 आयु वर्ग के 65.2 प्रतिशत, 11-14 आयु वर्ग के 25.48 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग में 8.20 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ शाताओं में जा रहे हैं। स्पष्ट है कि इन वर्गों का एक बड़ा वर्ग शाताओं से बाहर है।

इन वर्गों की शिक्षा तथा आदिवासी शिक्षा की विशेष समस्याओं का देखते हुये म० प्र० में इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी का कार्य आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग को सौंपा गया है। वर्ष 1964-65 से यह विभाग इनकी शिक्षा की देख-रेख करता है। योजना यद्यपि शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण होती है लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा होता है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी अभी हम इन वर्गों की शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे हैं। इस वर्ग का बालिकाओं की शिक्षा और भी चिन्ताजनक है। अति एवं अवरोध की समस्या भी इन वर्गों में बहुत अधिक है।

अभी तक की शैक्षिक प्रगति—मध्य प्रदेश में 1971 की जनगणना के आधार पर 57 52 लाख जनसंख्या है जो 1980 में लगभग 71 लाख हो गई है। इनकी साक्षरता का प्रतिशत इस प्रकार है—

साक्षरता 1971 की स्थिति—(म० प्र०)

	सभी वर्ग	अनुसूचित जाति
पुरुष	32 76	22 15
महिला	10 84	3 88
योग	22 12	12 33

स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का वर्ग साक्षरता में काफी पीछे है।

दल संख्या और उसका प्रतिशत

मध्य प्रदेश

	अनुसूचित जाति	बालक	बालिका	योग
(अ) कक्षा I-V तक की दल संख्या (लाखों में)		3 98	1 30	5 28
(ब) 6-11 आयु वर्ग में प्रतिशत		82 00	29 40	58 00
(स) कक्षा VI-VII तक की दल संख्या (लाखों में)		0 85	0 16	1 01
(द) 11-14 आयु वर्ग में प्रतिशत		34 40	7 00	21 20
(य) कक्षा 9-11 में दर्ज संख्या		0 36	0 05	0 41
(र) 14-17 आयु वर्ग में प्रतिशत		13 88	2 15	8 20

हरिजना की शैक्षिक प्रगति प्रदेश में बहुत पिछड़ी है। आदिवासियों की शिक्षा तो और भी कम है। अखिल भारतीय स्तर पर इनकी शैक्षिक स्थिति इस प्रकार है—

जन सख्या प्रतिशत भारत

आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग
6-11 आयु वर्ग	89.3	43.4	66.4
11-14 " "	25.6	10.0	17.9

राष्ट्रीय स्तर 6-11 आयु वर्ग में शाला जा रह छात्रों का प्रतिशत 66.4 है। वहाँ प्रदेश में यह प्रतिशत 58 है किन्तु 11-14 आयु वर्ग में प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है।

अनुसूचित जाति की शिक्षा के अवरोधक कारण

इस जाति वर्ग की शिक्षा के प्रमुख अवरोधक कारण इस प्रकार हैं—

(1) गरीबी।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की बासका की इच्छा, आकर्षणों के अनुरूप न होना।

(3) शाला समय और अवकाश अनुकूल न होना।

(4) सामाजिक और व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान न रखा जाना।

(5) इन वर्गों के बच्चा में शाला त्याग की प्रवृत्ति अधिक है।

(6) इन वर्गों के बालक अनुपस्थित बहुत रहते हैं जिसका कारण है गरीबी, शालाएँ अनाकंपक होना आदि।

(7) शाला का टाइम टेबुल उनके अनुकूल नहीं है। वह बाँध रखते हैं जब कि बालक स्वच्छंद रहना चाहते हैं।

(8) परीक्षा में हम वह बातें पूछते हैं जो वह जानता ही नहीं है।

(9) अभी तक शालाएँ ऐसी जगह थी जहाँ वह मानसिक रूप से पढ़ने को तैयार नहीं हैं। जहाँ ये बालक रहते हैं वहाँ शाला ही नहीं है।

(10) समाज में यात्रा रुक्मिणी, शिक्षा के प्रति अरुचि।

(11) यह वर्ग जानता है कि जितने समय में बालक पढ़ेगा उतने समय में वह ज्यादा काम कर लेगा जिससे आर्थिक लाभ हो सकता है अतः अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं।

हरिजनों की शिक्षा के लिये स्विच्चे गये प्रयत्न

1—हरिजनों के लिये दृढ़ से आताएँ खोलना छात्रों से उन्हीं की वस्तु में ।

2—आयन आलापों की स्थापना कर विरल ज्ञानों के हरिजन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ।

3—बौद्धिककेतर शिक्षा केन्द्रों के द्वारा ज्ञानात्मिक या ज्ञान न आये हुये 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था की गई । इन केन्द्रों पर सुविधासुधार समय में ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं । इन केन्द्रों से यह वर्ग काफी लाभान्वित हुआ है ।

4—नए आलापों की स्थापना छोटे-छोटे ज्ञानों में की गई है जिससे इन वर्गों के बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

5—छात्रावासों की सुविधा प्रदान की गई ।

6—तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में भर्तियों के लिये आरक्षण की सुविधा ।

7—नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा ।

8—प्रोत्साहन कार्यक्रमों की व्यवस्था ।

(i) बुक बैंक योजना—वर्ष 1955 से हरिजन आदिवासियों के बच्चों को जो क्लास 3 से 11 तक अध्ययनरत हैं उन्हें निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जा रही हैं ।

(ii) बालिकाओं की गणवेश—इस वर्ग की बच्चियों को आलाप में आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित मदद दिये जाते हैं ।

(iii) मध्याह्न आहार कार्यक्रम—प्रदेश के उपयोजना क्षेत्र में आदिम आदिवासी विभाग द्वारा प्राथमिक आलाप में अध्ययनरत बच्चों का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित है । वर्ष 80-81 से शिक्षा विभाग द्वारा भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

(iv) छात्र वृत्तियाँ—सभी हरिजन छात्रों को मेट्रिक पूर्व एवं मेट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने की योजना द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है ।

9—बिहान की शिक्षा—आदिवासी क्षेत्रों में हरिजन, आदिवासियों के लिए विद्यालय की शिक्षा उसके प्रसार-प्रसार की कारणर व्यवस्था की गई है ।

10—मिलन दिवसों का आयोजन—शिक्षा में गुणात्मक विकास, शिक्षा में रुचि का विकास हा इसके लिए मिलन दिवसों का आयोजन किया जाता है ।

सप्ताह में एक दिन सभी हरिजन आदिवासी बच्चे मिलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।

11—मिलन मंडई—हरिजन आदिवासियों का यह प्रमुख शैक्षिक महोत्सव वर्ष 1979 से प्राग्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएँ अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक प्रतिभा का परिचय देते हैं।

12—छेलकूद परिसरों का विकास—हरिजन आदिवासी बालकों के लिए छेलकूद परिसरों का विकास किया गया है।

13—स्काउटिंग एवं गाइडिंग का प्रशिक्षण—आदिवासी एवं हरिजन बच्चों के लिए बालचर शिक्षा का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

14—पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार—गंदी बरितिया, हरिजनो, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की इच्छाओं, रुचियों के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा रहा है, इसके लिए यूनीसेफ के द्वारा संचालित प्रायोजना चल रही है। परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों में सुधार किया गया है और उनका लेख परीक्षण चल रहा है।

15—बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण—अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से नियम लिया गया है कि बालक-बालिकाओं का शालाओं में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय। स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी बीमारी का निदान, इलाज और सप्ताह दो जाती है।

छठी योजना की गृह रचना—छठी योजना में हरिजनो की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे। प्रयासों की रूप-रेखा इस प्रकार है—

1—हरिजन विशेषांश योजना का निर्माण—वर्ष 79-80 से ही हरिजन विशेषांश योजना का निर्माण किया जाने लगा है। यह योजना हरिजनों को सामाजिक करन वाली योजनाओं का आयोजन का तल है। हमारे सविधान में हरिजनो की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का सकल्प लिया गया है। हरिजन विशेषांश योजना में निम्नांकित चीजें निहित हैं।

- (i) अनुसूचित जातियों के विकास का कार्यक्रम परिवारमूलक होगा।
- (ii) सामाजिक होन वाले हरिजन परिवारों की सध्या।
- (iii) प्रत्येक कार्यक्रम चाह शैक्षिक हो, आर्थिक हो उसके क्रिया-व्ययन की समुचित व्यवस्था।
- (iv) योजनाओं में क्रियान्वयन तल का विकास।

(८) योजनाओं का मूल्यांकन ।

2—सम्य क्षेत्र

(i) मध्य प्रदेश में 45 राजस्व जिला में से 19 जिले ऐसे हैं जहाँ हरिजन जनसंख्या 15 प्रतिशत है वह जिले सम्य जिले होंगे ।

(ii) तहसीला में से 42 तहसीले ऐसी हैं जिनमें हरिजन जनसंख्या 20% से अधिक है, इन्हें पहले लिया जायगा ।

(iii) प्रदेश में 459 विकास खण्डों में से 26 जिला में स्थित 89 विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें हरिजन जनसंख्या 20% से अधिक है । उन पटवारी हल्का की संख्या 69 है जिनमें हरिजन जनसंख्या 50% से अधिक है ।

(iv) ग्राम स्तर पर हरिजन बाहुल्य बस्तियाँ या बस्ती समूह हैं जिसकी आशादा ग्राम की जनसंख्या की आधी है, ऐसे 472 बस्ती समूह हैं जिनमें 2400 गाव सम्मिलित हैं । ग्राम स्तर पर इन्हें सम्य क्षेत्र बनाया जायगा ।

3—शालाओं की स्थापना—सम्य यह होगा कि प्राथमिक शाखाएँ हरिजन बस्ती या उसके बिल्कुल निकट स्थापित की जायेंगी जिससे उनके बच्चों को कोई शिक्षक या कठिनाई न हो ।

(4) आश्रम शालाओं की स्थापना

(5) छात्रावासों का विशेष प्रबंध व उनमें वृद्धि

(6) छात्र वृत्तियों का प्रदाय

(7) बुक बैंक योजना

(8) शुल्क भागी

(9) सेवाओं में आरक्षण

(10) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार

(11) विकास के लिए तीन स्वरूप होंगे

(i) प्रोत्साहन

(ii) संरक्षण

(iii) आर्थिक उद्यान ।

(12) हरिजन विकास की योजनाओं के क्रिया वन हेतु अमले का विस्तार

(13) भौतिक सुविधाओं का विकास

(14) गुणात्मक विकास के प्रयास

(15) विज्ञान शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रसार

शिला में नए आयाम एय नशापार

(16) औपचारिकतर शिक्षा केन्द्रों का निर्माण

(17) हरिजन कल्याण के लिए शाघ और उससे प्राप्त निष्कर्षों पर
तया-वचन ।

मध्य प्रदेश में शालय शिक्षा के लिए छठी योजना में 74 करोड़ की आयो-
ता राशि निर्धारित की गई है जिसमें से 14% के हिसाब से लगभग 11 करोड़
राशि हरिजनों के शैक्षिक विकास पर व्यय की जानी प्रस्तावित है । यदि
७०। योजना की व्यूह रचना को अच्छी प्रकार तथा बिना किसी व्यवधान के
पूरा किया गया तो अवश्य ही अच्छे परिणाम सामने आ सकेंगे । यद्यपि हमें
लक्ष्य पूरे करने के लिए एक विशाल राशि तथा योजना तल की आवश्यकता
होगी फिर भी सीमित साधनों में अधिक से अधिक विकास करने का हमारा
सक्षय होगा ।

●

प्रौढ शिक्षा

(Adult Education)

हमने शिक्षा की सकुचित धारणा अपना रखी है। जो स्कूल नहीं गया जिसे पढ़ना-लिखना नहीं आता है उसे हमने निरक्षर मान लिया है। यदि हम जीवन भी सही शिक्षा मिला है, हम सब काम सहीके से कर लेते हैं सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम, स्नेह, दया, भाव भी है, अपने धर्म का सही ज्ञान है तो भी हमें साक्षर या पढ़ा-लिखा नहीं समझा जाता है। इसके विपरीत हम स्कूलों, कॉलेजों में पढ़कर गैरारूपन करते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं ताड़-फाड़ करते हैं, धधे का कोई ज्ञान नहीं, तब भी हम साक्षर हैं और पढ़-लिखा म गिनती है। इसका परिणाम यह हो रहा है जो सामन हैं, विशेष एवं गहन प्रयासों के बावजूद भी निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि "लिखने-पढ़ने तथा गणित का शुष्क ज्ञान एक ग्रामीण के जीवन का स्थायी अंग नहीं बन सकता है। उनको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो वह अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग कर सके। यह ज्ञान उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए, उनको इसकी भूख हानी चाहिए। एक ग्रामीण को ग्रामीण गणित, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण इतिहास तथा ऐसा ज्ञान दे जो वह प्रतिदिन प्रयोग कर सके।" "गांधी जी के विचारों का वस्तुतः सही ज्ञान नहीं पहचाना जा सका और हम भटकते ही रहे।

भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार "यद्यपि माध्म्यता का प्रतिशत सन् 1951 में 16% से बढ़कर 1961 में 24% और सन् 1966 में 28.6% हो गया है ता भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में दशकों और पीछे धकेल दिया है। इससे जा शिक्षा मिलती है वह स्पष्ट है कि सारक्षरता द्रुत गति से बढ़ाने के लिए परम्परागत तरीके समझग व्यय है। यदि इस प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो अभिनव राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है।"

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो बी० के० आर० बी० राव के मतानुसार "प्रौढ शिक्षा और प्रौढ साक्षरता के बिना न तो उस विस्तार और गति में आर्थिक और

सामाजिक विकास संभव है जिसकी हम आवश्यकता है और न हो हमारे आर्थिक सामाजिक विकास को बड़े तत्त्व गुणात्मक शक्ति मिल सकती है जो मूल्य और हितधारिता को दृष्टि से उसे साधक बनाए। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक विकास के किन्हीं कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता का प्रथम स्थान मिलना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा क्या है?—प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ निरक्षर प्रौढ़ स्त्रियाँ और पुरुषों को लिखना-पढ़ना और मकगणित सिखाना है। लेकिन यह सकीण परिभाषा उचित नहीं कहो जा सकती है। केन्द्रीय शिक्षा समारोहकार बोर्ड के अनुसार “प्रौढ़ शिक्षा वेदस व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही अपने को सीमित न रखे बरन उसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित की जावे जिसमें प्रत्येक नागरिक जन तत्वीय सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने को तैयार रहे।”

शिक्षा आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि “यह वह शिक्षा है जिससे द्वारा लोगो में नागरिकता की चेतना उत्पन्न हो और उनमें सामाजिक मुसगठन की भावना की वृद्धि की जाती है। यह शिक्षा बड़ी आयु के लोगों का केवल अक्षर ज्ञान ही कर गतुष्ट नहीं हो जाती। इसका लक्ष्य सामाजिक जनता में एक सुनिश्चित मन का निर्माण करना है। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में समाज शिक्षा लक्ष्य यह रहता है कि लोगो में व्यक्तिगत रूप से और समाज के एक सदस्य के तौर पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट भावना उत्पन्न की जाय। आगे शिक्षा आयोग ने लिखा है “केवल पढ़ लिख लेने की योग्यता प्राप्त कर लेने का हम साक्षरता नहीं मानते। साक्षरता तभी साधक होती है जब वह कार्यक्रम हो—न्यायधारित हो।”

प्रौढ़ शिक्षा का नया स्वरूप—प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना में व्यापक परिवर्तन आया है। अब यह लिखने-पढ़ने और हिसाब-किताब जानने में योग्यता हासिल कर लेने की परम्परागत साक्षरता तक सीमित नहीं है। दश के सामाजिक, आर्थिक दृश्य पट में जो परिवर्तन आ रहा है उसका कारण मानवीय साधना के सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार—“प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत जितना कि स्वयं जीवन है। इसी आवश्यकताएँ सामाजिक स्तरीय पड़ाव से भिन्न हैं।” इसलिए समाज और व्यक्ति की इन नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को तब किया गया है। औपचारिकतर शिक्षा के नए दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे नैतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है जो सी.ए.टी.ए. पर समुदाय और व्यक्ति की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा स्थानीय वातावरण एवं राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध हो। यद्यपि

ऐसी शिक्षा सुविधाएँ सभी वर्ग के सोखने वाला को दी जानी हैं लेकिन यह सोचा गया है कि "सुविधाएँ मुख्यतः 15-25 के महत्वपूर्ण आयु समूह के युवाओं को दी जायगी। इसके लिए एक प्रौढ शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका कार्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना और सरकार को सलाह देना है।

अंतराष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "नवीन सञ्चार के लिए नवीन व्यक्ति चाहिए"। प्रौढ शिक्षा वास्तव में शैक्षिक प्रक्रिया का स्वाभाविक उच्चतम विकास है। समाज में सभी के विकास के लिए प्रौढ शिक्षा का स्वरूप विभिन्न होता है। यह केवल साक्षरता प्रदान करने या थोड़ा बहुत सांस्कृतिक सामाजिक ज्ञान देने के रूप में नहीं रहता है। यह तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सुरक्षा, सामाजिक समानता, एवं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हम बटिबद्ध हैं। परन्तु महा के अधिकांश व्यक्ति स्कूल गए ही नहीं अतः भारत जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी सुविधाओं के अनुसार दश विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्रौढ शिक्षा व्यवस्थित की जानी चाहिए।

हम हठिवादी, परम्परागत साक्षरता के स्थान पर क्रियात्मक साक्षरता की देश में आवश्यकता है। ऐसी क्रियात्मक साक्षरता जिससे मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक रूप से समाज में अपना उचित स्थान पाने योग्य बन सके। अर्थात् ऐसी साक्षरता हो जो मनुष्य के मन का शिक्षित कर सके। इस प्रकार की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए जायें।

- (i) उपचारात्मक शिक्षा
- (ii) व्यावसायिक शिक्षा
- (iii) स्वास्थ्य शिक्षा
- (iv) मनोरंजन की शिक्षा
- (v) सांस्कृतिक शिक्षा
- (vi) सामाजिक संगठन की उत्पत्ति के लिए शिक्षा
- (vii) राष्ट्रीय साधना के रक्षण और सुधार के लिए शिक्षा
- (viii) सामाजिक आदर्शों की प्रेरणा के लिए शिक्षा
- (ix) सहयोगी वर्ग और संस्थाओं के निर्माण के लिए शिक्षा

इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं, इच्छाओं से जुड़ सकेगी।

प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता—प्रौढ़ शिक्षा की नई अवधारणा में 15-25 आयु वर्ग के लोगों को त्रियात्मक सागरता को सिया गया है। 80% में अधिक हमारी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें अधिकांश भाग उन लोगों का है जो आदिवासी और वृषक हैं। वे सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। किसी समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा उसके सदस्यों को समानता का अवसर प्रदान करने हेतु शिक्षा आधारभूत साधन है। आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का कार्यक्रम एवं कार्य विस्तृत है। यह किसी व्यक्ति के संस्कार ग्रहण में उस सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक अंग है जो कि उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसका उद्देश्य व्यक्तियों के चरित्र निर्माण, अभिवृद्धि, कुशलता तथा नैतिक गुणों का विकास है जिसकी विधिवत शिक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा स्वयं एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया से प्राप्ति होती है। ग्रामीण वृषक भूमि, आवास, तथा सजीव वस्तुओं के विषय में पर्याप्त बुद्धिमत्ता के साथ वृषि कार्य की कुशलता एवं कला सीख लेते हैं। अतः इनकी शिक्षा परम्परागत न होकर ऐसे औपचारिकतर शिक्षा से जाय जो उन्हें उत्तम व्यवहार बनाने में सहायक हो। चूंकि हमारा देश इन्हीं उत्तम नागरिकों का कुशलता पर आधारित है अतः इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक प्रौढ़ एवं माता पिता शिक्षित नहीं होते तब प्रेरणा का भाव जागृत नहीं होता अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन और समाज की पुनर्रचना जैसे कोई कार्य अथवा शैक्षिक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। प्रौढ़ शिक्षा की सही मापने में आवश्यकता देश के विकास हेतु निम्नलिखित पहलुओं के लिए आवश्यक है।

- (i) व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु।
- (ii) प्रजातन्त्र की सफलता हेतु।
- (iii) आर्थिक विकास हेतु।
- (iv) राष्ट्रीय एकता हेतु।
- (v) नागरिकता की मजबूती हेतु।
- (vi) नवीन ज्ञान और कौशल सीखने के लिए।
- (vii) स्वस्थ मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य

प्रौढ़ों की शिक्षा का उद्देश्य निम्नानुसार हो सकता है।

1—शालाओं में अल्पतम युवाओं को बुनियादी ज्ञान एवं परीक्षा-लिखने का कौशल प्राप्त करने हेतु प्रेरणा देना तथा उनमें त्रियात्मिक अवगणित विकास करना।

2—उनके अंदर कृषि सम्बन्धी कुशलताएँ एवं कृषिएतर कौशल का जिनमे विभिन्न शिल्पो का भी समावेश हो, विकास करना ।

3—स्वस्थ जीवन, परिवार-कल्याण, खाद्य-पदार्थों की सुरक्षा, सहायी समितिमा, कल्याणकारी क्रियाया एवं नागरिकता के विषय में ज्ञान देना ।

4—उनमे समुचित अभिवृद्धि तथा शैक्षिक एवं नवाचार प्रवृत्तिया सहित अन्य समुचित विभिन्न विकासात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना ।

हिंदुस्तानी तालिमी सच ने प्रौढ शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं—

1—प्रौढ शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रौढों की साक्षरता नहीं अपितु प्रौढों की जीवन पर्यंत शिक्षा है जो उन्हें अनेक सर्वांगीण विकास में सहायता दे ।

2—यह शिक्षा जीवन पर्यन्त और प्रत्येक स्तर के लिए उपयोगी होनी चाहिए ।

3—जिस प्रकार के भी शिल्प का चयन किया जाय वह दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो, शिक्षा का माध्यम बन सके और पर्याप्त प्रवीणता के साथ जीवन से सम्बन्धित विषयों पर सिखाया जा सके ।

4—सामान्य ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचि तथा उनके सामाजिक एवं नागरिक वातावरण के अनुकूल हो । अतः इस प्रकार के विषय अपनाए जाय जिनसे उनमें वैयक्तिक तथा घर एवं गाँव की सफाई का ध्यान सदैव बना रहे, भाई बारे की भावना का विकास हो, वे मानव अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित नियम और परम्पराओं का ज्ञान विकसित हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्राथमिक नियम, पारिवारिक लेखा जोखा और माता-पिता के कृतव्य आदि विषयों से पूरी जानकारी प्राप्त हो ।

5—उत्तम जीवन हेतु प्रौढ शिक्षा मेला, स्थोहारों और सांस्कृतिक समारोहों से सम्बन्धित हो ।

6—गाव का स्कूल प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है । अतः प्रौढ शिक्षा का सम्बन्ध गाव के स्कूल से होना चाहिए । इससे एक ओर वो प्रौढ प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता को समझेंगे, दूसरी ओर बालक भी प्रौढ शिक्षा की प्रभावात्मकता की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वयं जीवन में उस दोष से बचेंगे ।

समाज शिक्षा या प्रौढ शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांट सकते हैं—

(1) व्यक्तिगत दृष्टि से ।

(ii) सामाजिक दृष्टि से ।

प्रौढ शिक्षा का आरम्भ बाल्यकाल में उत्पन्न समी को दूर करना है। जो वास्तव नहीं सीख पाया उसे बाद के वर्षों में सीखता है जिससे उसकी बहुत सी युग सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक जीवन के प्रति उसका ज्ञान बढ़े।

शिक्षा शास्त्री प्रो० एस० एन० मुकर्जी ने प्रौढ शिक्षा या समाज शिक्षा के के तीन उद्देश्य बताए हैं।

- (i) साक्षरता का विकास करके स्वस्थ मन का निर्माण करना।
- (ii) आर्थिक स्तर को ऊपर उठान के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- (iii) वर्तमान और अधिकार के प्रति जागरूक रखने के लिए नागरिकता की भावना विकसित करना।

प्रौढ शिक्षा की उपलब्धियाँ—दश में 1971 तक प्रौढ शिक्षा की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं—

(संख्या लाखों में)

आयुवर्ग	1961 की जनगणना		1971 की जनगणना	
	साक्षरों की संख्या/प्रति०	निरक्षरों की संख्या/प्रति०	साक्षरों की संख्या/प्रति०	निरक्षरों की संख्या/प्रति०
1	2	3	4	5
5-14	336 6 (29 5)	803 2 (70 5)	523 3 (34 9)	973 6 (65 1)
15-24	263 3 (36 0)	468 8 (64 0)	430 1 (47 5)	475 9 (52 5)
25-34	192 3 (28 5)	481 9 (71 5)	260 0 (33 9)	506 1 (66 1)
35 और उससे ऊपर	262 7 (22 3)	917 7 (77 7)	366 2 (24 7)	1126 7 (75 5)

(कोष्ठक में दिये आंकड़े सम्बंधित आयुवर्गों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बताते हैं)

उपरोक्त तालिका से इतना वा स्पष्ट है कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है किन्तु दूसरा पहलू भी है कि निरक्षरों की संख्या हर वर्ग में बढ़ी है।

5-14 आयु वर्ग में 1961 से 1971 में निरक्षरता की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई है, 15-24 आयु वर्ग में निरक्षरता की संख्या में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है, 25-34 आयु वर्ग में ढाई गुनी और 35 से ऊपर के आयु वर्ग लगभग चार गुनी निरक्षर हो गये हैं। ये आँकड़े हमारे लिये चुनौती भरे हैं।

प्रौढ शिक्षा का क्षेत्र—प्रौढ शिक्षा का क्षेत्र असीमित है। यह एक जीवन पथन शिक्षा है। प्रौढ शिक्षा में अनेक पक्ष सम्मिलित हैं यथा व्यावसायिक, सामाजिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि।

भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित बातों के समावेश की बात कही है—

- (i) निरक्षरता का निभूला।
- (ii) निरक्षर शिक्षा।
- (iii) पत्राचार पाठ्यक्रम।
- (iv) पुस्तकालय।
- (v) प्रौढ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान।
- (vi) प्रौढ शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन।

अतः प्रौढ शिक्षा निम्नतर शिक्षा के आधार पर होना चाहिये जो विविध रूपों से विभिन्न वर्गों के लिये उपयुक्त हो। पहला वर्ग उन लोगों का है जो शैक्षिक संस्थाओं में या अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित तथ्य शिक्षा की योजनाओं में अंगवर्तित अभ्यसनों के लिये दूसरों के साथ मिलकर समूह बनाते हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपने घर पर उच्च समय पढ़ना है जो उन्हें इस उद्देश्य से मिल सके अती मुश्किल अनुसार सहायता चाहते हैं। प्रौढ शिक्षा ऐसी हानी चाहिये जो विविध उद्देश्य पूरा करे।

प्रसिद्ध शिक्षा नारसी प्रो० कबीर ने प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिखा है कि समाज शिक्षा पद्धतियों कार्यक्रम में निहित है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं का यथा सम्भव अधिकतम रूप से पूरा करना है, इन कार्यक्रम में पाँच बातें हैं—

- (i) साक्षरता।
- (ii) स्वास्थ्य नियमों का ज्ञान।
- (iii) व्यक्तियों के आर्थिक स्तर को उत्तम बनाया जा सके।
- (iv) अपना व्यवसाय और अतिरिक्त के अति पूरक के साथ प्रयत्न की शिक्षा।

श्रीष्ठ शिक्षा का आरम्भ बाल्यकास में उत्पन्न कमी को दूर करना है। जो बालक नहीं सीख पाया उसे बाद के वर्षों में सीखता है जिससे उसकी बहुत सी युग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वार्षिक विकास और सांस्कृतिक जीवन के प्रति उसका पान बढे।

शिक्षा शास्त्री प्रो० एस० एन० मुखर्जी ने श्रीष्ठ शिक्षा या समाज शिक्षा के के तीन उद्देश्य बताए हैं।

- (i) साक्षरता का विकास करके स्वस्थ मन का निर्माण करना।
- (ii) वार्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- (iii) कृतव्य और अधिकार के प्रति जागरूक रखने के लिए नागरिकता की प्राप्ति विकसित करना।

श्रीष्ठ शिक्षा की उपलब्धिया—देश में 1971 तक श्रीष्ठ शिक्षा की उपलब्धिया निम्नानुसार हैं—

आयुवर्ग	1961 की जनगणना		(सख्या लाखों में)	
	साक्षरों की सख्या/प्रति०	निरक्षरों की सख्या/प्रति०	1971 की जनगणना साक्षरों की सख्या/प्रति०	निरक्षरों की सख्या/प्रति०
1	2	3	4	5
5-14	336 6 (29 5)	803 2 (70 5)	523 3 (34 9)	973 6 (65 1)
15-24	263 3 (36 0)	468 8 (64 0)	430 1 (47 5)	475 9 (52 5)
25-34	192 3 (28 5)	481 9 (71 5)	260 0 (33 9)	506 1 (66 1)
35 और उससे ऊपर	262 7 (22 3)	917 7 (77 7)	366 2 (24 5)	1126 7 (75 5)

(नोट: क में दिये आँकड़े सम्बन्धित आयुवर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बताते हैं)

उपर्युक्त तालिका से इतना सा स्पष्ट है कि साक्षरता, का प्रतिशत बढ़ा है किन्तु दूसरा पहलू भी है कि निरक्षरों का सख्या हर वग में बढ़ी है।

- (ii) महिला मण्डल की स्थापना ।
- (iii) राहवो पारम की स्थापना ।
- (iv) मास्ट्रिन कार्यक्रम का आयोजन ।
- (v) विकास मंत्र का आयोजन ।
- (vi) विचार समूह का गठन ।

- 5 शालाभा में समुदाय का त्रिआत्मक सहयोग प्राप्त करना ।
- 6 शिक्षकों अधिकांश, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क ।
- 7 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ।
- 8 दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग ।
- 9 प्रशासन एवं दृष्ट-रक्षक नियम कुशल संगठन ।
- 10 प्रौढ निरक्षरों का मनावैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण करना ।
- 11 साक्षरता कार्यक्रम में निरन्तरता बनाय रखना ।

श्री ३ शिक्षा हेतु किये गये प्रयास

- 1 राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बाड का गठन ।
- 2 निम्नलिखित कार्यक्रम हाथ में लिये गये —
 - (i) कृषकों का व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम ।
 - (ii) 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम ।
 - (iii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम ।
- 3 1975-76 में 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकतर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इसका उद्देश्य 15-25 आयु वर्ग के युवाओं को ऐसी अल्पकाल शिक्षा देना है जो उनका आजीवन लाभ और आर्थिक विकास के अन्तर्गत तत्काल स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित है । यह यह है कि इस आयु वर्ग के युवाओं में प्रारम्भ में साक्षरता साधना का प्रयास किया जाय । यह कार्यक्रम 1. 7. 76 में 50 व 110 शिक्षा केंद्रों में प्रारम्भ किया गया । 1977-78 में 50 और 25 केंद्रों में ।

शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार
स्वस्थ रूपा का व्यवस्था करना ।

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा एक व्यापक जीवन की शिक्षा है और निरन्तर चलन वाली प्रक्रिया है । इसका क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता है । क्रियात्मक साक्षरता ही इसका सच्चा स्वल्प और विषय क्षेत्र है । प्रौढ़ शिक्षा में क्रियात्मक साक्षरता हेतु सुमात्र

प्रौढ़ शिक्षा की विधियाँ सामान्यतः कई हो सकती हैं । इन्हें माटे रूप में तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) अभ्यास प्रधान विधियाँ ।

(ii) छात्र प्रधान विधियाँ ।

(iii) सहयोगात्मक विधियाँ एवं सामूहिक विधियाँ ।

किन्तु जैसा कहा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ अब व्यापक रूप में लिया गया है । अतः इस प्रकार का शिक्षा के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम हाँ—

1 सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सर्वेक्षण ।

2 ऐसी कक्षाओं की व्यवस्था जिनमें व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम हो इसमें क्रियाशाल वृत्ति सम्बन्धी ज्ञान एवं विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों का ज्ञान सम्मिलित किया जाय । इस कक्षा के माध्यम से स्थानांतरण शिल्प का मौखिक तथा अमौखिक पद्धति से शिक्षण दिया जा सकता है ।

3 वैश्विक सामग्री का विकास ।

(i) क्रियात्मक साक्षरता में शामिल होने वाले सदस्यों के लिये ।

(ii) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सम्बन्धित पठन तथा प्रदर्शन सामग्री ।

(iii) अभ्यास पुस्तकें ।

(iv) शिक्षकों हेतु मार्ग दिशिका ।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक क्रियाओं का आयोजन ।

(i) युवक मण्डल की स्थापना ।

- (ii) महिला मण्डल की स्थापना ।
 - (iii) राईयो फोरम की स्थापना ।
 - (iv) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ।
 - (v) विकास मेला का आयोजन ।
 - (vi) विचार समूहों का गठन ।
- 5 शालाभा में समुदाय का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करना ।
 - 6 शिक्षका अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पंचायतों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क ।
 - 7 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ।
 - 8 दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग ।
 - 9 प्रशासन एवं दल-रेखा के लिये कुशल संगठन ।
 - 10 प्रौढ निरीक्षकों का मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देना ।
 - 11 साक्षरता कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखना ।

प्रौढ शिक्षा हेतु किये गये प्रयास

- 1 राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड का गठन ।
- 2 निम्नलिखित कार्यक्रम हाथ में लिये गए —
 - (i) बचपन का व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम ।
 - (ii) 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम ।
 - (iii) शहरी श्रमिकों के लिये औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम ।
- 3 1975-76 से 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकतर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इसका उद्देश्य 15-25 आयु वर्ग के युवाओं का ऐसी अपूर्ण शिक्षा देना है जो उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप तथा स्थानीय परिस्थितियों से सम्बद्ध हो । सत्य यह है कि इस आयु वर्ग के सर्वदलशोभ युवाओं में मानवीय साधना का विकास किया जाय । यह कार्यक्रम 1975-76 में देश के 110 जिलों में प्रारम्भ किया गया । 1977-78 में 50 और केन्द्र चले गये ।

शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार

- 4 1975-76 से ही औद्योगिक श्रमिकों के काम शैक्षणिक स्तर और उत्पादकता का बढ़ाने में मदद देने के उद्देश्य से गहरी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जारी रखे गये।
- 5 इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों का वित्तीय सहाय्य दी गई। 150 से अधिक संगठन प्रौढ़ शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं।
- 6 यूनीसफ की सहायता प्राप्त प्रायोजना द्वारा विद्यार्थियों को सागरता हेतु योजना का क्रिया चयन।

पर्यावरणीय शिक्षा

(Environmental Education)

हमारी सोवप्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुसार—“दा तरह का शिक्षा होती है—एक ता पढ़न-लिखन की शिक्षा, स्कूल में जब बच्चा जाता है ता आप उसका पढ़ाने है। यह शिक्षा दिन के खास समय प्रारम्भ होती है और जब बच्चा घर जाता है तो एक खास समय में यह समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी शिक्षा भी है और वह है जिस समय बालक जन्म लेता है सभी से शुरू होती है और जब वह बड़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है तब तक वह कुछ सीखता जाता है। ऐसी शिक्षा का ही हमें दक्ष में प्रचार करना है। व्यक्ति चाहे जितना भा छाटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी घर का, चाहे शहर का हो या देहात का, एक ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करने की प्यास सबके अन्दर आ जाये। यह हमारे अध्यापकगण का सबसे बड़ा फलस्फ है, यह बीज, यह प्यास, हमारे बच्चों के दिलों में बँट डालें।”

प्रधान मंत्री जी के उपयुक्त विचार हमारे लिये चुनौती हैं। हमने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। अभी तक हमारी शिक्षा जीवनोपयोगी नहीं बन सकी क्योंकि जनजीवन, वातावरण से दूर थी। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप शिक्षा योजना में समाविष्ट होना ही चाहिये। पर्यावरण पर आधारित शिक्षा ही बालकों के लिये हितकर एवं रुचिपूर्ण होगी। पर्यावरण की शिक्षा ही सही शिक्षा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- (1) हमारे के विभिन्न क्षेत्रों के देशों में पर्यावरण शिक्षा पर विचारों, समाचारों, एवं अनुभवों को बढ़ावा देना।
- (2) पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य विषय वस्तु और प्रविधिमा पर समन्वित अनुसंधान के विकास को प्रोत्साहित करना।
- (3) पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रविधियों, पाठ्यग्रन्थों, अध्यापनीय सामग्री व कार्यक्रमों की योजना करना।

(4) पर्यावरण शिक्षा के विनाश हेतु आवश्यक कमचारी वर्ग, शिक्षक, प्राध्यापक, याजना तैयार करने वाले, शोध कार्यकर्ता, व शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण व स्तरोन्नयन ।

(5) पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों में सभी देशों को तकनीकी सहायता व सेवाएँ उपलब्ध कराना ।

शैक्षिक व्यवसाय के संगठनों के अखिल विश्व संघ (W C O T P) में शैक्षिक संगठनों के अखिल भारतीय संघ को एक पायलट-प्रायोजना सौंपा । यह प्रायोजना म० प्र० शासन शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रारम्भ की गई । म० प्र० शासन ने हमेशा ही नवीन चुनौतियाँ और नवाचारों के प्रति अपनी अनुकूलता दिखाई है । म० प्र० मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों का राज्य है और पर्यावरण शिक्षा की प्रायोजना उसे जीवन से जोड़ देगी । ग्रामीण शालाओं और शाला के बाहर के लिये अधिक उपयोगी शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण मुख्य कार्य होगा । पाठ्यक्रम कृषि वातावरण पर आधारित होगा । अब ग्रामीण विकास के लिये शिक्षा, समुचित सामाजिक व आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान देगी । शिक्षा का हमारा उद्देश्य नवीन नौकरियों की व्यवस्था, खेतिहर भूमि का पूरा वितरण, स्वास्थ्य सुधार, उत्तम भोजन की वृद्धि, व्यक्तियों के लिये भ्रमण, तथा शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की सम्भावनाओं की प्राप्ति होना चाहिये ।

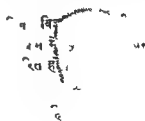
म० प्र० में पर्यावरण शिक्षा के तात्कालिक कार्य

(1) म० प्र० के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा के विषयों को शामिल किया जायँ जो रा० टी० अनु० प्रशि० परिषद के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में हैं ।

(2) कक्षा 1 व 2 के लिये विषय की भाँति पढ़ाने के लिये म० प्र० का पाठ्यक्रम पर

(3) किसी भी नवाचार की योजना का चयन कर लिया जायँ

(4) छात्रों को प्रेरित करने के लिये



- (5) अधिक से अधिक शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा के तत्वों का समझना चाहिये।
- (6) शाला और समाज का उत्पादक सम्बन्धों में एकीकृत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरे शब्दों में अपने बच्चा व प्रौढ़ों को पर्यावरण के मामले में शिक्षा देना, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति उन्हें जागरूक करना, सामाजिक उपयोगी अभिवृत्तियों की उत्पत्ति तथा समस्याओं का हल खोजने की क्षमताओं का विकास करना है। इसमें समाज का भाग लेना व सहयोग आवश्यक है। अतः हमें समाज पर आधारित पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है।
- (7) अध्यापक व समाज के नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पर्यावरण की ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाय।
- (8) स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वातावरण पर आधारित वैश्व सामग्री तैयार करना।
- (9) शाला के बाहर औपचारिकताओं की आवश्यकता है और शाला कुटुम्ब व समाज के बीच की दूरी को भरा जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश की पाइलट प्रायोजना के उद्देश्य

- (1) यह योजना भारत व एशिया के अन्य देशों के लिये आदर्श व प्रेरणा प्रस्तुत करेगी जिससे वे इसी प्रकार का प्रायोजना का स्वीकार कर सकें।
- (2) यह एक ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करेगी जो कि कृषि पर्यावरण पर आधारित होगा।
- (3) यह प्राथमिक शाला पाठ्यक्रम में एकीकृत दृष्टिकोण का उद्घोष करेगी जिसका कि आधुनिकीकरण व पुनरोत्थान होगा।
- (4) अध्यापकों को वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने व उसे कृषि पर्यावरण पर आधारित करने की आवश्यकता महसूस करने में सहायता दी जायगी।
- (5) विभिन्न स्थानों की पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों में अंतर रहता है अतः शिक्षक कृषि पर्यावरण पाठ्यक्रम पर आधारित पाठों का स्वयं तैयार करेंगे। यह ग्रामीण आवश्यकताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप होगा।

- (6) शिक्षक पर आधारित ग्रह रचना का विकास करना जिससे जनता में जागरूकता बढ़े और पर्यावरण शिक्षा के बारे में जनता की अभिवृत्ति में परिवर्तन होना में सहायता मिल सक।
- (7) अध्यापकों की शिक्षा शास्त्रियों और अन्य लोगों को पाठ्यक्रम निर्माण कार्य में सम्मिलित करना जिससे पाठ्यक्रम सभी को स्वीकार्य हो।
- (8) अन्य देशों के ऐसे विशेषज्ञों से चर्चा करना जो अपने देश में इस प्रकार के कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं।
- (9) विभिन्न क्षेत्रों में तैयार किये गये पाठों पर चर्चा एवं उनका क्षेत्र परीक्षण।

पर्यावरण शिक्षा पर परामर्शदायी समिति—1978 में, म० प्र० के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पर्यावरण शिक्षा पर एक परामर्शदायी समिति का निर्माण हुआ जिसके सदस्यों के रूप में लोक शिक्षण सचिव, तथा ग्रामीण विकास व पर्यावरण विज्ञान के अनेक विशेषज्ञ नियुक्त हुए। इस समिति ने प्रदेश के 4 जिलों हनुमानगढ़, जयपुर, जालंधर, और दिसा की 16 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाइलट योजना प्रारम्भ करने की अनुमति दी।

पर्यावरणीय शिक्षा क्या है ?—हमारे पर्यावरण के तीन अंग हैं—पृथ्वी, हवा और जल। इन तीनों के विषय में ज्ञान और मूल्यों का विकास करना ही पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य विश्व जनसंख्या का पर्यावरण और उससे सम्बन्धित समस्याओं की ओर ध्यान दिखाना है तथा मनुष्यों में ऐसा ज्ञान, कुशलता, अभिवृत्ति, प्रोत्साहन पैदा करना है कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से वर्तमान समस्याओं का हल निकाल सके तथा कई समस्याओं को पैदा न होने दें। अब पर्यावरण शिक्षा केवल प्रदूषण रोकने, प्रकृति व अस्तित्व को रक्षित, जल प्रदूषण, हवा और भोजन का प्रदूषण रोकने से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसके अलावा भी अधिक कुछ है।

पर्यावरण को सीखने के स्रोत के रूप में प्रयोग करना कोई नया विचार नहीं है। मनुष्य हमेशा ही प्रकृति से सीखता आया है। उसने अपनी आवश्यकताओं, जीवन की परिस्थितियों के आधार पर अपने अस्तित्व का बनाए रखने की कुशलताओं और अभिवृत्तियों का विकास किया है।

पर्यावरणीय शिक्षा के तीन अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं।

1. पर्यावरण द्वारा सीखना—यह कुशलताएँ विकसित करने हैं पर्यावरण का उपयोग है। यह प्राथमिक विद्यालय से सम्बद्ध है।

2 पर्यावरण के विषय में साक्ष्यता—पर्यावरण का ज बिना तथा अजीबान वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना ।

3 पर्यावरण के लिए संरक्षण—पर्यावरण का जानना, इन सुरक्षित रखना ।

पर्यावरण शिक्षा द्वारा मु य रूप से तब करा, पूछन, जानन का कता का विकास होता है । यह शिक्षा मानव का अपना पारा ओर के वातावरण, संसार का वस्तुओं के पार में एकत्रीकरण, वर्गीकरण प्रयोग और उससे निष्पन्न निरालन का प्रवृत्ति करता है । पर्यावरण का कोई भी पहलू अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त है । पर्यावरण शिक्षा में भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों परिवेश निहित है । अभी तक गैदातित्व रूप से दस मायना धी, धन वास्तविक और विचारमय स्वरूप प्रदान किया जा रहा है ।

पर्यावरण का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है । पर्यावरण के अन्तर्गत हमारे पारा पार का वस्तुएं, क्षेत्र और परिस्थितियाँ सामिल हैं । यह शिक्षा एक ऐसा समय साधन है जिसके द्वारा मानव में गद्य कुलनाशा एव क्षमताओं का विकास किया जाता है जिसके माध्यम से वह प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक परिवेशा पारस्परिक सम्बन्धों का स्पष्ट कल्पना करत हुए उनकी मानव जीवन में विकास में उपयोगिता समझन हेतु सामर्थमान बनाता है । इन तीन परियशों के उपयोग के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । यही कारण है कि पर्यावरणीय शिक्षा हमारी शिक्षा का अनिवार्य अंग है । प्राथमिक स्तर के बालक के परिवेशा पर्यावरण से आरम्भ करके उससे निकटतम भौगोलिक पर्यावरण से ही नहीं है बरना जिन घटनाओं, समस्याओं और आविष्कारों से उस प्रेरितिया करनी होती है वह सभी उसके परिवेश में है । उसका घर, उसका परिवार, उसकी शाला, उसका पड़ोस, गाँव और आस-पास के नदी-नाल, पहाड़ पहाड़ियाँ, जंगल वनस्पतियाँ, एव जीव जंतु सो उसके परिवेश में हैं । वह पृथ्वी और आकाश में भी रुचि लेता है । इतना ही नहीं सामाजिक और धार्मिक संस्था और पर्वों के माध्यम से वह राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक महत्व के महापुरुषों का जीवन घटनाओं और गाथाओं के सम्पर्क में आता है जो हमारे इतिहास, संस्कृति के विकास में सहायक हुई हैं । वह अपने दैनिक म ऊँचा के विभिन्न रूपों और तरह तरह की मशीनों के उपयोग के आविष्कारों के सम्पर्क में भी आता है जिससे उसका जीवन है । इस कारण इन सब के प्रति उसकी रुचि स्वाभाविक है अध्ययन में वह उसका प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही

रुचि लेता है और उसके लिए ये धन परस्पर इनने मुसम्बद्ध हाव हैं कि उन्हें अलग करना वास्तव के लिए अस्वाभाविक ही होगा।

पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता—छाटी बस्ताबा में बालक इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि वे विशेषतः विज्ञान तथा गणित के अमूर्त मिटाता की समझ सकें। वे मूर्त वस्तुओं की ओर आकृष्ट होते हैं। वे सामान्य वस्तुओं तथा घटनाओं के विषय में ज्ञान के लिए जिज्ञासु होते हैं, अतएव पर्यावरणीय अध्ययन के द्वारा उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ एवं स्वस्थ आदतों का विकास हो सकेगा, वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। और चूँकि इस आयु के बालक समूह में काम करना पसंद करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन, समूह काम के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा तथा ज्ञानक अध्ययन में न केवल रुचि लेगा वरन् स्वयं सक्रिय रहेगा।

मनोवैज्ञानिक पक्ष (अ)—यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बालक सालाओं में कुछ सीखता है उससे वही अधिक ज्ञान के बाहर सीखता है। बालक का निकटवर्ती पर्यावरण उसका सामाजिक सम्पर्क, मिल मण्डली एवं गृह का वातावरण उसके वास्तविक शिक्षक हैं जिसे वह अनुकूल या प्रतिकूल प्रेरणार्थ प्राप्त करता है। अतएव यह आवश्यक है कि छाटी आयु के बालक की शिक्षा वातावरण से निरन्तर सम्बंधित है तथा प्राथमिक स्तर की प्रथम दो बस्ताओं में सम्पूर्ण शिक्षा का अधिकांश भाग पर्यावरणीय शिक्षा के स्वरूप में ही हो। पिगेट (Piaget) एवं अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधकाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बालक जब तक 11 या 12 वर्ष के नहीं हो जाय तब तक उनमें सामान्य औपचारिक व सैद्धांतिक तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। छोटे बच्चे जो प्राथमिक बस्ताओं में पढ़ते हैं सम्पूर्ण वातावरण को एक पूर्णतः प्राप्त इकाई के रूप में देखते हैं न कि विभिन्न घटनाओं से घुसक घुसक प्रवाह के रूप में जो अलग अलग विषय विभागों में विभाजित है। इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसी शिक्षण संरचनाओं या प्रकरणाँ की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जो बालक की रुचि व अनुसार हो तथा जो प्रत्यक्ष व्यापहारिक स्थिति से सैद्धांतिक औपचारिक विषय शिक्षण की ओर ले जाने वाले हों।

(अ) पर्यावरणीय शिक्षा पूर्णतः औचित्य पूर्ण है क्योंकि—

- (1) वातावरण की यह शिक्षा बच्चे का उनसे निकटवर्ती सामाजिक व भौतिक परिवेश से परिचित करावेगा।
- (2) उनमें अच्छी स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी आदतों का विकास होगा।
- (3) वे सामाजिक व व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छे चरित्र के प्रति सचेत-शील होंगे।

तात्पर्य यह है कि पर्यावरणीय शिक्षा यह दुनिया है जा कथा से सगी हुई है जहा जाया जा सकता है जिसे देखा व अनुभव किया जा सकता है व जा विषय वस्तु से सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से खेल और मेले से, पोखरे, घराने, चाद, सितारे व पाम पडोसो के जोखित प्राणिया आदि से प्राप्त की जा सकती है ।

पर्यावरणीय शिक्षा के लाभ

- (1) बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे ।
- (2) ऐसा ज्ञान साधक वैज्ञानिक व यथायथादी होगा ।
- (3) बालका मे से 'क्या' और 'कैसे' की प्रक्रिया का विकास होगा ।
- (4) प्रत्यक्ष अनुभवों का संग्रह विविध वर्गीय होगा ।
- (5) ऐसा संग्रह बाल मस्तिष्क मे सही प्रतिभासा (Images) का निर्माण करेगा जिसके आधार पर उपयुक्त प्रत्यया (Concepts) का निर्माण होगा ।
- (6) शिक्षा जीवनोपयोगी होकर वास्तविक भी होगी ।
- (7) बालका मे निरीक्षण, प्रयोग तथा आत्म क्रिया की प्रवृत्तिया का विकास होगा ।
- (8) उनमे वैज्ञानिक ढंग पर चिंतन करने की श्रुय अथवा अन्तर्दृष्टि का विकास हो सकेगा ।

शिक्षण विधियों का उ-मुखीकरण—पर्यावरण शिक्षा के अ नगत शिक्षण विधिया को नवीन परिप्रेक्ष्य मे देखना होगा । ये कोई नवीन विधिमा नही होगी । केवल परम्परागत विधिया म ही सशोधन कर नए आयामा को जोडना होगा । ऐसी विधिमा का प्रयोग करता होगा जो बालक/बालिकाओं के न केवल मानसिक परिवेश के अनुकूल हा बल्कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण स भी समरस हा । ऐसी विधि का लक्ष्य यह होगा कि बालका मे प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करना व तर्क करने की क्षमता का विकास हो सके । वे आत्मक्रिया या स्वयं विश्लेषण द्वारा अपनी जिनामा एवं उत्तुमरता को सम-धान कर सकें और उनमे खाज, अवेषण, एवं प्रयोग कर सकने की मानसिक अभिवृत्ति विकसित हो सके । ये प्रत्यक्ष 'परिवेश परक' ज्ञान का अजन करे जिससे वे जीवनोपयोगी तत्वा को केवल मैद्धानिक रूप मे ग्रहण ही न करि अपने जीवन मे व्यवहृत भी कर सकें ।

इसके लिए शिक्षका का भा उन्मुखीकरण आवश्यक होगा। उन्मुखीकरण में निम्नलिखित लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा—

- (1) मानद्रिया के माध्यम से शिक्षा।
- (2) प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति।
- (3) प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग।
- (4) प्रकृति दशन।
- (5) वस्तु संग्रह।

पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित बातें समाविष्ट होना चाहिए—

- (1) पर्यावरण से सम्बंधित कहानी, सघुक्चाएँ मौखिक दृष्टांत।
- (2) राचक मौखिक फाय
- (3) प्रत्यक्ष अनुभव और मौखिक अभ्यास।
- (4) शैक्षणिक पर्यटन।
- (5) दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग।
- (6) सजीव एवं निर्जीव तत्वों का प्रत्यक्ष अध्ययन।
- (7) इवाई जन्म सतत मूल्यांकन।

क्या पढाया जाए—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना होगा।

- (1) छोट बालकों की आयु, क्षमता व मानसिक परिस्थिति को ध्यान में रखत हुए पर्यावरणीय शिक्षा अतिरकता के दोष से मुक्त हा।
- (2) बच्चे इस माध्य बन सके कि वे स्वस्थ रहने क सामा द नियमों को जान, उह प्रयोग कर व अपन रहन-सहन को उनके अनुकूल बनावें।
- (3) वे स्वच्छता के नियमों का पालन करें व वातावरण का भी शुद्ध रतें।
- (4) व शुद्ध वायु पर्याप्त प्रकाश, व भूय शक्ति के महत्त्व से अवगत हो व जीवन व लिए उनकी आवश्यकताओं से अवगत हा।
- (5) उनमें सतुलित व पौष्टिक आहार ग्रहण करने व स्वास्थ्य के लिए उनकी उत्पादकता को आदत का विकास हो।
- (6) व यह जान सके कि पठ पीठे बन-सम्पदा एवं व व प्राणी मानवीय वातावरण के अभिन्न अंग हैं एवं उह ध्यय हो नष्ट न कर उनकी सुरक्षा एवं ग्रहन उत्तरदायित्व है।

विज्ञान व गणित—पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा बालक में ऐसी कुशलता और अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है जो उस अपने चारों ओर के भौतिक, भौतिक वातावरण का समझने के लिए आवश्यक होती है। प्रकृति के साधना का उपयोग यदि सावधानीपूर्वक न किया गया तो बालक असंतुलन उत्पन्न होगा। इस प्रकार पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत बालक-बालिकाओं को वायु प्रदूषण, अपोषण, प्राकृतिक साधना की सुरक्षा तथा पोषक भोजन की कमी जैसे तत्त्वों का विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए। इट, खिड़की, दरवाजे, फन-फून, तिनखी, पीछे वृत्त आदि के द्वारा जोड़-घटाना, गुणा भाग, सिखाया जा सकता है।

सामाजिक विज्ञान—इसमें प्राकृतिक व सामाजिक दोनों परिवेश सामिल है। माया शिक्षा—माया आत्मभिव्यक्ति का अवशानमान साधन है। इसमें

सर्वेश्वर शाल सामाजिक चिन्तन से लेकर गहन तक एक विचार-विमर्श एक निष्पत्ति की मानसिक याग्यताओं का एकीकृत समावेश रहता है जो आयु व अनुभव की वृद्धि के साथ विकसित होता है। पर्यावरणीय शिक्षा में माया शिक्षण का विशेष महत्व है। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा—

- (1) पुस्तकों उपयुक्त तैयार की जाएँ, इनमें संशोधन, परिवर्तन परिवर्धन किया जाय।
- (2) शब्द भंडार पर्याप्त हो।
- (3) पाठ्य-सामग्री अच्छा के दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो।
- (4) स्थानीय पर्यावरण का ध्यान में रखा जाय।

मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय शिक्षा के शान्तिकारी कदम का शुल्काव की गई है।

दूरदर्शन द्वारा शिक्षा

(Education through Television)

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास करना है। प्रजाताम्रिण देश के सुव्याप्य नागरिक तैयार करना हमारे शिक्षा का प्रमुख मन्त्र है जहाँ जहाँ परम्परागत पुस्तक का अध्ययन, अध्यापन ही पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा की प्रक्रिया को व्यावहारिक जगत के अधिकांश निकट साना होगा, तथा ज्ञान बढ़ाने के सभी उपलब्ध साधन अपनाने होंगे। आज विज्ञान और तकनीकों का युग है। आज की दुनियाँ में आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और तकनीकों का ज्ञान जाना किसी भी देश का अपनी गरीबी और बकरी दूर करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। पशु की अपना व्यव कई गुना आसानी से बढ़ गई है, छात्र संख्या कई गुनी हो गई है। हमें शिक्षा, अध्यापन के क्षेत्र में भी परिवर्तन करना होगा। हमें अध्यापन में परम्परागत तरीके बदलने होंगे। टेलीविजन, रेडियो से शिक्षा का ज्ञान सभी है।

वर्तमान विज्ञान के युग में विकासशील देश के लिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक एवं आजीविका आधार भूत वैज्ञानिक शिक्षाओं को जानकारों रहें तथा उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो। इस उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर भारत शासन ने शासकों में विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निश्चय किया। इस दिशा में नए पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय ऐश्वर्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित किया गया। इस पाठ्यक्रम को विभिन्न राज्यों ने अपनी-अपनी सुविधा एवं स्थिति अनुसार संशोधित कर अपना लिया है। मध्य प्रदेश में इस कार्य के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित हुई कि अधिकांश शिक्षक जो प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में हैं वे विज्ञान, गणित विषयों में निष्णात (Expert) नहीं हैं। हमारे स्कूल भी ग्रामीण अंचल के दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जहाँ विज्ञान व्यवस्था अथवा विषयों की शैक्षणिक सुविधा भी नहीं है। अतः बड़े पैमाने पर शिक्षकों का प्रशिक्षण करने की दिशा में हमने दूरदर्शन का उपयोग किया।

दूरदर्शन का शिक्षा में प्रयोग—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा देने का प्रथम प्रयोग अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड हट महोदय ने किया।

उन्होंने परम्परागत शिक्षण से हट कर दूरदर्शन (Television) का उपयोग किया। अनेक विरोधों के उपरान्त इसे सभी लोगों ने स्वीकार किया कि टेलीविजन, शिक्षा देने के लिए आधुनिकतम उत्तम साधन है। प्रायः सभी विकसित एवं विकासशील देश शिक्षा देने के लिए दूरदर्शन का उपयोग कर रहे हैं।

म० प्र० में 1 अगस्त 1975 से अमेरिकी उपग्रह एस० टी० एस० 6 से दूरदर्शन का कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। जहाँ एक ओर पिछड़े हुए गाँवों के प्राथमिक स्तर के बालकों को सामान्य विज्ञान पढ़ाने के लिए दूरदर्शन का प्रयोग किया गया वहीं एक साथ कम समय में एवं कम खर्च में अधिक से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को पाठ्यवस्तु और पाठ्यविधि में प्रशिक्षण हेतु भी दूरदर्शन का प्रयोग किया गया। आधुनिक समस्याओं के हल के लिए अतिरिक्त तकनीकों के अनुप्रयोग के प्रयत्नों का यही से प्रारम्भ हुआ। लिखने-पढ़ने के पाठों का उपग्रह के माध्यम से प्रसारण हुआ। उसी उपग्रह से ग्रामीण आम जनता के लिए कृषि, तकनीकी, सिंचाई, पापण, भोजन की तैयारी, जन सुरक्षण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, शिशुओं की देखभाल, तथा अन्य ऐसे ही विषयों सम्बन्धी निर्देश प्रसारित हुए जिससे कि उनका जीवन स्तर उठे। विषया की विविधता तथा जन जीवन से सम्बद्धता के कारण ही यह उपग्रह "लोकों का मुख उपग्रह" का ख्याति अर्जित कर सका।

मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्र छत्तीसगढ़ को उपग्रह सैनिक दूरदर्शन प्रयोग हेतु चुना गया। छत्तीसगढ़ अक्सर के 400 ग्रामों में दूरदर्शन सेंट्रों की स्थापना की गई। रायपुर जिले में 169 केंद्र, दुर्ग जिले में 90 केंद्र, राजनांदगांव गाँव जिले में 58 केंद्र, बिलासपुर जिले में 83 केंद्र, इस प्रकार कुल 400 केंद्र खोले गए और 1 अगस्त 1975 से ही दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त काल प्राथमिक शालाओं के लिए तथा सामकाल प्रौढों के लिए रोचक और ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। सन् 1975 के अक्टूबर में सभी 400 दूरदर्शन केंद्रों में 4000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए 12 दिवसीय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें प्रत्येक दूरदर्शन केंद्र के 10 शिक्षकों को एक टीचर मानीटर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। टीचर मानीटरों को पूर्व में ही रा० शी० अ० प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उन्मुखीकृत किया गया था। जुलाई 1976 में 4000 शिक्षकों का भी विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

उपरान्त 400 शालाओं में जिनमें यह दूरदर्शन का प्रयोग चला उसमें 50,000 छात्र पढ़ते थे। 196 दिनों तक प्रतिदिन 22½ मिनट का दूरदर्शन

कायक्रम दिखाया गया, दूसरे शब्दा में छात्रों ने 73 घंटों के दूरदर्शन कायक्रम का लाभ उठाया। ये कार्यक्रम 5 से 12 वर्ष के बच्चों में एक साथ दिये। यह भी पढ़ने में सोचा गया था कि शास्त्रों के बाहर के बच्चे भी इन कायक्रमों का लाभ उठा सकें इस दृष्टि से यह प्रयत्न किया गया कि कायक्रमों को कक्षा शिक्षण से ही सीमित न रखा जाय। अतः ये कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रेरक एवं शानियग्रह सामग्री के रूप में ही दिये गए। फिर भी अधिकांश कायक्रम ऐसे थे जो प्राथमिक शास्त्र पाठ्यक्रम से सीधे सम्बद्ध थे। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ, शिक्षकों का जो पदान में सहायता मिली वह शिक्षा जगत के लिए अमूल्य है।

म० प्र० में दूरदर्शन कायक्रम की उपलब्धियाँ—1 अगस्त 1957 से 31 जुलाई 1976 तक जो दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग किया गया उसकी निम्नांकित उपलब्धियाँ हुई—

- (I) शिक्षकों और छात्रों का वैज्ञानिक धारणाओं का अधिार स्पष्ट करने में सहायता मिली।
- (ii) बालक क्रियाकलापों तथा सामूहिक चर्चाओं में सम्मिलित हुए।
- (iii) बच्चों के आचरण में परिवर्तन आया।
- (iv) शिक्षा के प्रति बालकों में लगाव पैदा हुआ।
- (v) विद्यार्थियों में छात्र सभ्यता में वृद्धि।
- (vi) बच्चों में उपस्थिति में वृद्धि।
- (vii) विज्ञान की ओर विद्यार्थियों की अभिरुचि।
- (viii) स्वतः निमित्त उपकरण निर्माण करने के कोशिश में वृद्धि।
- (ix) छात्रों में समस्या निवारण-मूलक प्रवृत्ति का जागरण।
- (x) शिक्षा का प्रशिक्षण।

हमारा देश और प्रदेश गाँवों में दूर-दूर फैला हुआ है अतः दूरदर्शन द्वारा शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व और आवश्यकता है।

दूरदर्शन द्वारा शिक्षा से लाभ—आज का युग तकनीकी और वैज्ञानिक छात्रों का युग है। हमें परम्परागत और दबियाजूसी विधि-विधान का त्यागकर वैज्ञानिक विधियों और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा से निम्नलिखित लाभ हैं—

- 1 शिक्षा प्रसार का द्रुतगामी साधन—हमारा देश गाँवों में बसा है। अभी भी काफी बड़ी संख्या अक्षिप्त है। म० प्र० में स्थिति और भी

विनिर्णीत है। 6-14 आयुवर्ग के 60% ही बालक/बालिकाएँ शालाओं में हैं। दूर-दूर तक फैले ग्रामीण अंचलों के बालका, प्रौढा को शिक्षा देने, शिक्षा का प्रशिक्षित करने के लिए दूरदर्शन एक अत्यंत उपयोगी साधन है।

- 2 बहूते स्थानों, वस्तुओं का ज्ञान—सभी विषया में ऐसे-ऐसे स्थानों, वस्तुओं का वर्णन होना है जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं है और न कभी देख सकते हैं। दूरदर्शन द्वारा उनका ज्ञान कराया जा सकता है। साथ और प्रतियाएँ उन्हें स्पष्ट चित्रा द्वारा समझाई जा सकती हैं।
- 3 कक्षा अध्यापन आकर्षक और सरल—दूरदर्शन द्वारा कक्षा अध्यापन का काफी रोचक और सरल बनाया जा सकता है। विद्यार्थी दूरदर्शन द्वारा शिक्षक के काफी रुचि लेते हैं और पढ़ाई हुई वस्तु को हृदयगत कर लेते हैं।
- 4 छात्रों के लिए रोचक—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में छात्रगण सक्रिय होते हैं वह पाठ या पाठ्यवस्तु रोचक लगते हैं। बिना उबल हुए के घटा मन लगाकर पढ़ सकते हैं।
- 5 छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि—हमारी शालाएँ अनानुसंगिक हैं, पढ़ाने की विधिमें पिढी-पिढाई है। अतः छात्र शालाओं में नहीं आते हैं, लेकिन दूरदर्शन द्वारा शिक्षा उन्हें रोचक लगती है, अतः उपस्थिति में आभासीतः वृद्धि होती है।
- 6 रोज सध्या में वृद्धि—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा देने में रोज सध्या में काफी वृद्धि होती है। कार्यक्रमों में मनोरंजन, दृश्य, श्रव्य सभी तत्व रहते हैं, अतः बालक अधिक से अधिक शालाओं में भर्ती होते हैं।
- 7 द्रष्टा और श्रव्य दोनों इंद्रियों का सक्रिय होना—शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है तो बालक केवल सुनते रहते हैं, लेकिन दूरदर्शन में वे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अतः उनका मन ज्यादा एकाग्र रहता है।
- 8 दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास—दूरदर्शन के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्र नेताओं, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का हम केवल रेडियो पर सुन सकते हैं, सुनने से उतना असर नहीं होता जितना प्रत्यक्ष देखकर और सुनकर होता है। इस दृष्टि से दूरदर्शन का अपना विशेष महत्त्व है।
- 9 बालका का सामूहिक अर्चाओं में संलग्न होना—दूरदर्शन का कार्यक्रम देख सुनकर बालक फिर सामूहिक अर्चाओं में संलग्न होते हैं, आपस में

चर्चाएँ करत हैं और इस प्रकार उनमें चर्चा करने एवं तर्क शक्ति को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

दूरदर्शन द्वारा शिक्षा की हानियाँ—जहाँ एक ओर दूरदर्शन, शिक्षा में एक सशक्त माध्यम है वहीं दूसरी ओर उसका उपयोग की हानियाँ भी हैं।

1. **प्रतिक्रिया का अभाव**—शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक प्रेरणा देता है और छात्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दूरदर्शन द्वारा उस प्रेरणाएँ तो मिलती रहती हैं किन्तु वह अपना प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता है। शिक्षा वास्तव में क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा ही होती है।
2. **शिक्षा बाँटित ज्ञान द्वारा**—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा इतना जल्दा-जल्दी दी जाती है कि छात्र प्रतिक्रिया व्यक्त न कर पान से बंझित हो जाता है, शिक्षा की गति इतनी तीव्र होता है कि वह समझ नहीं पाता है।
3. **शिक्षक के व्यक्तित्व का अभाव** दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में शिक्षक न होने से छात्रों को शिक्षा एक यांत्रिक जैसी भावना होती है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्रों पर पड़ना है, उसके आचार-विचार, वाग-मृदा से छात्र प्रभावित होता है। अतः शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है वह इसमें नहीं होता है।
4. **छात्र शिक्षक सम्पर्क का अभाव**—इसमें छात्र और शिक्षक का सम्पर्क ही नहीं हो पाता है। छात्र अपने शिक्षक का देखता है और शिक्षक अपने छात्रों को। अध्यापन विधि तदनुसार तन्वीन की जा सकती है। शिक्षक, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है जब कि दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में संभव नहीं है।
5. **छात्रों की समस्याओं का उचित हल नहीं**—शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण करता है तो शका समाधान भी करता जाता है लेकिन दूरदर्शन में केवल सूचनाएँ, ज्ञान की बात ही बताई जाती है बीच में शका समाधान करने का छात्रों को अवसर नहीं मिलता है। शिक्षण के समय हम छात्रों की प्रवृत्तियाँ, मनावृत्तियाँ का निर्माण करते हैं। यह सभी बातें छात्र और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष विचारों के आदान-प्रदान द्वारा ही संभव है।
6. **सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा**—छात्रों का मानसिक स्तर अलग-अलग होता है, अलग अलग वातावरण से भी छात्र आए हुए होते हैं,

शिक्षक अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का निवारण करता है। लेकिन दूरदर्शन द्वारा सभी स्तर के वासका को एक ही समय एक जैसी शिक्षा दी जाती है जो ठीक नहीं बही जा सकती है।

उपयुक्त साम और हानि के मुद्दा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दूरदर्शन द्वारा हानियाँ हैं लेकिन लाभ अधिक हैं, वैज्ञानिक युग में हम नवीनतम शैक्षिक उपकरणों साधना का उपयोग करना ही चाहिए। रही बात इसकी कि हमारा देश गरीब देश है और जो काम सस्ते में और सरलता से हो सकता है उसमें महंगे उपकरण साधन आवश्यक प्रतीत नहीं होत हैं। जीवन के मूल्य भी कुछ होत हैं। सभी चीज यांत्रिक विधि से चलन लगे तो जीवन नीरस हो जायगा और उसमें रसता का अभाव हो जायगा। शिक्षा द्वारा जो जीवन के सही मूल्य, प्रेम, दया, स्नेह आदर समर्पण के भाव पैदा होत हैं, वे सभी बर्द हो जायग, फिर जीवन में यह ही क्या जायगा? इसी भीतिरता के कारण हमारे प्राचीन गुरुकुला और आज के स्कूला में कितना फर्क आ गया है। दूरदर्शन आए तो आए हमारा गुम्मा की परम्परा नहीं टूटनी चाहिए।

पढ़ो और कमाओ योजना

(Learn and Earn Scheme)

हमारा अतीत भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा होगा लेकिन हम लगता है कि वर्तमान में ही हम कहीं भटक गए हैं। अंग्रेजा के समय से मेकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का हम ढोल पीटते आ रहे हैं, लकीर में फकीर बने हुए हैं। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं कर पाया है। शास्त्राण्योत्ती, छात्र सख्या और शिक्षक सख्या में वृद्धि हुई, साक्षरता बढ़ी लेकिन ठीक इसके विपरीत भयंकर बेरोजगारी और निरक्षरता भी बढ़ी है। अपने व्यवसाय को छोड़कर बालक बालिकाएँ पढ़कर नौकरी की तलाश में दौड़ने लगे। कहावत चरिताय हो गई कि “अधिक पढ़े तो घर से गए, थोड़ा पढ़ सों हम से गए”। हमारी भागी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था-अस्त व्यस्त सी हो गई है।

वस्तुतः ज्ञान की सामकता तभी है जब वह व्यावहारिक हो। ज्ञान के द्वारा हमारे संस्कारों, कार्यों एवं व्यवहार का परिष्कार होता है। हमारी प्राचीन शिक्षा “जीवन के लिए शिक्षा” थी। वह शिक्षा व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध थी, उसमें ज्ञान और काम एक मूल में बँधे थे। उस समय गुरुकुल प्रणाली में भी छात्रगण विद्या अध्ययन करते थे और अपना काम भी स्वयं करते थे। इस प्रकार अध्ययन के साथ स्वावलम्बन की शिक्षा भी उन्हें मिलती थी।

जैसा हम जानते हैं कि मेकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल कार्यालयीय कार्य के लिए क्लर्क और अफसर पढ़ा करना मात्र था, अतः शिक्षा का समाज, श्रम, उत्पादकता और व्यावहारिक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। शिक्षित वर्ग श्रम, ग्राम्य जीवन और उत्पादकता से अलग होता गया। अतः अंग्रेजी शासन काल से ही शिक्षाविदों ने शासन का ध्यान श्रम और आर्कायन करने के प्रयास किए कि शिक्षा को उत्तरदायी मुन्शी बनाया जाय।

1 वुड का शिप्मा डिस्पेंच (1854 ई०)—वुड्स डिस्पेंच में कहा गया कि वतमान शिक्षा पुस्तकीय है अतः व्यावसायिक शिक्षा एवं हाथ से काम करने अर्थात् हस्तकला की शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी।

2 हटर कमीशन (1882)—इसके बाद हटर कमीशन द्वारा भी शिक्षा को व्यावसायो-मुखी बनाने की सिफारिश की गई थी किन्तु तत्कालीन शासन ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया। इसके उपरांत नियुक्त शिक्षा आयोग न टेक्नीकल और औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनुशसाएँ की किन्तु व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए।

3 एवट एव वुड रिपोर्ट—1936 के आसपास जब बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयीन स्नातकों की राजभार न मिलने या छात्रों खर्च न हो सकने की समस्या उत्पन्न हुई तब तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने दो शिप्माविदों एव एवट एव वुड की शिक्षा के पुनर्गठन खास तौर पर व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। एवट एव वुड की अनुशसाओं का यह प्रभाव हुआ कि नए ढंग की तकनीकी संस्थाएँ खोली गईं जिन्हें आजकल पॉलीटेक्नीक कहा जाना लगा है। किन्तु हमारी जनसंख्या वृद्धि सामान्य शिक्षा और उससे बढ़ती बेरोजगारी के कारण व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में शासन द्वारा की गई नाम मात्र की यह पहल कारगर सिद्ध नहीं हुई।

4 महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा एवं वर्धा सम्मेलन—हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी शिक्षा का व्यावसायो-मुखी बनाने की भरसक चेष्टा एवं अपील की। स्वयं भी शिक्षा विद होने के नाते बुनियादी शिक्षा को प्रतिपादित किया जिसमें शिक्षा को ग्रामो-मुखी बनाने, उत्पादन से सम्बद्ध करने और हस्त-कौशल प्रधान बनाने की ओर जोर दिया गया था। उनका कहना था कि उत्पादन कार्य को न केवल शालीय पाठ्यक्रम में रखा जाय बल्कि शिक्षा को सद्याग केन्द्रित बनाया जाये।

महात्मा गांधी के नई तालीम के शिक्षा दर्शन को काय रूप में परिणित करने के लिए अक्टूबर 1973 में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया जिसमें निम्नानुसार प्रस्ताव पारित हुआ। “यह सम्मेलन महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करता है। इस 7 वर्ष की कालावधि तक शिक्षा का स्वरूप किसी न किसी प्रकार शारीरिक एवं उत्पादन कार्य से जोड़ा जाना चाहिए और अन्य सभी क्षमताओं का विकास अथवा प्रशिक्षण जहाँ तक आवश्यक के मातावरण से सम्बन्धित हस्त उद्योग (गिल्ड) के अनुकूल

चाहिए।" वैसे गांधी जी की बुनियादी शिक्षा रूस में पोलीटेक्नीकल प्लान से सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों में समान थी। आज रूस में पोलीटेक्नीकल स्कूला का ऐसा जाल सा बिछा है कि उनकी सारी शिक्षा व्यावसायी मुखी हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि हम गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को ठीक ढंग से लागू नहीं कर सके।

5 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) एवं उद्योग—भारत की स्वायत्तता के बाद ही नियुक्त सेकण्डरी एजुकेशन कमिशन जिसे मुदालियर कमिशन कहा जाता है, ने भी व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में देश को न मुख करने के लिए प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक शाळा में उद्योग विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने पर बल दिया था। इसका उद्देश्य यह था कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का तारतम्य उच्च शिक्षा तक चल सके एवं इन उद्योगों के माध्यम से छात्र अपने भावी व्यवसाय की ओर व्यवहारिक रूप से उत्सुख हो सकें। हमारे साधना, धन, शक्ति का अभाव, उद्योगों का गलत चयन के कारण हमें कोई लाभ नहीं मिल सका। हमारी शिक्षा की आलोचना और भी तेज़तर्रार होती गई।

6 शिक्षा आयोग (1964-66) एवं कार्यानुभव—प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक तालमेल रखने और समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से गठित 'शिक्षा आयोग' (1964-66) जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है, ने भी उत्पादक कार्य को शिक्षा का एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार किया है। प्रायोगिकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों की बढ़ती हुई आवश्यकता की दृष्टि से कोठारी आयोग ने महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग के 'उद्योग' को कार्यानुभव के नाम से सम्मोहित किया। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 'कार्यानुभव' की उपाययता पर बल देते हुए आयोग ने उसे वर्तमान तकनीक से निरन्तरता के साथ सम्बद्ध करने की अनुशंसा की है। प्राकृतिक वातावरण में वस्तु-वारदानों जैसा दृष्टि क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से कार्य करने का सुझाव ही आयोग ने किया है एवं उच्च शिक्षा में अधिक प्रवीणता उपलब्ध कर छात्र अपनी आजीविका का साधन भी उसे बनावे। इस क्रम में 10+2+3 पद्धति की अनुशंसा भी आयोग द्वारा की गई है। आयोग द्वारा अनुशंसित कार्यानुभव का अथ विद्यालय, घर, कर्मशाला, घेत या कारखाना में आयोजित उत्पादन कार्य या इसी प्रकार की किसी उपायन स्थिति में भाग लेना है। एक सुबद्धस्थित कार्यानुभव कार्यक्रम के द्वारा नए कलाओं में नगर या उत्पादित द्रव्य के रूप में कुछ कार्य हो

की समावना है जिससे बासब अपना खच भी चला सकता है। कार्यानुभव की शिक्षा किताबी ज्ञान की अपेक्षा हाथ से काम पर ज्यादा बल देती है। इस प्रकार यह गांधी जी की विचार धारा से मेल खाती है।

7 ईश्वर भाई पटेल समिति एवं समाजोन्मोगी उत्पादक कार्य—जून 1977 में गठित “ईश्वर भाई पटेल समिति” ने शिक्षा में कार्यानुभव की उपयोगिता एवं उपादेयता को तो स्वीकार किंतु उसने यह अनुभव किया कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वह वर्तमान साधना की दृष्टि से अधिक महत्वाकांक्षी योजना प्रतिभासित होती है। अतः इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अनुसंधान सहित उसे “समाजोपयोगी उत्पादक कार्य” का नाम दिया तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसे अनिवार्य स्थान देने की सिफारिश की।

8 राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977—श्री श्रीम नारायण की अध्यक्षता में 18 से 20 दिसम्बर 1977 तक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अनुसंधान की गई कि शांता समय का 50 प्रतिशत समय उत्पादक, रचनात्मक एवं मनोरजनात्मक गतिविधियां में लगाया जाना चाहिए।

म० प्र० की पढाई कमाओ योजना—महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का आधार उद्योग एवं ‘शिक्षा आयोग’ की कार्यानुभव की सिफारिशों को वास्तविक असली जाना पहचानने में अग्रणी होने का कार्य हमारे प्रदेश में वर्ष 1978 में “पढाई और कमाओ योजना” प्रारम्भ कर किया गया। मध्य प्रदेश के शालेय शिक्षा जगत में 2 अक्टूबर 1978 गांधी जयन्ती दिवस एवं अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण दिवस है। इस ऐतिहासिक दिवस पर छह केन्द्र-रामपुर, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, सीहोर और खरपीन स्थित शा० उ० मा० विद्यालयों में छात्रों के लिए एक नवीन ‘पढाई कमाओ योजना’ प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में इन केन्द्रों पर उद्योग शिक्षा के निशर्द्धन में टाट पट्टी एवं चाकस्टिक निमाण होता है। उत्पादक कार्य करने वाले छात्रों, निशर्द्धों को उचित पारिधमिक भी दिया जाता है। अतः शालेय शिक्षा में यह एक क्रांतिकारी योजना है जिसके तहत बच्चे पढने के साथ-साथ कुछ अजिन भी करते हैं और स्वावलम्बन का पाठ भी सीखते हैं।

लोक शिक्षण सचालक म० प्र० ने जुलाई 1979 में इस योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। समिति के संस्थापक शिक्षक एवं अभिभावकों से साक्षात्कार किया एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत

शिक्षा सचिव, सोन शिक्षा सचालक एवं आदी ग्रामीणों परित्त के प्रवृत्ति निवेदक न इसका परीक्षण किया । समा पहलुआ पर विचार कर एवं सभी आर स समयन प्राप्त होने पर शिक्षा व मोक्ष व्यापीकरण के उद्देश्य से शिक्षा विभाग म० प्र० न इस योजना के अतिरिक्त त्रियान्वयन का निगम किया । तदनुसार ॥ अक्टूबर 1979 को 101 टाटपट्टी एवं 101 चाकस्टिक बतान के उत्पादन केन्द्र छोले गए । प्रदेश की शालाआ में इस योजना व प्रति अपार उत्साह है । 30 जून 80 तक इन उत्पादन केन्द्रा पर 10 लाख रुपया का टाटपट्टी एवं डेढ़ लाख रुपया की चाकस्टिक पैपार की जा चुकी है ।

योजना की आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि—काय, उद्योग, उत्पादक काय, कार्यानुभव या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पूरा रूप से मनोविज्ञान पर आधारित हैं । प्रत्येक बालक में रचना, सप्रह एवं आत्मदर्शन की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं । इस दृष्टि से प्रत्येक उत्पादक या रचनात्मक कार्य में बालक की उपर्युक्त प्रवृत्तियों के प्रकाशन का सर्वाधिक अनुकूल अवसर उपलब्ध होता है । फिर भी इतने बड़े अंतराल के बाद भी बालकों को इस ओर उन्मुख नहीं किया जा सका यह एक चुनौती है । महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा से लेकर वर्तमान ईश्वर भाई पटेल समिति तक सभी शिक्षा विद्, आयोग, उत्पादक काय रच नात्मक काय की उपादेयता, आवश्यकता को बताना चल आ रहे हैं । शिक्षा विद् के माग-दर्शन, तथा शासन द्वारा पहल किए जान के बाद भी उत्पादक काय करने लही रूप में गया नहीं उभर कर आ सके ? यह एक समस्या थी जिसके कारण इस समस्या का निपटता से अध्ययन आवश्यक समझा गया ।

म० प्र० में साल 1980 तक 60 हजार प्राथमिक शालाएँ (जिनमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, औपचारिकतर शिक्षा केन्द्र सामिल हैं) 10,071 पूर्व माध्यमिक शालाएँ थी । सामान्यतः प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र टाटपट्टियाँ पर बैठे हैं । हमारे पास इतना बजट प्रावधान नहीं रहता है कि सभी शालाआ को 'यूनितम आवश्यकता—टाटपट्टी और चाक उपलब्ध करा सकेँ । शासकीय प्रयास एवं जनमहयोग का दोहन करने पर भी समस्या की पूर्ति नहीं हो पा रही है । इसी तरह इन शालाआ के लिए एक करोड़ मूल्य का चाकस्टिक खरीदी जाती है । मध्य प्रदेश में चाकस्टिक उत्पादन के लिए कई बड़ा उद्योग केन्द्र नहीं है । सन् 1937 से म० प्र० में बुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ था, तब से शालाआ में उत्पादक काय की प्रोत्साहन देने के लिए अविरल प्रयत्न किए जाते रहे हैं । सन् 1966 में शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बाद शालाआ में कार्यानुभव की प्रोत्साहन किया गया । इसी क्रम में शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की प्रारम्भ करने

की अनुमति की। परिणामस्वरूप राज्य ने समाजापयोगी कार्य (एस० यू० पी० डब्ल्यू) के अन्तर्गत एक विस्तृत योजना विकसित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः "पढ़ो और कमाओ" योजना इसी प्रयास का एक नया स्वरूप है।

योजना के उद्देश्य—पढ़ो और कमाओ योजना के निम्नानुसार उद्देश्य हैं—

1 प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक—हमारी वर्तमान शिक्षा बालक के जीवन और समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई नहीं है। संविधान में दिए गए वायदे कि 6-14 आयु समूह के बालकों की प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराई जाय, को पूरा नहीं कर सका है। 6-14 आयु वर्ग के लगभग 50 प्रतिशत ही बालक-बालिकाएँ शालाओं में आ सकी हैं और इतने ही शालाओं के बाहर हैं। कारण स्पष्ट है कि बालक अपने माता पिता के साथ जीविकोपार्जन में सगे रहते हैं और शिक्षा उन्हें उतनी तत्काल फलदायी नहीं दिखती है। 'पढ़ो और कमाओ योजना' से उन्हें पढ़ने के सार-साथ धन की प्राप्ति भी होगी। अतः बालक शालाओं में आयेँगे और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

2 शिक्षा में क्षति और अवरोध का निदान—बालक इसलिए शाला छोड़ देते हैं कि वे अपने माँ-बाप का परेलू कार्यों में सहायता करते हैं। प्राथमिक स्तर आठे-आन लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक बालक शाला छोड़ देते हैं, आठवीं तक तो लगभग 75 प्रतिशत छोड़ देते हैं। इस प्रकार शिक्षा में काफी क्षति का स्थिति निर्मित हुई है। इस योजना में बालक को पारिवारिक मिलना है अतः इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।

3 सृजनात्मक क्षमता का विकास—आज की शिक्षा जो केवल पुस्तकीय है उससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, छात्रों को कार्य का अवसर नहीं मिलता है। इस योजना से छात्र, कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अभी टाटपट्टी, चाक का निर्माण हो रहा है आगे अन्य काष्ठकला आदि के कार्य भी करेंगे। इस प्रकार उत्पादक कार्यों में कार्यरत रहकर छात्रों में कौशल का विकास होगा एवं उनमें सृजनात्मक भाव विकसित होगा।

4 बालक/बालिकाओं को स्वावलम्बन की ओर उन्मुख करना—इन उत्पादक कार्यों को करते हुए बालक अध्ययन के साथ-साथ कुछ अर्जित भी करेंगे जिससे उनके व्यय की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार वे अपने छात्र जीवन में ही स्वावलम्बी बनेँगे ही साथ-साथ उनमें प्रवीणता प्राप्त कर अपनी जीविका भी भावी जीवन में चला सकेंगे।

की अनुमति की। परिणामस्वरूप राज्य ने समाजापयोगी कार्य (एस० यू० पी० स्कूल) के अंतर्गत एक विस्तृत योजना विकसित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः "पढ़ा और बमाओ" योजना इसी प्रयास का एक नया स्वरूप है।

योजना का उद्देश्य—पढ़ा और बमाओ योजना का निम्नानुसार उद्देश्य है—

1. प्राथमिक शिक्षा के लोचध्यापीकरण में सहायक—हमारी वर्तमान शिक्षा बालक के जीवन और समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में कुछो हद नहीं है। संविधान में दिए गए वायदा कि 6-14 आयु समूह के बालकों की प्राथमिक शिक्षा मुलम बराई जाय, को पूरा नहीं कर सक है। 6-14 आयु वर्ग के लगभग 30 प्रतिशत ही बालक-बालिकाएँ शालाओं में आ सक हैं और इन्ने ही शालाओं के बाहर है। कारण स्पष्ट है कि बालक अपन माता पिता के साथ जोड़िकापाजन में सगे रहत हैं और शिक्षा उह उनकी वकान फनदायी नहीं दिछती है। 'पढ़ा बमाओ योजना' से उह पठन के सार साथ अप की प्राप्ति भी होगी। अत बालक शालाओं में आयेंगे और हमारा नय प्राप्त हो सकगा।

2. शिक्षा में क्षति और अवरोध का निदान—बालक इसनिए शाला छोड देत हैं कि व अपने मां बाप का घरेलू कामों में सहायता करत हैं। प्राथमिक स्तर बाउ-आउ लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक बालक शाला छोड देते हैं, बाउवी तक तो लगभग 75 प्रतिशत छोड देत है। इस प्रकार शिक्षा में काफी क्षति का स्थिति निमित्त हुई है। इस योजना में चूकि बालकों को पारिश्रमिक मिलता है अत इस समस्या पर बावू पाया जा सकेगा।

3. सृजनारम्भ क्षमता का विकास—आज की शिक्षा जो केवल पुस्तकीय है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, छात्रों का कार्य का अवसर नहीं मिलता है। इस योजना से छात्र, कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अभी टाटपट्टी, चाक का निर्माण हो रहा है आगे अन्य काष्ठकला आदि के कार्य भी करेंगे। इस प्रकार उत्पादक कार्यों में कार्यरत रहकर छात्रों में कोशल का विकास हागा एव उनमें सृजनारम्भ भाव विकसित होगा।

4. बालक/बालिकाओं को स्वावलम्बन की ओर उमुख करना—इन उत्पादक कार्यों को करते हुए बालक अध्ययन के साथ साथ कुछ अर्जित भी करेंगे जिससे उनके व्यय की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार वे अपने छान जीवन में ता स्वावलम्बी बनेंगे ही साथ उनमें प्रवीणता प्राप्त कर अपनी जीविका भी भावा जावन में चला सकेंगे।

5 पुस्तकीय ज्ञान को उत्पादक कार्य से जोड़ना—पुस्तकीय ज्ञान से केवल मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक, संयोगात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए उत्पादक कार्य ही अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान का उत्पादक कार्यों से सम्बद्ध कर इस योजना द्वारा बालक का समग्र विकास हो सकेगा।

6 छात्रों को प्रायोगिकों की ओर उन्मुख करना—विज्ञानसौलभ दश में छात्रों को शरणीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इन छात्रों के माध्यम से हम अपने छात्रों में ऐसी प्रवृत्ति द सकेंगे तथा ऐसा दृष्टभूमि निर्मित कर सकेंगे कि भविष्य में वे बल वारिधियों के लिए कुशल व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हो सकें।

7 छात्रों समय का उचित उपयोग—छात्रों में छात्रों समय का स्वल्प उपयोग करना शिक्षकों और छात्रों का समस्या रहता है। यदि छात्रों को उनके छात्रों समय में उपयुक्त एवं राबक उत्पादक कार्य मिल सके तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास तो करेंगे ही, समाज के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होंगे।

8 छात्रों के भवन, उपकरण और जनशक्ति का उपयोग—अभी छात्रों भवन उपकरण और छात्र एवं शिक्षकों की शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता था। इस योजना से हमारे स्कूल जीवन बरखाने होंगे जहाँ ज्ञान के साथ छात्रों को कर्म प्राप्ति भी होगी। छात्रों की फलतः शक्ति का उपयोग होगा। छात्रों में उपकरण उपकरणों का भी समुचित उपयोग होगा।

9 बालकों में श्रम की भावना का विकास—यह विश्वव्यापी बात है श्रम से कतराते हैं। इस योजना द्वारा उन्हें अध्ययन के समय उत्पादक कार्य करते रहने से श्रम का महत्व पता होगा तथा उनमें श्रम की भावना का विकास होगा।

10 बेरोजगारी की समस्या का निदान—इस बेरोजगारी की समस्या का स्वतः निदान हो जाता है। अध्ययन के समय भी छात्रों कुछ अतिवृत्त करता है पढ़कर भी वह नींद के लिए बैठकता नहीं फिरेगा।

11 बड़ों और कमजोरों की भावना का समग्र—यह एक अतिशय उपयोगी बात है कि बालक उत्पादक कार्यों को करते, सीखते, ज्ञान प्राप्त करते हुए कुछ कमाते भी हैं।

12 अनुशासन की भावना का विकास—छात्रों रहने से विद्यालय जीवन बनता है। कार्य करते रहने से बालक व्यस्त रहते हैं उनमें अनुशासन की भावना पैदा होती है।

13 भ्रातृत्व भावना का विकास—साथ-साथ काम करते रहने से आपस में भाई चार की भावना विकसित होती है ।

14 छुआ छत की भावना दूर होना—सभी बालक जब एक साथ काम करते हैं तो उनमें अपने ही आप छुआ-छत की भावना हट जाती है सब मिल-जुल कर कार्य करते हैं ।

15 स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क—बालक जब पढ़ने से साथ-साथ उत्पादक कार्य करेंगे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होने से मस्तिष्क भी सहो दिशा में काम करेगा ।

उत्पादक कार्यों को करने में कठिनाइयाँ

1—आवश्यक पूँजी का अभाव—दश व अथ राज्या के समान ही यद्यपि म० प्र० में मुनियानी शिक्षा एवं कार्यों-मुखी शिक्षा का अंगीकार दिया गया था किन्तु इच्छित सफलता प्राप्त न होने का प्रमुख कारण आवश्यक पूँजी और उपकरणों का अभाव था । हमारे पास इतना वित्तीय प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक शाला के लिए आवश्यक पूँजी और उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें । कच्चा माल प्राप्त करना भी समस्या है जिसके लिए पूँजी आवश्यक होती है ।

2—उत्पादित माल के विज्ञापन की समस्या—यह निश्चित है कि कुशल कारीगरों द्वारा उत्पादित अच्छे माल की अपेक्षा छात्रों द्वारा बनाया गया माल उतना आकर्षण नहीं होता है, अब माल का विज्ञापन की समस्या रहती है ।

3—अभिप्रेरणा का अभाव—बालक उसी कार्य में रुचि लेता है जिसमें उसे फायदा हो । निश्चित रूप से इन कौशलों का दीर्घगामी प्रभाव उनके भावी जीवन पर पड़ता है परन्तु अभी तक उनका तरफाल लाभ नहीं था अतः कार्यानुभव विकसित नहीं हो सके । परिणाम-स्वरूप किसी में भी रुचि नहीं रही । गाँधी जी ने बार-बार यह कहा था कि छात्रों को पारिथमिक मिलना चाहिए ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें, किन्तु यह सम्भव नहीं हुआ ।

4—प्रदेश में टाटपट्टी एवं चाक के निर्माण के आधार—पहो कमाओ योजना में प्रारम्भ में टाटपट्टी और चाक का निर्माण ही चुना गया है इनका मुख्य आधार यह है —

- 1—इन गोना वस्तुआ का प्रमुख उपमान्ता स्वयं शिगा विभाग ही है, जहाँ इन चीजों के लिए बाजार घोजन का आवश्यकता नही है।
- 2—राज्य की अनेक बुनियादी प्रक्रिया मर्यादा, शानाआ म टाटपट्टी और पान सिटिफ बनान के लिए प्रक्रियाएँ एव योग्य शिगा उप-सामग्री हैं।
- 3—टाटपट्टी बनान के लिए लकड़ी के कचरा कम खर्चों हैं और इनके रखरखाव तथा मरम्मत के लिए बिनाप मावशानी की आवश्यकता नही है।
- 4—बड़ा चीपा स 11वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी इन कचरा पर आराम से काम कर सकते हैं और इन्हें बचान के लिए कोई समस्याएँ उपस्थित नहीं होती हैं। सगभम एक सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण इन कचरा के संचालन के लिए पर्याप्त होता है।
- 5—टाटपट्टी बनान की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है और उन्नामन केन्द्र छुट्टियों व दिन तथा शाला समय के पूर्व और बाद में चुन सके जा सकते हैं ताकि अकबाश के समय का सदुपयोग कर सकें एव घन कमा सकें।
- 6—चाकसिटिफ भी शालाआ व लिए अत्यन्त आवश्यक है और शिगा-विभाग स्वयं इसका उपभोक्ता है।
- 7—चाक व निर्माण में लगने वाला साँचा कम खर्चों और सरलता से चलाया जाने वाला है। इसका रख रखाव में भी कुछ खर्च नहीं होता है।
- 8—चाक बनान के लिए आवश्यक बिस्मस पाउडर अपन पड़ोसी राज्य राजस्थान में उपलब्ध है और इसका लाना से जाना भी सरल है।
- 9—प्रायः छात्राएँ चाक बनाने में अधिक रुचि लेती हैं और इसमें सामुहिक कार्य का भी गुंजाइश है।
- 10—बिस्मस पाउडर और पानी का मधान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण को सचि में ढाल दिया जाता है और पत्रह मिनट के बाद 100 चाकसिटिफ, सुखान के बाद दूसरे दिन के उपयोग हेतु तैयार हो जाते हैं।
- 11—इस प्रक्रिया में छोटे बच्चे विशेष रुचि लेते हैं तथा तत्कालिक परिणाम उन्हें उत्साह से भर देता है।

उत्पादन केन्द्रों के प्रकार—योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के केन्द्र कायम रहेंगे —

1—बुनियादी प्रशिक्षण सस्पाएँ—ये केन्द्र उत्पादन केन्द्रों के साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी कार्य करेंगे । ये केन्द्र उन शिक्षकों का भी प्रशिक्षित करेंगे जो बाद में पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे । अतः इन केन्द्रों को प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (ट्रेनिंग-रूम-प्रोडक्शन सेंटर—टी०सी० पी० सी०) कहा जायगा ।

2 उत्पादक केन्द्र—बाकी शालाएँ जहाँ केन्द्र होंगे वे केवल उत्पादक केन्द्र होंगे ।

पारिश्रमिक—इसमें छात्रों और प्रभारों शिक्षक दोनों को पारिश्रमिक देने का प्रावधान है । बनाए गए माल के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है ।

कार्य का समय—कार्य करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था है —

1—उद्योग के कालखण्ड में छात्र काम कर सकेंगे ।

2—दो पारी वाली शाला में पहली पारी के छात्र दूसरी पारी में और दूसरी पारी के छात्र पहली पारी में कार्य करेंगे ।

3—अवकाश के समय या शाला समय के पूर्व या बाद में, छुट्टी के दिन या उद्योग कक्ष खुले रहेंगे और छात्र उत्पादन कार्य कर सकेंगे ।

प्रायोजना की प्रशासनिक व्यवस्था—इस प्रायोजना की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार का है —

1—लोक शिक्षण संचालनालय में एक प्रकाष्ठ स्थापित है जिसमें एक सहायक संचालक को इसका प्रभारी बनाया गया है ।

2—प्रत्येक समाग्रीय शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में भी एक प्रकाष्ठ की स्थापना की गई है जिसका कार्य एक अधिकारी देखता है ।

3—उत्पादन केन्द्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए तथा सस्या में जाकर मार्ग-दर्शन देने हेतु प्रत्येक समाग में एक-एक साम्य उद्योग-शिक्षक को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

4—म० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् की आर से भी दो उद्योग विशेषज्ञ तथा एक अधिकारी इस कार्य का व्यवस्था को सुगम रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं ।

5—छात्रों के कार्य की प्रगति को प्राप्ताह्न देने की दृष्टि से यय में एव बार प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था की गई है। संभाग में प्रथम आने वाले छात्रों तथा छात्राध्यापक की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। ये प्रतियोगिताएं राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित होंगी।

6—राज्य शिक्षा संस्थान में योजना के लिए मागदर्शन एवं योजना का मूल्यांकन करने के लिए 'पढ़ा बमाभा योजना' प्रवाण्ट की स्थापना की गई है।

योजना का मूल्यांकन—इस योजना का मूल्यांकन 3 वर्ष के प्रयोग के बाद 1981 में किया जायगा। वैसे म० प्र० छात्री एवं प्रामोद्याग परिषद् अपनी पूजा विनियम की दृष्टि से प्रतिवष मूल्यांकन करती है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के काय के लिए अभिलेख रले जात हैं। प्राचाय द्वारा विषय शिक्षकों के सहयोग से उद्योगशील छात्रों के विषयवार मूल्यांकन के परिणामों का गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि उत्पादन की आय के लोम का उसके जानाजन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तीन वष के अंत में शैिक लेखों, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रायोगिक काय के द्वारा योजना का मूल्यांकन किया जायगा। मूल्यांकन एवं नियोजन का काय राज्य शिक्षा संस्थान के माग-दर्शन में किया जायगा।

भावी स्प्रूह रचना

- 1—साहित्य सृजन—पढो और बमाभा योजना के अंतगत सभी उद्योगों पर साहित्य सृजन का काम राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० के तत्वावधान में सम्पन्न होगा। इसमें न केवल उद्योगों पर पुस्तकें बनाई जावेंगी बरद् उद्योगों से सम्बन्धित ज्ञान और काय द्वारा शिक्षा तथा स्वाभाविक सम्वाद पर भी साहित्य तैयार किया जायेगा।
- 2—यह योजना छात्रों में अतन्धिक लोकप्रिय हुई है। अनेकों शालाओं से उत्पादक काय के नए क्षेत्ता की सूचियों व मुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना को बढे पैमाने पर बढाया जायगा।
- 3—शीघ्र ही निवट भविष्य में कुछ उत्पादक काय जैसे—पन्तीचर निर्माण, बमहा उद्योग, कुर्सी बुनाई, बुक बाइंडिंग, सिलाई आदि के उद्योग भी जोडे जा सकते हैं।
- 4 - केन्द्रों की सख्या में वृद्धि होगी तदनुसार इसके लिए प्रशासनिक आमले की भी व्यवस्था हाने की आशा है।

शालाओ मे उत्पादक काय सम्बन्धी राष्ट्रीय सगोष्ठी

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के 91वें स्थापना दिवस पर स्कूलो मे उत्पादक काय विषय पर 31 जुलाई से 2 अगस्त 1980 तक एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इसमे 17 प्रदेशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। राष्ट्रीय संगोष्ठी मे निम्नानुसार विचार पारित किए गए—

- 1—कक्षा 1 से 10 तक उत्पादक काय को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय। इस हेतु विद्यालयो मे सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावे तथा छात्रो को पारिश्रमिक दिया जावे।
- 2—विद्यालयो मे अध्ययन की अवधि 5 से घटाकर 4 घटे की जावे, शेष 1 घट का उपयोग छात्रो द्वारा उत्पादक काय मे किया जावे।
- 3—विद्यालयो मे उत्पादक काय के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया जावे।
- 4—विद्यालय के प्राचार्य को एक अलग खाता खोलकर उत्पादक काय की राशि उसमे जमा करने तथा छात्रा को पारिश्रमिक देने की अनुमति दी जाय।
- 5—शासकीय विभागा के उपयोग मे आने वाली सामग्री का उत्पादन विद्यालयो मे किया जाय ताकि बनी हुई सामग्री के विक्रय मे सुविधा हो।
- 6 प्रशिक्षण सस्थाओ मे चल रह उद्योग कार्यों से आमूल परिवर्तन किया जाय ताकि छात्राध्यापक उन उत्पादन कार्यों मे कुशल हो जिन्हे विद्यालय के छात्र करना चाहते हैं।
- 7 समाचार पत्र टेलीविजन, रेडियो आदि जन सचार माध्यमो से विद्यालयो मे उत्पादक काय की योजना का व्यापक विनापन किया जावे।

समाजोपयोगी कार्यों की सूची—राष्ट्रीय संगोष्ठी ने निम्नलिखित समाजोपयोगी उत्पादन कार्यों की सूची स्थानीय परिवेश मे बच्चे माल की सहज उपलब्धि के आधार पर प्रस्तावित का गई—

(अ) कार्यालयोपयोग की वस्तुएँ—

- | | |
|-----------|------------|
| 1—गोद | 4—टग्स |
| 2—स्याही | 5—फाइल |
| 3—तिप्ताफ | 6—फाइल पेड |

शिगा म नए बायाम एव नवाचार

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 7—फाइल बवर | 15—फर्नोवर रिपमरिंग |
| 8—स्टाम्प पैड | 16—बुक बाइडिंग |
| 9—रस्तर | 17—रही की टोवरी |
| 10—सकड़ी के पेपर बट | 18—बॉम की बिक |
| 11—सोल स्टैड | 19—बृत्तों की बुनाई करना |
| 12—बर स्टाम्प मर्किंग | 20—झाड़ू बनाना |
| 13—पिन कुशन (लकड़ी का) | 21—सकड़ी की ड्रे |
| 14—मूचना पटल | |

(ख) शिल्लन सामग्री—

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1—हस्टर | 4—की वाट |
| 2—ब्लैक बाड-रोन अप तथा साग | 6—हटर (टुकुस एव दापान फा) |
| 3—पाइटर | 5—ब्लक बोट स्टैड |

(स) छात्राओं के लिए—

- 1—सिलाई
- 2—बुनाई
- 3—नाटिल बक
- 4—मशीन द्वारा स्वेटर बुनाई

89522 -

(द) प्रयोगशाला सामग्री संग्रह—

- 1—पुष्प क्रम सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों का संग्रह
- 2—विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह
- 3—विभिन्न प्रकार के बीज तथा फलों का संग्रह
- 4—विभिन्न प्राणियों (जीव जन्तुओं) का संग्रह

उपयुक्त सूची कायकारी समूह द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त तैयारी की गई है। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं व अनुसूच पर ध्यान दिया जा सकता है।

शाला सगम योजना

(School Complex Scheme)

आवश्यकता—गिन्ना आयाग (1964-66) ने अनुशंसा की है कि माध्यमिक स्तर पर नैतिक सुधार, शिक्षा में गुणात्मक विकास तथा प्रशासन में बचावट सान एवं प्रशासन के विकास को ध्यान में रखते हुए शाला सगम को स्थापना की जाय। वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारियों को इतना अधिक पता है कि वे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं का समुचित निरीक्षण और पर्यावरण नहीं कर पाते हैं। जिनका विस्तृत पैमाने पर शिक्षण, छात्रा, कमचारियों की समस्याओं, कठिनाइयों का निवारण भी शीघ्र नहीं हो पाता है। शाला सगम योजना के तहत सत्ता और प्रशासन का विवेकीकरण होगा और इसमें शिक्षण कमचारियों की समस्याएँ मूलभूत में सहज मिलेंगी। आज के माहौल में विभिन्न प्रकार की शालाएँ अपनी-अपनी अपनी और अपना-अपना राग अलाप रही हैं। अगर कोई शाला या शिक्षक अच्छे हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं तो उसका दूसरी शाला या शिक्षक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई शाला खराब है तो उसका सामने कोई आदेश नहीं है। कुछ शालाओं में अच्छे उपकरण हैं वहाँ के छात्र लाभान्वित होते हैं दूसरी ओर जहाँ उपकरणों की कमी है वहाँ के छात्र वंचित रह जाते हैं। अतः एक क्षेत्र या परिमर की शालाएँ मिलकर आपस में काम करे मिल जुनकर अपनी समस्याएँ हल करें, अपने-अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करें यही शाला सगम का मूल मूल है। विभिन्न स्तर की समस्याओं का दल में मिलकर काम करना चाहिए।

शाला सगम की व्यवस्था—कोठारा आयाग की अनुशंसा के अनुसार एक उच्चतर माध्यमिक शाला के आसपास 6 से 8 किला मोटर के क्षेत्र की 5-6 पूर्व माध्यमिक शालाएँ तथा 25 से 30 प्राथमिक शालाएँ मिलकर एक शाला सगम बनाया जाय। केन्द्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य को शाला सगम का प्रभारी बनाया जायगा। इसके दूसरे खण्ड में प्रत्येक पूर्व माध्यमिक शाला एक उपकेन्द्र के रूप में। इससे सम्बद्ध समस्त प्राथमिक शालाएँ। पूर्व माध्यमिक शाला का प्रधानाध्यापक सभापति। केन्द्रीय उ० मा०

शा० के प्राचार्य को निरीक्षण और पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए एक उप प्राचार्य वेतन मान 400-800 दिया जायगा। कार्यालयीन कार्य के लिए एक गणक तथा एक लिपिक दिए जाने का प्रावधान होगा।

शाला संगम के उद्देश्य—शाला संगम के निम्नानुसार उद्देश्य हैं—

- 1 शालाबा का अलग-अलग दूर करना, उन्हें निबट साना।
- 2 प्रशासन का विके द्रीकरण।
- 3 प्रशासन में कसावट लाना।
- 4 शिक्षा में गुणात्मकता का विकास।
- 5 शैक्षिक व्यवस्था में सुधार।
- 6 शैक्षिक साधना। उपकरणों का समुचित उपयोग।
- 7 पूर्व माध्यमिक शालाओं, प्राथमिक शालाओं का समुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण।
- 8 शालाओं एवं शिक्षकों की कठिनाइयाँ का त्वरित निवारण।
- 9 मिल जुलकर सम्मिलित रूप में सुधार कार्य के लिए प्रारसहित करना।
- 10 आपस में एक दूसरे का सहयोग एवं माय दर्शन देने के लिए प्रेरित करना।

कार्य एवं अधिकार—तीन प्रकार के कार्य एवं अधिकार होंगे।

- 1 शैक्षणिक अधिकार
- 2 वित्तीय अधिकार
- 3 प्रशासनिक अधिकार

(1) शैक्षणिक अधिकार

- 1 एक इकाई के रूप में संगम के सभी स्त्रुता के लिए समान मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण।
- 2 समस्त विद्यालयों में ऐसी सुविधाएँ जो अलग अलग नहीं दी जा सकती हैं उन्हें पूरे संगम के उपयोग हेतु सामूहिक रूप में उपलब्ध कराना। ये सुविधाएँ के द्रीय स्कूल (शाला संगम केन्द्र) में उपलब्ध होंगी, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, फिल्म, आदि। इसी प्रकार प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी गठन केन्द्रों में करना।

मे हागा तथा सगम व अतगन आने वाले सभी स्कूल उसका उपयोग कर सकेंगे ।

- 3 शिक्षका का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शालासगम के केन्द्र पर गोष्ठियाँ आयोजित की जा सकती हैं जिसमें शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है ।
- 4 पूरे सगम स्कूलों के लिए मिल जुलकर एक योजना बनाई जा सकती है जो सभी के लिए समान होगी ।
- 5 आवश्यकतानुसार एक सगम में शिक्षकों की आवश्यकता वाले स्कूल में शिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा ।
- 6 केंद्रीय उ० भा० शाला के प्राचार्य एवं विषय विशेषज्ञ, शिक्षक शैक्षिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उचित निर्देशन की व्यवस्था करेंगे ।
- 7 वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन सभी शालाओं में एक साथ और एक जैसा होगा ।
- 8 सगम के सभी स्कूलों के लिए शाला पंचांग का निर्माण एवं उसके अनुसार छात्रों का आयोजन ।
- 9 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एवं बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार सेवा विभाग के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तनों से शिक्षकों को परिचित कराने हेतु कार्य गण्टिया का आयोजन ।
- 10 नवीन योजनाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग देना ।

(2) वित्तीय अधिकार

- 1 सगम के अतगत आने वाले सभी शालाओं के शिक्षकों के कमचारियों को वेतन वितरण का अधिकार सगम व द्र के प्राचार्यों को होगा ।
- 2 सगम की शालाओं के लिए सामान क्रय करत का अधिकार केंद्रीय प्राचार्य का होगा ।
- 3 टूटी-फूटी चीजों के अपलखन का अधिकार प्राचार्यों का होगा ।
- 4 जन सहयोग्य से वित्त व्यवस्था करना तथा उसके न्यय का अधिकार ।
- 5 आवश्यकतानुसार शिक्षकों का यात्रा भत्ता अग्रिम प्रदान करने एवं यात्राभत्ता देयता को पारित करने का अधिकार शालासगम के केंद्रीय प्राचार्यों का होगा ।

(3) प्रशासनिक अधिकार

- 1—निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार ।
- 2—देशीय उ० मादि के प्राचाय का संगम के अतर्गत आनुवाले शाखाओं के शिक्षकों कमचारियों के नियुक्ति स्थानांतर सम्बन्धा अधिकार होगा ।
- 3—पैक्षिक गारिठिया मे भाग लेन जान के लिए शिक्षकों के भेदन का अधिकार प्राचाय का होगा ।
- 4—एक शाखा से दूसरी शाखा में शिक्षकों का भेदन का अधिकार ।
- 5—शिक्षकों, कमचारियों की शपनाय चरित्तावली लिखन का अधिकार ।
- 6—छुट्टियाँ, अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार ।
- 7—यद्य समस्याएँ एवं प्रकरण निपटान का अधिकार ।
- 8—शिक्षण के लिए संगम की शाखाओं में उपलब्ध सामग्री एवं औता का आदान प्रदान भा प्राचाय कर सकेगा ।
- 9—पैक्षिक धायों में सहायता करन के लिए सहायक शाखा निरीक्षका का सहभाग प्राचाय का प्राप्त रहेगा ।
- 10—शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं शिक्षा के साथ व्यापारिकरण के लिए योजना बनान, योजनाओं का कार्याचयन करन और मूल्यानन आदि के सभी अधिकार शाखा संगम के प्राचाय का हूँगे ।

शाखा संगम से लाभ

- 1—सून्दावन एवं जाँच के लिए उत्तम पद्धतियाँ का मूलगत ।
- 2—सामूहिक मे एमी साधन सामग्री उपलब्ध कराना जा कि अलग-अलग रूप से शाखा को दाना समय नहीं है ।
- 3—उच्चतर माध्यमिक शाखा से विशिष्ट विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था ।
- 4—योग्यता प्राप्त शिक्षकों के लिए सेवा दानीन प्रसि 171 तया कम योग्यता वाले शिक्षकों का स्तर ऊँचा उठाने की व्यवस्था ।
- 5—छुट्टी पर जान वाले शिक्षकों की व्यवस्था ।
- 6—पाठ्यपुस्तकों का चयन एवं मूल्यानन, शिक्षक सङ्गिका बनाना एवं सहायक सामग्री का निमाण ।
- 7—पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना में सुधार ।

8—पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन तथा उनके लिए अनश्लिय रंग-मच उपलब्ध कराना ।

9—अतश्लिय स्पर्धाओं का आयोजन ।

10—अच्छे व्यक्तियों का चुनाव ।

शक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन

- (1) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम पुनरचना ।
- (2) विशेष पाठों के अध्ययन के लिए उपकरणों का निर्माण ।
- (3) सहायक सामग्री का निमाण एवं उसका उपयोग ।
- (4) प्रदर्शन पाठ का आयोजन ।
- (5) नए शिक्षकों को पाठसूत्र एवं तैयारी के लिए प्रेरित करना ।
- (6) नई पद्धतियों का प्रदर्शन ।
- (7) शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक अनुसन्धान ।
- (8) शिक्षकों द्वारा अन्य शालाओं के शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण ।
- (9) शिक्षा आदान प्रदान ।
- (10) उद्योग एवं कला विषयों के शिक्षण का आयोजन ।
- (11) सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु कार्य गोष्ठियाँ तथा सम्मेलन ।
- (12) गृह कार्य सुधार योजना ।
- (13) परीक्षा का आयोजन ।
- (14) विषय समितियों का गठन ।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन

निम्नांकित सहगामी क्रियाएँ आयोजित की जा सकती हैं—

- 1—विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम ।
- 2—अतश्लिय वाद विवाद ।
- 3—अतश्लिय खेलकूद ।
- 4—सांस्कृतिक कार्यक्रम ।
- 5—सम्मिलित रूप से पत्रिका का प्रकाशन ।
- 6—विविध समारोह ।
- 7—राष्ट्रीय पर्व ।

- 8—कायानुभव ।
- 9—वास्तवर ।
- 10—शालेय पत्रिका ।
- 11—शिक्षण, छात्रों द्वारा दृश्यीय स्थानों का भ्रमण ।

उपलब्ध साधनों का विनिमय

- 1—विषय सामग्री ।
- 2—पुस्तकें ।
- 3—खेल-सामग्री ।
- 4—सहायक सामग्री ।
- 5—सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सामग्री ।
- 6—दर्शनीचर ।
- 7—विचार सामग्री ।

इस प्रकार शाला सगम एक ऐसी इकाई होगी जो स्वयं में परिपूर्ण होगी । इससे शैक्षिक कार्य में गति आयगी । प्रशासन सक्षम होगा । सहयोग की भावना का विकास होगा ।

म० प्र० में शाला सगम योजना का प्रयोग

मूलावक सहायता प्राप्त प्रायोजन क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण योजना के क्रिया-व्यय हेतु सन् 1972 में शाला सगम बनाए गए थे, किन्तु उनका वह स्वरूप नहीं था जो होना चाहिए । जैसे ही वह योजना समाप्त हुई शाला सगम भी समाप्त हो गए ।

उसके बाद से आज प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है, अतः पुनः सर्वेक्षण कर पुनः शाला सगम बनाए जाना प्रस्तावित किया गया ।

वर्ष 80-81 में प्रयोग के तौर पर 54 शैक्षिक जिला न से 12 जिला में यह योजना लागू की गई है । प्रयोग के जिले और उनके अन्तर्गत शालाएँ व शाला सगम इस प्रकार है

क्र० जिला शास० उ० मा० शालाएँ पूर्व भा० श० प्रथम० शालाएँ शाला सगम

1— देवास	22	126	664	13
2—सिवनी	27	147	928	23
3—जाजगीर	28	283	1557	32
4—होश गावाड	33	168	965	23
5—दुग	28	190	911	26
6—सतना	42	185	1022	36
7—महासमुद्र	32	221	1574	28
8—शिवपुरी	18	108	643	15
9—टीकमगढ़	19	108	643	16
10—अम्बिकापुर	33	90	754	25
11—राजगढ़	22	122	685	16
12—उज्जैन	33	179	870	25

प्रारम्भ में इन शाला सगमों पर विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। प्रयोग के बाद पूरे राज्य में शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तथा नए परिप्रेक्षा में सर्वेक्षण कर शाला सगमों की स्थापना की जा सकेगी।

म० प्र० में इस योजना के तहत प्रस्ताव है कि प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पोषक माध्यमिक शालाओं की तथा उनकी भी पोषक प्राथमिक शालाओं को मिलाकर एक शाला समुह (स्कूल कॉम्प्लेक्स) बनाया जायगा तथा उसमें स्थित सभी प्राथमिक, मिडिल, तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था का भार शाला सगम के प्राचार्य को दिया जायगा। आसपास जो छोटे उच्चतर माध्य० विद्यालय होंगे वे भी शाला सगम के सदस्य होंगे। विद्यमान जिला शिक्षा अधिकारी और सभागीय शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालयों के बदले हर जिले में एक जिला शिक्षा अधीक्षक रखा जाना प्रस्तावित है जो प्रथम श्रेणी का अधिकारी होगा जो शाला समुह के प्राचार्यों पर नियंत्रण रखेगा तथा उसकी सहायता से पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था करेगा। इस तरह हर राजस्व जिले के लिए एक जिला शिक्षा अधीक्षक होगा। इनका काम देखने के लिए क्षेत्रीय समुक्त सनातन होंगे। वर्तमान सभागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय समाप्त होंगे। सहायक जिला शाला निरीक्षक जो अभी तक शिक्षक के स्तर के होते हैं वे व्याख्याता के स्तर के होंगे तथा उनका नाम प्राथमिक तथा

माध्यमिक शालाआ का नियमित तथा लगातार निरीक्षण करना होगा। इन निरीक्षण प्रति वेन्ना के आधार पर व्यवस्था तथा पढाई के स्तर में सुधार करने की जिम्मेदारी शाला सगम के प्रधान प्रचार की होगी।

सनकता—शाला सगम की विभिन्न शालाआ में मंठेय होने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं—

- (1) किसी प्रकार का तनाव का वातावरण न बन।
- (2) मित्रता का भावना के साथ माग दर्शन।
- (3) निरीक्षण अधिकारी के रूप में काय न किया जाय।
- (4) शिक्षका में विश्वास और सद्भाव पैदा किया जाय।
- (5) आपस में मधुर सम्बन्ध रह।
- (6) छार-छारे और प्रभावपूर्ण ढंग से काय किया जाय।
- (7) रुचि और उत्साह बंध भर बना रहे।
- (8) योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके।
- (9) अधिक लिखा पढी और कठोरता से काम न लिया जाय।
- (10) कम से कम आर्थिक भार शालाआ पर डाला जाय।

होशंगाबाद विज्ञान योजना

(Hoshangabad Science Project)

पृष्ठभूमि—सभी ओर स शिक्षा में परिवर्तन की मांग जो पकड़ रही है। परम्परागत शिक्षा और प्रणाली से कोई संतुष्ट नहीं है। कुछ विद्वान आज की शिक्षा का व्यावहारिक बनाने की कहते हैं और कुछ व्यावसायिक। पुस्तकीय ज्ञान को निरर्थक माना जान लगा है। एक वग की राय तो यहां तक है कि तकनीकी शिक्षा की निरर्थक है। कसा के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्ति तो बेकार हैं ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी नौकरी की तलाश में है। दुख तो उस समय होता है जब मशान बिजली तथा विभिन्न उद्योगों से सम्बंधित तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति स्वतः व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और मामूली से नौकरों के लिए हाथताबा मचाने हैं। इन सबके मूल में शिक्षा की गलत पद्धति है। जिस तरह कला मूह के छात्रों का व्याख्यान देकर शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा भी भाषण द्वारा दी जाती है। हमारे बालक विज्ञान की शिक्षा का रट लेते हैं। पढ़ के कितने भाग होत है, फूला के कितने अंग होत है, किसी चीज का बनावट कैसा हानी है? इन सबके बारे में हम बालकों को रटवा देते हैं। आक्सोजन का निर्माण लैड आक्साइड (सीसे के आक्साइड) से होता है। कभी कभी बालक सास का सासा रटकर उसका पर्याय कांच भी रट लगा है और जत में “कांच का गम करके आक्सीजन बनती है” यह गलत धारणा उसे रह जाती है। ज्यामिति की आकृतियाँ हमने कागज पर ही डाइग बक्स के सहारे बच्चों का सिखाई हैं कभी उनका उपयोग या व्यावहारिक रूप में उन्हें बड़ होने में बनाने की बात नहीं समझाई और न ही उनके अनुभवों का कुरेदा कि वे कुछ उसके आधार पर ही जिज्ञासा का उत्तर दे सकें। परिणाम यही हुआ जो हमारे सामने है कि ज्ञान का रटकर भाषण तो दे सकते हैं लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपंगु हैं।

दश की परम्परागत शिक्षा ने विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। भारत में उपाधि प्राप्त वैज्ञानिकों का संख्या विश्व में तीसरे नम्बर पर है किन्तु वैज्ञानिक खोज करने वाला न भारत का स्थान साठवें नम्बर पर था नहीं है। विज्ञान शिक्षण का वर्तमान पद्धति से समा का पीछा होना अनि-

वर्ग है। शिक्षा में परिवर्तन की बात तो बड़े-बड़े मनीषी और जन नेता तो करते हैं लेकिन परिवर्तन जिस दिशा में और क्या है यह सही रूप में किसी ने भी नहीं सुझाया। हमारे सामने आज भी शिक्षा के बारे में अनेक प्रश्न हैं यथा रटकर परीक्षा देने के बाद उन तथ्या की जीवन में साक्षरता क्यों नहीं रह जाती है? बच्चे को क्या विज्ञान के क्या रटना पड़ता है जो उनकी भावी जिंदगी में काम नहीं आता है? उस ज्ञान से क्या लाभ जिससे व्यावहारिक समस्याएँ न सुलझाई जा सकें। प्रारम्भिक शिक्षा में विज्ञान की पढ़ाई की पद्धति का सर्वेक्षण एवं विवेचन करने पर ये प्रश्न उभरकर सामने आए कि बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास क्यों नहीं होता है? रटने और समझ का कोई सम्बन्ध नहीं है। उस शिक्षा का क्या लाभ है जो शाला की पहारदीवारी में प्राप्त होकर वास्तविक जीवन में अनुभवों से दूर है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो बड़ा एवं मे भर्ती होत हैं उनके 70-80 प्रतिशत बालक कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पूर्व छात्र छोड़ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम केवल 20 प्रतिशत बालकों के लिए ही आज की शिक्षा का लाभ आम कर रहे हैं। 80 प्रतिशत बालकों के लिए हमने कुछ नहीं साधा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम शिक्षा के उद्देश्य पुनः परिभाषित करना होंगे। विज्ञान की शिक्षा द्वारा बालकों में ऐसे कौशल और अभिवृत्तियाँ का विकास करना होगा जिससे वे अपने परिवेश और अनुभव में सही शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो उनके जीवन में काम आ सके।

होशंगाबाद विज्ञान की शुरुआत—इस तरह के ढेर मारे सवालियों का हल खोजने के लिए डा० अनिल सदगोपाल और उनके सहयोगियों ने म० प्र० में एक प्रयोग प्रारम्भ करने का निणय लिया ताकि शिक्षक या पुस्तक के द्वारा प्रश्न और उत्तर एक साथ देकर चिंतन व विचार को बूझित कर देने वाली पद्धति से हटकर विज्ञान पढ़ाने की एक ऐसी पद्धति विकसित हो सके कि विज्ञान के सवाल बच्चों के सामने एक आरंभिक सीमा तक तो दूसरी ओर उच्च प्रश्नों से पूछने की प्रेरणा मिल सके। होशंगाबाद जिले का दो स्वेच्छिक मत्स्याई-फ्रेंड्स रूरल सेंटर (Friends Rural Centre) रमूलिया और विशोर भारती बलदेवी सामने आई। विज्ञान पढ़ाने की खोजपूर्ण प्रयोग निष्ठा और पर्यावरण पर आधारित पद्धति का विकसित करने का इहो न बोधा उठाया।

सन् 1972 में रमूलिया और विशोर भारती ने मिलकर एक पुस्तक तैयार कर फरवरी 1972 में लोक शिक्षण संचालक म० प्र० को प्रस्तुत किया। बच्चे स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करें, प्रयोगों को अवलोकन करें और

लियें। फिर उन अवलोकन के आधार पर अपने साधियों और शिक्षकों से चर्चा करके स्वयं ही मुक्त रूप से निष्कर्ष निकालें। छात्रों को शिक्षक से सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाय और उन सवालों का हल छात्रों के लिए उचित प्रयोगों की रचना करने के लिए सक्षम बनाया जाय। शिक्षक की भूमिका सर्वज्ञाता होने के बजाय, प्रश्ना सोत, मार्ग-दर्शक व सहयोगी जैसी होनी चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परम्परागत, छात्र शिक्षक सम्बन्ध, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धति यदि बदलने पड़े तो उसकी भी तैयारी हो। परीक्षा सेन का उग भी बदल दिया जाये। प्रस्तुत प्रस्ताव में सरकारी स्कूलों की छान्चि में इस अभिनव प्रयोग का करने की पूरी स्वतन्त्रता की अपेक्षा की गई।

म० प्र० राज्य शासन ने होशंगाबाद जिले के सोलह स्कूलों में इस प्रयोग को करने की अनुमति प्रदान की। इनमें से नौ स्कूल रमूलिया के आसपास हाशंगाबाद इलाका में गये और सात स्कूल किशोर भारती के आस-पास यन्वेडी ब्लाक में। इस प्रयोग का प्रारम्भ करने की प्रमुख भूमिका अखिल भारतीय विधान शिक्षण संघ (भौतिकी अध्ययन ग्रुप) और टाटा इस्टोडियट्स आफ फंडामेंटल रिसर्च (भारत सरकार) बम्बई के शिक्षका, वैज्ञानिकों और गांधी छात्रों ने निभाई। इस कार्य के लिए मई 1972 में उन्मुखीकरण हेतु 40 शालेय शिक्षक चुने गये। ये शिक्षक अधिकांश हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्तर के और कुछ स्नातक। अधिकांश शिक्षकों का माता विज्ञान विषय नहीं था या था तो उससे काफी दिना से सम्बन्ध टूट चुका था। प्रारम्भ में शिक्षका ने प्रश्न पूछने में शिक्षक दिखाई लेकिन बाद में वे खुलकर चर्चा करने के लिए आश्वस्त हो गए। ऐसे शिक्षकों का शिविर अपने आप में एक बड़ी और अभूतपूर्व घटना थी। इस उन्मुखीकरण शिविर में खोजपूर्व एवं प्रयोग निष्ठ विधि अपनाई गई। शालेय शिक्षका ने वैज्ञानिकता, शिक्षाविदों और गांधी छात्रों के साथ विज्ञान के प्रयोग किए और गहन चर्चा की। एक प्रयोग किया गया। एक पौधे की टहनी काटकर लाल स्याही के घोल में रखी गई। लगभग आधे घंटे बाद पत्तियों की शिराएँ लाल होने लगीं। यह देखकर शिक्षक न दा० अनिल सदगोपाल जी से पूछा कि यदि नीली स्याही के घोल में टहनी रखे तो क्या होगा। दा० अनिल जी ने वज्रिष्ठ उत्तर दिया कि “मुख नहीं मालूम—इसके लिए तो प्रयोग ही करना होगा।” उन शिक्षक ने तत्काल कहा, “तो फिर आपको पी० एच० डी० कैसे प्राप्त हो गई।” वस्तुतः इस घटना से शिक्षका का भी यह बात समझ में आई कि उन्हें भी बख्श में ऐसी

स्थिति में बच्चों के सामने यह मानना पड़ेगा कि “मैं नहीं जानता, पर आओ इसका उत्तर मिलकर खोजा जाय।”

ग्रामीण शालाओं में होशंगाबाद विज्ञान के प्रयोग—शिक्षकों के उन्मुखीकरण के बाद जुलाई 1972 से साल्ट शासकाय मिडिल स्कूलों में इन प्रशिक्षित शिक्षकों ने नए ढंग से विज्ञान पढ़ाना प्रारम्भ किया। उह प्रयोग हेतु एक उपयुक्त किट दी गई। बच्चे चार-चार का टोलिया में बटकर प्रयोग करते और शिक्षकों के साथ भ्रमण भी करने। लगानार प्रश्न और उत्तर का सिम सिला जारी रहना। प्रशिक्षण देने वाल समूह के सदस्य बराबर समय समय पर शालाओं में जात और कक्षा की परिस्थिति में बच्चा और शिक्षकों की कठिनाइयों को समझने व उनको हल करने के सुमाव रखन। प्रयोगनिष्ठ विधि से सम्बाधित सर समस्याओं, बच्चा और शिक्षकों के सुझावों और अन्य जानकारी को भी इकट्ठा किया जाता था। स्कूल अनुवर्तन (Follow up) की यह प्रक्रिया और जानकारी एवं सुझाव, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का एक आवश्यक अंग माना गया और साथ-ही-साथ इन अनुभवों, जानकारी एवं सुझावों का उपयोग पुस्तक, किट व प्रशिक्षण विधि के विकास में किया गया।

सामान्य हमारी प्रचलित पाठ्यपुस्तक शहरो में बैठकर नगराव परिवेश के आधार पर लिखी जाती हैं लेकिन इस कार्यक्रम में कार्य-पुस्तक, किट और शिक्षण विधि उही परिस्थितियों में तैयार किए गए जिनमें विद्यार्थी व शिक्षक थे। छोटे-छोटे यह अनुभव हुआ कि विज्ञान का जो हम होवा समझ बैठे थे वसा नहीं है। विज्ञान की शिक्षा न ता विदगी है और न महगी है। विज्ञान तो हमारे परिवेश के आस-पास ही घना, जगना, नदी, नाला, पहाड़, अम राइया में बिखरा पड़ा है जो उहाने खोज निकास। इस प्रकार साल्ट स्कूलों में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण जारी रहा और विज्ञान शिक्षा के सापनाओं तक अनवरत दीठ रूप जारी रही।

होशंगाबाद विज्ञान का विस्तार—सन् 1973 के प्रारम्भ में त्रिन्को विश्व-विद्यालय और इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (बानपुर बम्बई) के वैज्ञानिक और ग्नेय छात्र भी इस याजना में जुड गए। त्रिन्को विश्वविद्यालय की टीम का इस कार्य में सम्बद्ध हान के लिए विश्वविद्यालय अनुमान आयोग ने विनीय सहायता दी। देश की शिक्षा व इतिहास में यह प्रथम मुखवसर था जब यह बाव व्यावहारिक रूप में स्वीकार का गई कि स्कूलों स्तर पर और यह भी गाँव के स्कूलों में, शिक्षा में परिवर्तन और सुधार के लिए विश्व-विद्यालय के सापा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वविद्यालय अनुमान के इस

पहले से म० प्र० शिक्षा विभाग ने भी अपने महाविद्यालयों के शिक्षकों को इस कार्यक्रम से जुड़ने की अनुमति प्रदान की। पिछले तीन वर्षों से छण्डा, धार, रामपुरा और बड़ानी के शासकीय महाविद्यालयों के कुछ अध्यापकों ने शालेय अनुवर्तन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। अक्टूबर 1977 में शिक्षा विभाग ने एक उत्साह प्रार्थनापत्र का उनके महाविद्यालयों से इस कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधित्व पर भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस प्रार्थनापत्र को तीन वर्षों की "टीचिंग फ्लोशिप" देकर उच्च शिक्षा की सामाजिक साधना के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया।

इस कार्यक्रम में ठोस परिणाम और नए नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षण पद्धति के विकास का क्रम जारी है। सन् 1977 के अक्टूबर में एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली और सोसायिटी सचालनालय के संयुक्त तत्वावधान में कियार भारती में एक कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में अनेक देशों के लगभग 40 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। इन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठकर यह तय उद्देश्य रखा कि गाँव की परिस्थितियों में वहाँ के कार्यकर्ता समाज सेवक और शिक्षक आपस में मिलन वाली भावों से पढ़ाई का रोचक बनाने वाली शिक्षण सामग्री बना सकें हैं। उद्देश्य नए साधनों का निर्माण भी किया और ग्रामीण पर्यावरण का जबदस्त संभावनाओं को उद्देश्य रखा।

1977 में यह प्रश्न सामने आया कि परम्परागत शिक्षा प्राप्त बालक और प्रयोग निष्ठ विधि से पढ़ाए गए बालक के ज्ञान सचय में कोई अन्तर तो नहीं है? आँकड़ा के सफल और विद्वान से पात हुआ कि प्रयोगनिष्ठ विधि में शिक्षित बालक, परम्परागत विधि से शिक्षित बालकों की तुलना में ज्ञान सचय की दृष्टि से किसी भी विषय में पीछे नहीं रहे। इस विधि से विद्यार्थियों में न केवल विद्यार्थी अपनी तकशक्ति, अवलोकन क्षमता, कल्पना-शीलता आदि गुणों का विकास किया वरन् साथ-साथ स्वयं ज्ञान अर्जित करने के तरीके भी साध लिए। प्रयोगनिष्ठ विधि का सफलता का इस मूल्यांकन को कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया।

सन् 1976-77 से विश्व भारती, बनारस और फ्रेडस रूरल सन्टर रमूलिया के कार्यकर्ताओं और शिक्षा विभाग म० प्र० ने विचार किया कि जब तक इस प्रयोग का अर्थ शासकीय शालाओं में लागू न किया जाय तब तक इसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व स्वीकार नहीं हो सकता है। प्रश्न सामने यह था कि ऐसे माध्यम और निष्ठावान व्यक्ति या इसी प्रयोग के लिए समर्पित हो वहाँ से आये। 1977 अक्टूबर, एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली तथा

शिक्षा विभाग म० प्र० के अधिकारियों तथा रमूलिया और किछोर भारती संस्थाओं के विज्ञान प्रशिक्षकों ने शासकीय तल के अंदर ही निष्ठावान और सक्षम कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करवा के नियुक्त किए। छात्र पुष्पा को, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाया, शासकीय महा विद्यालया, विश्वविद्यालया से लिया जाय तथा ये 40-50 छात्र पुष्पा होशंगाबाद जिले के सभी मिडिल स्कूलों में इन पद्धति का प्रेक्षण के लिए भेज दिये जायेंगे साथ में इस कार्यक्रम से सम्बद्ध पुगना विज्ञान शिक्षण दल भी रहेगा। दूसरा एक कार्यकारी समूह (Working group) का भी गठन किया जाई जिसमें होशंगाबाद जिले के ही २० मा० विद्यालयों के शिक्षक, सहायक शिक्षा शाखा निरीक्षक और मिडिल स्कूलों के कुछ प्रधानाध्यापक शामिल किए गए। कार्यकारी समूह का प्रमुख कार्य शालेय अनुवर्तन, कक्षा की परिस्थिति में शिक्षक की समस्याओं को सुलझाना और नए सुझावों को इकट्ठा करना होगा। इस प्रकार काठारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर म० प्र० ने प्रथम बार विश्वविद्यालय स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूलों तक एक साधा मूल स्थापित किया गया।

शिक्षा विभाग म० प्र० एवं एन-साई-आर-टी० नई दिल्ली, ने जुलाई 1978 से होशंगाबाद जिले के 206 मिडिल स्कूलों में बच्चा को प्रयोगनिष्ठ विधि से विज्ञान शिक्षण देने का नियुक्त किया। लोक शिक्षण संचालनालय म० प्र० ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुवर्तन का वित्तीय भार उठाया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ने विज्ञान के क्विज देने का नियुक्त किया तथा भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों को इस कार्यक्रम में जुटने के लिए पांच साल का एक बजट आवंटित किया। म० प्र० पाठ्य पुस्तक निगम ने पिछले 6 वर्षों से सहायित का गई एक नए ढंग की पाठ्यपुस्तक को होशंगाबाद जिले के लिए विशेष रूप से प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया।

होशंगाबाद पद्धति—बच्चे अपने हाथ से विज्ञान के प्रयोग करते हैं और उन पर अपने सॉल्यूशंस तथा जिज्ञासा से चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका प्रेरक, मार्गदर्शक तथा सहायकी की तरह है। शिक्षक अपना ओर से बच्चा को कुछ भी नहीं बताते हैं। इन विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकें में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसे बच्चे रट लें। बच्चा स्वयं कर्ता है और सीखता है। इसे प्रयोगनिष्ठ विधि कहा गया है। इस प्रयोगनिष्ठ विधि के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, कक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली विकसित की गई है। इनका होशंगाबाद पद्धति या प्रायोजन के नाम से

जाना जाता है। होगयावाद प्रायोजना के जनक डॉ० अनिल सदगोपाल का कहना है कि प्रयोग कर रहे बच्चे ज्ञान की दृष्टि से पाछे नहीं हैं वरन् इस समय उनमें अभिव्यक्ति की कुछ कमी है। हमने प्रयोगनिष्ठ विधि को अपनाया है। इस विधि में परम्परागत विद्यालयों का भाति शिदाव अपनी ओर से कुछ नहीं बसायगा वरन् छात्र स्वयं प्रयोग करेंगे और कारण समझन का प्रयास करत हैं। य बच्चे चूँकि प्रयोग करवे सापत्त हैं अतः वे जानत सब कुछ हैं। उनमें ज्ञान तो अधिक है केवल वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमने परम्परागत विद्यालयों में अपनाई जाने वाली उस पद्धति को छोड़ दिया है जिसमें शिक्षक का शब्दों का या पुस्तक की भाषा को रटकर बच्चे बताने लगते हैं। परम्परागत शास्त्रों के बच्चे जब रटी हुई बात को दुहराते हैं तो हमें भ्रम होता है कि उनका ज्ञान में वृद्धि हुई है। अगर हमने परम्परागत पद्धति से हटकर बच्चा के ज्ञान की जाँच का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से ज्ञान नए बच्चा के ज्ञान से हम सतुष्ट हो जात। ज्ञान और अभिव्यक्ति में सम्बन्ध अवश्य है लेकिन अभी प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था है कुछ वर्षों में अभिव्यक्ति की कमजोरी भी मिट जायगी।

होगयावाद विज्ञान पद्धति करके सीखने के विद्वान्त पर आधारित है। है। हमारा सम्पूर्ण प्रयोग पूर्ण अनुभव, पूर्ण पर्यावरण तथा पूर्ण ज्ञान के सूत्र पर आधारित है। प्रयोगनिष्ठ विधि में केवल प्रयोग ही नहीं होत वरन् ध्यानशक्त्यानुसार हम अवलोकन और भ्रमण भी कराने हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस धारणा को तोड़न का प्रयत्न इस पद्धति और प्रायोजना में किया गया है।

पाठ्यपुस्तकें बनाने का यहाँ एक तरीका अपनाया गया है। विज्ञान शिक्षण दल, बच्चों और शिक्षकों से संसक्तता है, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए पुस्तकें में सुधार करत हैं। जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति ठीक तरह से नहीं होत लगती है जिसकी प्राप्त करन के लिए पाठ लिखा है तब तक लगातार संशोधन किया जाता है। विशार भारती में जाकर कोई भी इस प्रक्रिया को देख सकता है।

होगयावाद प्रायोजना में कक्षा ॥ से सभी प्रयोग अवलोकन पर आधारित है। कक्षा 7 से बच्चों में चिन्तन विकसित करन का प्रयास किया जाता है। कक्षा 8 में अधिक प्रियास किया जाता है। अभी इस प्रयोग को प्राथमिक स्तर पर प्रारम्भ करने में कुछ कठिनाई है। डॉ० अनिल ने बताया कि उनका सम्बन्ध टाटा इन्स्टीट्यूट बम्बई से है। वहाँ माध्यमिक स्तर के बच्चों

पर ही प्रयोग किया गया है, अतः उसका ही अनुभव यहाँ उपयोग किया जा रहा है। दूसरे प्राथमिक स्तर के बच्चे आयु में छोटे होते हैं अतः उनसे साथ प्रयोग करने में कठिनाई हुई। उन बच्चों का पढ़ाने के लिए अभी हमारे पास कौशल नहीं है। प्राथमिक शालाओं में अधिकांश गरीब बच्चे रहते हैं अतः हमें पहले गरीबी से जुड़ना होगा और अभी हम तत्काल वैसा नहीं कर पा रहे हैं।

करके सीखने का सिद्धांत हम बहुत पहले जानते थे और उससे महत्व की भी जानकारी थी। किन्तु अभी तक प्रशिक्षण मस्थाओं में इससे महत्व पर ध्यान देना नहीं रहे इसे व्यवहार में कभी नहीं लाए। 'करके सीखा' के सिद्धांत को होशंगाबाद परियोजना में मूर्त रूप दे दिया गया है। इस प्रयोग से हम इतने चमकते हुए कि इसे एक नवीन पद्धति, अनूठी पद्धति और नवाचार कहेंगे। वास्तव में यह विधि नई नहीं है हम सभी जानते थे और ध्यान देते थे। उस्ताही शिक्षक यदा-कदा इसके द्वारा कक्षा में विज्ञान शिक्षण भी करते थे। यह तो पुरातन विधि है इसका केवल प्रयोग नया है। इस प्रयोग से एक बात स्पष्ट हो गई है कि ध्यान या पुस्तक पढ़ने से या पढ़ाने से सही शिक्षण नहीं हो सकता है धन बच्चा स्वयं करे और सीखे अर्थात् कर्म और ज्ञान साथ-साथ चले। कर्म रूपी ज्ञान में ज्ञान रूपी ज्ञान साथ-साथ जुना जायेगा तभी शिक्षा रूपी सुंदर वस्तु बन कर तैयार होगी।

होशंगाबाद पद्धति की कार्य विधि, समस्याएँ व चुनौतियाँ—होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर 1980 तक लगभग डेढ़ वय पूरा कर चुका है। इस अवधि में अनेक समस्याएँ और चुनौतियाँ भी आई हैं। एक प्रशिक्षण शिविर जून 1978 में होशंगाबाद में आयोजित किया गया। इस शिविर में कार्यक्रम से पहली बार जुड़ने वाले छात्र दल के सदस्यों का उद्घाटन किया गया। इससे बाद जुलाई 1978 में जिने भर के लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक और कार्यकारी दल के लगभग 100 सदस्य नमदा महाविद्यालय में विचार-विमर्श हेतु एकर हुए। इन दोनों शिविरों में मूलतः और किशोर भारत के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रोजनस कापज कोषाल शास्त्रीय महाविद्यालय के विज्ञान विभाग के छात्र प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। उसके बाद कई शिविर और ह्रा चुके हैं। होशंगाबाद शिबि के 500 से अधिक शिक्षक प्रयोगनिष्ठ विधि से विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

एन-सी-ई आर टी० से प्राप्त विट्स के वितरण तथा विज्ञान गोलियों के लिए जिने की ग्यारह उच्चतर माध्यमिक शालाओं को संयम कर बनाया

गया है। इन संगम केन्द्रों तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों, सहायक जिला शाला निरीक्षकों तथा मिडिल स्कूलों के प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों के बीच क्षेत्रीय स्तरों का लेकर सम्पर्क एवं सवाद का वातावरण बन चुका है। कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक शैक्षणिक जिम्मेदारों को भी जोड़ा गया है।

होशंगाबाद विज्ञान के विस्तार में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे किट्स का समय पर न मिलना। प्रयोग की कक्षा 1 स 11 तक विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान के सस्ते किट्स तैयार किए जाय, कुछ वहाँ किए भी गए हैं। शाला संगम योजना से भी उपकरणों की समस्या हल की जा सकती है। शिक्षकों के प्रशिक्षण भी गंभीर योजना बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो सकती है।

कहना न होगा कि डा० अनिल सदगोपाल जी तथा उनके साथियों ने अपने अथक परिश्रम, लगन और साधना में होशंगाबाद जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अनुकरणीय कार्य करके अथवा शिक्षकों के लिए मार्ग प्रशस्त करे।

विज्ञान की नई पद्धति के आकषण

- 1—बच्चों की सीखों पर आधारित,
- 2—वातावरण और अनुभवों पर आधारित
- 3—बालक की अहम भूमिका।
- 4—शिक्षक का तटस्थ रहना कि तु मागदर्शक के रूप में।
- 5—शाला-विद्यार्थियों को वापिस शाला लाने में सहायक।
- 6—शिक्षा के आधुनिक परिवर्तन में सहायक।
- 7—विज्ञान का ग्रामीणीकरण।
- 8—बालकों की जिज्ञासा का समाधान।
- 9—बालकों की तत्काल शक्ति को उभारना तथा अध्ययन में नई रचरता लाना।
- 10—विज्ञान की सस्ती और सहज प्रणाली।
- 11—बालकों में नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
- 12—बालकों का पूरी स्वतन्त्रता।
- 13—शालाओं की उदासी खत्म होकर मुखर वातावरण।
- 14—प्रयोगनिष्ठ विधि द्वारा समस्त विषयों का शिक्षण।

15—बालका में बौद्धिक का विकास ।

विज्ञान की परम्परागत शिक्षण पद्धति और नवीन पद्धति में अंतर

पहले विज्ञान की शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका अधिक था । शिक्षक प्रयोग करके दिखाता था और छात्र मान लिया करत थे कि जो कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वही ठीक है । उसमें छात्र को दखन का कम अवसर था । सदाहरण के लिए शिक्षक ने बताया घुम्बर में दो ध्रुव होते हैं तो बालक ने मान लिया । अब नई पद्धति में स्थिति भिन्न है छात्र घुम्बर के साथ खेलगा, उपडोषा और उसके बारे में बड़ी जानकारी प्राप्त करेगा । नई विधि में शिक्षक की भूमिका अहम् नहीं है, शिक्षक तटस्थ है । वह केवल प्रयोग करते हुए बालक का यदि वह वहाँ दृष्ट रहा है तो इसका मान करेगा कि छात्र अपना प्रयोग सहो कर, सके । किसी योजना का पता तत्काल नहीं मिलता आने वाली पीढ़ियाँ में मिलगा । अभी बहुत कुछ जानना है । इस नई विधि में बच्चे विशेषता से भी एक बंदम आते हैं । प्रयोग निपट विधि की कसौटी शिक्षक और बच्चा है । लोग न विज्ञान को अच्छा और हीवा बना दिया है । जब हम कहते हैं कि बच्चा को विज्ञान सिखाना है तो एक चिन्तन बनता है प्रयोगशाला का, क्योंकि बिना इसके पढ़ाएँ कैसे ? हमारे यहाँ छात्र तब करेंगे जब महंग उपकरण हा, काफी पैसा हो, लेकिन सी० वी० रमन, बमू जैसे वैज्ञानिकों ने मामूली उपकरणों से खोजें की । सोखने के सस्ते और सरल तरीके हैं । खेती की सारी प्रक्रिया विज्ञान से भरी हुई है । जो होवा विज्ञान का हमारे भीतर बिठा दिया गया है उसे भगाना है । हम गरीब देश के निवासी हैं, इसलिए यह कहना कि हम विज्ञान नहीं साध सकते, गलत है । हम सस्ते उपकरणों से नया विज्ञान पैदा करेंगे, सीखेंगे, यही नई पद्धति की प्रमुख विशेषता है ।

शालेय शिक्षा से सम्बन्धित यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजनाएँ (Unicef Projects Relating to School Education)

आज के इस युग में इस विश्वास को सारे विश्व के लोग ने स्वीकार किया है कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन शिक्षा है। शिक्षा से एक नैतिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक किन्तु रक्तहीन क्रांति संभव है। तन्नुसार भारत, शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं विस्तार हेतु सतत प्रयत्नशील है।

भारत स्वतन्त्र होते ही हमने संविधान की धारा 45 में यह स्वीकार किया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चा का अनिवार्य रूप से शालाओं में शिक्षा द्युलामा जाय और उन्ह नि शुल्क शिक्षा दी जाय। यह संवैधानिक दायित्व 1960 तक पूरा हो जाना चाहिए था। कि तु वतमान में हमारे देश में 6-11 आयु के शाला में दर्ज बालक-बालिकाओं का प्रतिशत 83 है और 11-14 वर्ष के बालक-बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 37 है। 50 प्र० में इन्ही आयु वर्गों में दर्ज सद्यः प्रतिशत क्रमशः 63 और 30.5 है। 50 प्र० में शिक्षा के लिए व्यापीकरण की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है।

शाला न जान वाले छात्रों में अनुसूचित जाति, जन जाति ग्रामीण अंचल के बालक तथा बालिकाएँ अधिक हैं। अनेक प्रयासों के बावजूद भी हम प्राथमिक शिक्षा के सावधानीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बालक सावधानीमय शिक्षा समस्या के केंद्र बिंदु हैं। प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और उसके सत्यात्मक तथा गुणात्मक सुधार के लिए बहुत आयासी प्रयास किए जाते हैं। पाठ्यक्रम नवीनीकरण, पाठ्यपुस्तकों में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, औपचारिकतर शिक्षा व्यवस्था, बहुत बिंदु प्रकाशित अनेक कार्यक्रमों के द्वारा हम प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

‘यूनीसेफ’ भारत में शिक्षा के गुणात्मक विस्तार और विकास के लिए अनेक शैक्षिक प्रायोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। पक्षों प्रायोजनाएँ प्राथमिक शिक्षा के मास्टर प्लान के परिच्छेद छह में सम्मिलित हैं और यह परिच्छेद भारत शासन और यूनीसेफ द्वारा स्वीकृत दस्तावेज है।

राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रायोजनाओं का संचालन राष्ट्रीय नैतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, करती है। मध्य प्रदेश में ये प्रायोजनाएँ शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान व मार्फत संचालित हैं। मध्य प्रदेश में यूनाइटेड का सहायता ने पाँच प्रायोजनाएँ शिक्षा के गुणात्मक एवं सञ्चालक मुद्दों की शिक्षा में कार्यान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के लोक व्यापकता की दिशा में बहुमुखी प्रायोजनाएँ समस्या के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक आधार पर प्रारम्भ की गई हैं।

प्रदेश में इस प्रकार की संचालित प्रायोजनाएँ इस प्रकार हैं—

- 1—प्रायोजना क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण।
- 2—प्रायोजना क्र० 2—प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण।
- 3—प्रायोजना क्र० 3—नामुदायिक शिक्षा एवं सह्याय का विवासात्मक गतिविधियाँ।
- 4—प्रायोजना क्र० 4—प्राथमिक शालाओं में पोषण स्वास्थ्य एवं परिवेश स्वच्छता शिक्षा।
- 5—प्रायोजना क्र० 5—प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम।

प्रायोजना क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण

यह योजना म० प्र० में 1972 से एन-सी-ई-आर टी० के माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। प्रदेश में यह प्रायोजना राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित की गई। यह प्रायोजना मुख्यतः विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास की दिशा में अग्रसर रही। जब विज्ञान का नवीन पाठ्यक्रम राज्य की प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में लागू किया गया तो प्रारम्भिक शालाओं के शिक्षकों में इसे कार्यान्वित करने की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न करने की एक गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। इस समस्या का मुलुखान के लिए विभाग द्वारा विज्ञान प्रशिक्षण की एक वृहद् योजना तैयार की गई और जुलाई 1972 में राज्य के लगभग 150 लाख शिक्षकों को विज्ञान प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया गया।

उद्देश्य —प्रायोजना के प्रमुख उद्देश्य ये थे—

- 1—विज्ञान शिक्षा का पुनर्गठन और विस्तार।
- 2—विज्ञान शिक्षक की प्रभावशाली बनाना।
- 3—पाठ्यक्रम का समुन्नत करना।

4—पाठ्यपुस्तको, शिक्षकों, प्रयोगशालाआ की विज्ञान शिक्षण हतु व्यवस्था करना ।

5—विज्ञान शिक्षा का गुणात्मक विकास ।

योजना का क्रियाचयन

1—यह योजना चार चरणों में क्रियावित की गई । प्रत्येक चरण में 10-12 जिले लिए गए । याजना के अ चर्गत प्रत्येक जिले की शाला सगमा म विभक्त किया गया था । एक शाला सगम में 100 125 शिक्षक बायरत थे । । शाला सगम का केद्र एव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बनाया गया और उसके आस-पास की पूव माध्यमिक और प्राथमिक शालाआ का उससे सम्बंध किया गया ।

2—शाला सगम केन्द्र के विज्ञान व्याख्याताआ का राज्य विज्ञान सस्थान एव अ य शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम से उमुखाकृत किया गया जिहाने ज्ञात पुरुषा के रूप में काय किया ।

3—प्राथमिक एव पूव माध्यमिक शालाओं के प्रत्येक शिक्षक का पूरे एक वष तक विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 10 माह पलाचार पाठ एव उनके अध्ययन में प्रत्येक माग दशन तथा सगमग डेड माह सस्था प्रशिक्षण शामिल हैं ।

4—शाला सगम केन्द्र के प्राचार्य एव ज्ञोत शिक्षका की मानदेय की व्यवस्था का मुख प्रावधान है ।

5—जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उह प्रमाण पत्र तथा 50 रुपये नगद पुष्कार दिया जाता है ।

प्रगति—यह प्रायोजना विभिन्न चरणों की पूरी करती हुई प्रदश के समस्त प्राथमिक आर पूव माध्यमिक शालाआ म पहुँच चुकी है । यह प्रायोजना अपनी पूणता पर है ।

प्रयोजना क्र० 2 प्राथमिक शिक्षा पाठयक्रम नवीनीकरण (PECR)

(Primary Education Curriculum Renewal)

अनेक प्रयासों के बावजूत भी हम सावमीमिक शिक्षा के सदय का प्राप्त नहीं कर सकें । इसका मुख्य कारण यह रहा कि जो शिक्षा हम बालका को देने आए हैं वह बालक तथा समाज की आकाक्षाआ एव आवश्यकताआ से जुडी हुई नहीं थी । बदलत समय और परिवेश में अब हमे इसकी आर ध्यान देना है ।

पाठ्यक्रम का नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। देशीय सुविधाओं के फैलाव एवं प्रसार के साथ-साथ पाठ्यक्रम का गुणात्मक नवीनीकरण एवं विकास आवश्यक है। बालक की जीवन पद्धति एवं उसे प्राप्त सामाजिक, आर्थिक अवसरों से इस पाठ्यक्रम का तालमेल मिलना अत्यंत आवश्यक है। यत यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम बालक के जीवन, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं तथा समाज में उसके जीवन सम्बन्धी समस्याओं पर आधारित हो। अन्य विषयों के प्रति-रिक्त पापन आहार, परिवेश की स्वच्छता, नागरिक सहभागिता एवं मांगान आदि का समावेश हो। परिणामस्वरूप ऐसे पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में स्थानीय बुनियादीकरण एवं स्थानीय आवश्यकताओं का भी सम्मिलित करना आवश्यक है।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने कहा है कि शिक्षा को व मूल सत्य प्राप्त करना चाहिए जा—

(अ) उत्पादकता में गह्राव हो।

(ब) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकाता को शक्ति प्रदान करें तथा प्रजातन्त्र का शक्तिशाली बनाएँ।

(स) आधुनिकता की गति में तबो साए और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन द्वारा चरित्र निर्माण करें।

अतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि हमारे अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के पूर्व शाला त्याग देते हैं, एवं सम्मिलित प्रयत्न, पाठ्यक्रम के सामाजिक विस्तार का तथा उसमें उत्पादक एवं उपयोगी नागरिकों के निर्माण एवं उनके प्रशिक्षण का किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम का विस्तार और विकास इस प्रकार किया जाय कि वह बालकों की भौतिक, भावनात्मक एवं सो दूर्य-बोध में सहायक हो सक। सामान्यतः शालाएँ बालकों के अविस्तर के इन दोषों की उपक्षा करती हैं तथा उसके बौद्धिक विकास पर ही ध्यान देती हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सामाजिकीकरण के सत्य ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के नए दवाव डाले हैं। यह स्पष्ट है कि शिक्षा तक सभी पहुँच तथा समान अवसरों की प्राप्ति अभी वोंसों दूर है। शिक्षा तक सभी पहुँच प्रथम आवश्यक कदम है पर तु इस कार्य को समान अवसरों की प्राप्ति के द्वारा समर्थन दिया जाना है। अभी भी गाँवों के समीप शाला सुविधा होन हुए भी प्रार्थन आदिवासी बच्चे शाला छोड़ देते हैं। अतः शाला की चालका का रोक रक्षा की शक्ति का विकास उद्देश्य युक्त एवं रुचिकर शिक्षा के माध्यम देकर

तथा मूल्यांकन की सरल पद्धति स्वीकार कर, किया जा सकता है। एक मम सामयिक पाठ्यक्रम के विकास के लिए बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पहचानना होगा। त्रिमासीक शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का स्थानीय स्वरूप देना होगा।

उद्देश्य — प्रायोजना के निम्नानुसार उद्देश्य हैं

- 1—प्राथमिक शिक्षा का सधमुलम बनाने की दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीनीकरण।
- 2—शालिकाओं, अनुमूर्चिन जाति, जन जाति, पहाड़ी तथा शहर के सुविधा वचित बालका के लिए पाठ्यक्रम विसित करना तथा उन्हें सामाय मैदातिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- 3—शिक्षा का बालक और ममाज की आकासाओं और आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना।
- 4—नवीन पाठ्यक्रम चर्चा के आधार पर शिक्षा सामग्री तैयार करना।
- 5—नवीन पाठ्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षा तकनीकी का विकास करना।
- 6—पाठ्यचर्चा तथा शिक्षा सामग्री के लिए शिक्षक समुदाय का प्रशिक्षण करना।
- 7—भक्ति एवं अवरोध कम करने का प्रयास करना।
- 8—गुणात्मक एवं शैक्षिक सुविधाओं का ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विस्तार करना।
- 9—स्थानीय परिवेश के माध्यम से बालका की सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना।
- 10—नवीन विसित पाठ्यक्रम का प्रायोगिक शालाओं के माध्यम से परीक्षण।

प्रायोजना की सीमा—प्रयाग के लिए यह प्रायोजना प्रारम्भ में वर्ष 1976 से तीन बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं—कुडेश्वर (जिला टोकमगढ़) पेड़ा (जिला बिलासपुर) और पिपलीदा (जिला रतलाम) के तत्वावधान में प्रत्येक के अत-गत 10-10 प्राथमिक शालाओं के हिसाब से 30 प्रायोगिक शालाओं में चालू की गई थी। वर्ष 1980-81 में इसका विस्तार 10 और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के अत-गत 100 अथ प्राथमिक शालाओं में किया गया है।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम—इस शिक्षा क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए पाठ्य-क्रम की शिक्षा योजना में निम्नलिखित विषय शिक्षण हेतु सम्मिलित किए गए हैं।

- 1—भाषा—(मातृ भाषा) शिक्षा के विशेष उपकरण के रूप में भाषा शिक्षण को विशेष स्थान एवं महत्व दिया जाता है।
- 2—सामाजिक अध्ययन—कक्षा 1 व 2 में सामाजिक अध्ययन को परिवेशीय अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए तथा कक्षा 3, 4, 5 में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 1 व 2 में परिवेशीय शिक्षा में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों शामिल होंगे।
- 3—गणित—बच्चा का परिचय संख्याओं एवं उनका दैनिक जीवन में उपयोग से कराया जाएगा।
- 4—सामान्य विज्ञान—प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान का शिक्षण वातावरण का शिक्षा के रूप में होना चाहिए। कक्षा एक व दो सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण को संयुक्त रूप से तथा बाद में दो विषयों में यथा वातावरणीय शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान।
- 5—कार्यानुभव—कार्यानुभव के प्रमुख उद्देश्य बालकों को हाथ से काम करने के अवसर प्रदान करना है ताकि वे प्रमुख कार्यों हेतु आवश्यक क्षमता उत्पन्न कर सकें।
- 6—कला शिक्षण—बालकों को अपनी कल्पना और भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु कला शिक्षण को शामिल किया गया है।

प्राथमिकता की प्रगति

- 1—नवाकृत पाठ्यक्रम रचना—राज्य में प्रचलित पाठ्यक्रम को वातावरण तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को जाँच कर बनाया गया।
- 2—राज्य तथा जिला स्तरीय समितियाँ गठित की गईं।
- 3—शिक्षकों तथा बुनियादी प्रशिक्षण सत्याओं के स्टाफ का समुचीकरण किया गया।
- 4—कम पुस्तिकाओं तथा पूरक पुस्तिकाओं का लेखन कार्य किया गया।
- 5—शिक्षकों के लिए मागदर्शिकाओं का निमाण।
- 6—छात्रों की दर्ज संपत्ति बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण किया गया।
- 7—क्षेत्रीय परीक्षण के लिए यूननम अधिगम सातत्य की स्पर्धा बना कर परीक्षण किया गया।

8—कायानुभव काय को उत्पादन से जाड़ा गया ।

प्रायोजना क्र० 3—सामुदायिक शिक्षा एवं सहयोग की विकासमक गति विधि—(Developmental Activities in Community Education and Participation) (DACEP)

भारत की 80 प्रतिशत जनता गाँवा में निवास करती है। अधिकांश जनता ग्रामीण एवं आदिम है और इनका सामाजिक स्थिति साधारण है। भारतीय जन समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास विभिन्न पहलुओं से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा का विकास तेज़ी से और अधिक हुआ है। किसी समाज के भाग्य का सुधारन में एक उसकी समस्या का समान सुअवसर जुटान में शिक्षा एक बुनियादी साधन है। इस दश में चाहें हालाँकि न रहा हो किन्तु मुसगठित शिक्षा का प्रावधान हमेशा रहा है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तृत अर्थ माना जाता है। उनकी शिक्षा जीवन पथन चरती हैं। चरित्र निर्माण, नैतिक गुणों का विकास, परिवार में सहभाग के साथ रहना बुढ़ों द्वारा कहानी, रामायण, महाभारत सुनना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना आदि उनकी सही शिक्षा है।

इस दश में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हमेशा से जनप्रिय रही है। किन्तु बीच में औपचारिक शालाएँ अधिक से अधिक साक्षरता कार्यक्रमों में उलझती गईं अतः हमारी औपचारिक या स्कूली शिक्षा जन जीवन से असंगत-विलग होती गई। शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने की समस्या, विशेषकर शैक्षिक दृष्टि से पिछले समुदाय में एक चुनौती है। सामुदायिक विकास के कार्यान्वयन से सम्बद्ध गत अनुभव और अन्य शैक्षिक कल्याण कार्यक्रम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि समुदाय की क्रियात्मक सम्बद्धता और सहभाग किसी कार्यक्रम की सफलता हेतु नितान्त आवश्यक है। जिस समुदाय के लिए कार्यक्रम संचालित किये जायें उस शिक्षित होना चाहिए अतः निरंतर उपयोगी कार्यक्रमों का प्रावधान आवश्यक है। ग्रामीण तथा कृषक वर्ग परम्पराओं से अधिक जुड़े रहते हैं और किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं करते हैं। अतः केवल बालकों और प्रौढ़ों का शिक्षित करने मात्र से हम अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होगा। इसमें सम्पूर्ण समुदाय को समाविष्ट करना होगा और उन्हें शिक्षित भी करना होगा। समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए तथा समाज का रूपांतर करने हेतु सामुदायिक शिक्षा और उसका सहभाग ही प्रभावी कदम है।

शिक्षा जैसा कि विकासमक कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता अनिवार्य है। समूचे समुदाय को शिक्षित किया जाना है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत न

केवल समुदाय का निश्चित करना है वरन् शिक्षा में उसकी महभागिता भी है। इस संघ में 'सर्निंग टु बी' से उद्धरण देना उपयुक्त होगा।

Education is developing continually to the point where it is becoming a function of the entire society. Larger and larger sections of population should therefore take part in it.

Auxiliaries and specialists from other professions should be called in to work beside professional teachers. Authorities should also enlist the co-operation of pupils and students in such a way that they teach themselves while instructing others and become imbued with the idea that acquiring an 'intellectual capital' involves its possessor in the duty of sharing it with others.

(Learning to be 218-219)

यह प्रयोजना भी राष्ट्रीय गैर अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् न मूलो-सक की सहायता से दीक्षित विचारों की गति का तेज करने हेतु प्रारम्भ की है। प्रयोजना के अन्तर्गत 0-35 वय की आयु समूह की जनसंख्या की उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना है। जब प्रौढ़ वय स्वयं शिक्षा की धार उभरूँगा तब वह अपने बालक बालिकाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा तथा सभी लाभस्वाधीनता की शिक्षा में उसकी सहभागिता एवं सक्रियता होगी।

प्रयोजना की विचार-पद्धति (Approach) की दो परम्पराएँ हैं—

- (1) बालका की शिक्षा तभी साधक होगी जब वह अपने सामाजिक, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन और विकास के साथ-साथ मिलकर चले, एवं
- (2) इन समूहों की शिक्षा-सेवा को संश्लेषित बनाकर एक संवादात्मक को अधिकतम शक्तिशाली एवं उपयोगी बनाया जाय।

प्रयोजना के उद्देश्य

- (1) प्रयोजना का प्रथम उद्देश्य ऐसी नवीन दीक्षित प्रियाओं का विकास एवं जाँच करना है जो उस बृहद् समुदाय की पूरतम शैक्षिक आवश्यकताओं को सामिल साधनों से, पूरा कर सके, जो अभी आर्थिक या पूरा किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहन हैं। सम्पूर्ण जन

समुदाय विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग, पहचानी इलाका, आदिम एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक यह प्रायोजना सीमित क्षमता की एक पहुँच है। सहकर्मियों और माताओं को शिक्षित करने की भी कठिन समस्या है।

- (2) द्वितीय उद्देश्य के अंतर्गत ऐसी शिक्षा का प्रावधान करना है जिसकी सहायता से छात्र उस विरोधाभास को दूर कर सकें जो शाला में सीखे गए ज्ञान और घर अथवा वातावरण में इस समय मौजूद है।

उपयुक्त उपागम (Access) इस बात पर निर्भर है कि—

- (अ) बालक को सार्यक शिक्षा दी जाय जो उसके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में धीरे-धीरे क्रमिक परिवर्तन एवं संशोधन ला सके। यह समुदाय की शिक्षा एवं प्रेरणा से ही उपलब्ध किया जा सकता है। यह केवल शिक्षा और शाला के बाहर बच्चा की नैतिक आवश्यकताओं को ही लक्षित नहीं करेगी अपितु शांति परित्यागी तथा माताओं को भी प्रभावित करेगी।
- (ब) एकीकृत शैक्षिक सेवाओं से इन समूहों में विशेषकर बालक में ही बालक के विकास हेतु एकीकृत सेवा कार्यक्रम अन्य सेवाओं के क्रिया-चयन को पुनः लागू कर उसे बनाया जा सकता है।

प्रायोजना के विशिष्ट उद्देश्य

- (1) शिशु, शाला से बाहर के बच्चे, स्कूल परित्यागी बच्चे तथा माताएँ जो अभी भी आश्रित एवं पूर्णरूप से शिक्षा से वंचित हैं उनकी न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- (2) बालक एवं प्रौढ़ विशेषकर स्त्रियों को शिक्षित करने की प्रक्रिया में समुदाय को भी सम्बद्ध करना।
- (3) औपचारिकतर शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना।
- (4) बालक की देख-भाल की एकीकृत सेवाओं एवं समुदाय में प्राप्त अन्य सामाजिक कल्याण सुविधाओं के प्रभाव को बढ़ाना।
- (5) शाला परित्यागी बालक का इस योग्य बनाना कि वह किसी स्तर पर शिक्षा की मुख्य धारा से स्वयं को जोड़ सके।
- (6) शांति न बाने वाले किशोर एवं प्रौढ़ों का क्रियात्मक शिक्षा (Functional Education) या व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना।
- (7) सम्पूर्ण समुदाय का विकास करना और प्रजातन्त्र के आदर्शों के अनुसार उनमें नागरिक गुणों का विकास करना।

प्रयोजना के कार्यक्रम

- (1) शिक्षा की प्रभावी, व्यावहारिक तथा साधक बनाने हेतु समग्र समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।
- (2) समुदाय की स्वास्थ्य, स्वच्छता, नागरिकता, पापक आहार तथा व्यावहारिक शिक्षा के विकास में उनका सक्रिय सहभाग प्राप्त करना।
- (3) विभिन्न आयु समूहों से सहभागियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जीवनापयोगी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- (4) सहभागियों की दैनिक आय और उद्भाग को विकसित तकनीक का ज्ञान देकर तथा सहकारिता के आधार पर विकास करने का प्रयास करना।
- (5) समुदाय के विभिन्न साम्य समस्याओं में उनकी क्षमता अनुसार क्रियात्मक शिक्षा के कार्यक्रमों से सहभाग प्राप्त करना।

विशिष्ट कार्यक्रम—प्रयोजना क्र० १ के अन्तर्गत 0-25 आयु वर्ग के लिए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं —

(1) 0-3 वर्षीय आयु समूह के बच्चे तथा माताओं हेतु कार्यक्रम

0-3 आयु समूह के बच्चे के लिए माताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। इसमें 7 वृत्त प्रसव पूर्व तथा प्रसवोपरांत रखी जान वाली सावधानियाँ हेतु प्रशिक्षण, अश्विष्वसा से मुक्ति तथा घस का महत्व आदि का ज्ञान दिए जाने का आयोजन है।

(2) 3-6 वर्ष के आयु समूह हेतु कार्यक्रम

यह आयु भावाटोलन तथा स्वातंत्र्य की आयु है। इस आयु में बालक जो कुछ सीखता है उसका आधार क्रिया है। अतएव इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, धृति में चमक, समृद्ध गान, समृद्ध में खेलना, अभिनय, समूह वाद विवाद, प्रतिभा, पोषण, पोषण पशुओं में प्रेम, रचनात्मक क्रियाकलाप आदि के ज्ञान का व्यवस्था की गई है।

(3) 6-14 वर्ष के आयु समूह हेतु कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 6-14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए है जो कि साधारण-वयस शाला में वचित रह या प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व किताबिन्दु पर शाला का नियमित अध्ययन छात्र गए। एत बालक बालिकाओं के लिए और चारित्रिक पर पाठ्यक्रम का योजना है किन्तु यह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के अन्तर्गत है।

(4) 10-25 वय की आयु वय हेतु कार्यक्रम

शाला स वचिन युवाओं के लिए यह कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ठेहें क्रियात्मक शिक्षा दना है तथा जीवन मे स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान करना है। अतः उनके ग्रामाण जीवन से सम्बद्ध जो उद्योग हैं यथा कृषि, पशुपालन, आगनवाड़ी, चमकला, बीटी पत्ता आदि की उनका व्यवस्थित जानकारी प्रदान करना है। इसके अनिरिक्त स्वास्थ्य, मनोरजन, सहकारिता आदि क कार्यक्रम चलाना भी है।

प्रायोजना म आयु का बधन नहीं है। यह जीवन पथत शैक्षिक कार्यक्रम है जिसम शारारिक, मानसिक सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। ये कार्यक्रम तीन स्तरा पर क्रियाचिन किए जान हैं —

1—प्रीडा के लिए कार्यक्रम

2—महिलाओं के लिए महिला मण्डल

3—युवका क लिए युवक मण्डल

इनमे शैक्षिक, स्वास्थ्य, नैतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, क्रीडा सम्बन्धी कार्यों का अभ्यास कराया जाता ह।

प्रायोजना का क्षेत्र

मध्य प्रदेश मे मत्र प्रायोजना वय 1976 से प्रायोजना क्र० 2 क साथ ही 2 बुनियादी प्रशिक्षण सस्याओं के माध्यम स दा ग्रामा म चल रही है। बुनियादी प्रशिक्षण सस्या कुडेशवर (जिला-टीकमगढ) का दण-रेख मे ग्राम पठा और बुनियादी प्रशिक्षण सस्या पठा (जिला विलासपुर) की दख-रेख म ग्राम बधी म याजना क अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे है। विस्तार के चरणा म 5 अय केन्द्रा की स्वीकृत प्राप्त टा चुकी है तथा 5 अय केन्द्रा के लिए निबारा-घीन है। यह प्रायोजना राज्य शिक्षा सस्यान म० प्र० भापाल के निर्देशन म क्रियाचिन हो रही है। इस योजना म औपचारिकतर शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, महिला शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा का भी सम्मिलित किया गया है।

प्रायोगिक क्षेत्र का चुनाव एवं सर्वेक्षण

सामुदायिक एवं सहभागिता की शिक्षा हनु दा ग्रामा का चुनाव करके सामुदायिक शिक्षा केंद्रा का स्थापित किया गया। टीकमगढ जिल म कुण्डवर विकास घण्ड का ग्राम पठा तथा विलासपुर जिले म पण्ड्रा विकास घण्ड का ग्राम बधी प्रयागाथ चयन किये गय।

सामुदायिक केंद्रों के रूप में चुने गये दोनों ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में निम्नानुसार जानकारों एकत्र की गई—

- 1 ग्राम की जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सुविधा वंचित वर्ग की संख्या।
- 2 साक्षरता की स्थिति।
- 3 0-3, 3-6, 6-14 एवं 15-25 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या।
- 4 शाळा की शिक्षा में लाभ न उठाने वाले 6-14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या।
- 5 मुख्य व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या का विवरण
- 6 उपलब्ध सुविधाएँ—सामुदायिक केंद्र के लिये, बालवाड़ी के लिये, त्रियाशील शिक्षा के लिये।
- 7 उपलब्ध सुविधाएँ—बस सेवा, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, युवक मण्डल, महिला समा।
- 8 स्थानाध्यक्ष सलाहकार व्यक्ति
- 9 क्षेत्र के क्रिमा-बलाप
- 10 कच्चे माल की उपलब्धि
- 11 सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक प्रदत्त
- 12 कार्यक्रमों हेतु थोड़ा स्थान
- 13 त्रियात्मक शिक्षा के लिये उपयुक्त समय
- 14 बालिकाओं एवं माताओं के लिये कार्यक्रम

किए गए कार्य—इस प्रयोजना में राज्य शिक्षा सस्थान के निर्देशन में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न हो चुके हैं।

- 1—सम्बन्धित शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
- 2—सामुदायिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
- 3—मागदर्शिकाओं का निर्माण
- 4—उद्योग प्रशिक्षण तथा आय वृद्धि के प्रयास
- 5—विभिन्न आयु समूह के सहभागिता हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा।
- 6—कार्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन।
- 7—राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न मासकीय विभागा के समन्वय से समितियों का निर्माण।

म० प्र० में प्रायोजना क्र० 3 के अतगत चलाए जा रहे कार्यानुभव—

1—कुडेश्वर केद्र (ग्राम—पठा म)

अ—साबुन बनाना

ब—भोमबलिया बनाना

स—जूट का काय

द—चाक बनाना

2—पेण्ड्रा केद्र (ग्राम—बधी मे)

अ—सीलिंग बैक्स (चपड़ा)

ब—रस्सी बनाना

स—रबड़ का काय

द—अगरबत्ती

य—साई बनाना ।

प्रायोजना क्र० 4 पोषण आहार स्वास्थ्य एवं परिवेश की स्वच्छता

(Nutrition Health Education and Environmental Sanitation)

यह प्रायोजना यूनीसेफ की सहायता से म० प्र० में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निर्देशन में मण्डला जिले में वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गई । प्रथम चरण में इसका परीक्षण किया जा रहा है तत्पश्चात् 500 प्राथमिक शालाओं में पुन इसका परीक्षण होगा ।

बालक एवं समाज एक दूसरे के प्रतिबिम्ब हैं । अत आहार पोषण एवं परिवेश स्वच्छता की जानकारी न केवल दोनों को पहुँचे बल्कि बदलते हुए परिवेश में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए दोनों का ही समान रूप से बाध्य किया जाना चाहिए ।

इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य पाठ्यक्रम में बिना पढ़ाई का भार अधिक किए हुए पोषण आहार एवं परिवेश की स्वच्छता सम्बन्धी धारणाओं का पाठ्यक्रम में समावेश करना है ।

प्रायोजना के उद्देश्य

(1) भोजन सम्बन्धी छाद्य-पदार्थों का ज्ञान व महत्व बनाना ।

(2) उपलब्ध छाद्य-पदार्थों को स्वादिष्ट व पोष्टिक बनाने हेतु प्रयास करना ।

- (3) खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में महाम्यता करना ।
- (4) भोज्य पदार्थों का संरक्षण व संग्रहण करना ।
- (5) समुचित पोषण भोजन की आवश्यकता, उचित पोषण का शारीरिक, मानसिक विकास एवं स्वच्छ तथा सुखी जीवन में योगदान का अवलोकन करना ।

यह प्रयोजना बहुसंख्यक समुदायों की गहनतम वैश्वीय आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्येय बहलू है । अल्पसुविधा प्राप्त घरों के बच्चे कुपोषण, अस्वास्थ्य-कर परिवेश तथा कृषि-क्षेत्रों के किसानों की शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं । एक अध्ययन लेटिन अमेरिका में किया गया तो पता चला कि बच्चे वर्ष में 50 दिन बीमारियाँ के कारण शाला नहीं जा पाते हैं, यद्यपि भारत में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है तथापि सुविधा वंचित क्षेत्रों में ऐसी ही दयनीय और चिन्तनीय स्थिति है । यह स्थिति शिक्षा के लोकव्यापीकरण में बाधक है ।

आज का वास्तविक पक्ष का नागरिक है, एक योग्य हम उसकी शिक्षा की चिन्ता कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य और आहार का भी ध्यान रखना होगा । देश में कुपोषण और अल्पपोषण की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है । हमारी आबादी का लगभग 14 प्रतिशत भाग 6-11 आयु वर्ग का है अतः सरकार द्वारा इनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं । वास्तव में कुपोषण का मुख्य कारण हमारी नासमझी है गरीबी उतनी नहीं है । हम संसदी चीजों में पीछे रह चुके हैं । जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी को सही और स्वच्छ ढंग से खाएँ तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं । अतः शिक्षा के द्वारा हम इस कुपोषण और अल्पपोषण की समस्या को हल कर सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों, शहर के गरीब परिवारों, आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या काफी जटिल है ।

भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस सम्बन्ध में काफी प्रयत्नशील है । वर्ल्ड हेल्थ आगनाइजेशन (डब्ल्यू० एच० आ०), यू० एन० वल्चर संगठन (एन० ए० ओ०) एवं यू० एन० प्रोजेक्ट इस कार्य में सहायक हैं । बी० जासन जिसे पोषण आहार और स्वास्थ्य शिक्षा का महाकाव्य माना जाता है, का कहना था कि हम वास्तव में केवल पोषण आहार तथा परिवेश स्वच्छता की शिक्षा ही दे, बाकी शिक्षा की अपनी आवश्यकता नहीं है । यू० एन० के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा में "पोषण आहार और परिवेश स्वच्छता

शिक्षा" की प्रायाजना प्रारम्भ की गई है। पूरे देश का 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। इनके मुख्य क्षेत्र हैं तामिलनाडु, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र यह प्रायाजना राज्य विमान सत्यान तथा गृह विमान महाविद्यालय जलपुर के निर्देशन में मण्डल-जिने के डिडोरी ब्लॉक में प्रायोगिक रूप में चलाई जा रही है।

स्वास्थ्य नागरिक बनने का पूर्व बालक की प्राथमिक नींव मजबूत, निराग और सहाय्य होना अनिवार्य है। अच्छा और मजबूत रोग तथा तत्वों की कमी से अनजान राग जोड़ हो जाते हैं। उनमें यह जागरूकता पैदा की जाती है कि वे स्वच्छ रहें, मुँह बने तथा अपने परिवेश की स्वच्छता और सुंदरता का भी ध्यान रखें। बालक के विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। उन्हें आरंभिक शक्ति के लिए आवश्यक तत्व चाहिए। बासक घर से बाहर भी रहता है। स्कूल के नए वातावरण में जाता है जहाँ उसे अनजान शारीरिक, मानसिक, समाजिक स्थिति से सामना करना पड़ता है। उसकी बहुत सी शक्ति इस नई स्थिति से सामना करने में भी खर्च होती है। ऐसी अवस्था में उसे पौष्टिक एवं तत्वों से युक्त भोजन न मिले तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विटामिन की कमी से हजारों बालक प्रतिवर्ष मर जाते हैं तथा अनेक बीमारियाँ से ग्रस्त होकर असमय में ही काल-व्यसित हो जाते हैं। अतः हम अपनी वर्तमान हालत में ही जा कुछ मिला रहें। उसी में ही सस्ते खाद्य-पदार्थों से आवश्यक तत्व बालक का उपलब्ध कराना होगा।

इसके साथ ही स्वयं की तथा परिवेश की स्वच्छता भी अत्यन्त आवश्यक है। बालक का स्वयं साफ रहने के साथ-साथ आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का शिक्षा भी उसे देना होगा। बालक का अच्छी आदतों का निमाण सिखाया होगा जिससे वह भविष्य में स्वस्थ, स्वच्छ और सुखी जीवन-यापन कर सके। हम सभी का यह वक्तव्य है कि स्कूलों और विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ पोषण आहार और परिवेश स्वच्छता की शिक्षा भी बालक का दी जाय तथा इसके लिए उनके माता-पिता को भी शिक्षित करना होगा।

पोषण शिक्षा का कार्यक्रम विस्तृत करने हेतु निम्न क्रमवत् कार्यक्रमों का प्रस्तावित है —

- 1— शाला में पढ़ने वाले एवं उनके माता-पिता को भोजन संबंधी आदत, भोजन के रूप में उपयोग होने वाली वस्तुएँ उनके पकाने की विधियाँ इन सबका सर्वेक्षण करना।

- 2—उनके वातावरण में होने वाली उपज, फल, फूल, जंगल में पाई जाने वाली आहार योग्य वस्तुओं का सर्वेक्षण ।
- 3—'आहार में उपयोगी वस्तुओं का रासायनिक विश्लेषण, प्रोटीन, बिक नाई, शर्करा, विटामिन तत्वा की मात्रा ।
- 4—उनकी उम्र, एवं अवस्था के अनुसार प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला सुतुलित भोजन प्रस्तावित करना ।
- 5—शालाओं में मौसमी फल, सब्जियाँ उगाने का प्रयास करना ।
- 6—बालकों के लिये सुतुलित आहार सामूहिक रूप से सस्ते दामों पर बनाकर शालाओं में वितरित करना ।
- 7—बालकों, महिलाओं तथा मनुष्यों की समय-समय पर डॉक्टरों जाँच कर उपचार करने का प्रबन्ध करना ।
- 8—पोषण शिक्षा सबंधी दिन, सप्ताह, माह आदि मनाने का शाला एवं समुदाय में प्रबन्ध करना ।
- 9—पोषण शिक्षा के तत्वा को अन्य विषयों से समावेश करना ।
- 10—समय-समय पर बालकों की आहार सबंधी आदतों का सर्वेक्षण करना ।

प्रायोजना क्र० 5—प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपायम
(Comprehensive Access to Primary Education)
(CAPE Project)

शिक्षा के लाभव्यापारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 'केप' योजना एक नया कार्यक्रम है । यह प्रायोजना 9-14 आयु वर्ग के सुविधाहीन बच्चे के लिए यूनी-सेफ की मदद से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य शिक्षा सस्थान में प्र० के निर्देशन में वर्ष 79-80 में प्रारम्भ की गई है । यह योजना उन बालक बालिकाओं के लिए है जो औपचारिक शालाओं में विनियम कारणों से नहीं आ पाते हैं । ऐसे बालकों के लिए ऐसी पाठ्यचर्या का विषय सामग्री निर्मित करना है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जीवन सम्बन्ध प्रत्यक्ष हो ।

देशीय विभिन्नताओं, सामाजिक विषमताओं तथा विभिन्न प्रकार के जाति-वर्ण के साधनों के कारण विषय सामग्री बहुत व्यापक सचीनी, स्थानीय विशेषताओं के अवयवों सहित एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होगी । इसका

सम्बन्ध बच्चे के वास्तविक परिवेश से होगा। इस तरह की पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं उसका परीक्षण शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक होगा।

प्रायोजना का उद्देश्य—इस प्रायोजना का उद्देश्य दूर स्थानों में अलग-अलग अचला में रह रहे बच्चों के लिए सामग्री तैयार कराकर उन्हें शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना है। निर्मित अध्ययन सामग्रियाँ समुदाय की तथा स्थानीय विशिष्टियों पर आधारित होगी।

प्राथमिक शिक्षा के व्यापक उपागम की यह परियोजना (केप) एक नया प्रयास है, केवल इसलिए नहीं कि यह अब तक उपेक्षित बच्चों के लिए है बल्कि इसलिए भी कि इसमें नई युक्ति एवं नई दृष्टि को अपनाया गया है। इस परियोजना में स्कूल के बाहर के बच्चों तक पहुँचने और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश की जायेगी, चाहे वे बच्चे कहीं भी हों। उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा किन्तु यदि उनकी इच्छा होगी तो इसकी व्यवस्था की जायेगी। इस बच्चा के लिए अधिगम सामग्री विषयो मुख पाठ्यपुस्तकें नहीं होगी अपितु इसमें कम समय के शिक्षण माध्यम होंगे जो उनकी विशिष्ट जरूरतों और समस्याओं पर आधारित होंगे। अधिगम सामग्री का लक्ष्य उनकी लिखना, पढ़ना और गणित की जानकारी देना व बजाय उनके जीवन में गूणात्मक सुधार करना होगा।

केप योजना का क्षेत्र

9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक—

—जो शाला त्यागी हो,

—जो कभी शाला न गए हो,

—जो मुख्यतः सुविधा वंचित क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

विशेषकर हरिजन, आदिवासी, ग्रामवासी अथवा पिछड़े क्षेत्रों के इन बच्चों के जीवन की समस्याओं पर आधारित शिक्षण सामग्री, पेक्का, माध्यमों ऐपो-सोड तथा केपसूलों के रूप में तैयार की जा रही है।

बड़ी संख्या में अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० देहली, योजना का राष्ट्रीय स्तर के द्र होगा, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सस्थान स्तर के द्र होगा, अन्य स्तर के द्र होंगे। बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाएँ, विकास एण्ड आदि।

कृत कार्य

1. अनुविद्यालय परिक्षण सस्थाओं के प्राचार्यों का उ मूखीकरण।

2—युनियादी प्रश्न० सस्याबा व ध्यापनाबा वा प्रश्नना ।

3—अधिगम पाठा (विषय) वा निमाण प्रारम्भ ।

पाठ्यचर्या में निहित परिवर्तन

पाठ्यचर्या विकास के मानदण्ड बनाने समय निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखा जायगा ।

1—समग्र

2—सूचीलापन

3—स्थानीय विशिष्टताएँ

4—समाजोपयोगी कार्य एवं समाज सेवा ।

समग्र—इस पाठ्यक्रम का ढाँचा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से तथा बालक और समुदाय की आवश्यकताओं से समग्र होगा। पाठ्यक्रम की विषय सामग्री में राष्ट्रीय और समाज की समस्याएँ सामान्य तौर पर एवं ढाँचा तथा समुदाय की समस्याएँ विशेष तौर पर प्रतिबिम्बित होंगी।

सूचीलापन—समग्र मूलक पाठ्यक्रम में सूचीलापन आवश्यक है अथवा प्रासंगिकता धारण होगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए अधिगम अनुभवों का विभिन्न प्रकार का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि वह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग प्रकार का होगा। अधिगम सामग्री अधिगम अनुभवों, प्रसंगों के सन्दर्भ में तैयार होगी। ज्ञान शाखा परन्तु विषयों के अन्तर्गत विकास समस्याएँ, वैयक्तिक, सामाजिक या सामुदायिक समस्याएँ विषय-सामग्री का रूप लेगी। इस प्रकार तरकाल परिवर्तन से सम्बद्ध स्थानीय विशिष्टताओं का अधिगम सामग्री में समावेश किया जा सकेगा।

स्थानीय विशिष्टताएँ—सम्बद्ध और सूचीले पाठ्यक्रम में स्थानीय विशिष्टताओं का अवयव होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की विषय सामग्री समस्याओं पर आधारित होना चाहिए और उसे सारे बालक के चारों ओर के वास्तविक परिवेश से लिया जाना चाहिए।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा

समाजोपयोगी कार्य बालक की शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित दसवर्षीय पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की रिपोर्ट

के अनुसार सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य (Socially Useful Productive Work—S U P W) ऐसा सोद्देश्य एवं अर्थपूर्ण कार्य है जिससे परिणामस्वरूप समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो। बच्चे का ज़रूरतों से सम्बन्धित माद्देश्य उत्पादन कार्य और सेवाएँ छात्र के लिए भी अर्थपूर्ण सिद्ध होंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चा की कला के भीतर और बाहर सामाजिक एवं आर्थिक कार्य-क्षेत्रों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे विभिन्न नामों का प्रशिक्षण और उनमें निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का समझने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

माध्यमों का विवेकीकरण—बालकों के लिए पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया और उसकी विषय-सामग्री में आमूल परिवर्तन की दृष्टि अपनाई गई है।

- (1) पाठ्यक्रम विवेकीकृत होगा और यह क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्य-क्षेत्रों द्वारा तैयार होगा। यह विद्यार्थियों और समुदाय की अपनी स्थिति में अंतर्क्रिया (Interaction) का परिणाम होगा। इससे स्थानीय विशिष्टता का तत्त्व पयास मात्रा में प्रतिबिम्बित होगा।
- (2) पाठ्यक्रम की विषय-सामग्री जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से ली जायगी जो विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण होंगी। विषय-सामग्री विभिन्न अधिगम प्रसंगा, अधिगम अनुभवों समझना, और गतिविधियों के समूह के रूप में होगी जिन्हें स्वयं अधिगम माध्यमों के रूप में परिवर्तित किया जायगा।
- (3) विकास कार्यक्रमों के आस पास चूा गए अधिगम प्रसंगा के ये माध्यम अल्प समय के होंगे (1 से 3 घंटे तक या आवश्यकतानुसार और भी कम समय के)।
- (4) यह मानने हुए कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का और उसके फलस्वरूप जीवन में गुणात्मक सुधार का प्रमुख साधन है, विषय-सामग्री का विकास बच्चे के परिवार और उसके परिवार, समुदाय के विकास सम्बन्धित पहलुओं से किया जायगा—जैसे अनाज का अधिक उत्पादन, बिजली उत्पादन लघु उद्योगों से सम्बन्धित कार्य-कलाप, वनरोपण, भू संरक्षण, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद उन्मूलन आदि आदि। इस प्रकार शिक्षा न केवल जीवन के लिए बल्कि जीवन में भी होगी। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सातत्य स्थापित किया जायगा।

- (5) विकेंद्रित पाठ्यक्रम की बुनियादी आवश्यकता के रूप में अधिगम प्रसंगों के विषय, यथासंभव, क्षेत्र में टूटे पहचाने जाएंगे ताकि उनसे विचार्यों की आवश्यकताओं का सही और प्रामाणिक सम्बन्ध प्रतिबिम्बित हो।

पाठ्यक्रम के विकास के अभिकरण (Agencies)

पाठ्यक्रम के विकास के निम्नलिखित अभिकरण होंगे।

- 1—प्राथमिक स्कूल
- 2—ग्रन्थ या जिज्ञा स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक गायान
- 3—प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ
- 4—विकास एवं विस्तार अधिकारी।

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ एवं शैक्षिक आयोजन (Five-Year Plans and Educational Activities in India)

भारत में शैक्षिक आयोजना का इतिहास काफी नया है। शैक्षिक आयोजन का प्रथम प्रयास 1938 में एक अशासकीय समिति (Un official Body) द्वारा किया गया तथा दूसरा 1944 में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। प्रथम आयोजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक विकास के सन्दर्भ में शैक्षिक विकास की ओर ध्यान देने का था और इस प्रकार इसे पूर्ण आयोजना कहा जा सकता है। दूसरी आयोजना में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया किन्तु एक भावी योजना तैयार की गई। चूंकि ये योजनाएँ कार्यान्वित नहीं की जा सकी इसलिए इनका कोई शिक्षा पर प्रभाव नहीं हुआ। तृतीय प्रयास भारत के स्वतन्त्र होने के उपरान्त 1951 में किया गया जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ। इस आयोजना में शिक्षा का राष्ट्रीय विकास का एक अंग माना गया, सम्य निर्धारित किए गए, प्राथमिकताएँ निश्चित की गई तथा वित्त की व्यवस्था की गई।

1 स्वतन्त्रता के पूर्व की अवधि

प्रथम राष्ट्रीय योजना—भारतीय अधिनियम 1935 के अन्तर्गत राज्या का स्वायत्तता प्रदान की गई तथा 1937 में अधिकांश राज्या में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। इस बीच एक केन्द्रीय सरकार बनाने की बात भी सोची गई और इसी के अनुक्रम में एक राष्ट्रीय क्रियाकलापों की विस्तृत योजना बनाने की बात भी सामने आई। 1938 में पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना परिषद् का गठन हुआ। योजना परिषद् ने अपनी दो उपसमितियाँ शैक्षिक विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए निर्माण की। एक उपसमिति सामान्य शिक्षा के लिए जिसके अध्यक्ष डा० राधाकृष्णन थे तथा दूसरी उपसमिति तकनीकी शिक्षा के लिए निर्माण की गई जिसके अध्यक्ष डॉ० मेघनाथ साहा थे। युद्ध एवं शांति के उद्देश्यों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सरकार के बीच अवसहमति एवं विचार भिन्नता हा जाने से प्रांतीय सरकारें भग्न हो गई तथा योजना का कार्य रुक गया।

2 युद्धोत्तर काल की शैक्षिक विकास आयोजना

1943 में गवर्नर जनरल 1 इच्छा प्रकट की कि भारत में युद्धोत्तर काल के विकास के लिए एक योजना बनाई जाय जिसमें शिक्षा का भी सामिल किया जाय। अतः इस सम्बन्ध में शासकीय प्रयास किया गया। इसी बीच 1938 से 1943 के बीच नियुक्त कई समितियों की शिक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी आ चुकी थी अतः उससे शिक्षा के सम्बन्ध में भावी योजना निर्णय का आधार भी मिल गया। तत्कालीन शिक्षा आयुक्त भारत सरकार जॉन सार्जेंट ने शिक्षा समितियों की रिपोर्टों का समन्वय कर युद्धोत्तर काल के शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में योजना का एक मसौदा तैयार किया जिसे सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। यह शैक्षिक योजना 40 वर्षीय थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य पा दश की 'पुनर्तम शैक्षिक आवश्यकताएँ' क्या हैं, उन्हें कब तक पूरा किया जा सकता है और उनका क्या व्यय होगा। चूंकि योजना के क्रियान्वयन में असन्नी मुद्रा आर्थिक पक्ष का होता है अतः उसकी समुचित व्यवस्था न होने से योजना केवल कागजी बनकर रह गई।

सार्जेंट योजना आन्दो मे

	आयु वर्ग अनुमानित दज सख्या	शिक्षा का स्तर व्यवस्था	अनुमानित वार्षिक व्यय लाक्षा में
1	3-6 आयु वर्ग (10 लाख)	पूव प्राथमिक (नर्सरी व्यवस्था)	320 00
2	6-11 वर्ष (359 लाख)	जूनियर बसिक (व्यवस्था I-V)	11400 00
3	11-14 वर्ष (156 लाख)	सीनियर बसिक (VI-VII)	8600 00
4	(अ) 14-17 वर्ष (73 लाख)	(अ) हाई स्कूल (IX-XI)	7900 00
5	(ब) 17-22 वर्ष (75 हजार)	(ब) तकनीकी, वाणिज्य एवं कला स्कूल	1000 00

6	(अ) 17-22 आयु वर्ग (240 लाख)	(अ) विश्वविद्यालयीन शिक्षा	960 00
	(ब) 17-22 आयुवर्ग (25 हजार)	(ब) तकनीकी, वाणिज्य एवं कृषि महाविद्यालय	इसका व्यय उपयुक्त 4(ब) में सामिल है।
7	17-19 आयु वर्ग (20 लाख) 20-22 आयु वर्ग (180 लाख)	शिक्षक प्रशिक्षण पूर्व स्नातक स्नातक	620 00
8	10-40 आयु वर्ग (9 करोड़)	प्रौढ शिक्षा	300 00
9	14-20 आयु वर्ग (320 लाख)	मनोरंजन एवं सामाजिक क्रियाकलाप	100 00
10		रोजगार ब्यूरो	60 00

कुल व्यय 31260 00 लाख

स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयाजन

योजना आयोग की स्थापना—1917 में दश आजाद हुआ। उससे बाद सभी शिक्षा में राष्ट्रीय विकास का काम हाथ में लिया गया। केन्द्र सरकार ने 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की मदद से राष्ट्र की सम्पूर्ण आयाजना का उसे भार सौंपा गया। योजना आयोग का काम विस्तृत नीतियाँ बनाना, प्राधाम बनाना, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार कर राष्ट्र के स्रोत को देखते हुए योजना का मसौदा तैयार करना तथा राशि निर्धारित करना है।

काम विधि—शैक्षिक आयाजना के लिए दो स्तरों पर प्रस्ताव बनते हैं प्रथम राज्य स्तर पर जहाँ शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव बनाने हैं दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। इन दोनों स्तरों के प्रस्तावों पर विचार करने तथा एक मसौदा तैयार करने के लिए कार्यकारी दल का निर्माण होता है जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय तथा राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सामिल

होते हैं। यह कार्यकारी दल छाटो-छाटी समितियाँ नियुक्त करता है जो शिक्षा के विभिन्न शाखाओं, पहलुओं पर विचार कर अपनी राय व्यक्त करती हैं। राज्य स्तर पर भी ऐसी समितियाँ बनती हैं जिनकी राय केन्द्रीय समिति मानती है। सभी समितियाँ के प्रस्तावों को एक कर शिक्षा मन्त्रालय अपने प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत करता है। योजना आयोग अन्य क्षेत्रों के विकास प्रस्तावों के साथ राष्ट्रीय उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए पंच वर्षीय योजना का मसौदा (Draft) तैयार करता है। इस राष्ट्र को राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) अंतिम रूप देता है और स्वीकार करता है।

योजना का स्वरूप निर्धारित करने, लक्ष्य तथा प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, विभिन्न सेक्टरों को राशि उपलब्ध कराने तथा अन्य ऐसे ही मामलों के लिए राष्ट्र विकास परिषद् सर्वोच्च संस्था है। देश का प्रधान मंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है। केन्द्रीय मंत्रीगण तथा राज्यों के मुख्य मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं। अंतिम रूप से स्वीकृत पंचवर्षीय योजना के मसौदे की जनता की आय राय जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है। सही सुझावों का मसौदे में सामिल कर लिया जाता है। लक्ष्य और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से निर्धारित कर राशि का बटन कर योजना को अंतिम स्वरूप देकर स्वीकृत कर दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने-अपने बजट में आयोजना के लिए राशि देकर मसौदा तथा राज्यों की विधानसभाओं में पास करवा लेती हैं और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की जनता की स्वीकृति मिल जाती है।

पंचवर्षीय योजनाएँ—सही रूप में राष्ट्रीय गिन्याकलाप की विस्तृत योजना स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन वर्ष बाद प्रारम्भ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारम्भ हुई। अभी तक की पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि इस प्रकार है—

1951-56	प्रथम पंचवर्षीय योजना
1956-61	द्वितीय "
1961-66	तृतीय "
1969-74	चतुर्थ "
1974-79	पाँचवीं "
1980-85	छठी "

इन सभी योजनाओं में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का अङ्ग माना गया तथा समाजवादी समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका को स्वीकार किया गया है।

निर्धारित लक्ष्य—पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निम्नांशुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ एवं शैक्षिक आयोजन

145

स्तर	आयुदम	1950-51 वास्तविक	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ पंचवर्षी योजना	छठी योजना
प्राथमिक स्तर	दर्ज लक्ष्य हजारों में	19150	28550	32540	50290	69500	91200
6-11 आयु वर्ग	प्रतिशत	42.6	60.0	62.7	76.1	92.2	103
माध्यमिक स्तर	"	3120	—	6387	10160	19000	28800
11-14 आयु वर्ग		12.7	—	22.5	29.8	47.4	57
उ० मा० स्तर	"	1220	—	3070	4610	9000	14400
14-17 आयु वर्ग		5.8	15.0	11.7	15.7	22.1	23
विश्वविद्यालय स्तर	"	300	720	—	1100	1600	—
17-23 आयु वर्ग		0.7	1.4	1.8	1.9	2.4	—

प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारम्भ हुई और 1955-56 में पूरी हुई। इस योजना में कहा गया कि स्वच्छ मनुष्य की शिक्षा और विकास नहीं होना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि पर्याप्त सात जुटाए जाय और शैक्षिक विकास का पूरा-पूरा प्रयास किया जाय।

प्रथम योजना में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अन्तर्गत अथवा स्तर पर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। बाकी अथवा योजनाओं में सभी स्तर पर कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रथम योजना में शिक्षा के लिए निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं।

- (i) विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण।
- (ii) शिक्षा की विवक्षित विधियों में नवाचार एवं शोध।
- (iii) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण।
- (iv) ग्रामिका, शिक्षिका, प्रौढा के लिए साहित्य का निर्माण।
- (v) वैज्ञानिक एवं सामाजिक शिक्षा के लिए समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- (vi) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिकतम सुविधाओं का विकास।
- (vii) विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार तथा स्नातकोत्तर पाठ्य एवं शोध का विकास।

इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र से 66% अनुदान हिंदी में प्रचार-प्रसार योजनाओं के लिए, 60% अनुदान स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, पूर्व प्राथमिक शालाओं, स्कूल सह सामुदायिक क्षेत्रों तथा समाज शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुई।

प्रथम आयोजना के लिए 2069 करोड़ की राशि निर्धारित की गई जिसमें से 151.66 करोड़ जो कि पूरी योजना राशि का 7.34 प्रतिशत है, शिक्षा के लिए आवंटित की गई।

योजना के लक्ष्य शालेय शिक्षा के लिए प्रथम योजना में अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए—

- (i) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 6-11 और 11-14 आयु वर्ग के लगभग 60% बालकों को दर्ज करना ।
- (ii) 6-11 आयु वर्ग की छात्राया का दज प्रतिशत जा 1950-51 में 23.3% था, उसे 1955-56 में 40% तक ले जाना ।
- (iii) उच्च-माध्यमिक स्तर पर 10 प्रतिशत दज संख्या का लक्ष्य तथा बालिकाया का खास तौर पर 10 प्रतिशत दज संख्या लक्ष्य पूरा करना ।

लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद यह भी अनुमान लगाना कि उपलब्ध शासकीय छात्रा से 6-11 आयुवर्ग के 55.7 प्रतिशत तथा 11-17 आयुवर्ग के 13.3 प्रतिशत बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अतः शेष के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग किया जाय तथा छात्रा को क्रापट के माध्यम उत्पादन कराकर पूरा किया जाय ।

6-14 आयुवर्ग के छात्रा के लिए बुनियादी शिक्षा पद्धति स्वीकार की गई । बुनियादी शिक्षा पद्धति में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया । शिक्षकों की भर्ती की गई । 5 वर्ष के बजाय 8 वर्षीय पूर्ण बुनियादी शिक्षा पद्धति अनुशसित की गई । परम्परागत प्राथमिक शालाया की अपेक्षा बुनियादी शालाएँ खोली गई तथा पुरानी शालाओं में क्रापट चालू करने के लिए क्रापट शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की अनुशसा की गई ।

माध्यमिक शिक्षा—चूँकि माध्यमिक शिक्षा आयाग का गठन हो चुका था और माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलू आयोग के परीक्षण के अंतर्गत थे अतः योजना में कुछ खास मुद्दों को ही ध्यान में रखा गया । माध्यमिक शिक्षा के विन्मनानुसार उद्देश्या की ओर योजना में ध्यान दिलाया गया था—

- (i) शिक्षा हमारे निशोर बच्चा की मनोवैज्ञानिक जरूरतों से सम्बद्ध हो ।
- (ii) शिक्षा हमारी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ से जुड़ी हो । शिक्षा का आधार व्यावसायोमुख हो ।
- (iii) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्ध हमारी माध्यमिक शिक्षा हो । बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए ।
- (iv) माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जो अधिक छात्रा में नवृत्त की भावना पैदा कर सके । माध्यमिक शिक्षा नेतृत्व की शिक्षा हो ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के कुल योजना बजट का 14 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित था और यह राशि 307 00 करोड़ थी। यह राशि प्रथम योजना से 80 प्रतिशत ज्यादा थी। इस योजना में प्रथम योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं।

- (i) बुनियादी शिक्षा
- (ii) प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) का विस्तार
- (iii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में ढाँचबर्सी पत्रेसन
- (iv) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षिक स्तर में सुधार
- (v) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार।
- (vi) समाज शिक्षा एवं सङ्घर्ष के विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

इस योजना में भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और केन्द्र ने शत-प्रतिशत राशि इस हेतु प्रदान की। जिन कार्यक्रमों को 60 प्रतिशत के श्रेय अनुदान प्राप्त हुआ, वे थे—प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दीन करना, मल्टी परपज शालाएँ स्थापित करना तथा इनके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षा विभागों में योजना और सांख्यिकी कक्षा का निमाण तथा हिंदी का प्रचार और प्रसार।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)—तृतीय योजना में शिक्षा के लिए आयोजना बजट 500 00 करोड़ था जो कि कुल आयोजना राशि का 7.5 प्रतिशत था। योजना काल में व्यय की राशि 156 00 करोड़ केन्द्र द्वारा दी गई तथा 440 00 करोड़ राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई। प्रावधानित राशि से व्यय ज्यादा हुआ।

तृतीय योजना में शिक्षा के निम्नलिखित मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया—

- (i) 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार।
- (ii) माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीन स्तर पर विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विस्तार।
- (iii) प्रत्येक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास।
- (iv) शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार।

- (v) छात्र वृत्ति, वृत्तिका, फीस माफी एवं छात्रों का आर्थिक सुविधाओं में वृद्धि ।
- (vi) छात्राशा की शिक्षा का असनुसन दूर करने के लिए बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न ।
- (vii) प्रारम्भिक शिक्षा का बुनियादी पद्धति में उ मुखीकरण ।
- (viii) शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालको में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता पैदा करना ।

शिक्षक प्रशिक्षण तथा बालिका शिक्षा के लिए केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ । माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा सुविधाओं, तथा शालेय स्तर पर बालका को छात्र वृत्तिया हेतु 75 प्रतिशत राशि के द्र से दी गई । तीसरी योजना के अंत में 6-11 आयु वर्ग में 76 7 प्रतिशत, 11-14 आयु वर्ग के 30 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग के 16 2 प्रतिशत बज सख्या का सक्ष्य प्राप्त कर सके जब कि दूसरी योजना के अंत में इही आयु समूहों में दर्ज सख्या का प्रतिशत क्रमशः 62 4, 22 5 और 10 6 था ।

चतुथ पंचवर्षीय योजना (1969-70 से 1973-74)—चौथी योजना अपने नियमित समय से तीन साल बाद प्रारम्भ हो सकी । इसकी अवधि 1969-70 से 1973-74 तक रही ।

चौथी योजना का उद्देश्य 6 से 14 वष के छात्रा को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के सवैधानिक निर्देश को पूरा करने की दिशा में प्रगति करना था । शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर स्तरा पर समेकन और विविधीकरण पर अधिक बल दिया गया जिससे विभिन्न प्रकार के उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो । इस याजना में शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मकता का विश्वास करने तथा पूर्व योजनाओं में किए गए काय और प्रगति की समीक्षा कर उसे आगे बढान पर बल दिया गया । निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा—निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा में क्षति एवं अवरोध को समाप्ति तथा पाठ्यक्रम का कार्योमुख बनाना ।

(ii) माध्यमिक शिक्षा—व्यावसायिक तथा टर्मिनल कोर्सेस का प्रावधान, तथा विज्ञान शिक्षा का गृहदीकरण ।

(iii) विश्वविद्यालयीन शिक्षा—छात्रा की रुचि का तबनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोडना, विज्ञान, स्नातकांतर शिक्षा तथा शोध काय का विस्तार ।

(iv) शिक्षक प्रशिक्षण—शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार एवं विस्तार तथा शिक्षकों की योग्यता वृद्धि पर वार्षिक वेतन वृद्धियों तथा वेतन में सुधार।

(v) शोध कार्य—पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतियों में शोध कार्य।

(vi) सामाजिक शिक्षा—प्रौढ शिक्षा तथा त्रियात्मक साक्षरता का विस्तार।

(vii) पाठ्य पुस्तकें—पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में लिखा जाना।

(viii) छात्रों की वित्तीय सुविधाएँ—छात्र वृत्तियाँ तथा शिक्षा के लिए ऋण में वृद्धि।

(ix) शिक्षा की तकनीकी—इसे सुधारा जायगा। कम व्यय में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करना। शिक्षा सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग और दोहन, समाज से शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त करना।

तीसरी और चौथी योजना के मध्य तीन वर्ष का अंतराल रहा जिसमें वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित होती रही। इन तीन वर्षों में शिक्षा योजना के लिए 322 4 करोड़ की राशि निर्धारित थी जिसमें से 240 9 करोड़ सामान्य शिक्षा और 81 5 करोड़ तकनीकी शिक्षा के लिए थी।

सशोधित चतुर्थ योजना के लक्ष्य

(i) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन आए, आर्थिक विकास में सहायक हो तथा विशेष विकास के कार्यों हेतु मानव शक्ति को प्रशिक्षित करे।

(ii) प्रारम्भिक शिक्षा का विकास।

(iii) पिछड़े क्षेत्रों, जातियों और बालिका शिक्षा पर विशेष बल तथा उनके लिए शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(iv) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान।

(v) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के स्तर तथा शोध कार्य में सुधार।

(vi) पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार तथा पुनर्लेखन।

(vii) शिक्षा की उपलब्ध सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग।

चतुर्थ आयोजना में शिक्षा के लिए 872 66 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जो पूरी आयोजना का 3 5 प्रतिशत थी। इस राशि में से 822 66

करोड़ की राशि पब्लिक सेक्टर तथा 50 करोड़ की राशि प्रायवेट सेक्टर के अन्तर्गत थी। राज्य की राशि में से 271.00 करोड़ बेतुल ने तथा 1551.66 करोड़ प्रा.उ. सरकारों ने हिस्सेदारी की। 69.1 करोड़ की राशि सामान्य शिक्षा तथा 125.5 करोड़ तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित थी।

चार पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर व्यय

व्यय करोड़ों में

मर्दें	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय यो० 1961-66	चतुर्थ योजना 1969-74
	84.80 (55.5%)	92.39 (33.6%)	186.00 (36.0%)	239.00 (30.4%)
प्रारम्भिक शिक्षा	20.20 (13.2%)	50.87 (18.5%)	90.09 (18.0%)	140 (17.8%)
माध्यमिक शिक्षा	13.70 (8.9%)	45.39 (16.5%)	75.00 (15.0%)	195.00 (24.8%)
विश्वविद्यालय शिक्षा	20.20 (13.2%)	52.20 (19.0%)	130.00 (26.0%)	106.00 (13.5%)
तकनीकी शिक्षा	14.00 (9.2%)	34.07 (12.4%)	25.00 (5.0%)	89.5 (11.4%)
अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रम	152.90 (100%)	275.00 (100%)	500.00 (100%)	786.00 (100%)

उपसन्धियाँ पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बशानुसार उपसन्धियाँ रही—

क्र०	शिक्षा का स्तर	1950-51 प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ			
		वर्ष की स्थिति योजना के अन्त में	वर्ष की योजना के अन्त में	वर्ष की योजना के अन्त में	वर्ष की योजना के अन्त में
1	कक्षा I से V विद्यार्थी	191 50	251 70	349 90	504 70 637 19
	6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या का प्रतिशत	42 6	52 8	62 4	76 7 84 0
2	कक्षा VI से VII के विद्यार्थी	31 2	42 9	67 0	105 3 150 45
	11-14 आयु वर्ग की संख्या का प्रतिशत	12 7	16 5	22 5	30 8 35 0
3	कक्षा IX से XI-II के विद्यार्थी	12 2	18 8	28 9	50 4 74 75
	14-17 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत	5 3	7 4	10 6	16 2 20 0
4	विश्वविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी	3 6	6 3	8 9	14 9 31 71
	17-23 आयु वर्ग का प्रतिशत	0 8	1 4	1 8	2 7 3 5

शिक्षा सस्याएँ और शिक्षक

शिक्षा की सस्याएँ	1950-51	55-56	60-61	65-66	73-74
शिक्षक					
प्राथमिक/जूनि०					
बेसिक स्कूल	209671	278135	330399	391064	461864
शिक्षक	537918	691249	741515	944377	1231622
मिडिल/सीनि०					
बेसिक स्कूल	13596	21730	49663	75798	87702
शिक्षक	85496	148394	345228	527754	758210
हाई/हायर से०					
स्कूल	7288	11093	19372	29863	39584
शिक्षक	126504	189794	296305	479060	739641

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा के हर स्तर पर चारों मात्राओं में प्रगति हुई है।

पाँचवी योजना (1974-1979)—पाँचवी योजना में भी शिक्षा के हर स्तर पर गुणात्मक और सत्यात्मक विस्तार का प्रयास किया गया। पाँचवी योजना में शिक्षा के लिए 1285 करोड़ की राशि निर्धारित की जिसमें 1129 करोड़ सामान्य शिक्षा तथा 156 करोड़ तकनीकी शिक्षा हेतु रखे गए।

पाँचवी योजना में निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया है—

- (i) सामाजिक याव दल के निश्चय सम्बन्धी सर्वोपरि कार्यक्रम के रूप में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।
- (ii) शिक्षा पद्धति को विकास की आवश्यकताओं तथा रोजगार का स्थिति के अनुसार बदलना।
- (iii) शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता।
- (iv) सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यों में विद्यार्थियों सहित विद्वान समुदाय का योगदान प्राप्त करना।

(v) हरिजन आदिवासिया तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास ।

विशेष प्रयासों के धारजू भी प्राथमिक स्तर पर चौथी योजना के अंत में 84 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ शामिल हो गईं, पाँचवी योजना के अंत तक 84.5% बालक-बालिकाएँ शामिल हो सकेंगे। इस प्रकार पूरी योजना काल में केवल आधे प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 3 प्रतिशत दर्ज संख्या में वृद्धि तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आधा प्रतिशत दर्ज संख्या में वृद्धि होगी है। शालाओं की संख्या शिक्षक संख्या में अपेक्षा वृद्धि हुई है। चौथी योजना की अपेक्षा पाँचवी योजना में योजना काल में 5 करोड़ की वृद्धि हुई है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)—छठी योजना भी अपने योजनाकाल से एक वर्ष आगे बढ़ गई। पाँचवी योजना की समाप्ति पर रॉलिंग प्लान की योजना का विचार किया गया और छठी योजना 1979-83 के लक्ष्य निर्धारित किए गए। बाद में रॉलिंग प्लान का विचार त्याग दिया गया और पूर्वानुसार पंचवर्षीय योजना 1980-85 का मसौदा तैयार किया गया।

अगस्त 1977 में राज्य व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों की शिक्षा से सम्बंधित मिन-मिन बातों पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति का आयोजन हुआ जिसमें निम्नानुसार अनुशंसाएँ की गईं—

- (i) छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति।
- (ii) प्रौढ शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम।
- (iii) शिक्षा की नई प्रणाली को उचित संशोधनों सहित छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व लागू करना।
- (iv) विशेष क्षेत्रों की प्राथमिकता देते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल करना।
- (v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा।
- (vi) हरिजन आदिवासियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम।

छठी योजना में बालिकाओं की शिक्षा, रिछे क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रम जिनमें अभिभावकों को अधिक प्रोत्साहन भी शामिल हैं, लागू किए जाना प्रस्तावित है। सध्यात्मक विस्तार के साथ गुणात्मक विस्तार को आरंभ अधिक ध्यान दिया

जायगा। खेल-कूद और समाज कल्याण की ओर भी विशेष बल दिया जायगा। छठी योजना में लगभग 2000 करोड़ की योजना राशि निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से लगभग 1825 करोड़ की राशि सामान्य शिक्षा तथा 175 करोड़ की राशि तकनीकी शिक्षा के लिए होगी।

6-11 आयुवर्ग में दर्ज सख्या का लक्ष्य 103 प्रतिशत, 11-14 आयु वर्ग में 57 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग में 23 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पाचवी योजना की उपलब्धि तथा छठी योजना के लक्ष्य

शिक्षा का स्तर	पांचवी योजना में उपलब्धि (1978-79)	छठी योजना के लक्ष्य (1980-85)
वर्ग I-V के कुल छात्र (लाखों में)	721 60	912 00
6-11 आयु वर्ग में प्रतिशत	84 5	103
वर्ग VI-VIII में कुल छात्र (लाखों में)	181 80	288
11-14 आयु वर्ग में प्रतिशत	38 10	57 00
वर्ग IX-XI-XII के कुल छात्र (लाखों में)	83 2	144 0
14-17 आयु वर्ग में कुल प्रतिशत	20 6	23
17-23 आयु वर्ग के कुल छात्र (लाखों में)	42 1	—

पाँचवी तथा छठी योजना में शिक्षा पर व्यय एवं सन्ध

(राशि करोड़ों में)

मर्	चार याजनाका म व्यय	पाँचवी योजना प्रावधान प्रतिशत	छठी योजना की राशि प्रावधान प्रतिशत	व्यय	राशि	प्रतिशत
प्रारम्भिक शिक्षा	694 7	410	31 9	300	900	45
माध्यमिक शिक्षा	366 6	250	19 5	163	268	14
विश्वविद्यालय	421 0	292	22 7	210	265	13
सामाजिक शिक्षा	56 22	18	1 4	9	200	10
संस्कृति	25 73	37	2 9	25	65	3
अन्य शैक्षिक कार्यक्रम	177 6	122	9 5	92	118	6
योग सामान्य शिक्षा	1741 8	1129	87 9	799	1816	91
तकनीकी शिक्षा	380 7	156	12 1	102	170	9
महायोग	2122 5	1285	100	901	1986	100

मध्य प्रदेश में पञ्चवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

सं० प्र० का निर्माण 1 नवम्बर 1956 को हुआ। उस समय प्रदेश में पहली पञ्चवर्षीय योजना समाप्त होने की थी। जिस समय प्रदेश का निर्माण हुआ इसके सामने अनेक समस्याएँ थीं। प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार थी।

(1) राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप शिक्षा की नए सिरे से व्यवस्था

बजट सत्यापन (साक्षात् म)

शाला का स्तर	1956	60-61	65-66	69-70	73-74	78-79	छठा योजना के समय
प्राथमिक स्तर	15 36	20 10	28 48	29 90	44 17	44 50	59 69
पूर्व मा०		(49 17	(55 93	(54 6	(72 01	(63	(70 12
स्तर	1 86	3 16	5 63	6 98	7 96	11 43	19 83
उ० मा०		(15 18	22 42	(23 2	(23 39	(30 5	(35
स्तर	0 57	1 24	2 69	3 52	3 86	4 33	7 00
		(6 69	(12 33	(13 0	(13 2	(13 5	(16 10
		प्रतिशत)	प्रतिशत)	प्रतिशत)	प्रतिशत)	प्रतिशत)	प्रतिशत)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पंचवी योजना क अंत तक दर्ज सख्या तीन गुनी हो गई, पूर्व माध्यमिक स्तर पर लगभग 6 गुनी और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 8 गुनी हो गई।

शिक्षा सत्यापन

शाला का प्रकार	1956	60-61	65-66	69-70	73-74	78-79
पूर्व प्राथमिक	214	415	417	548	712	970
प्राथमिक	44499	57064	71631	78984	114402	114902
पूर्व माध्यमिक	15326	21898	33402	36309	39744	56876
उच्चतर माध्यमिक	7507	13730	21437	23842	22918	32931

इकाई शिक्षण एव सतत् मूल्यांकन योजना

(Unit Education and Evaluation)

पृष्ठभूमि—हम साग हमेशा से परम्परावादी रहे हैं। शिक्षा में तो हम और भी परम्परागत ढंग से काय करत रहे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किए गए प्रयोग तत्काल फल नहीं देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनन्य प्रयोग किए और जब तक उसके परिणाम आने की हूप हमने दूसरा प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। हमने अपने तरीके से बालक को पढ़ाया, अलग अलग ढंग से परीक्षाएँ की और विद्यार्थी अपने भाग्य से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होते गए। साल भर बालक परिश्रम करता था और वार्षिक परीक्षा के समय यदि किसी पक्ष में घीमार पड़ गया तो वह भर की मेहनत बेकार चली जाती थी। अर्थात् उसकी वष भर की गई मेहनत थोड़ी ही दर में बेकार हो जाती थी। विषय के पाठ्यक्रम की परम्परागत ढंग से अनेक अक्षा में बाँट दिया गया था। इन विषयांशों का आपस में कोई विषय सम्बन्ध नहीं था और न ही विभाजन का कोई दैक्षिक आधार। हर विषयांश अपने आत में लगभग स्वतन्त्र था और पूरे पाठ्यक्रम में यह डोलेशन से सम्बन्ध था। विषयांशों के अलग अलग करने की यह पद्धति पाठ्यक्रम रचना के मनोवैज्ञानिक मिठा न में पड़े थी। इससे प्रत्येक विषय में विभिन्न अक्षा एव अंशों से पूर्णता एव एकीकरण लाना सम्भव नहीं था। लेकिन यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का गठन और एकीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर हो।

पाठ्यक्रम के प्रस्तुतीकरण की पुरानी पद्धति में प्रत्येक शाखा में भिन्न-भिन्न रीति और गति से शिक्षण एव पान दिया जाता था। वही शिक्षक अल्प समय में पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु को पूरा कर दत थे और किसी शाखा में पूरा वष में भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता था। कहीं-कहीं शेष बचा पाठ्यक्रम दो बार दिन अतिरिक्त समय में पढ़ाएँ लगाकर पूरा कर लिया जाता था। इसी प्रकार की हरेकशाखा में हमारी शिक्षा चल रही थी। बालक शाखाओं में आत में क्या नहीं भी आत में। जब साल भर के परिश्रम का मूल्यांकन एक बार ही होता था तो निश्चय ही बालक अनुत्तीर्ण होते थे और अनुत्तीर्ण होने के बाद या तो बालक शाखा छोड़ जात या एक ही अक्षा में कई साल बने रहते थे। अक्षा एव व दो में

अत्यंत दयनीय और चिन्तनीय स्थिति थी। 100 बालक कक्षा में भर्ती होते हैं तो लगभग 31 बालक कक्षा 5 उत्तीर्ण करते हैं और 66 लड़के बीच में जानाएँ छोड़ जाते हैं। कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते 24 छात्र हो रह जाते हैं। ये जानते थे कि साल भर के बीच उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में कोई मूल्यांकन जाना ही नहीं है। यदि छिमादी परीक्षा होनी भी थी तो उसका उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने में कोई योगदान नहीं था। अतः निराशा के वातावरण में बालक अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। उन्हीं की देखा देखी अन्य बालक भी शालाआ में नहीं आए। हमने अपनी गलती बच्चा के स्तर पर धर ली। इन सब परिस्थितियों ने हमें कुछ सोचने को मजबूर किया। हमारे सामने प्रश्न बिन्दु लगा दिया। अतः इन सब समस्याओं से निपटने के लिए इकाई शिक्षण और सतत् मूल्यांकन की योजना प्रारम्भ की गई।

इकाई बार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण—म० प्र० में समस्त प्राथमिक शालाओं में वर्ष 1972-73 से प्राथमिक कक्षाओं में इकाई बार पाठ्यक्रम तैयार तदनुसार अध्यापन काम प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक इकाई शिक्षण के साथ साथ सतत् मूल्यांकन का काम भी किया जा रहा है। वर्ष 1974-75 से पूर्व माध्यमिक शालाओं तथा जुलाई 1970 से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में इकाई बार शिक्षण प्रारम्भ किया गया।

प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को 10 इकाइयाँ में विभाजित किया गया है। इकाई शिक्षण में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को नए सिरे से गठित किया गया है। यह पुनर्गठन अधिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं तक पूर्ण है। प्रत्येक इकाई ज्ञान का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण, समग्र एवं विस्तृत गठन है जो अपनी उप-इकाइयाँ से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। इकाईयों का निर्माण बालक की रुचि एवं आवश्यकताओं पर आधारित है या इस विषय या पाठ के किसी विशिष्ट उद्देश्य पर। मारितन महाद्वय या इस योजना के समर्थक थे, न इकाइयाँ का आधार छात्रों के व्यक्तित्व में कोई विशेष परिवर्तन लाना भी बतलाया है। हमारे प्रदेश में पाठ्यक्रम अधिस्तरीय विषय क्षेत्र है। यहाँ प्रायः इकाइयाँ का आधार प्रकरणों की आपसी एकता एवं एकरूपता और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में एवं मानसिक शक्तियों में वांछित परिवर्तन लाना है। विषय के उद्देश्यों की स्पष्ट एवं निश्चित बनाने के लिए इकाई शिक्षण बहुत उपयोगी एवं प्रभावी है।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि परम्परागत शिक्षण में समय की पाबन्दी नहीं थी। किन्हीं शालाओं में पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त कर दिया जाता

परखने के लिए प्रत्येक इकाई में अंका की प्राप्ति का स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। उत्तम स्तर के लिए 5 अंक, अच्छे स्तर के लिए 4, साधारण के लिए-3, पास होने योग्य के लिए-2, असतोपजनक के लिए-1 तथा अनुत्तीर्ण के लिए-0 अंक। इस तरह शून्य और एक अंक पाने वाले छात्रों का शैक्षिक स्तर सुधारन के लिए कक्षा शिक्षक अतिरिक्त प्रयास करता है और सामान्य स्तर लाने हेतु बराबर मूल्यांकन भी करता है। इस तरह सतत् मूल्यांकन में एक योग्य शिक्षक अपने छात्रों के प्रति इतना सचेतनशील और सचेत रहता है कि कोई भी छात्र कमजोर रहने की बहुत कम गुंजाइश रखता है।

इस प्रकार मासिक मूल्यांकन, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी में छात्रों के सीख पाने के स्तर का अनुरूप निम्नलिखित आधारों पर ली जाती है—(1) लेखन के आधार पर, (2) मौखिक मूल्यांकन, (3) प्रयोगात्मक कार्यों के आधार पर मूल्यांकन, (4) प्रेरण विधि पर आधारित मूल्यांकन, (5) प्रत्यक्ष सम्पर्क, (6) छात्रों के सृजनात्मक क्रिया कलाप।

लिखित परीक्षा में निबन्धात्मक, वर्णनात्मक वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन होता है। मौखिक मूल्यांकन कक्षा पहली और दूसरी के लिए ही है। छात्रों के विविध क्रिया कलाप जैसे हस्तकौशल, मूलाद्योग, गृह कार्य तथा साक्षात्कारों के आधार मानकर भी मूल्यांकन किया जाता है।

इकाई शिक्षण और सतत् मूल्यांकन के लाभ

- (1) सतत् मूल्यांकन इकाई शिक्षण का अभिन्न अंग है। प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन होता है अतः छात्रों में नियमित अध्ययन करने की आदत का विकास हुआ है।
- (2) बालक कक्षाओं में भी ध्यान देते हैं वह जानता है कि प्रत्येक इकाई के बाद उसकी परीक्षा होगी।
- (3) बच्चे परिश्रम करते हैं और प्रत्येक लघु परीक्षा को तैयारी करते जाते हैं।
- (4) बालकों को प्रति माह अपनी उपलब्धि का ज्ञान रहता है। परीक्षा फल का ज्ञान अनुप्रेरणा के लिए एक भाव्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है।
- (5) बालकों में प्रतिस्पर्धा और उत्साह की भावना पैदा होती है।

- (6) पहले माता
एक बार ह
विवरण मिल
- (7) पालकों और
- (8) एक सफल
मिली भाति
- (9) छात्रों और
- (10) बच्चों को
- (11) अनुशासन की
- (12) अध्यापकों व
- (13) छात्रों का
- (14) छात्र की
- (15) प्रशासकीय
हाने से निरीक्षण
का काम चल
- (16) पालक के रूप
को जाने में अति
भी वही अर्थ पूरा
- (17) शिक्षकों में नियम
- (18) कमजोर बच्चों
की प्रति इकाई

इस प्रकार इकाई
कदम है। इसमें शिक्षा
शालाओं के पाठ्यक्रम का
शिक्षण और सतत
चुकी है। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक
अभी तक इसके काफी अच्छे

प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण

(Unversalisation of Elementary Education)

हमारा चिंतन हमेशा अटपटा सा रहता है। हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोचते हैं। ऊपर वाला की चिन्ता हम पहले करते हैं बाद में नीचे वालों की। हमारी शिक्षा में भी हमने वही चिन्ता की दिशा को माना है। बड़े बच्चों की चिन्ता हमने काफी की है और बहुत उनका ध्यान रखा है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खूब खोले हैं और खोलते चले जा रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया। उसी के मानस पुत्रों के रूप में प्रास्ता में भी उच्च शिक्षा अनुदान आयोगों का गठन हुआ। हमने शालेय शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग की कभी कल्पना ही नहीं की है। एक शिक्षक तथा कुछ राशि स्वीकृत कर हम प्राथमिक शाला खोल देने हैं, शिक्षक कहाँ रहगा, शाला कहाँ सगेगी इसकी कोई बात नहीं? महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के छात्रों को जो माहौल, जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे छोटे बच्चों को कहाँ मिलेंगी? छोटे को तो हम कहीं भी चयनरे पर, पटेल के बराड़े में या मंदिर में गिठाल कर पढा सकन हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अपने भवन ही नहीं कहीं-कहीं अनुपम भवन हैं, विशाल बहुमजिली अट्टालिकाएँ हैं। ये सब उन छात्रों के लिए हैं जो उम्र में बड़े हैं तथा घाबे समय के लिए शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, सगता है जैसे सफरीह करने जाते हो। वहाँ, कर्नाचर, उपकरण, पुस्तकालय, खेल-कूद की सुविधा, छात्रावास आदि सभी ठीक ठाक हैं, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा जिस माहौल में अपने बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उसे हम सभी जानते हैं। छोटे बच्चे बेचारे कुछ बोलने नहीं, कहने नहीं इसलिए उन्हें शायद सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, या दानवीरो का कभी है, या फिर वित्तीय साधन इतने नहीं हैं कि हम सबको बराबर सुविधाएँ जुटा पावें। यह भी सच है कि प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है और साधन सीमित है। परिवार और देश का समीकरण कुछ भिन्न मालूम पड़ता है। परिवार में जहाँ छोटे को ज्यादा हिस्सा मिलता है मुश्किल सुविधाएँ ज्यादा मिलती हैं कुछ बेसे भी और कुछ रो कर, रूठकर बड़ी देश में यह समीकरण उल्टा मालूम पड़ता है। बड़े लोग कुछ सुविधाएँ बेसे ही लेते हैं

और दाब धीस से। छोटा को जहाँ भी पढ़ाया जाय, जो भी पढ़ाया जाय सब ठीक सा लगता है। ऐसी स्थिति में जा होना था वही होता चला आ रहा है। अब हमारे सामने बसनी मुद्दा है प्रारम्भिक शिक्षा के लोक-यापन करण का और वह भी सीमित वित्तीय साधना के अंतर्गत। वस्तुतः हमारे सामन यह एक गंभीर चुनौती है।

प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए गठित राष्ट्रीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें छात्रों की दज संख्या की दृष्टि से पिछड़े भाठ राज्यों की सूची में म० प्र० का भी नाम सामिल किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 33 वर्ष बाद और म० प्र० निर्माण से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं बही जा सकती है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 45 में सविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंतर्गत 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प है। लेकिन इतन साल बाद भी यह संकल्प पूरा नहीं हो सका। 6-14 वर्ष की 109 लाख बच्चे म० प्र० में हैं। इनमें केवल 50.9 लाख शांताभा में पढ़ रहे हैं अर्थात् 51% ही शांताभा में आ सके हैं। 6-11 वर्ष के 63.05% तथा 11-14 आयु वर्ग के 30.5% बच्चे ही स्कूलों में पढ़ते हैं। सविधान के संकल्प का पूरा करण के लिए 6-11 आयु वर्ग के शेष 37 प्रतिशत बच्चे तथा 11-14 आयु वर्ग के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में लाने का भगीरप प्रयास हमें करना है। इसके लिए हमें समयबद्ध और व्यावहारिक योजना बनानी होगी। शिक्षा के लोक व्यापीकरण की समस्याएँ—प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के माग में अनेक समस्याएँ हैं। म० प्र० में प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं—

- 1—प्रदत्त का वित्पूत पैसात्र।
- 2—भौगोलिक असमानताएँ तथा परिस्थितियाँ।
- 3—अनुसूचित जाति और जन जाति।
- 4—जितने बालक शामिलार्ण शांताओ से बाहर हैं उनमें से निहाई संख्या बालिकाओं की है। इस प्रकार बालिकाओं की एक बड़ी संख्या शांताओ में लानी है।
- 5—पानका की गरीबी तथा उनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता।
- 6—सबसे जटिल समस्या शांता-यापी बच्चा की है। प्रत्येक वर्ष 100 लाख नए बच्चे 1 म गर्त होते हैं केवल 34 ही वर्षा 5 पास करते हैं और केवल 19 ही वर्षा 8 पास करते हैं।

7—शासनाओं में बालकों को लाने के माध्यम वाली समस्या यह है कि वे वक्ता 8 उत्तीर्ण करने तक शाला न छोड़ें ।

8—वित्तीय समस्या ।

9—शासनाओं का बालावरण अनाकंपक, शाला समय उपयुक्त न होना तथा पाठ्यक्रम उपयोगी न होना ।

म० प्र० में वर्तमान स्थिति

1 प्राथमिक शिक्षा—म० प्र० में 75 प्रतिशत बस्तियां में या उनके 1 कि० मी० के अंदर प्राथमिक शालाएं हैं। शेष 25 प्रतिशत बस्तियों में प्रदेश की कुल 10 प्रतिशत जनसंख्या है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 6-11 आयु वर्ग के बच्चे जो 79-80 वर्ष की स्थिति में 38 प्रतिशत हैं, और प्राथमिक शालाओं में नहीं आ रहे हैं उनमें से लगभग 10 प्रतिशत तो इसलिए नहीं आते कि आस पास शाला उपलब्ध नहीं है जब कि 28 प्रतिशत अन्य कारणा से नहीं आते हैं। इन 10 प्रतिशत बच्चों के लिए हम शालाएं खोलनी होंगी। 30 मितम्बर 1978 की स्थिति में 300 से अधिक जनसंख्या वाली लगभग 2400 बस्तियां में जिनमें 1150 आदिवासी क्षेत्रों में हैं, स्कूल नहीं हैं। वर्ष 80-81 में ऐसी सभी बस्तियां में शालाएं खोली गई हैं। इसके अलावा 300 से कम जनसंख्या वाली लगभग 24000 बस्तियां में शालाएं नहीं हैं जिनमें से 12000 बस्तियां आदिवासी क्षेत्रों में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में जनसंख्या वितरणी होती है, आदिवासी क्षेत्रों में स्थित ऐसी बस्तियां में अधिक-से-अधिक शालाएं खोलने का प्रयास किया जाना होगा। गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी हम ऐसी जगह उन्नतता से शालाएं खोलने की अनुमति ग्रामन से मिलना चाहिए जहां कुछ जन सहयोग प्राप्त हो सकें।

2 पूर्व माध्यमिक शिक्षा—म० प्र० में 78-79 की स्थिति में 6 प्राथमिक शालाओं के लिए एक पूर्व माध्यमिक शाला है (अखिल भारतीय औसत प्रति 9 प्राथमिक शाला पर दो पूर्व माध्यमिक शाला है)। एक पूर्व माध्यमिक शाला औसतन लगभग 50 वर्ष कि० मा० (अखिल भारतीय औसत 30 वर्ष कि० मी०) तथा लगभग 5000 जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत 5500 जनसंख्या) के लिए है। यद्यपि जनसंख्या के आधार पर हम अखिल भारतीय औसत से बेहतर हैं तथापि क्षेत्रफल के औसत में अखिल भारतीय स्तर में 60 प्रतिशत पर ही हैं। यह सब विरल आबादी का ब्रह्म है। क्षेत्रफल में भी अखिल भारतीय स्तर में पहुँचने के लिए यदि ऐसे स्थानों में जहाँ से तीन

शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार

कितनी मीटर क्षेत्र में (क्षेत्रफल लगभग 28 वर्ग कि० मी० होगा) जिसमें 500 या अधिक जनसंख्या है एक पुर्व माध्यमिक शाला आवश्यक होगी। इस प्रकार लगभग 8500 पुर्व माध्यमिक शालाएं आवश्यक होंगी। प्रदेश में जिस स्तर पर पुर्व माध्यमिक शालाएं खोली गई हैं उस हिसाब से हम लगभग 20 वर्ष में ये शालाएं खोल सकेंगे। संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए अधिक पुर्व माध्यमिक शालाएं खोलनी होंगी। शालाएं खोलने के लिए मुख्य रूप से दो खर्चे होंगे हैं—एक तो शिक्षक। रा बतन तथा दूसरा इमारत बनाने में। सोसरे वर्ष लगभग 19,000 तथा चौथे वर्ष में लगभग 22,000 रु० होता है। उसके बाद प्रति वर्ष लगभग 25000 रु० खर्च होता है। इस आधार पर 8500 पुर्व माध्यमिक शालाएं खोलने से चौथे वर्ष से लगभग 25 करोड़ रु० प्रतिवर्ष लगेगे। शालाभवन बनाने में लगभग 1 लाख रु० लगते हैं, इस हिसाब से शाला भवनो पर भी एक विशाल राशि व्यय होगी।

जं सटया की समीक्षा (1978) (दज सटया लाखो मे)

भारत		म० प्र०		योग प्रतिशत	
आयु वर्ग	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत	बा० बालि०
6-11	432	281	1385	29.88	13.98
11-14	125	90	59	10.185	47.779
6-14	557	90	340	10.898	69.37
				67.16	64.54
				31.50	75.75

उपयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 6-11 आयु वर्ग में हम राष्ट्रीय स्तर से लगभग 22 प्रतिशत पीछे हैं, 11-14 आयु वर्ग में 12 प्रतिशत और 6-14 आयु वर्ग में 18 प्रतिशत दज संख्या में पीछड़े हुए हैं।

छटी योजना 80-85 की स्थिति—म० प्र० में छटी याचना के अंत में जो समाविष्ट बालका की संख्या प्रोपिन की गई है वह इतनी ज्यादा है कि हमें अतिरिक्त भर्ता होने वाले छात्रों के लिए काफी वैलिक सुविधाएं जुटानी होगी।

मध्य प्रदेश

आयु वर्ग	31 मार्च से 85 को बालका की कुल संख्या (लाखों में)		अतिरिक्त दर्ज होने वाला की संख्या (लाखों में)	
	कुल	बालिकाएँ	कुल	बालिकाएँ
6-11	85 13	40 66	41 27	26 70
11-14	48 08	23 30	27 63	20 64
6-14	133 21	63 96	68 90	47 34

इस प्रकार यदि छोटी योजना के अंत तक हमें सरिधान की मंशा को पूरा करना है और 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को शालाभा में लाना है तो 69 लाख लड़का को जिनमें लगभग 47 लाख लड़कियां होंगी—इन सबके लिए हमें अतिरिक्त व्यवस्था करना होगा।

छोटी योजना में व्यूह रचना—छोटी योजना 1980-85 में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें काफी प्रयास करना होगा। चूंकि वित्तीय साधना की कमी रहती है अतः सीमित साधना में ही अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु हमें प्रमुख रूप से जिन दिशाओं में वृद्धि कार्य करना है, वे ये हैं—

- (1) बालिकाओं की शिक्षा।
- (2) अनुसूचित जाति और जन जातियों की शिक्षा।
- (3) शाला त्यागी और शाला अप्रवेशी बालकों की शिक्षा।
- (4) शिक्षा में गुणात्मकता के प्रयास।
- (5) शालाओं में भौतिक सुविधाओं का विकास।

बालिकाओं की शिक्षा—शिक्षा के लोक व्यापीकरण में सबसे प्रमुख समस्या बालिकाओं की शिक्षा की है। 30 सितम्बर 1979 की स्थिति में 6-11 आयु वर्ग की बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 42 है तथा 11-14 आयु वर्ग में

शिक्षा में नए मायाम एवं नवाचार

15-30 प्रतिशत हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि 6-11 आयु वर्ग की 58 प्रतिशत तथा 11-14 आयु वर्ग की 83.7 प्रतिशत बालिकाएँ स्कूलों के बाहर हैं। बालिकाओं की इतनी बड़ी संख्या को स्कूलों में लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इसके लिए हम बहुत मायामों का प्रयास करना होगा। बालिकाओं की दृष्टि बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास जो हम कर रहे हैं वे छोटी योजनाओं में भी चालू रहेंगे तथा कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं—

- 1—गरीब बालिकाओं के लिए गणवेश की व्यवस्था।
- 2—हर्जित तथा आन्विषी छात्राओं की निशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
- 3—बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था।
- 4—उपयोजना क्षेत्र में आश्रम शालाओं की स्थापना।
- 5—पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाओं की स्थापना।
- 6—महिला शिक्षकों की नियुक्ति।
- 7—औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 9-14 आयु वर्ग की शाला स्थापना।
- 8—महिला शिक्षकों के लिए आश्रम शालाओं की स्थापना।
- 9—गरीब बालिकाओं के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।
- 10—छात्राओं की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन।
- 11—उपयोजना क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातों की एक विभाजन संस्था है। प्र.स.स. 13.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा कुछ आबादी का 21 प्रतिशत जनजातों हैं। इनकी विद्यालय आबादी के दोषों को दूर करना भी एक बड़ा कार्य होगा। इनकी शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है—

अनुसूचित जाति (दज सप्या 1979-80)

आयु वग	बासक	बासिका	योग	प्रतिशत
6-11	448992	151615	600607	62 2
11-14	109453	20203	129656	25 4
अनु० जन जाति				

आयुवग	बासक	बासिका	योग	प्रतिशत
6-11	539979	176243	716222	49 5
11-14	79787	16069	95856	12 2

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित और अनु० जनजाति की शिक्षा भी काफी पीछे है। छठी योजना के अंत तक इनकी दज सप्या लभ्य प्राप्त करने के लिए गहन प्रयास करना होगा—

छठी योजना में इन वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष याजनाएँ प्रस्तावित हैं—

- (1) अनुसूचित एवं जन जाति के छात्रा के लिए मध्याह्न आहार की व्यवस्था।
- (2) कक्षा 3 से 11 तक अध्ययनरत अनु जाति व जन जाति के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके।
- (3) छात्राओं का मुपन गणवेश।
- (4) छात्र वृत्तियों की अदायगी।
- (5) गरीब अभिभावक को आर्थिक प्रोत्साहन देकर छात्र सख्या में वृद्धि।
- (6) छात्र वृद्धि हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहन।
- (7) 300 या 300 से अधिक जनसख्या वाली बस्तिया में शालाएँ खोली जाना।
- (8) पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाओं की स्थापना।
- (9) बिरली आबादी वाले क्षेत्र में माध्यम शालाओं की स्थापना।

- (10) शालावृत्ता की स्थापना ।
- (11) मिलन मंडई कार्यक्रमों का आयोजन ।
- (12) खेल कूद के लिए विशेष कार्यक्रम ।
- (13) विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु म्युजियम का स्थापना ।
- (14) स्थानीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों की रचना एवं शिक्षण ।
- (15) स्वाउटिंग एवं गार्डिंग में प्रशिक्षण ।
- (16) शिक्षक शिक्षिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण ।
- (17) पुस्तकालयों की स्थापना ।
- (18) 9-14 आयु वर्ग के शाला स्थापना एवं शाला अप्रवेशी, बुविद्या वचित बालकों के लिए औपचारिकतर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना ।

शाला स्थापना एवं शाला अप्रवेशी बालकों की शिक्षा

9-14 आयु वर्ग के ऐसे छात्र छात्राएँ जिन्होंने बीच में शाला छोड़ दी हैं या स्कूल गए ही नहीं, उनके लिए औपचारिकतर शिक्षा व्यवस्था फरवरी सन् 1975 से म० प्र० में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1979-80 तक प्रदेश में 2450 औपचारिकतर शिक्षा केन्द्र संचालित हैं जिनमें लगभग 45000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। छठी योजना में लगभग 60 हजार केन्द्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि छात्रों की वृहद् संख्या जो शालाओं से बाहर है यदि शिक्षित करना है तो यही एक विकल्प है। हमारे पास इतने औपचारिक साधन नहीं हैं कि हम इन छात्रों का स्कूल छोड़कर शिक्षित कर सकें। वित्तीय प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ष इन्हें खोला जाना आवश्यक होगा।

शिक्षा में गुणात्मकता के प्रयास—शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए यह एक आवश्यक बात है कि बालक शाला आने के साथ शाला में रहें भी। इसके लिए हमें शिक्षा में गुणवत्ता के प्रयास करने होंगे। छठी योजना में कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार किए जाने का प्रावधान है—

- (1) पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण ।
- (2) शिक्षकों का विज्ञान एवं भाषा में प्रशिक्षण ।
- (3) राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना ।
- (4) आदर्श शालाओं की स्थापना ।
- (5) प्रशासन का सुदृढीकरण ।
- (6) शाला सगमों की स्थापना ।
- (7) स्थानीय भाषा में शिक्षण ।

(8) पाठ्यक्रम में स्थानोद्य आवश्यकतानुसार परिवर्तन ।

(9) पुस्तकालयों की स्थापना ।

(10) शास्त्राया की स्थापना ।

भौतिक सुविधाओं का विकास—प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए शास्त्राया और शिक्षकों के लिए भौतिक सुविधाएँ भी आवश्यक हैं । निम्नानुसार भौतिक सुविधाएँ छठी योजना में किए गए हैं—

(1) शास्त्राओं में फर्नीचर टाट पट्टी का प्रदाय ।

(2) विज्ञान किट का प्रदान ।

(3) शास्त्रा भवना का निर्माण ।

(4) शिक्षकों के लिए आवास गृहा का निर्माण ।

उपयुक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी हम छठी योजना के अंत तक 6-11 आयु वर्ग में लगभग 80 प्रतिशत तथा 11-14 आयु वर्ग में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे सक्षय का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से भी कम होगा । इस प्रकार हम एक विशाल और पवित्र कार्य में जुटना होगा । हमें अपने सीमित साधना में ही पूरा प्रयास करके इस पुनीत कार्य को पूरा करना है । यद्यपि हमारे पास भौतिक और वित्तीय साधना की कमी है लेकिन हमारे पास चाह है और लक्ष्य तक पहुँचने की आकांक्षा है । इसलिए मजिल अवश्य मिलेगी ।

छात्रवृत्तियाँ एवं प्रतिभा की खोज

(Scholarships and Talent Search)

प्रत्येक व्यक्ति का अवसर की समानता मिलना चाहिए जिससे वह शिक्षित होकर देश का अच्छा नागरिक बन सके और स्वयं का भी विकास कर सके। सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति सभी समभव है जब कि प्रत्येक शिक्षा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र का क्यों न हो, शैक्षिक अवसरों की समानता मिले। हमारे देश और विशेषतः से मध्य प्रदेश में अनेक भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषमताएँ और भिन्नताएँ हैं। मध्य प्रदेश के एक ही समाग में इंदौर नगर या इन्दौर जिला सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है तो उसी समाग का झाबुआ जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अनेक सुविधाएँ हाते हुए भी शैक्षिक अवसरों की असमानताएँ विद्यमान हैं।

शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण

- 1—हम अभी भी सभी बस्तियों में शालाएँ नहीं खोल सके हैं, अतः जहाँ शालाएँ हैं वहाँ के बालकों का अधिक शिक्षा की सुविधा है और जहाँ शाला नहीं हैं वहाँ के बालकों का शिक्षा प्राप्त करने का कम अवसर मिलता है।
- 2—जहाँ या जिन बस्तियों में शालाएँ भी हैं वहाँ के गरीब वर्ग के बालकों शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बालकों से पीछे रहते हैं।
- 3—सभी जगहों की शालाओं में समान सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मध्य प्रदेश के समान अवसर भी नहीं हैं।
- 4—बालकों का घरेलू परिवेश भी भिन्न-भिन्न है, जो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक प्रमुख कारण है। सुविधा वंचित व्यक्तियों के बालक बालिकाएँ, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में निवास करने वाले बालक-बालिकाएँ, शहर के निवासियों की अपेक्षा शिक्षा प्राप्ति के कम अवसर प्राप्त कर पाते हैं।

5—गरीबी-रेश एवं प्रदेश में व्याप्त गरीबी भा अवसरों की समानता में बाधक है।

उपयुक्त विषयताओं को दूर करना इतनी जल्दी आसान नहीं है क्योंकि अभी तो हम शिक्षा खोजत जा रहे हैं। शिक्षा के साव-जनीकरण तथा लोकतन्त्र की प्रगति और सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के अवसरों की समानता उपलब्ध कराने हेतु सघन प्रयास किए जाय। इससे हम विषयताओं को पूरा-पूरा दूर न भी कर सकें तो भी कम तो कर ही सकते हैं।

शैक्षिक अवसरों की विषमता का मध्य प्रदेश या देश में सबसे प्रमुख कारण है—गरीबी/मनुष्य को अपने बाल बच्चों के पेट भरने की समस्या सबसे प्रमुख है। वह शिक्षा की बात बाद में सोचना है और रोटी की बात पहले। अतः शैक्षिक अवसरों की विषमताओं को हटाने के लिए प्रमुख प्रत्यक्ष यह होना चाहिए कि हम अभिभावकों या उनके बालकों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद दें। अतः यह आर्थिक मदद हम छात्रों को छात्र वृत्तियाँ प्रदान कर दे सकते हैं। इससे एक ओर जहाँ प्रतिभा की खोज होगी वही दूसरी ओर उन्हें अच्छी शालाओं की व्यवस्था कर उन्हें अनुकूल शिक्षा भी दे सकते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के सौक्य व्यापीकरण के लिए सुविधाहीन तथा प्रतिभावान बालकों को शिक्षा के सुअवसर जुटाने के उद्देश्य से तथा प्रतिभाओं को खोज कर उनके विकास के माग विकसित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ कायम करने का अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। छात्रवृत्तियों पर होने वाला व्यय में निरंतर वृद्धि की जा रही है। दश की समस्त शासकों में अध्ययनरत प्रतिभाओं तथा सुविधाहीन गरीब बालक बालिकाओं को चाहें वे किसी वर्ग या क्षेत्र में हों, छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के प्रति शासन पूर्णतया सजग है। पूर्व में छात्रवृत्तियों का लाभ केवल गरीब या उच्च वर्ग के बालकों को ही प्राप्त हो पाता था क्योंकि गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बालक उस स्तर तक नहीं आ पाते थे जिस स्तर पर उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती थी, परन्तु वर्तमान में शासन का ध्यान गरीब एवं पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण जनता में छिपी प्रतिभाओं की ओर भी गया है। इन प्रतिभाओं की निरंतर खोज की जा रही है तथा उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए अवसरों की विषमताओं को दूर करने की शिक्षा में प्रयत्न किए जा रहे हैं एवं इस दिशा में हमने काफी सफलता भी प्राप्त की है।

छात्रवृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ प्रदान करने के कार्यक्रम को दो स्तरों में विभक्त किया जा सकता है —

- (1) केन्द्रीय स्तर पर
- (2) राज्य स्तर पर।

केन्द्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ

ये छात्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। ये छात्रवृत्तियाँ योग्यता के आधार पर दी जाती हैं तथा इनका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। भारत सरकार प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर कुछ निश्चित छात्रवृत्तियाँ बाँट देती है। इन्हें राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार देती हैं। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ निम्नानुसार हैं।

- (1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (सावजनिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाने वाली राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति।
- (2) आवासीय माध्यमिक स्कूला के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।
- (3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना।
- (4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना।
- (5) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति।
- (6) राष्ट्रीय सांख्यिकी खोज छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्तियों का विवरण—इन राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार है—

(1) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति—उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या हाई स्कूल परीक्षा (सावजनिक परीक्षा) में प्राप्तियों के आधार पर योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक प्राप्ति के लिए अलग-अलग संख्या निश्चित है। हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी के बाद पढ़ने वाले छात्र छात्रावास को य प्रदान की जाती है।

(2) आवासीय छात्रवृत्ति योजना—हर प्रदेश में कुछ आवासीय पब्लिक स्कूल हैं। प्रतिभावान छात्रों को आवासीय छात्रवृत्ति परीक्षा द्वारा चुनकर उच्च आवासीय पब्लिक स्कूलों में भर्ती कर शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती है।

(3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा/छात्रवृत्ति योजना—इस परीक्षा द्वारा अच्छे प्रतिभावान बालकों को चुनकर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे वे आगे की पढ़ाई चालू रख सकें।

(4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना—शिक्षा के क्षेत्र में भारत शासन की अनेक योजनाओं में से विज्ञान प्रतिभा खोज एक महत्वपूर्ण

नियम

- 1 राज्य क प्रत्येक विकास खण्ड क लिए दा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
 - 2 इस परीक्षा म कक्षा 8 की सावजनिक परीक्षा म उत्तीर्ण छात्र प्रति ब्लाक प्रथम 20 छात्र बैठ सकते हैं।
 - 3 ये छात्र वृत्तियाँ तीन वर्षों के लिए हैं ज़ा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं मे नियमित पढ़न पर दी जाता है। प्रति वर्ष 9 की एव 10 की कक्षाओं म उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - 4 राज्य की चयनीकृत आदेश उच्चतर माध्यमिक शालाओं मे अध्ययन करने पर ही छात्रवृत्ति मिलती है।
 - 5 ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति की राशि 100 रु० प्रति माह है जो कक्षा उत्तीर्ण करने पर तीन वर्षों तक प्राप्त होती है।
 - 6 समुदायिक विकास खण्ड/ब्लादिम जानि विराम खण्ड के 10 हजार जनसंख्या स कम जनसंख्या वाले क्षेत्र म स्थित पूव माध्यमिक शाला से आठवी कक्षा उत्तीर्ण करने वाला छात्र जा विकास खण्ड की प्रावीण्य सूची म प्रथम 20 छात्रों म जाया ह्वा इस परीक्षा मे बैठ सकता है।
- घोशना का क्रिया-कथन—ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत म० प्र० म आयोजित परीक्षा म छात्रवृत्ति की स्थिति इस प्रकार है—

योजना वर्ष	निधारित छात्र वृत्तियाँ की संख्या	छात्रवृत्तियाँ क प्राप्त छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति की राशि
1971-72			
1972-73	914	597	110800
1973-74	914	803	932500
1974-75	914	772	1308000
1975-76	914	726	14,72,800
1976-77	914	779 ¹	11,15,000
1977-78	914	779	11,15,000
1978-79	914	775	11,80,000
1979-80	916	805	12,12,420
		824	17,40,000

सं० प्र० मन्त्र 1972 से लेकर वर्ष 1980 तक ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों की कक्षावार स्थिति तथा व्यय गई छात्र वृत्तियाँ इस प्रकार हैं—

वर्ष	छात्रों की संख्या	कक्षा	व्यय गई छात्र-वृत्तियाँ
1971-72	558	9 वीं	317
1972-73	1045	9 वीं, 10वीं	61
1973-74	1572	9वीं, 10वीं एवं 11वीं	142
1974-75	1941	बही	188
1975-76	1325	तथैव	68
1976-77	1416	तथैव	135
1977-78	1416	तथैव	139
1978-79	1718	तथैव	108
1979-80	1800	तथैव	92

उपर्युक्त आंकड़ा से पता चलता है कि लगभग 20% छात्र वृत्तियाँ व्यय चली जाती हैं।

(6) राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्र-वृत्ति—संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्र वृत्तियाँ का भी राज्यवार कोटा निश्चिन् है।

राज्य स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ

राज्य स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ/शिष्यवृत्तियाँ भी कई प्रकार की हैं। प्रजातान्त्रिक देश में शिक्षा के समान व्यवसर प्राप्त होने की दिशा में छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ एक महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रतिभावान, मेधावां तथा निधन छात्रों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियों एवं शिष्य

में 45% से कम अंक प्राप्त करने वाला कोई भी छात्र इसका पात्र नहीं हो सकता है।

2—हरिजन/आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ—उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत प्रत्येक हरिजन आदिवासी छात्र, छात्रा को निर्धारित दर पर आ० जा० क० विभाग द्वारा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

3—मृत अपंग शासकीय कर्मचारियों के बालकों का छात्रवृत्ति—यह छात्र वृत्ति 3 वर्षों के लिए दाय होती है।

4—शालाओं में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के लिए खेलकूद छात्रवृत्ति—छात्र वृत्तियों की कुल संख्या 28 है जिसमें आधी छात्राओं के लिए है।

5—पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को छात्र वृत्तियाँ—पूर्व माध्यमिक स्तर पूरा के करने पर ये छात्र वृत्तियाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी 3 वर्ष के लिए चालू रहती हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित परीक्षा में सफल होने पर यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ होती है।

6—समर्पण करने वाले डाकुओं के बालकों एवं दस्यु पीड़ित बालकों को छात्र वृत्तियाँ—यह सीमित साधनों वाले छात्रों को दाय होनी हैं और इनका निर्धारण क्लेरेटर करता है।

7—सैनिक स्कूल रोवा में अध्ययनरत बालकों की छात्रवृत्तियाँ—सैनिक स्कूल रोवा में अध्ययन रत सभी उच्चतर माध्यमिक बालकों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

8—ग्रामीण प्रतिभा छात्र छात्र वृत्ति—ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज एवं उन्हें शिक्षा के सुमवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण शालाओं से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र जो विकास खण्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम बीस में स्थान प्राप्त करते हैं, इस छात्र वृत्ति की परीक्षा में वैदिके-पाल होते हैं। प्रति विकास खण्ड 2 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 100 रु० प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। अवधि तीन वर्ष है।

9—सांस्कृतिक प्रतिभा खोज—भारत के समस्त राज्यों में 100 छात्र-वृत्तियाँ हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर दाय हैं, केन्द्र सरकार देती हैं। राज्य सरकार ता वैदिक धर्म का काम करती है।

- 10—मृत सैनिका के बच्चा एवं पत्नियों को छात्रवृत्ति—पिछले भारत-पाक युद्ध या भारत-चीन युद्ध में मृत सैनिकों के बच्चों एवं पत्नियों को आग-पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- 11—योग्यता एवं निधनता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति—उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वर्ष के लिए तथा पुनः प्रवेशना पत्र देने पर आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है।
- 12—उच्चतर माध्यमिक शास्त्रांशों में ससृजन विषय (डी ग्रुप) में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ—इन छात्रवृत्तियों की संख्या पूरे प्रदेश के लिए प्रति वर्ष 74 है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की संख्या 9 से 11 तक ससृजन विषय 'डी' ग्रुप में होना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति 3 वर्षों के लिए दी जाती है।

महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रवृत्तियाँ

- 1—हरिजन एवं आदिवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ उच्च शिक्षा में पढ़ रहे प्रत्येक हरिजन, आदिवासी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- 2—संगीत तथा कला हेतु छात्रवृत्तियाँ—यह छात्रवृत्तियाँ, गायन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला एवं नृत्यकला आदि के लिए दी जाती हैं, अवधि 2 वर्ष, राशि 25 रु० प्रति माह।
- 3—शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्ति—उपाधि पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। स्नातक स्तर पर तीन वर्षों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
- 4—विज्ञान के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति—विज्ञान के मेधावी छात्रों को स्नातक स्तर पर 60 रु० प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 75 रु० प्रति माह के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दी जाती है। भारत शासन द्वारा बी० एम० सी० के लिए 150 रु० प्रति माह, एम० ए० सी० के लिए 200 तथा पी० एच० डी० के लिए 350 रु० प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।
- 5—योग्यता एवं निधनता के आधार पर विशेष छात्रवृत्तियाँ—एक मुख्य अनुष्ठान या अन्य छात्रों को निधनता तथा योग्यता के आधार पर

एक पाठ्य की आयु सोमा के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अन्य छात्र वृत्तियाँ

- 1—संगीत एवं कला के लिए छात्र वृत्तियाँ—गायन, वादन, नृत्य, चित्र-कला, मूर्ति-कला, वास्तु कला, प्रत्येक के लिए तीन-तीन छात्र वृत्तियाँ हैं। ये योग्यता के आधार पर निर्दिष्ट होती हैं।
- 2—नौ सेना तथा सेना छात्रवृत्तियाँ—इनकी संख्या 8 है। ये छात्र वृत्तियाँ योग्यता के आधार पर कमांडेंट, भारनाथ राष्ट्रीय मिलिटरी कालेज देहरादून, वेष्टन सुपरिटेन्डेंट ट्रेनिंगशिप बम्बई, तथा डिस्ट्री डायरेक्टर मरीन इंजीनियरिंग कसकला, की सिफारिशों पर स्वीकृत की जाती हैं। ये छात्र वृत्तियाँ 10%—प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए स्वीकृत होती हैं।
- 3—राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति—इन छात्र वृत्तियों की संख्या 8 है। इनमें से 6 छात्र वृत्तियाँ छात्रों के लिए हैं, जब, यस और वायु सेना में प्रत्येक के लिए दो-दो के हिसाब से। शेष 2 छात्र वृत्तियाँ घन सेना में छात्रों के लिए हैं।
- 4—शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्ति—पल्लोपाधि एवं प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ये छात्र वृत्तियाँ हैं। प्रत्येक के लिए 15-15 छात्र वृत्तियाँ हैं।
- 5—संस्कृत शास्त्राग्रे में छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ—
(अ) प्रथम स्तर पर 100 छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ।
(ब) मध्यमा स्तर पर—इस स्तर पर छात्रवृत्तियाँ वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय की प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा अंश समकक्ष परीक्षा में 'यून-सम 60% अंक पाने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

प्रथमा स्तर पर 10 रु० प्रति माह के हिसाब से 3 वर्षों के लिए पूर्व मध्यमा स्तर पर 20 रु० प्रतिमाह के हिसाब से 2 वर्षों के लिए तथा उत्तमा स्तर पर 25 रु० प्रति माह के हिसाब से 2 वर्षों के लिए छात्र वृत्ति एवं शिष्य वृत्ति दी जाती है।

वर्तमान कार्यक्रम की अपर्याप्तता

1 छात्र वृत्ति देने का कार्यक्रम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

वर्तमान में यह कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ विस्तार की ज़रूरत

भी आवश्यकता है। बहुत से गरीब छात्र अभी भी आर्थिक परेशानी की वजह से बीच में पढ़ना छोड़ देने हैं। हरिजन एवं आदिवासी छात्रों के लिए तो अनिवार्य रूप से छात्र वृत्तियाँ और शिक्ष्य वृत्तियाँ, नि शुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान है किन्तु जो गरीब हैं किन्तु गैर आदिवासी हैं उन्हें छात्र वृत्तियाँ या अन्य वित्तीय सहायता का पूरा-पूरा प्रावधान नहीं है।

- 2—बहुत सी छात्र वृत्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। ऐसी व्यवस्था की कमी है कि इनका पूरा लाभ उठाया जा सके।
- 3—छात्र वृत्तियों के लिए उपयुक्त छात्र चयन करने के तरीके भी पूर्णतया ठीक नहीं हैं।
- 4—ग्रामीण बालकों का स्तर कुछ कम होने से वे शहरी बालकों की प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाते हैं।
- 5—राष्ट्रीय छात्र वृत्तियों का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। कहीं कोई कमी अवश्य है।
- 6—किसी छात्र वृत्ति के लिए निश्चित शर्तनामों में ही पढ़ने का बंधन है, जो उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है।
- 7—जो छात्रवृत्ति धारी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर शालाएँ छोड़ कर चले जाते हैं उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रहनी है। अतः उन्हें मार्ग दर्शन देने हेतु कोई कार्यक्रम नहीं रह जाता है।
- 8—छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह नहीं मिलती है जिससे गरीब छात्रों को दिक्कत आती है।
- 9—छात्रवृत्तियों की राशि भी पर्याप्त नहीं है।

छात्र-वृत्ति कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव

छात्रवृत्ति योजना की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित सुझावों को काय रूप दिया जाना आवश्यक है—

- (1) शालेय स्तर पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम में विस्तार किया जाना चाहिये। इन छात्र वृत्तियों को महाविद्यालयीन स्तर पर भी चालू रखा जाना चाहिये ताकि बालकों की पढ़ाई का क्रम न टूटे।
- (2) छात्रवृत्तियों के लिये योग्य छात्रों को चयन करने के नियमों तथा शर्तों में सुधार एवं कुछ नये तरीके धाँज जाँच ताकि निष्पक्ष रूप से छात्रों को लाभ मिल सके।

शिक्षा म नए आयाम एव नवाचार

- (3) छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से महरी और ग्रामाण क्षेत्र की शालाओं को असंग-असंग माना जाव ।
- (4) छात्र वृत्तियाँ के लिय बालवा को प्रेरित करन क लिये गहन प्रचार-प्रसार आवश्यक है ।
- (5) शिक्षा सत्याएँ सत्तारम्भ स ही मेधावी छात्रा का चयन कर आव-श्यकतानुसार उनका विवास करने तथा प्रतिस्पर्धा पराकाष्ठा के लिये उन्हें तैयार करने हेतु सत्यागत योजना बना सकती हैं ।
- (6) छात्रवृत्ति धारियों के अध्ययन हेतु जो शालाएँ शासन द्वारा चयन की जाती हैं उनको सर्व सुविधा सम्पन्न बनाया जाना चाहिये ।
- (7) छात्रवृत्ति पाने वाले जो छात्र हायर सेकेंडरी या मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु मागदर्शन, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा उनके बारे म सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनके लिय विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाय ।
- (8) छात्र वृत्तियों की राशि समय-समय पर बढ़ाई जानी चाहिय जिससे छात्रो को असुविधा न हो ।
- (9) छात्र वृत्ति अदायगी की प्रक्रिया सरल बनाई जाय ।
- (10) छात्र वृत्ति को राशि प्रति माह वितरित की जानी चाहिय ।
- (11) राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिय छात्रा को तैयार करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाया जावे ।

सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो टीचिंग)

(Micro-teaching)

पृष्ठभूमि—बासकों की शिक्षा के लिये शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण साधन है जन अच्छे शिक्षकों की तैयारी के लिये हम अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में इसी मूल तत्त्व के प्रति हमारी प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा शिक्षा महाविद्यालय समर्पित हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं, शिक्षा महाविद्यालयों की सहायता में काफी वृद्धि हुई है किन्तु गुणवत्तात्मक दृष्टि से उतना अपेक्षित विश्वास नहीं हुआ है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं, शिक्षा महाविद्यालयों में प्रचलित कार्यक्रमों की प्रायः यह आलोचना की जाती है कि वे अत्यधिक जड़ एवं परम्परावादी होने के कारण शिक्षा के बदलते हुए रूपों को पूरा करने में भी असमर्थ हैं। इन कार्यक्रमों में व्यावहारिक कार्य के बजाय सैद्धांतिक चर्चाओं को अधिक स्थान दिया गया है। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान हम देते हैं उसका हमारे मागदर्शन एवं प्रयत्न में किये जाने वाले अध्यापन अभ्यास से बहुत कम सम्बन्ध रहता है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं, शिक्षा महाविद्यालयों में जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है वह व्यवहार में कम उपयोग होता है। उनसे न तो प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता ही संतुष्ट हैं और न ही प्रशिक्षण देने वाले विद्वत्जन, फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करने की अनेक शिक्षा-शास्त्री तैयार कर रहे हैं। शिक्षा महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं के 200 दिनों के शिक्षा सत्र में केवल 40 काल खण्ड में ही अध्यापन अभ्यास कराया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप देने एवं उसमें सुधार करने के लिये सभी आयोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) कोठारी आयोग (1964-66) तथा वर्तमान में एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनेक संगोष्ठियों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नई दिशा देने के लिये कार्यक्रमों पर चर्चा हो चुकी है। इन शिक्षा आयोगों ने प्रशिक्षण संस्थाओं के आपसी सम्बन्धों तथा शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध, पाठ्यक्रम पाठ्य विधियों, शिक्षण विधियों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार प्रकट किये हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घुंरो है जिस पर शिक्षा की गुणवत्ता आधारित है। किन्तु शिक्षक प्रशिक्षण की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है। पाठ-सप्त निर्माण की विधि में मनोविज्ञान के उत्प्रेरणा एवं सीखने सम्बन्धी आधुनिक सिद्धांता के लिये स्थान नहीं है। ज्ञानवर्धन के ही ठपर अधिक ध्यान दिया जाता है और शिक्षा के अधिक स्थायी उद्देश्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम परम्परागत तरीके से हरवट के पाँच पदों (steps) का मशीन की तरह अनुकरण करते हैं। पाठयाजना और अध्यापन अभ्यास के लिये पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन भी अधिक प्रभावशाली नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण में प्रयुक्त विधियों तथा गणनाओं में प्रति दिन काम आने वाली विधियों में कोई समानता नहीं रहती है। शिक्षक प्रशिक्षक भी इन विधियों में कोई आस्था पैदा नहीं कर पाते हैं जिनका कि वे समर्थन करते हैं। परिणाम यह होता है कि छात्राध्यापक अपनी प्रशिक्षण उपाधि लेकर श्यामपट पर लेखन के साथ व्याख्यान की पुरानी पद्धति अपना लेते हैं।

उपयुक्त परिस्थिति हम शिक्षकों की तैयारी के समग्र कार्यक्रम पर गंभीरता से विचार करने को बाध्य करती है। यदि हम शिक्षण के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करना है तो सामान्य शिक्षण और कक्षा में शिक्षक व्यवहार पर गंभीरतापूर्वक एवं निरन्तर अनुसंधान करना होगा। विभिन्न प्रकार की नई प्रविधियों, कक्षा शिक्षण में शिक्षक के व्यवहार, गुण आदि के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन करना होगा। पुरानी कार्यप्रणाली, शिक्षा पद्धतियाँ हमें बदलनी होंगी और नई विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे शिक्षकों में शिक्षण कला के बहुमुखी पक्ष विकसित हो सकें। सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो टीचिंग) प्रणाली इस शिक्षा में एक नई विचार धारा है जो कि शिक्षक का सम्पूर्ण कार्यकाल में एक कुशल शिक्षक बनाए रखती है।

सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग—माइक्रो टीचिंग का सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक अभिनव प्रविधि (तकनीक) है। इसका प्रारम्भ छठवें शताब्दी के प्रारम्भ में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। यह पद्धति विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत में प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त की जा रही है। इस प्रविधि के अनेक पहलुओं पर शोध कार्य हो चुके हैं। यह प्रविधि शिक्षकों के कक्षापन व्यवहारों में परिवर्तन हेतु प्रभावी पाया गया है। यतिनर, वोग, गुडकाइड, बालनवेच, पासी शाह, अब्राहम आदि अनेक विद्वानों ने इसे प्रविधि के सम्बन्ध में शोध कार्य किये हैं। यह प्रविधि प्रश्नोत्तर कोशल (Questioning Skill), पुनर्वर्तन (Re-inforcement) कोशल के विकास में भी अत्यन्त प्रभावी पाई गई है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान एवं बालिका शिक्षा निधि समिति

(National Teacher Welfare Foundation and Girls Education Fund Committee)

समाज में शिक्षकों के सम्मान और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना तथा सकट काम में उनकी सहायता की दृष्टि से अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25 जून 1962 में की गई। प्रतिष्ठान का मुख्यालय दिल्ली में है तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यकारिणी समितियाँ हैं। मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं तथा संचालक लाक शिक्षण इसके सचिव-कोषाध्यक्ष।

प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षक कल्याण निधि है। इस निधि में जनता, अभिभावक, बालिका एवं शिक्षकों के चन्दे से धन एकत्रित होता है। शिक्षकगण इस निधि को अपने वय की सामूहिक सुरक्षा का साधन मानकर इसमें योग्यशक्ति चँदा देते हैं एवं अन्य लोग शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर आर्थिक मदद करते हैं। प्रति वय लगभग 4-5 लाख रुपया इस निधि में एकत्र होता है। राज्य में जो भी राशि एकत्र होती है उसमें से 20 प्रतिशत राशि केंद्रीय निधि में जाती है तथा 80 प्रतिशत राशि राज्य में शिक्षक कल्याण गतिविधियाँ को चलाने के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति के पास रह जाता है। इस शिक्षक कल्याण निधि का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित नियमों के द्वारा किया जाता है। सारा धन मग्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठान के नाम पर होता है और उसके धन में जमा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एक बड़ी वन्द्रीय निधि स्थापित कर रहा है जिसकी सहायता से निम्न भविष्य में देश व्यापी शिक्षक कल्याण योजनाएँ प्रारम्भ की जा सकेंगी। म० प्र० में अभी तक 30 लाख से ज्यादा रुपयों की राशि एकत्र हुई जिसमें से 80 प्रतिशत राशि राज्य में रही तथा उससे अन्य शिक्षक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की गई।

म० प्र० शाखा के कार्य

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की मध्य प्रदेश शाखा ने काय कलाप इस प्रकार हैं—

- (1) सभागोय मुख्यालयों में राज्यस्तरीय शिक्षक दिवस आयोजन—वर्ष 1974 तक राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह प्रदेश स्तर पर राजधानी भापाल में ही आयोजित किया जाता था तथा इसमें केवल परम्परा का निर्वाह मात्र होता था। इससे इन आयोजना में शिक्षकों तथा अन्यो की रुचि घटने लगी थी। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस आयोजनों की इस नीरमता और निर्जीवता को भंग करने के लिए यह निणय लिया गया कि यह आयोजन बारी-बारी से प्रत्येक सभागोय मुख्यालय पर आयोजित किया जाय। उक्त निणय के अनुसार 1975 का शिक्षक दिवस राजधानी से परे हटकर रायपुर में आयोजित किया गया। इस प्रकार के आयोजनों से शिक्षक दिवस का आयोजन पूजन सजीव एवं सशक्त हो उठा है और इसके माध्यम से शिक्षकों तथा अन्य नागरिका के बीच परस्पर सौहार्द एवं सम्मान को एक अपूर्व भावना विकसित हुई है।

- (2) राज्य स्तरीय शिष्य पुरस्कार—अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने के लिए वर्ष 1974 स म० प्र० में राज्य स्तरीय शिष्य पुरस्कार की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्र-स्तर पर इस प्रकार की शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना विगत अनेक वर्षों से चल रही है किन्तु उस योजना की एक परिमीमा यह थी कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों की मद्या के अनुपात में काफी कम थे तथा ये पुरस्कार 20 वर्ष से अधिक नैतिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्राप्त होते हैं जो कि पुरस्कार प्राप्ति के समय तक अपने सेवा काल के अन्तिम चरण में पहुँच चुके होते हैं।

वस्तुस्थिति, परिश्रमी एवं सक्तीय शिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने की इस व्यवस्था के अतर्गत सेवा के मध्यकाल में 10 से 20 वर्ष की सेवा वाले, उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रोत्साहन एवं सम्मान की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस राज्य के शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने का एक उत्कृष्ट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अतर्गत प्रत्येक सभाग से 10 उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रमाण पत्र तथा 501 रुपये मगद

पुरस्कार देकर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के समारोह के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। इस राज्य स्तरीय पुरस्कार व्यवस्था के फलस्वरूप कम दीर्घकाल अनुभव वाले शिक्षकों को भी अपना शिक्षण उत्कृष्ट बनाने हेतु नई प्रेरणा मिली है।

- (3) शिक्षकों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्तियाँ—म० प्र० में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालायाँ में ऐसे अनेक शिक्षक हैं जिनका कि सारा जीवन दूसरों के घर में दीपक बनाने में व्यतीत हो जाता है किन्तु वे निधनता एवं शिक्षा के द्रा से दूर कार्यरत होने से अपने बच्चा के उच्च तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षकों के होनहार पुत्र/पुत्रियाँ की आर्थिक सहायता करने का नियम भी प्रतिष्ठान द्वारा लिया गया तथा इस नियम के फलस्वरूप यह योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत 1000 रूपय वार्षिक छात्रवृत्ति प्रति छात्र प्रदान की जाती है।

- (4) सकटग्रस्त शिक्षकों/शिक्षक परिवारों को आर्थिक सहायता—शिक्षण कल्याण निधि से राज्य शाखा मुद्रपत सकटग्रस्त शिक्षकों और शिक्षक परिवारों को सहायता पहुँचाती है। यह सहायता प्रतिष्ठान की महासमिति द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाती है। शिक्षकों/शिक्षक परिवार के सदस्यों की बीमारी, कन्या विवाह, शिक्षकों की विधवाओं के भरण-पोषण, चोरी, अग्निकांड की पूर्ति, अपंगता की स्थिति आदि कार्यों के लिए इसमें सहायता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षक कल्याण की कई अन्य योजनाएँ भी शिक्षण कल्याण प्रतिष्ठान के विचाराधीन हैं—

- (i) राज्य के चुने हुए अस्पताला में शिक्षकों एवं उनके परिवारों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष चिकित्सा बार्दों का निर्माण।
- (ii) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिक्षक सदन का निर्माण।
- (iii) राज्य के प्रमुख पयटन केंद्रों में शिक्षकों एवं उनके आश्रितों के लिए अवकाश गृहों की स्थापना।
- (iv) शिक्षकों की सहकारी संस्थाएँ निर्मित कर उनके माध्यम से राष्ट्रीय-कृत पाठ्यपुस्तकों के विक्रय की व्यवस्था करना।

इन योजनाओं के क्रिया काल के लिए मुख्य समस्या समुचित राशि उपलब्ध होना पर निर्भर है। इसलिए सबका यह पुनीत कर्तव्य है कि शिक्षक कल्याण निधि के लिए मुक्त हस्त से धन लिया जाय।

बालिका शिक्षा-निधि समिति

मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा निधि की स्थापना राज्य शासन द्वारा 14 नवम्बर 1972 में की गई एवं पञ्जीयन 13 दिसम्बर 1972 को दिया गया। बालिका शिक्षा निधि समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है जिससे अधिक से अधिक सख्या में बालिकाओं को आसानी से पढ़ाया जा सके। इस समिति के संरक्षक मध्य प्रदेश के राज्यपाल, साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति इस प्रकार है।

- 1 अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री
- 2 उपाध्यक्ष—शिक्षा सचिव
- 3 सदस्य—वित्त सचिव
- 4 , —ग्रामिण जाति कल्याण विभाग के संचालक
- 5 , —संचालक समाज कल्याण म० प्र०
- 6 , —अध्यक्ष म० प्र० महिला शिक्षा परिषद्
- 7 सचिव—संचालक लोक शिक्षण।

समिति के मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य की बालिकाओं या शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने का दृष्टि से निशुल्क गणवेश देना, पुस्तकें प्रदान करना, मध्याह्न भोजन, एवं महिला शिक्षिका आवास-गृहों का निर्माण तथा अन्य बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम। म० प्र० शासन शिक्षा-विभाग समय-समय पर इस समिति को अनुदान देता है।

बालिका शिक्षा निधि से निम्नानुसार कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे—

- 1—पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना—बक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना।
- 2 निशुल्क गणवेश—गरीब बालिकाओं को निशुल्क गणवेश।
- 3 मध्याह्न भोजन—गरीब बालिकाओं को खानाओं में खाने के लिए मध्याह्न आहार की व्यवस्था।

- 4 शिक्षिका आवास गृह—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाएँ अपनी आवास सुरक्षा न होने से वहाँ नहीं जाती हैं। अतः बालिका शिक्षा निधि से शिक्षिका आवास गृहों के निर्माण विचारगद्योतन है।

उद्देश्य

- (1) राज्य में बालिका शिक्षा प्रसार करना विशेषकर प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर।
- (2) पिछड़ी जातियों एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा के साधन जुटाना।
- (3) छात्रावासों को बिना भूतल गणवेश की व्यवस्था करना।
- (4) छात्रावासों को बिना भूतल पुस्तकें देने की व्यवस्था करना।
- (5) छात्रावासों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।
- (6) महिला शिक्षिकाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना।
- (7) बालिका शिक्षा प्रसार हेतु अन्य उपयोगी एवं सम्बद्ध कार्य करना।

कार्यपाल—शासकीय सदस्य, पदन सदस्य होंगे। अशासकीय सदस्यों का नामनाम दा कर का होगा। आजीवन सदस्य भूतल पय त सदस्य होंगे।

कार्यालय—मन्त्रालय लाव शिक्षण म० प्र० भोपाल।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण

(Curriculum and Renewal of Text Books)

पाठ्यक्रम नवीनीकरण की आवश्यकता—जिन प्रतिदिन बल्लता हुआ पान एवं विज्ञान तथा टेक्नालाजी के द्रुतगति के विप्लव व परिणामस्वरूप संसार के प्रत्येक दश में पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। आवश्यकताओं के अनुरूप हम अपने पाठ्यक्रमों को बदलना आवश्यक होता है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जहाँ पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से सशोधित और विकसित है वहाँ भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन और परिवर्धन की माँग की जाती है फिर भारत जैसे विकासशील देश में तो पाठ्यक्रम के बदलाव वह भी समय-समय पर अत्यन्त आवश्यक है। हमारा परम्परागत पाठ्यक्रम इतना बोलित है तथा पुराना है कि उसमें सशोधन आवश्यक हो गया है। इसमें बाक नई बातों को जोड़ना होगा और पुरानी अनावश्यक बातों को निकासना होगा।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य कायालियों के लिये कम चारा और अधिकारी पैदा करना था जो तब से भारतीय हैं किन्तु मन से अंग्रेज तथा अंग्रेजियत का हमारा है। परस्वरूप पाठ्यक्रम भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरचित किया गया। स्वतन्त्र भारत में शिक्षा में परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा का आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। पाठ्यक्रम, संविधान की भाँति देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अतएव उसे जनजीवन की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं बदलते हुये सामाजिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी बारीकियाँ से मेल खाता हुआ होना चाहिये। शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में उपादेयता, सामाजिक, राष्ट्रीय समन्वय, आधुनिकीकरण को बढ़ावा एवं सामाजिक नैतिक एवं आत्मिक मूल्यों का सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस प्रकार अभी तक जो शिक्षा पर आरोप था कि वह बालक और समाज से अलग है उसका निराकरण हो सकेगा। अब पाठ्यक्रम और उससे फिर दो जान वाली शिक्षा को जीवन की आवश्यकताओं एवं प्रतिदिन की सामाजिक

समस्याओं से जोड़ना होगा। शिक्षा का जीवन जीने वालों के जज्बातों से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है।

पाठ्यक्रम नवीनीकरण के लिये आवश्यक तत्व—किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनीकरण के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है।

- 1—साधनपूर्वक किया गया समुचित शोध जिससे सिखाये जाने वाले ज्ञान का चुनाव आधार उपयुक्त ढंग से निर्धारित किया जा सके। यह कार्य राज्य स्तरीय शिक्षा सस्थाना, एन० सी० ई० आर० टी० तथा शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किया जावे।
- 2—बालकों के अध्ययन के लिये पाठ्यपुस्तकें, अध्ययन सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का समुचित विकास।
- 3—शिक्षकों का उन्मुखीकरण, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा शिक्षा सगठनों द्वारा।
- 4—शालाओं को प्रयोग करने की समुचित स्वतन्त्रता। इनके प्रयोग में लाये जाने वाले पाठ्यक्रम अलग से विकसित किये जायें।
- 5—पाठ्यक्रम को उपलब्ध शिक्षकों, साधना, भौतिक सुविधाओं का मद्दे नजर रखते हुये सुधारना।
- 6—सशायन या परिवर्धित पाठ्यक्रम का क्रमशः लागू करना। यह आवश्यक नहीं है कि सभी शालाओं में नवीकृत पाठ्यक्रम एक साथ तथा सभी विषयों में प्रारम्भ किया जाय। शाला के साधनों के अनुरूप एक या अनेक विषयों में नवीकृत पाठ्यक्रम का लागू करने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। प्रारम्भ में भाषा, विज्ञान और गणित विषयों के नवीनीकृत पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जा सकता है।
- 7—माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सामान्य एवं नये पाठ्यक्रम दोनों में कुछ समय तक बाह्य परीक्षा का प्रबन्ध।
- 8—सम्पूर्ण राज्य में विषय शिक्षक सगठनों का विकास करके विषय शिक्षण को सम्पन्न तथा उन्नत बनाना, साथ ही इन विषयों के मूल्यांकन में सुधार करना। यह कार्य शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को करना चाहिये।
- 9—कुछ शालाओं में क्षेत्र परीक्षण के बाद सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करना।

2—बालक विज्ञान में जिज्ञासा के तरीके सीखे तथा वह समुदाय के जीवन में विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग कर सके ।

3—बालकों को चार मूल अरीय सम्बन्धी कार्यों में सुविधाओं का विज्ञान करना चाहिए । वह समुदाय में जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग कर सके ।

4—बालक प्रथम भाषा जो प्रायः उसको मातृ भाषा होती है उस पर सख्त सीखे जहाँ यह भाव-भाव से तथा लेखी-रुद्ध बातचीत से अपने विचार व्यक्त कर सके । वह द्वितीय भाषा पढ़ना भी सीखे ।

5—बालक स्वच्छता एवं स्वच्छ जीवन व्यतीत करने हेतु अपना दृष्टिकोण विकसित करे ।

6—बालक कुछ उपयोगी कार्य करे तथा धर्म के प्रति आदर की स्वस्थ अभिरुचि विकसित करे ।

7—बालक अच्छाई एवं मुँदरता में रुचि उत्पन्न कर सके तथा आसपास को भी देखे-भाले ।

8—बालक दूसरों से सहयोग करना सीखे तथा सामाजिक उत्तरदायित्व साफ-साफ कार्य करने की उपयोगिता को समझे । अन्य वांछनीय चारित्रिक एवं व्यक्तित्व के गुण जैसे पहल (Initiative) नेतृत्व, दया, ईमानदारी के विकास के साथ-साथ, स्कूल तथा पढाई के साथ ही समाज का विकास हो ।

9—बालक स्वतन्त्र रूप से अपने आपको रचनात्मक क्रियाशील मानकर कर सके तथा स्वाध्याय की आदत बना सके ।

उपर्युक्त उद्देश्य और परम्परागत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की तुलना यह स्पष्ट करती है कि प्राथमिक शिक्षा के कुछ नवीन उद्देश्य माने गए हैं—ये उद्देश्य हैं—श्रियानुभव, स्वस्थ जीवन, पढाई में उचित स्वच्छता, समाज के जीवन में विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग तथा रचनात्मक आत्मविकास ।

सूनीषेक सहायता प्राप्त प्रायोजना द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम नवीनीकरण

सूनीषेक सहायता प्राप्त प्रया०—क० 2—“प्राथमिक पाठ्यक्रम नवीनीकरण के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम परिवर्तन का आधार बड़ा होगा जैसा 10+2 शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर सुझाया गया है ।

इसी प्रकार प्रायोजना क्र० 5—“प्राथमिक पाठ्यक्रम व्यापक उपागम” में भी हमारा लक्ष्य बड़ी है । विनिश्चित यह है कि हम उपर्युक्त और सुविधा

वर्षों बालिका की शिक्षित करे, उन्हें जीवन की शिक्षा दे क्योंकि इस वर्ग की अभी तक हम जिनकी चिन्ता करनी चाहिए थी नहीं की थी।

नवीन शिक्षण तकनीक—नवीन विकसित एवं परम्परागत पाठ्यक्रम को ठीक से व्यवस्थित करने तथा लागू करने के लिए कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा, समान सेवा आदि क्षेत्रों को सक्षम बनाना होगा। शास्त्र स्तर पर विशेष विषयों का चुनाव कब, कैसे किया जाय यह सुनिश्चित करना होगा। नवीन शिक्षण विधियों तथा तकनीकों से शिक्षकों को परिचित कराना होगा। उन्हें उत्प्रेरित करना होगा। अवलोकन, प्रश्नोत्तर, भ्रमण, रेडियो, चतुर्विध आदि का उपयोग, प्रयोगशाला आदि नवीन विधियाँ में उन्हें पारंगत करना होगा। पर्यवर्तन की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

नवीन शिक्षण तकनीकों का उपयोग कैसे बढ़ाया जाय ?

- (1) वर्कशाप, सेमिनार, शालाभा का अवलोकन आदि आयोजन हो।
- (2) शिक्षक भाग दक्षिण तैयार की जाय।
- (3) शिक्षकों का नवाचार में स्वतन्त्रता दी जाय।
- (4) भाषा, विज्ञान, कार्यानुभव के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाय।
- (5) शिक्षा सभायाँ, राज्य स्तरीय सभायाँ की, शिक्षा महाविद्यालयों को अपने क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास के लिए सक्रिय किया जाय।
- (6) विषय शिक्षक संगठनों का विकास किया जाय।
- (7) शिक्षा प्रशासन में मुस्तैदी लाई जाय।

पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण की आवश्यकता—स्वतन्त्र भारत में हमने जो शिक्षा के लोकव्यापारण का सक्षम लिया था वह इतने वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। राष्ट्रीय-स्तर पर 6-11 आयु वर्ग में 83% दर्ज सख्या तथा 11-14 आयुवर्ग में 38 प्रतिशत दर्ज सख्या के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं। म० प्र० में यह स्थिति और भी खराब है। यहाँ 6-11 आयु वर्ग में 63% तथा 11-14 आयु वर्ग में 30.5 प्रतिशत बालक/बालिकाएँ ही शालाओं में आ रहे हैं। 6-14 आयु समूह को लें तो लगभग आधे बालक/बालिकाएँ शालाओं से बाहर हैं। हमने छात्र कृतियाँ, मुफ्त पुस्तकें, गणवेश और छात्र-वास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है तो भी इच्छित सक्षम की प्राप्ति नहीं हो सकी है। जो बच्चे स्कूल आते भी हैं वे कठिन कारणों से शाला त्याग देते हैं। कक्षा 5 पास करने के पूर्व लगभग 66% बालक शाला त्याग देते हैं।

और कक्षा 8 पास करत-करत 75 प्रतिशत ज्ञान त्याग देते हैं। इन सबके प्रमुख दो कारण हैं—बालिका की गरीबी तथा शिक्षा में अरुचि।

किए गए सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हुई है कि सभी बच्चे जा ज्ञान-त्यागी या ज्ञान-अप्रवेशी हैं वे निश्चय सभी नहीं हैं। कुछ उनमें समथ हैं। हमारी जो धारणा थी कि हमारी शिक्षा हमारा पाठ्यक्रम हमारी पाठ्यपुस्तकें जीवन की इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, शिक्षा जीवन से अलग विलग है वह स्पष्ट रूप से सामने आया है। यदि सभी बच्चा को पढ़ाना है तो अविलम्ब दो काम करने होंगे, एक तो एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होगा जो बच्चा और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनके भविष्य के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए सक्षम बना सके। दूसरा काम हमें करना होगा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन का।

शिक्षा का आकषक बनाने के लिए जीवनोपयोगी बनाना होगा। पुस्तकों का जीवन से जोड़न पर ही वे गाँव में रहने वाले बहुसंख्यक समाज के लिए जीवनोपयोगी बन सकेंगी। इससे शिक्षा की साक्षरता बढ़ेगी और उससे आकषण बढ़ेगा। वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का समझाने की शैली जो अपनाई गई है वह बहुत व्यर्थ साध्य है एवं सभी परिवर्तन के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए छोटे बालकों को पानी उबालने के लिए काच का बीकर और स्ट्रिट लैंप का उदाहरण देकर समझाया गया है। कक्षा 1 में 'न' नल का 'ज' जहाज का आदि बताकर वर्णमाला के अक्षरों को समझाया गया है। गाँव के बच्चा न बीकर, स्ट्रिट लैंप, नल और जहाज नहीं देखा है। यदि हम पाठ्यपुस्तकों के उदाहरण बच्चा के आसपास के परिवेश से दें तो उनकी समझ में भी आयेगी और वे अध्ययन में रुचि भी लेंगे।

बालिकाएँ तथा उनके अभिभावक भी शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बालिकाओं की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। अतः हम उनके लिए उपयोगी एवं पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें निर्माण करना होगा जिसमें बालिकाओं को ऐसा ज्ञान मिल सके जो उन्हें भविष्य में सुखद जीवन निर्वाह करने में सहायक सिद्ध हो।

आज पूरी तरह विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक की तानाशाही चल रही है। शिक्षकण ज्ञान को पढ़ात-ममज्ञात हैं जो पाठ्यपुस्तक में लिखा रहता है। पुस्तक ही ज्ञान राशि की सचिनी कोष बन गई है। शिक्षक स्वयं चिंतन न कर पुस्तक पढ़ता है और छात्र को भी किताब पढ़ने का निर्देश देता है। परिणाम यह हुआ कि हमारा सम्बन्ध वास्तविक स्थिति से छूट गया है, हम

अपने वास्तविक जीवन, परिवेश में अनगण्य हो गए हैं। शिक्षक और छात्र में सोचने, चिन्तन करने की शक्ति समाप्त हो रहा है। पाठ्यपुस्तक में जिस प्रकार हिन्दी के पाठ पढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में भाषाचर्चा कराया जाता है। न तो विज्ञान में प्रयोगों की आवश्यकता समझी जाती है और न ही भूगोल में मानचित्रों की। चूंकि शिक्षण पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर हो गए हैं अतः पाठ्यपुस्तकों को इस प्रकार लिखने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है कि वे बच्चों के परिवेश के आधार पर लिखी जाएं ताकि वे अपने परिवेश से जुड़े रहें उसमें उनका तात्पर्य बना रहे।

एक बार हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्र बिनाकुल ही पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर हैं दूसरी ओर हमारी पुस्तकें शहरी परिवेश पर आधारित हैं अतः ग्रामीण बच्चों को ग्राह्य और बाधक नहीं हैं। अतः पाठ्यपुस्तकों के नवीनीकरण की योजना आवश्यक हुई। इस योजना के अनुसार ग्राम भारती, बालिका भारती, गृह भारती, माँ भारती आदि पुस्तकें तैयार की गई हैं। आदिवासी बालकों के लिए वन भारती तैयार हुई है।

ग्राम भारती

- (1) कक्षा 1 से 5 तक समस्त विषयों की नई किताबें जो ग्रामीण परिवेश के लिए लिखी गई हैं, ग्राम भारती कहा गया है। इनमें म० प्र० शासन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक शास्त्री पाठ्यक्रम का यथावत स्वीकार किया गया है।
- (2) जात से अज्ञान के शिक्षण मूल पर ग्राम भारती का दर्शन विकसित किया गया है।
- (3) सभी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में हैं। हिन्दी व क्षेत्रीय बोलियों में प्रयोग हो रहे शब्दों के सम्बंधों के आधार पर एक विशिष्ट भाषा नीति का पालन किया गया है।
- (4) ग्राम भारती की पुस्तकें शासन द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के समतुल्य एवं समान स्तरीय बनाई गई हैं।
- (5) प्रचलित राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें शहरी परिवेश पर आधारित होने के कारण ग्रामीण बच्चों के लिए अव्यक्त गम्य एवं अमानवज्ञानिक थीं अतः ग्राम भारती की पाठ्यपुस्तकों में शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की अंतर्धारणाओं एवं विषयवस्तु को ग्रामीण बच्चों के

- (3) यह भिन्न प्रकार की शिक्षा नहीं है। इसका स्तर बालिका व स्तर सतम नहीं है दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है परीक्षा एक समान है।
- (4) बालिका भारती की पुस्तिका को ग्रामीण पर्यावरण पर आधारित करके बालिकाओं के लिए इस प्रकार लिखा गया है कि उनके लिए बाध्यगम्य तथा जीवनापयोगी बन सके।
- (5) सभी विषयों के लिए प्राथमिक स्तर की बालिका भारती पाठ्य-पुस्तकें लिखी गई हैं तथा सभी को इच्छानुसार पाठ्यपुस्तकें पढ़ने की छूट रहेगी।

गृह भारती—कक्षा 1 से गृह विज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित कर जो पुस्तकें लिखी जायगी उन्हें गृह भारती कहा जायगा। गृह विज्ञान और गृह भारती में आधारभूत अंतर है। गृह विज्ञान तो एक विषय है जब कि गृह भारती एक पूर्ण शिक्षा दर्शन है। गृह भारती में गृह विज्ञान विषय का कार्य के रूप में, ज्ञान का आधार माना गया है। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने उद्योग, प्रवृत्ति और समाज के माध्यम से शिक्षा देने के जिस सिद्धांत को रखा था उसी का यह व्यावहारिक रूप है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्य करेगी जैसे कि खाना बनाएंगी, कपड़ा सिलेगी या घर सजाएंगी। यह सभी कार्य करने के लिए उन्हें जिन गणि, विज्ञान, भाषा की आवश्यकता होगी उतना ज्ञान व स्वाभाविक रूप में प्राप्त करती रहेगी।

गृह भारती में ऐसा पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है जो जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित हो और जिसकी समस्त सामग्री ग्रामीण समाज में उपलब्ध हो। गृह भारती का पाठ्यक्रम बनाने के लिए तीन प्रकार से प्रयास होगा—

- (1) अध्यापिकाएँ ग्रामीण बालिकाओं के कार्यालयों का अध्ययन कर उसके भविष्य के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का समर्थन और उसके परिवेश, साधन, और स्रोतों का पता लगावें। इस प्रकार स्वयं सोचकर पाठ्यक्रम बनाया जावेगा तो सही स्वाभाविक और व्यावहारिक होगा।
- (2) कक्षा 1 से गृह विज्ञान प्रारम्भ होकर स्नातकोत्तर तक चलेगा। इस गृह भारती का संकल्प कहा जायगा। गृह भारती का संकल्प कक्षा 1 से प्रारम्भ होकर विश्वविद्यालय तक होगा।
- (3) इसका पाठ्यक्रम और स्तर म० प्र० शासन द्वारा स्वीकृत सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो रहेगा।

शैक्षिक सांख्यिकी

(Educational Statistics)

सांख्यिकी क्या है ? हम कई काम करते तो रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि वह क्या है ? महिलाएँ घरों में रोजाना ही दाल, चावल बनाती हैं, दो चार चावल टटोलकर पूरे चावला के पकने या कच्चे होने का पता लग जाता है । पूरे महीने का खजाना हम सभी बनाते हैं, तापक्रम की नाप करते हैं, जनसंख्या की गणना करते हैं । इन सभी रोजमर्रा के क्रियाकलापों में सांख्यिकी एवं सांख्यिकी विधियाँ स्पष्ट नजर आती हैं । सांख्यिकी में आँकड़ों का पक्षपात रहित, सकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं विवेचन निहित है । इस प्रकार सांख्यिकी उन तथ्यों के सकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है जो विधिपूर्वक संकलित किए गए हों जिनके सकलन में किसी प्रकार का पक्षपात न किया गया हो और जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के हेतु संकलित किए गए हों ।

सांख्यिकीय आँकड़ों की विशेषताएँ—सांख्यिकीय तथ्यों / आँकड़ों की चार प्रमुख विशेषताएँ होनी चाहिए—

- (1) पक्षपात रहित—सारे तथ्य / आँकड़े पक्षपात रहित हों ।
- (2) समय पर उपलब्ध हो—आँकड़े समय पर उपलब्ध हों तभी सही उपयोग हो सकता है ।
- (3) सही हों—जो तथ्य एकत्र किए जाय वे सही हों ।
- (4) प्रमाणिकता—तथ्य प्रमाणिक हों ।

शैक्षिक सांख्यिकी क्या है ?—शिक्षा से सम्बंधित सभी प्रकार के तथ्य या आँकड़े शैक्षिक सांख्यिकी के अन्तर्गत आते हैं यथा छात्रों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग में उनकी संख्या, स्तरवार छात्र संख्या, शैक्षणिक संख्या, परीक्षा परिणाम, शिक्षा से सम्बंधित आय व्यय के आँकड़े, शाला भवनों की संख्या आदि आदि ।

आज के युग में सांख्यिकी का महत्व काफी बढ़ गया है । आज कोई भी सूचना बिना सांख्यिकी के अधूरी मानी जाती है । हम जितना भी सम्बा छोड़ा भाषण दे लेकिन उसमें तथ्य या आँकड़े न दिए जाय तो वह बलबलदाँर नहीं

बन सकता है। सांख्यिकी द्वारा हमारे कफन की पुष्टि होनी है। प्रदेश या राष्ट्र की आर्थिक, वैश्विक स्थिति, वैश्विक विस्तार आदि ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग करते हैं। आयोजना काय बिना सांख्यिकी तथ्यों की सहायता लिए हो ही नहीं सकता है। अनुसंधान तो सांख्यिकी के बिना असंभव न सही, अधूरा तो है ही। कई तथ्यों का पूर्वानुमान सांख्यिकीय विधि या द्वारा किया जाता है। अगले 5-10 वर्षों में हमारे जनसंख्या क्या होगी उसके लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ होंगी इनका पूर्वानुमान सांख्यिकी द्वारा ही लगाया जा सकता है।

सांख्यिकी के काय एवं उद्देश्य—सांख्यिकी के निम्नानुसार काय और उद्देश्य हैं—

(1) जटिल तथ्यों का सरल रूप में प्रस्तुत करना—जटिल तथ्यों की सांख्यिकीय विधियों द्वारा हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उससे महिन्क में स्पष्ट बात समझ में आ जाती है। रेखा चित्र, स्तम्भ चित्र आदि द्वारा स्पष्ट बात समझ में आ जाती है।

(2) तथ्यों से सम्बन्धित आँकड़ों को प्रकट करना—जटिल तथ्यों की सरलता से प्रकट किया जा सकता है। यदि हम कहें कि अधिकांश छात्र पढ़ते आ रहे हैं तो स्पष्ट बात नहीं होती है यदि इसी को कहा जाय कि 80 प्रतिशत बालक शाळाओं में आ रहे हैं तो स्थिति का सही अंदाज लगता है।

(3) तुलनात्मक अध्ययन—एक प्रकार के तथ्यों की तुलना दूसरे तथ्यों से करने पर सही स्थिति पता लगती है। उदाहरण के लिए आदिवासी छात्रों की शिक्षा की तुलना जब हम गैर आदिवासी छात्रों से करते हैं तो ही सही स्थिति हमारे सामने आती है। पिछली जनगणना के आँकड़ों से अभी की जनगणना के आँकड़ों से करने पर कई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या कितनी बढ़ी, साक्षरता कितनी बढ़ी, आदि अनेक बातों का अंदाज तुलना करने पर ही होता है।

(4) शोध कार्यों में सहायता—शोध काय में सांख्यिकी अत्यन्त आवश्यक है। सांख्यिकी शोध कार्य में सहायता करती है। जब तक सांख्यिकी का प्रयोग न होगा शोध-कार्य प्राथमिक नहीं माना जा सकता है।

सांख्यिकीय निष्कर्षों के मोपान—आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित मोपान (Steps) प्रयोग में लाये जाते हैं—

(1) कार्य की आयोजना (Planning)

- (2) आँकड़ों का एकत्रीकरण (Collection of Data)
- (3) आँकड़ों का सम्पादन (Compilation of Data)
- (4) वर्गीकरण तथा सारिणीबद्ध (Classification & Tabulation of Data)
- (5) प्रस्तुतीकरण (Presentation)
 - (अ) ग्राफ द्वारा
 - (ब) रेखा चित्रों द्वारा
 - (स) चित्रों द्वारा
- (6) विश्लेषण (Analysis of Data)
- (7) विवेचन (Interpretation of Data)
- (8) रिपोर्ट लिखना (Report Writing)

इन सोपानों से गुजरते हुए जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वे सही होंगे।

शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग—आज शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के प्रयोग की अनिवार्यता काफी बढ़ गई है। शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग इस प्रकार है—

1. बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता पता लगाने के लिए—आज यह अनिवार्य हो गया है कि बच्चा की व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाय जिससे उनके अनुकूल वह शिक्षा दी जा सके। इसके लिए बुद्धि परीक्षण, रचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण होने लगे हैं।

2. दो विषयों के प्राप्तांकों में सह सम्बन्ध निकालने के लिए—शालाओं के दो परीक्षाओं के प्राप्तांकों के बीच सह सम्बन्ध गुणांक निकालकर यह ज्ञात किया जाता है कि किन-किन विषयों में समान योग्यता निहित है।

3. परीक्षाओं का प्रभावीकरण (Standardisation)—आजकल परीक्षाओं का प्रमाणीकरण करने हेतु मनावैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान्य स्तरों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है जैसे प्रतिशतीय सामान्य स्तर (Percentile Norm) आयु सम्बन्धी सामान्य स्तर (Age Norm), श्रेणी सम्बन्धी सामान्य स्तर (Grade Norm) आदि। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय विधियाँ का प्रयोग किया जाता है।

4. शैक्षिक शोध में उपयोग—शिक्षा सम्बन्धी शोधों तथा पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षा सम्बन्धी माग दर्शन, बालकों द्वारा यह कार्य किया जाना,

पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की उपयुक्तता, शाला समय और अवकाश की उपयुक्तता, आदि विषयों पर शोध कार्यों में सांख्यिकी का प्रयोग नितान्त आवश्यक है।

5 आयोजना कार्यों के लिए—शैक्षिक आयोजन में सांख्यिकी का प्रयोग अपरिहार्य रूप से किया जाता है। शिक्षा की वार्षिक, एवं पञ्चवर्षीय योजनाएँ सांख्यिकी पर ही आधारित हैं। अगले वर्षों में हमें कितनी खानाएँ खोसनी होगी, कितने शिक्षक चाहिए होंगे, क्या व्यय होगा, साधन, उपकरण शाला भवन कितने आवश्यक होंगे यह सब सांख्यिकी द्वारा ही पूर्वानुमान लगाकर आयोजना किया जाना समभव है।

6 बजट में उपयोग—शैक्षिक बजट तो पूरा सांख्यिकीय आँकड़ों का ही है। पिछले वर्षों में कितना व्यय हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में कितना बजट शिक्षा के लिए आवश्यक होगा यह सब सांख्यिकी द्वारा ज्ञात-कर योजना बनाना समभव होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में सांख्यिकी के बिना न तो हम सोच सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, और न कुछ बोल सकते हैं। सांख्यिकीय आँकड़ों के साथ कही हुई बात ही सही और स्पष्ट मानी जा सकती है।

देश एवं मध्य प्रदेश से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी

(1) साक्षरता प्रतिशत (1971)

	भारत	मध्य प्रदेश
कुल	29 45	22 14
पुरुष	39 45	32 70
महिला	18 70	10 92

(2) स्कूल जाने योग्य बालक बालिकाओं की कुल जनसंख्या (1978)

आयु वर्ग	भारत		मध्य प्रदेश
	बातन-बालि०	कुल जनसंख्या प्रतिशत	बालक-बालि०
6-11	8 37 करोड़	13 5%	71 5 लाख
11-14	4 60 ,,	7 4%	37 7 ,,

14-17	4 20 „	6 8%	43 5 „
6-17	17 20 „	27 7%	152 5 „

(3) शालाओं की संख्या (78-71)

संस्थाओं का प्रकार	भारत	म० प्र०
1 पूर्व प्राथमिक शालाएँ	9172	482
2 प्राथमिक शालाएँ	474993	54417
3 मिडिल स्कूल	110902	9540
4 उच्चतर मा० शालाएँ	43842	2133
5 इंटर कालेज	3017	^
6 बुनि०प्रशि०संस्थाएँ	857	47
7 शिक्षा महाविद्यालय	496	15
8 कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय	3271	230
9 विश्वविद्यालय	106	10

(4) छात्र संख्या स्तरवार (1978-79) (संख्या लाखों में)

स्तर	भारत	मध्य प्रदेश
1 कक्षा I-V (साखी में)	723 90	44 50
6-11 आयु वर्ग में प्रतिशत	48 9	63 00
2 कक्षा VI-VIII (साखी में)	185 10	11 43
11-14 आयु वर्ग में प्रतिशत	39 8	30 50
3 कक्षा IX-XI-XII	90 80	4 33
14-17 आयु वर्ग में प्रतिशत	20 6	13 00

(5) शिक्षक संख्या (1978-79)

शालाएँ	भारत	मध्य प्रदेश
1 प्राथमिक शालाएँ	1294793	111208
2 पूर्य माध्यमिक शालाएँ	812075	55586
3 उच्च/उच्चतर माध्य० शालाएँ	749096	31691
योग	28,55,964	1,98,735

6 हरिजन आदिवासियों छात्रों की दल सख्या (लाखों में) (1978-79)

भारत

मध्यप्रदेश

स्तर	हरिजन	आदि	हरि०	आदि०
6-11 आयु वर्ग	101 59 (79 9)	42 01 (66 4)	5 46 (65 2)	6 38 (49 50)
11-14 आयु वर्ग	19 02 (26 5)	6 40 (17 9)	1 21 (8 42)	0 89 (12 63)
14-17 आयु वर्ग	8 26	2 71	0 34 (2 15)	0 23 (3 68)

(7) शिक्षक छात्र अनुपात

	भारत	मध्य प्रदेश
प्राथमिक	40	38
माध्यमिक	32	25
उच्चतर माध्यमिक	25	22

(8) एक शाळा द्वारा घोषित औसत क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)

	भारत	मध्य प्रदेश
प्राथमिक शाळा	6	8
माध्यमिक शाळा	30	50
उच्चतर मा० शाळा	75	213

(9) एक शाळा द्वारा सामावित औसत जनसंख्या

	भारत	मध्य प्रदेश
प्राथमिक शाळा	1335	800
माध्यमिक शाळा	5500	5000
उच्चतर मा० शा०	14,750	20,000

(10) प्रति शाळा औसत दल सख्या

	भारत	मध्य प्रदेश
प्राथमिक शाळा	150	74
माध्यमिक शाळा	160	158
उच्चतर माध्यमिक शाळा	620	335

भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों की शिक्षा संस्थाएँ, छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या

(1) संस्थाएँ	1950-51	55 56	60-61	65-66	78-79
(1) प्राथमिक/सू० बेसिक	209671	278135	330399	391064	474952
(2) मिडिल/सीनि० बेसिक	13596	21730	49663	75798	110902
(3) हाई/शायर से० स्कूल -	7288	10838	17257	27477	46473
(4) सह० उ० मा० वि०	—	255	2115	2386	—
(5) प्रशिक्षण संस्थाएँ	782	930	1138	601	857
(6) ट्रेनिंग कॉलेज	53	107	478	1272	1296
(7) कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय	542	772	1122	1788	3271
(8) विश्व विद्यालय	27	32	45	64	106
(अ) छात्र संख्या					
(1) कक्षा I से V की दर्ज संख्या (साथों में)	191 50	251 70	349 90	504 70	723 90
6-11 आयु वर्ग में प्रति०	42 6	52 8	62 4	76 7	84 9
(2) कक्षा VI से VIII की दर्ज संख्या (साथों में)	31 20	42 90	67 00	105 30	185 10

11-14 आयु वर्ग में प्रति०

(3) कक्षा IX से XI-XII

(साक्षी में)

14-17 आयु वर्ग में प्रति०

(4) कक्षा विज्ञान, वाणिज्य

महावि० में दर्ज सब्बा

(साक्षी में)

17-23 आयु वर्ग में प्रति०

(5) विश्व विद्यालय स्तर पर

विज्ञान पत्र रहे छात्रों का

प्रतिशत

(स) शिक्षक सब्बा

(1) प्राथमिक शालाओं में

प्रशि० शिक्षकों का प्रति०

(2) मिडिल स्कूलों में प्रति०

शिक्षकों का प्रतिशत

(3) हाई, हायर मेक० स्कूलों में

(4) महाविद्यालयों, विश्व

विद्यालयों में

165

1880

127

1220

53

360

08

378

537918

588

85496

533

126504

18648

225

2890

106

890

18

269

741515

641

345228

665

296305

41759

308

5040

162

1490

27

293

944377

705

527774

769

479060

66882

398

9080

206

3030

41

—

1294793

853

812075

880

749096

—

शासन और योग्य हरिजन एवं आदिवासी बालक/बालिकाओं को प्रतिगत जनसंख्या (1978-85)
(संख्या एकड़ों में)

(Scheduled Caste)

(1) Group 6-11	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	9427	9655	9888	10128	10373	10624	10880	11144
Male	4884	5008	5136	5267	5401	5539	5680	5825
Female	4543	4651	4752	4861	4972	5085	5200	5321

(2) Age Group 11-14

Total	4950	5124	5304	5486	5678	5876	6081	6294
Male	3568	3655	3746	3839	3936	4035	4139	4244
Female	2382	2469	2558	2647	2742	2841	2942	3050

(3) अनुसूचित जन जाति (Schedule Tribes)

	78	79	80	81	82	83	84	85
(1) Age Group 6-11								
Total	14504	14855	15214	15582	15959	16345	16740	17145
Male	7290	7481	7642	7868	8069	8274	8486	8702
Female	7210	7374	7572	7714	7890	8071	8254	8443
(2) Age Group 11-14								
Total	7615	7882	8157	8441	8736	9041	9357	9683
Male	3837	3967	4102	4242	4386	4535	4689	4849
Female	3778	3915	4053	4199	4350	4506	4668	4834
(3) Age Group 14-17								
Total	4963	5079	5197	5317	5440	5566	5694	5825

Male	2555	2620	2689	2758	2829	2901	2975	3051
Female	2408	2459	3108	2559	2611	2665	2719	2774
4) Age Group 14-17								
Total	7637	7814	7996	8181	8370	8564	8761	8962
Male	3821	3919	4022	4126	4232	4311	4453	4567
Female	3816	3895	3974	4055	4138	4223	4308	4395

11/12/21

मध्य प्रदेश निर्माण से अब तक शैक्षिक प्रगति (शालेय शिक्षा)

(अ) शाखाएँ	1956-57	1960-61	1965-66	1970-71	1974-75	1979-80
पूर्व प्राथमिक	70	169	276	296	394	482
प्राथमिक एवं उपशाखाएँ	22,762	27,781	34,435	36,980	51,055	56,402
पूर्व माध्यमिक	1,604	2,445	4,547	5,851	8,346	6,540
उच्चतर माध्यमिक	414	774	1,297	1,656	1,995	2,133
(ब) छात्र सख्या						
पूर्व प्राथमिक	4,916	11,594	16,632	20,256	24,469	66,619
प्राथमिक-उपशाखा	12,71,000	16,81,000	23,75,000	25,96,242	35,89,766	43,12,102
पूर्व माध्यमिक	3,42,000	4,88,000	8,16,000	9,96,567	11,07,866	14,78,132
उच्चतर माध्यमिक	1,55,000	2,78,000	4,96,000	5,89,690	6,11,297	7,27,239
(स) शिक्षा सख्या						
पूर्व-प्राथमिक	214	415	471	548	712	780
प्राथमिक-उपशाखा	44,499	57,064	71,631	79,943	1,05,485	1,13,187
पूर्व माध्यमिक	15,326	21,898	33,402	3,336	46,670	57,931
उच्चतर माध्यमिक	7,507	13,730	21,437	25,291	30,854	32,794

शालेय शिक्षा पर व्यय (लाखों में)

	व्ययोजन	आयोजनोत्तर	योग
1956-57	230,00	493,39	723,39
1960-61	388,00	905,05	1293,05
1965-66	730,00	2730,51	2730,51
1970-71	476,81	4341,69	4818,50
1974-75	254,19	7677,00	7931,19
1979-80	918,00	11792,00	12710,00

